

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—पौष 7, शक 1937

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 3-9-2015-50-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) "परित्यक्त" से ऐसा लावारिस और परित्यक्त बालक अभिप्रेत है, जो समिति द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया है,
- (ख) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 33) तथा संशोधित अधिनियम, 2011 (2011 का सं. 12) द्वारा यथा-संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) अभिप्रेत है।
- (ग) "बालक का सर्वोत्तम हित" से किशोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया निर्णय अभिप्रेत है।
- (घ) "बालक के अनुकूल" से ऐसी कोई प्रक्रिया और निर्वचन, दृष्टिकोण, वातावरण एवं व्यवहार अभिप्रेत है जो मानवीय, विचारशील एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।
- (ङ) "समुदाय सेवा" का अभिप्राय है कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों द्वारा अन्य न्यायिक उपचार और शास्तियों के स्थान पर, समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा, जो तिरस्कारपूर्ण और अमानवीय न हो, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हो सकेंगे।
 - (एक) पार्क की सफाई करना।
 - (दो) यातायात प्रबंधन में सहायता करना।
 - (तीन) परिचर्या गृहों में वृद्धों की सेवा करना।
 - (दो) यातायात प्रबंधन में सहायता करना।
 - (तीन) परिचर्या गृहों में वृद्धों की सेवा करना।
 - (चार) स्थानीय अग्निशमन या पुलिस विभाग की सहायता करना।
 - (पांच) स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करना।
 - (छह) विकलांग बच्चों की सेवा करना।
- (च) "निरोध" से विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले में सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, "संरक्षणात्मक अभिरक्षा" अभिप्रेत है।
- (छ) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र।
- (ज) "वैयक्तिक देखरेख योजना" किसी किशोर या बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस किशोर या बालक की आयु-विशिष्ट और लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस किशोर और बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे किशोर या बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से उसके साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और इस योजना में किशोर अथवा बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।
 - (एक) स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।

- (दो) यातायात प्रबंधन में सहायता करना।
 (तीन) परिचर्या गृहों में वृद्धों की सेवा करना।
 (चार) स्थानीय अग्निशमन या पुलिस विभाग की सहायता करना।
 (पांच) स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करना।
 (छह) विकलांग बच्चों की सेवा करना।
- (च) "निरोध" से विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले में सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, "संरक्षणात्मक अभिरक्षा" अभिप्रेत है।
- (छ) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र।
- (ज) **"वैयक्तिक देखरेख योजना"** किसी किशोर या बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस किशोर या बालक की आयु-विशिष्ट और लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस किशोर और बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे किशोर या बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से उसके साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और इस योजना में किशोर अथवा बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।
- (एक) स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।
 (दो) भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं।
 (तीन) शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं।
 (चार) विश्राम, सृजनात्मकता एवं खेलकूद।
 (पांच) भावनात्मक लगाव और नातेदारी।
 (छह) सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण।
 (सात) समाज की मुख्य धारा में शामिल करना ; तथा
 (आठ) निर्मुक्त तथा प्रत्यावर्तन के पश्चात् उसका अनुवर्तन।
- (झ) **"संस्था"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उप धारा (3) तथा धारा 37 के अधीन स्थापित, प्रमाणित या मान्यताप्राप्त एवं रजिस्ट्रीकृत कोई प्रेक्षणगृह या कोई विशेष गृह या कोई बालगृह या कोई आश्रय गृह।
- (ञ) **"प्रभारी अधिकारी"** अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे अन्य किसी पदनाम से अभिप्रेत है, संस्था के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त व्यक्ति;
- (ट) **"अनाथ"** से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका माता-पिता या इच्छुक एवं सक्षम विधिक अथवा नैसर्गिक संरक्षक नहीं है,
- (ठ) **"सुरक्षित स्थान"** से अभिप्रेत, है विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के लिये अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (3) और धारा 16 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित एवं मान्यताप्राप्त कोई संस्था

- (ड) "मान्यताप्राप्त" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) और (झ) के अनुसार, मान्यता प्रदान किए गए व्यक्ति, जिनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माना गया हो या वे संस्थाएं, जिनको सक्षम अधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त माना गया हो या वे संस्थाएं अथवा अभिकरण अथवा स्वैच्छिक संगठन, जिनको बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या परवर्ती देखरेख संगठन के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धारा 37 की उप धारा (1), धारा 41 की उप धारा (4) और धारा 44 के खण्ड (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो,
- (ढ) "पंजीकरण" से अभिप्रेत है, वे सभी संस्थाएं या अभिकरण या स्वैच्छिक संगठन जो धारा 34 की उप धारा (3) के अधीन देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को आवासीय देखभाल प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं;
- (ण) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार,
- (त) "निराश्रित और कामकाजी बालक" से अभिप्रेत है, वे बालक जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) (1) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार जीवन निर्वाह, देखरेख, संरक्षण एवं सहायता के दृश्यमान साधनों से रहित हों,
- (थ) "अभ्यर्पित बच्चे" से अभिप्रेत है, समिति के राय में शारीरिक, भावनात्मक एवं ऐसे सामाजिक कारणों से त्यागे गये बच्चे जो माता-पिता या अभिभावक के वश में नहीं है,
- (द) "विशेष आवश्यकताओं वाला बालक" विशेष आवश्यकताओं वाला बालक वह होगा जिसकी उचित देखरेख और पुनर्वास सुकर बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाएं या मध्यक्षेप आवश्यक हों।
- (ध) "पोषक देखरेख" से अभिप्रेत है किसी बालक का केन्द्रक (न्यूक्लीय) कुटुम्ब या समूह पोषण गृह के साथ रखा जाना।
- (न) "दत्तक पूर्व पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है किसी बालक का किसी कुटुम्ब में किसी स्थायी गृह में बालक के पुनर्वास तक अस्थायी रूप से रखा जाना।
- (प) "पोषक बालक" से अभिप्रेत है ऐसा बालक जिसे पोषक माता-पिता या पोषक कुटुम्ब के साथ रखा गया हो।
- (फ) "पोषक माता-पिता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो किसी बालक के माता-पिता नहीं हैं, किंतु जो सम्पत्ति आदि के आवश्यक विधिक अधिकारों के बिना बालक के माता-पिता के रूप में उसकी देखरेख और भरण-पोषण के लिए जिम्मेदारी लेने को रजामंद हैं।
- (ब) "विस्तारित कुटुम्ब" से अभिप्रेत है बालक के वे रिश्तेदार, जिनके साथ उसे पोषण देखरेख में रखा जा सकता है।
- (भ) "समूह पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है एक कुटुम्ब में या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे समूह पोषक गृह में बालकों के किसी समूह की देखरेख।
- (म) "जिम्मेदारी लेना" से अभिप्रेत है बालक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा संपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना।
- (ब) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय 2किशोर न्याय एवं बालकों के संरक्षण के आधारभूत सिद्धान्त

3. इन नियमों के प्रशासन में अनुपालित किए जाने वाले आधारभूत सिद्धान्त,—

- (1) जब इन नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन करते समय, यथास्थिति, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण या अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुपालन करेगा और इनसे मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे।
- (2) निम्नलिखित सिद्धांत, अन्य बातों के साथ, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुप्रयोग, निर्वचन एवं कार्यान्वयन का आधार होंगे।

(एक) निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धान्त—

- (क) किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर को 18 वर्ष की आयु तक असदभावनापूर्वक या आपराधिक आशय रखने का दोषी नहीं माना जाएगा।
- (ख) किशोरों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को समस्त न्याय एवं संरक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे या किशोर से प्रथम संपर्क से लेकर वैकल्पिक देखभाल एवं पश्चात्तर्वर्ती देखरेख तक मान्यता दी जाएगी।
- (ग) किसी किशोर अथवा बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर जिसे वह जीवित रहने के लिए, या वातावरण या परिस्थितियों के कारणों से अथवा वयस्कों के नियंत्रणाधीन अथवा साथियों के दबाव में किए गए किसी विधिविरुद्ध आचरण को निर्दोषिता के सिद्धांतों के अन्तर्गत शामिल किया जाए।
- (घ) निर्दोषिता का उपधारणा के सिद्धान्त के मूलभूत घटक इस प्रकार हैं :—

(एक) निर्दोषिता की आयु,— निर्दोषिता की आयु वह आयु होती है, जिससे कम आयु में किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक पर दाण्डिक न्याय प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है। बीजिंग नियम 4 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक उत्तरदायित्व की प्रारम्भिक आयु के रूप में बहुत कम आयु निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुरूप विश्व भर में किसी किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता की आयु अठारह वर्ष से अधिक मानी जाती है।

(दो) निर्दोषिता के सिद्धान्त का प्रक्रियात्मक संरक्षण,— संविधान और अन्य संविधियों द्वारा वयस्कों को प्रत्याभूत किए गए सभी प्रक्रियात्मक रक्षोपाय और वे रक्षोपाय जो किशोर या बालक की निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को बल प्रदान करते हैं, वे सभी रक्षोपाय किशोरों या बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को प्रत्याभूत होंगे।

(तीन) विधिक सहायता और वादार्थ संरक्षक के उपबंध,— विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को यह अधिकार है कि उन पर लगाए गए आरोपों के विषय में उन्हें सूचित किया जाए तथा उन्हें विधिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के खर्च पर विधिक सेवा के माध्यम से वादार्थ संरक्षक, कनूनी सहायता और ऐसी अन्य कोई सहायता प्रदान करने के उपबंध किए जाएं। इन उपबंधों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला स्वयं प्रस्तुत करने का अधिकार किशोरों को दिए जाने का उपबंध भी शामिल किया जाएगा।

(दो) गरिमा और स्वाभिमान का सिद्धान्त,—

(क) बालक की गरिमा एवं स्वाभिमान के भावों के अनुरूप व्यवहार किशोर न्याय का मूल सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त वैश्विक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद में उल्लिखित इस मूल मानवाधिकार को दर्शाता है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र होते हैं तथा गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से एक समान हैं। गरिमा के सम्मान के अन्तर्गत किसी को अपमानित न किया जाना, व्यक्तिगत पहचान, सीमाओं एवं स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाना भी है, किसी को कलंकित न किया जाए, सूचनाएं प्रदान की जाएं तथा उसके कार्यों के लिए दोषी न ठहराया जाए।

(ख) किसी किशोर या बालक के गरिमा एवं स्वाभिमान के अधिकार को उसके मामले से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान, विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा बालक के साथ प्रथम सम्पर्क से लेकर उससे संबंधित सभी उपायों के कार्यान्वयन तक, पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।

(तीन) सुने जाने के अधिकार का सिद्धान्त:— किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर प्रत्येक बालक के उसके स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बालक को सुने जाने के अधिकार के अन्तर्गत उसके विकासात्मक स्तर के अनुरूप उससे बात करने के लिए उपयुक्त साधनों एवं प्रक्रियाओं का सृजन, बालकों के अपने जीवन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी

सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना तथा विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के समुचित अवसर प्रदान करना भी शामिल है।

(चार) सर्वोत्तम हित का सिद्धांत:—

- (क) किशोर न्याय प्रशासन के संदर्भ में लिए जाने वाले सभी विनिश्चयों में, मुख्यतः किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होगा।
- (ख) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त से अभिप्रेत है कि उदाहरणार्थ दाण्डिक न्याय, दण्ड एवं निरोध के परम्परागत उद्देश्य के स्थान पर किशोर न्याय के, पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के निश्चित उद्देश्य होने चाहिए।
- (ग) प्रत्येक बालक की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित करके बालक को जीवन जीने और अपनी पूर्ण क्षमतानुसार विकसित होने में सहायता करने के उद्देश्य से इस सिद्धांत के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास सुनिश्चित किया गया है।

(पांच) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत:—

- (क) बालकों का पालन-पोषण करने, उनकी देखरेख करने, उन्हें सहायता प्रदान करने एवं उनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः उनके जन्मदाता माता-पिता का होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, यह उत्तरदायित्व इन बालकों को दत्तक के लिए इच्छुक अथवा पालक माता-पिता को सौंपा जा सकता है।
- (ख) उस बालक के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में बालक के जन्मदाता परिवार को भागीदार बनाया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा किया जाना उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो।
- (ग) जन्मदाता, दत्तकग्रहण करने वाला या पालक (इसी क्रम में) परिवार बालक के लिए उत्तरदायी होगा तथा उक्त परिवार अधिनियम के अधीन किशोर या बालक को आवश्यक देखरेख, सहायता एवं संरक्षण प्रदान करेगा तथा अपनी देखरेख व अभिरक्षा में रखेगा, जब तक कि सर्वोत्तम हित का उपाय अथवा अन्यथा आदेश न दिया गया हो।

(छह) सुरक्षा का सिद्धान्त (किसी भी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार न हो):—

- (क) आरंभिक सम्पर्क से लेकर जितने समय तक वह देखरेख और संरक्षण प्रणाली के सभी प्रक्रमों के सम्पर्क में रहता है और उसके पश्चात् भी किशोर न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शारीरिक दण्ड

अथवा जेलों में एकान्त परिरोध अथवा अन्य किसी प्रकार के परिरोध के अधीन किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को उत्पीडित नहीं किया जाएगा और किशोर या बालक के संवेदनशील मन को किसी भी प्रकार के आघात से बचाने के लिए उसकी पूरी देखरेख की जाएगी।

- (ख) प्रत्येक बालक की देखरेख और संरक्षण के नाम पर किसी भी प्रकार के निर्बंधनात्मक उपायों व प्रक्रियों का सहारा लिए बिना उसकी देखरेख और संरक्षण में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का गुरुत्तर दायित्व राज्य का है।

(सात) सकारात्मक उपाय,—

- (क) सावधानी पूर्वक तैयार की गई वैयक्तिक देखरेख योजनाओं के माध्यम से किशोर या बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के उद्देश्य से परिवार, स्वयंसेवकों एवं अन्य सामुदायिक समूहों जैसे स्कूलों और मुख्यधारा की अन्य सामुदायिक संस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं के रूप में सभी संभव संशोधन पूरी तरह जुटाने वाले सकारात्मक उपाय करने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए।
- (ख) सकारात्मक उपायों का उद्देश्य असुरक्षा को कम करना तथा विधि के अधीन अंतर्क्षेप की आवश्यकताओं को कम करना और किशोर अथवा बालकों के साथ प्रभावी, न्यायोचित एवं मानवीय व्यवहार करना है।
- (ग) सकारात्मक उपायों में, स्वास्थ्य, शिक्षा, नातेदारी, आजीविका, सुविधाएं, सृजनात्मकता एवं खेलकूद के अवसर भी शामिल हैं।
- (घ) ऐसे सकारात्मक उपायों के द्वारा बालकों की पहचान विकसित होनी चाहिए तथा उन्हें विकास के लिए हर तरह का अनुकूल वातावरण प्राप्त होना चाहिए।

(आठ) कलंकित न करने वाले शब्दों, निर्णय एवं कार्यवाही का सिद्धान्त,—अधिनियम के अनुसार, कलंकित न करने वाले शब्दों का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित कार्यवाहियों में, जैसे, गिरफ्तारी, रिमाण्ड, आरोपी, आरोप-पत्र, विचारण, अभियोजन, वारन्ट, समन, दोषसिद्धि, अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे प्रतिकूल अथवा अभियोग परख शब्दों के प्रयोग का निषेध किया गया है।

(नौ) अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धान्त—

- (क) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर द्वारा स्वयं अथवा सक्षम प्राधिकारी या किशोर अथवा बालक की ओर से कार्यवाही में भाग ले रहे या दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा उस किशोर या बालक के अधिकारों का अधित्यजन न तो अनुरोध है और न ही विधिमान्य होगा।
- (ख) किसी मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जाना उस अधिकार का अधित्यजन नहीं है।

(दस) समता और अविभेद का सिद्धान्त—

(क) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर के साथ आयु, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मूलवंश, जातियता, धर्म, जाति, सांस्कृतिक परम्पराओं, कार्य उस किशोर या बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावकों के कार्यकलापों या व्यवहार अथवा किशोर या बालक की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रतिष्ठा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम के अधीन पहुंच, अवसरों, व्यवहार की दृष्टि से समता का अधिकार दिया जाएगा।

(ग्यारह) एकांतता एवं गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त—

कार्यवाहियों तथा देखरेख एवं संरक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान, सभी साधनों के द्वारा किशोर या बालक की एकांतता एवं गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा।

(बारह) अन्तिम विकल्प का सिद्धान्त—

किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अन्तिम विकल्प के रूप में ही किसी संस्था में भेजा जाएगा और वह भी न्यूनतम समयावधि के लिए।

(तेरह) प्रत्यावर्तन एवं पुनरुद्धार का सिद्धान्त—

(क) प्रत्येक बालक या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर का यह अधिकार है कि उसका अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हो तथा उसे समान सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पुनः प्राप्त हो, जिसमें वह अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आने या उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण के पूर्व रह रहा था।

(ख) कोई बालक, जिसका अपने परिवार से सम्पर्क न रह गया हो, अधिनियम के अधीन संरक्षण का पात्र होगा तथा उसे यथाशीघ्र उसके परिवार में वापस पहुंचाया जाए, किन्तु ऐसा तब नहीं किया जाएगा जबकि ऐसा करना बच्चे या किशोर के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध हो।

(चौदह) नव प्रारम्भ का सिद्धान्त—

(क) नव प्रारम्भ का सिद्धान्त बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के पिछले अभिलेखों को समाप्त करना सुनिश्चित कर उसे नवजीवन शुरू करने के लिए बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य अभिकथित या दाण्डिक विधि के टकराव के लिए पहचान किए गए बालकों पर किसी न्यायिक कार्यवाही का आश्रय लिए बिना अन्य उपाय करेगा।

अध्याय 3

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर

4. किशोर न्याय बोर्ड— प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड होंगे, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया जाएगा।

5. किशोर न्याय बोर्ड की संरचना —

- (1) बोर्ड में, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे:

परंतु बोर्ड का मजिस्ट्रेट, बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके त्वरित निपटान में यथावश्यक उपाय करेगा।

- (2) प्रत्येक ऐसी न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

- (3)

(एक) बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण में विशेष ज्ञान रखने वाले या इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(दो) ऐसा विशेष ज्ञान रखने वाला या प्रशिक्षण प्राप्त प्रधान मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने की दशा में, राज्य सरकार संबंधित मजिस्ट्रेट को बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण विषय का ऐसा अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जो वह आवश्यक समझे।

- (4) दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, कि नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, इन नियमों के नियम 91 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

- (5) केन्द्रीय सरकार की समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अनुसार, राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकारी, किशोर न्याय के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के विषय का यथावश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करेगी।

6. बोर्ड का कार्यकाल -

- (1) बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा तथा सदस्यों की नियुक्ति भी बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।
- (2) कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोर्ड के अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा तथा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल का कोई विस्तार राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा बोर्ड के सदस्यों के निष्पादन के मूल्यांकन तथा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड की बैठकों में उनकी भागीदारी तथा मामलों के निपटान में उनके योगदान का आवश्यक रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् किया जाएगा।
- (4) कोई सदस्य किसी भी समय, एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है अथवा अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (5) के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकता है।
- (5) बोर्ड में हुई किसी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति बोर्ड के शेष कार्यकाल के दौरान पद धारण करेगा।

7. बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं -

- (1) बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की आयु पैंतीस वर्ष से कम न होगी, उसे सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा समाज विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम पांच वर्ष तक वह बाल कल्याण से संबंधित प्रशासनिक उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से अंतर्वलित रहा हो।
- (2) शिक्षक, चिकित्सक, सेवानिवृत्त लोकसेवक जो किशोरों से संबंधित कार्य का अनुभव या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो बाल कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो।
- (3) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होगा, यदि वह:
 - (क) किसी विधि के अधीन दोषी सिद्ध हुआ हो,
 - (ख) बच्चों से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने अथवा अन्य किसी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले या अनैतिक कार्य में शामिल रहा हो,

- (ग) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय एवं ध्यान न दे सकता हो, सेवारत शासकीय सेवक हो अथवा विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (घ) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित अर्हताएं एवं अनुभव को पूरा न करता हो तो ऐसे मामले में चयन समिति विधिवत जांच करके और इस तथ्य के सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार करेगी और रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई सूची में से अगले व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी।

8. बैठक एवं यात्रा भत्ते — बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्तों का प्रदाय किया जाएगा।

9. बोर्ड की बैठकें —

- (1) बोर्ड अपनी बैठकों को किसी संप्रेक्षण गृह में अथवा संप्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अवधारित किसी स्थान अथवा अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा।
- (2) जहां बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित करेगा, वे परिसर बालकों के अनुकूल होंगे तथा वे किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसे नहीं दिखेंगे, उदाहरणार्थ बोर्ड के सदस्यों के आसन मंच पर नहीं होंगे और बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहां पर साक्षियों का कटघरा भी नहीं होगा।
- (3) बोर्ड सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और संबंधित प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो।
- (4) किसी एक वर्ष में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम तीन चौथाई आवश्यक होगी।
- (5) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में न्यूनतम पांच घंटे उपस्थित रहेगा।

10. बोर्ड के कार्य :- बोर्ड, अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात् :-

(क) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का न्याय निर्णयन एवं निपटान करना,

(ख) अधिनियम की धारा 23 से 28 के अधीन आने वाले अपराधों का संज्ञान लेना,

(ग) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए कार्यरत संस्थाओं को मानीटर करना और ध्यान में आई कमियों के मामलों में बोर्ड के सुझावों के आधार पर सुधार के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना,

(घ) यथास्थिति संबंधित सरकारी कार्यकर्ताओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुपालन न किए जाने के मामले पर, राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु अनुशंसा करना,

(ङ) आवश्यक अवसंरचना या सुविधाएं प्रदान अथवा सृजित करने के लिए जिला प्राधिकारियों एवं पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करना, ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय एवं उपचार के न्यूनतम मानक बनाए रखे जा सकें,

(च) देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले मामलों के संबंध में समिति के साथ सम्पर्क बनाए रखना,

(छ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जांच एवं निपटान को सुकर बनाने के लिए अन्य जिलों के बोर्ड के साथ सम्पर्क करना,

(ज) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली अकल्पित परिस्थितियों से निपटने तथा किशोरों के सर्वोत्तम हित में ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करना,

(झ) अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के विषय में तिमाही सूचना, जिला राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित राज्य सरकार तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (2) के अधीन समीक्षा के लिए भेजना,

(ञ) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

11. पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेशी के पूर्व एवं पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही:-

- (1) पुलिस अधिकारी, कानून के उल्लंघन के आरोपी किशोर को पकड़ते ही, इन सबको सूचित करेंगे।
 - (क) निकटतम पुलिस थाने के नामनिर्दिष्ट किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी को ताकि वह इस मामले का प्रभार लें।
 - (ख) विधि के उल्लंघन के अभिकथित किशोर के माता-पिता या संरक्षक को उस किशोर के पकड़े जाने के साथ-साथ बोर्ड के पते, जहां किशोर को प्रस्तुत किया जाएगा और उस तारीख एवं समय की सूचना देगा, जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना हो।
 - (ग) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी, जिससे कि वह किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य पारिस्थितिक तथ्यों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके, जो कि बोर्ड के जांच कार्य में सहायक हो।
- (2) किशोर के पकड़े जाने के तुरंत पश्चात् उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसार किशोर को 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जहां अधिनियम की धारा 63 की उप धारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध न हो, तो वहां किशोर को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी ही उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पकड़ने वाली पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं भेजेगी या प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में विलंब नहीं करेगी, यदि ऐसा कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ "अपराधी" जैसा व्यवहार नहीं करेंगे बल्कि उसे परिस्थिति के शिकार व्यक्ति की भांति देखेंगे। विशेष किशोर पुलिस विधि का उल्लंघन वाले किशोर को पुनः अपराधिक गतिविधियों की ओर जाने से रोकने के लिए कदम उठाएगी बालक को सम्प्रेक्षण गृह भेजना आखिरी विकल्प होगा जमानती एवं गैर जमानती अपराधों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर।

को थाने से ही जमानत देनी चाहिए यदि किसी कारणवश किशोर या बालक को किशोर बाल कल्याण अधिकारी/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत न कर पाए तो किशोर बालक को थाने में नहीं रखा जा सकता उसे सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने तक बालगृह या सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाएगा।

(4) किसी जिले में सभी नामनिर्दिष्ट किशोर या बाल कल्याण अधिकारियों एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों की सूची, उनके सम्पर्क के ब्यौरे सहित प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाई जाएगी।

(5) पुलिस या पुलिस के पदधारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में उपलब्ध सम्पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचनाएं एकत्र करेंगे और किशोर के माता-पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर के व्यवहार की जानकारी देंगे।

(6) पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, एवं अभिकथित अपराध के अभिलेख भी लेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।

(7) पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर को पकड़ने की अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करेंगे, जिनमें उस पर गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हों। (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को सात वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।)

(8) ऐसे मामलों में, जहां ऐसा प्रतीत हो कि किशोर को पकड़ा जाना उसके हित में है, उन मामलों में पुलिस प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी संबंधित किशोर को देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक मानते हुए उसके साथ व्यवहार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के समय अपनी रिपोर्ट में किशोर की देखरेख और संरक्षण की जरूरत दर्शाएंगे तथा बोर्ड से इन नियमों के नियम 13 (1) (ख) के अंतर्गत उपयुक्त आदेश पारित करने का अनुरोध करेंगे।

(9) जिन मामलों में अपराध गंभीर नहीं है, (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।) तथा जहां किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक नहीं है, उन सभी में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी माता-पिता या संरक्षकों को सूचित करेंगे कि जो अपराध किए जाने के आरोप उनके बालक या प्रतिपाल्य द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति के बारे में लगाए गए हैं, उन अपराधों की प्रकृति तथा

उस बालक की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना बोर्ड को भेजी गई है, जिसे पश्चात्पूर्ति सुनवाई के लिए किशोर को बुलाने की शक्ति होगी।

(10) बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित न करने की दशा में, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले पर कार्यवाही करते समय पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करना अथवा आरोप-पत्र फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा, सिवाय वहां, जहां किशोर द्वारा किसी गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना अभिकथित हो, जैसे बलात्कार, हत्या या जब ऐसे अपराधों में वयस्कों का साथ देना अभिकथित किया गया हो बल्कि साधारण अपराधों के मामलों में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर पर जो अपराध करना अभिकथित किया गया हो, उस अभिकथित अपराध की सूचना अपनी साधारण दैनिक डायरी में दर्ज करके किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन परिस्थितियों तथा कथित आरोपों का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट बोर्ड की पहली सुनवाई से पहले भेजेंगे।

(12) राज्य सरकार, केवल उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करेगा, जो परिवीक्षा सेवाएं परामर्श, मामला कार्य, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई के किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो तथा जिनके पास संरक्षण अभिकरणों के रूप में वे क्षमताएं, सुविधाएं, विशेषज्ञता हो, जिनके द्वारा वे किशोर को पकड़े जाने के समय, किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ-साथ जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी की सहायता कर सकें, बोर्ड के समय किशोर को प्रस्तुत किए जाने तक उसकी देखरेख कर सकें और उस किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता कर सकें।

(13) पकड़े गए किशोरों तथा जितनी अवधि तक उन्हें पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी या मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन की देखरेख में रखा गया, उस अवधि के दौरान उन किशोरों को सुरक्षा तथा भोजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

(14) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष किशोर को प्रस्तुत करते समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की अगली बैठक में कराने की आवश्यकता होगी।

12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :-

(1) किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेंगे।

(2) यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति प्रथम दृष्ट्या किशोर या बालक होने का विनिश्चय यथास्थिति, बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक बनावट अथवा दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी और तदनुसार उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेजेगी।

(3) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जांच करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करेंगे :-

(क) (एक) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके न होने पर;

(दो) जहां पहली बार गया (प्ले स्कूल छोड़कर), उस स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और उसके उपलब्ध न होने पर;

(तीन) नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के (एक), (दो) अथवा (तीन) की अनुपलब्धता में ही सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड, जो किशोर अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा, की राय ली जाएगी। यदि आयु का बिल्कुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो, तो न्यायालय अथवा बोर्ड या यथास्थिति, समिति कारणों का अभिलेख करते हुए, यदि आवश्यक समझे तो बच्चे अथवा किशोर को एक वर्ष कम की आयु का लाभ दे सकती है।

और ऐसे किसी मामले में यथास्थिति, ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करते समय बोर्ड या न्यायालय या समिति किशोर या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो), (तीन) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थिति में खण्ड (ख) में दर्शाए गए चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु के संबंध में निर्णायक साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।

- (4) यदि उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट निर्णायक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि अपराध करने की तारीख को बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से कम थी, तो यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति लिखित आदेश पारित करेंगे, जिसमें अधिनियम के प्रयोजन के लिए किशोर या बालक की आयु अभिकथित होगी एवं यह घोषणा होगी कि वह किशोर है या नहीं और इस आदेश की प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।
- (5) जिन मामलों में, अधिनियम की धारा 7 (क) धारा 64 एवं इन नियमों के निबंधनों में आगे और जांच किए जाने की अपेक्षा हो, उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में इस नियम के उप नियम (3) में यथा उल्लिखित प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने और ऐसे साक्ष्य की जांच करने के उपरान्त न्यायालय या बोर्ड द्वारा आगे और जांच नहीं की जाएगी।
- (6) इस नियम में उल्लिखित उपबंध निपटाए जा चुके उन मामलों पर भी लागू होंगे, जहां उप नियम (3) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार संबंधित किशोर की आयु या अवस्था का निर्धारण नहीं किया गया, ताकि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत दण्डादेश से अभिमुक्त किया जा सके।

13. प्रस्तुत करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां :-

- (1) किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के समय उस किशोर को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा संबंधित किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन परिस्थितियों एवं अभिकथित अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं, उन अपराधों का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और बोर्ड इस रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करके प्रथम संक्षिप्त जांच में उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित करेगा, अर्थात् :-
 - (क) यदि किशोर द्वारा विधि के उल्लंघन का साक्ष्य निराधार पाया जाता है अथवा वह किशोर विधि का उल्लंघन करने के छोटे-मोटे मामले में शामिल रहा है तो मामले का निपटान।
 - (ख) जब किशोर या बालक को प्रथम बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो बोर्ड तत्काल यह अवधारित करेगा कि क्या किशोर या बालक को जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है। यदि किशोर या बालक जमानत पर निर्मुक्त

किया जा सकता हो तो न्यायालय, किशोर या बालक को या तो माता-पिता, संरक्षक और उचित व्यक्ति/संस्था के लिए किशोर या बालक द्वारा व्यक्तिगत बांड या किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखकर निर्मुक्त करेगी।

- (ग) किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यदि किशोर को स्पष्ट शब्दों में देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद माना गया है तो उस किशोर से संबंधित मामले का समिति को हस्तांतरण।
- (घ) प्रपत्र- एक में आदेश पारित करके किशोर को यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में छोड़ते समय अगली तारीख को जांच के लिए किशोर को प्रस्तुत करने या उसके साथ प्रस्तुत होने का निर्देश।
- (ङ) किशोर के किसी गंभीर अपराध में लिप्त होने के मामलों में ही प्रपत्र- दो में आदेश जारी करके जांच कार्य के लंबित रहने तक उस किशोर को संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त संस्था में रखना।
- (च) जिन मामलों में जांच कार्य के लंबित रहते किशोर को छोड़ा जा रहा हो, उन सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की जो अगली तारीख अधिसूचित करेगा, वह प्रथम संक्षिप्त जांच के पश्चात् 15 दिन के भीतर होनी चाहिए। बोर्ड प्रपत्र- तीन में जारी आदेश के द्वारा संबद्ध परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मांगेगा।

(2) बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

- (क) जांच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी है, दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा।
- (ख) अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियां यथासंभव साधारण ढंग से की जाएंगी तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस किशोर के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले।

- (ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जांच में शामिल होगा।
- (घ) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका हो, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जांच के माध्यम से निपटाएगा, जबकि गंभीर अपराधों के जिन मामलों में सात वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जांच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी।
- (ङ) गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो समन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित जांच के दौरान गवाहों की परीक्षा के समय बोर्ड इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि जांच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि किशोर से प्रश्न किए जा सकें और किशोर के पुनरुद्धार संबंधी अधिकारों के अनुकूल उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके।
- (4) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड किशोर से बाल अनुकूल रीति में सवाल-जबाब करेगा, ताकि वह किशोर सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में एवं प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों एवं परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।
- (5) बालक को उसे विरुद्ध आरोपों को तत्परता से तथा प्रत्यक्षत ऐसी भाषा तथा रीति में सूचित किए जाएंगे, जो वह जानता हो, ताकि उसके द्वारा पूरी तरह से समझा जाना सुनिश्चित हो सके।
- (6) बालक को संस्वीकार (कन्फेस) करने या परिसाक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बालक से जानकारी निकलवाने के लिए किसी प्रकार की यातना या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
- (7) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड, उस किशोर के पकड़े जाने की परिस्थितियां एवं उसके कथित अपराध का ब्योरा दर्शाने वाली पुलिस की रिपोर्ट तथा बोर्ड के प्रपत्र-तीन में जारी आदेशानुसार

- परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र-चार में प्रस्तुत की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर सकेगा।
- (8) बोर्ड द्वारा प्रत्येक जांच कार्यवाही प्रथम संक्षिप्त जांच की तारीख से चार मास के भीतर पूरी की जाएगी और केवल उन अपवादात्मक मामलों में बोर्ड कारण को अभिलिखित करते हुए जांच कार्य की अवधि दो मास के लिए बढ़ा सकेगा, जिनमें विभिन्न देशों के नागरिक शामिल हो, आरोपियों की संख्या ज्यादा हो तथा गवाहों को प्रस्तुत करने में अनपेक्षित विलंब हो।
 - (9) गंभीर अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में चार या छह मास से अधिक विलंब होने पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
 - (10) जिन मामलों में किशोर पर गंभीर अपराध करने के आरोप लगाए जाने के कारण कार्यवाही में छह मास से अधिक देरी होती है तो बोर्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवधिक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें देरी के कारण तथा मामले को शीघ्र निपटाने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा।

14. विधिक सहायता :-

- (1) बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां ऐसे वातावरण में की जाएंगी जो प्रतिकूल न हो और जांच प्रक्रिया के दौरान परामर्श एवं निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार जैसे प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।
- (2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (3) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपनी विधिक सेवाएं प्रदान करें।
- (4) राज्य विधिक सहायता सेवा की सहायता की कमी होने पर बोर्ड का यह दायित्व होगा वह मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक विधि सेवा संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों के विधि सेवा क्लिनिकों से विधिक सेवाएं प्राप्त करें।
- (5) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के माता-पिता से संपर्क करने तथा उन किशोरों के विषय में सामाजिक एवं पुनर्वासात्मक सूचना प्राप्त करने जैसे अर्ध-विधिक कार्यों के लिए छात्र विधिक सेवा स्वयं सेवियों और गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों को अभिनियोजित कर सकेगा।

15. जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्प :-

- (1) बोर्ड सभी जांच कार्य चार मास की निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करेगा तथा अभिकथित अपराध में किशोर की संलिप्तता पाए जाने पर अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित निपटान के संबंध में सात आदेशों में से कोई एक आदेश पारित करेगा।
- (2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड अपने आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।
- (3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के लिए अनिवार्य रूप से वैयक्तिक देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह वैयक्तिक देखरेख योजना संबंधित किशोर एवं यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।
- (4) जिन मामलों में बोर्ड संबंधित किशोर को सलाह एवं भर्त्सना या सामूहिक परामर्श में किशोर की भागीदारी के पश्चात् निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देता है, उन मामलों में बोर्ड को जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को ऐसे वैयक्तिक परामर्श, सामूहिक परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का निर्देश भी देगा।
- (5) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस किशोर को रखा गया, उस व्यक्ति को प्रपत्र-पांच में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह किशोर का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।
- (6) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को प्रपत्र छह में प्रतिभूति के बिना मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।
- (7) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उपयुक्त संस्था या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त संस्था या विशेष गृह

उस किशोर के माता-पिता अथवा संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो।

- (8) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखता है या जहां किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश दे सकेगा कि उस किशोर को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।
- (9) जिस मामले में बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए, उस मामले में बोर्ड ऐसे किशोर को उपयुक्त देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए निकटतम समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आवश्यक आदेश देगा।
- (10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किशोर को विशेष गृह में निरुद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा।
- (11) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उसके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विश्वास है कि उस किशोर को विशेष गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस विशेष गृह में रहने वाले अन्य किशोरों के हित में है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किशोर को सुरक्षित स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से रखे जाने का आदेश देगा।
- (12) विधि का उल्लंघन करने वाले विशेष श्रेणी के किशोरों को विशेष गृह के स्थान पर अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर निरुद्ध करने के अनुपालन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
- (13) किसी भी मामलों में किसी किशोर को निरुद्ध किए जाने की अवधि अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) के खंड (छ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह—

- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठन के साथ करार के अधीन उतने संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगी और संधारित कर सकेगी, जो विधि का उल्लंघन करने वाले कथित किसी बालक को अधिनियम के अधीन उससे

संबंधित किसी जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से रखने के लिए अपेक्षित हों।

- (2) लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक् संस्थाएं संधारित की जाएंगी।
- (3) संस्था के बच्चों का वर्गीकरण किया जाएगा तथा उनके अपराध की डिग्री तथा उनकी आयु के अनुसार उन्हें निम्नानुसार पृथक्-पृथक् किया जाएगा।
- (4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में प्रमाणित भी कर सकेगी या मान्यता भी दे सकेगी।

संप्रेक्षण गृह के उद्देश्य -

- (1) शिक्षा जारी रखने के अवसर सृजनात्मक अनौपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे, विशेष रूप से यदि बालक ऐसे स्कूल में उपस्थित रहा है तो औपचारिक शिक्षा में उसकी अभिरुचि बनाए रखने में उसे समर्थ बनाएंगे।
- (2) विधि का उल्लंघन करने वाले कथित बालकों को उनकी स्थिति के बारे में उनकी भावनाओं तथा भय के संबंध में व्यवहार करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें विधिक सहायता देने हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विशेष परामर्श (काउंसिलिंग) सत्र संचालित किए जा सकेंगे।
- (3) किसी भी मामले में, संप्रेक्षण की इस अल्प कालावधि के दौरान भी बालकों को उनके समय का सृजनात्मक उपयोग करने के अवसर दिए जाएंगे।

संप्रेक्षण गृह का प्रबंध-

संप्रेक्षण गृह का प्रबंध, संस्था के अधीक्षक के रूप में पद धारण करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण के आयुक्त/संचालक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की संप्रेक्षण गृह में अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा होगी।

बालक का प्रवेश-

- (1) संप्रेक्षणगृह में बालक को रात दिन किसी भी समय प्रवेश दिया जाएगा और संप्रेक्षणगृह का भारसाधक अधिकारी, समय का ध्यान किए बिना बालक को प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा।
- (2) संप्रेक्षणगृह या किसी सुरक्षित स्थान पर बालक का प्रवेश, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा मुद्रा (सील) लगा हुआ स्थानन आदेश जारी करके किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से भिन्न कोई बालक किसी संप्रेक्षणगृह में नहीं रखा जाएगा।

- (3) भारसाधक अधिकारी, रात्रि के दौरान लाए गए किसी बालक को अगले दिन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने तक संप्रेक्षणगृह में निरुद्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत होगा।
- (4) भारसाधक अधिकारी, किसी ऐसे बालक को प्रवेश देने से इंकार करेगा जिसकी आयु, पहचान चिन्ह तथा वह अपराध जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, विशेष रूप से वर्णित न किए गए हो, परंतु प्रवेश से तब भी इंकार किया जा सकेगा, यदि स्थानन आदेश सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित न हो या शुद्धियां उचित रूप से अनुप्रमाणित न हो या बिना मुद्रा (सील) लगाए हुए लाया गया हो।
- (5) अधीक्षक/भारसाधक अधिकारी, यह देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा कि किसी बालक को अप्राधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं दिया गया है। तब किसी बालक को अनिश्चित समय पर प्रवेश दिया जाता है तो वह उसकी उचित जांच पड़ताल करेगा।

विशेष गृह :-

- (1) राज्य सरकार या तो अपनी ओर से या स्वैच्छिक संगठन के साथ करार के अधीन प्रत्येक जिले में या जिलों के किसी समूह में विशेष गृह स्थापित करेगी और संधारित करेगी, जो विधि का उल्लंघन करने वाले उन बालकों को रखने उनकी देखरेख, उपचार तथा पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिन्हें विधि के विरुद्ध उनके क्रियाकलापों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया गया हो।
- (2) लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक् संस्थाएं संधारित की जाएंगी।
- (3) संस्थाओं के बच्चों को उनके अपराध की डिग्री तथा उनकी आयु के अनुसार निम्नानुसार वर्गीकृत तथा पृथक् किया जाएगा—
 - (क) 12 वर्ष तक का आयु समूह;
 - (ख) 12 वर्ष से 16 वर्ष तक का आयु समूह;
 - (ग) 16 वर्ष से 18 वर्ष तक का आयु समूह।
- (4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को, विशेषगृह के रूप में भी प्रमाणित कर सकेगी या मान्यता दे सकेगी।

शेष गृह के उद्देश्य—

- (1) विशेष गृह के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
 - (क) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी ऐसे किशोर को लेना, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया गया हो।
 - (ख) भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समर्थन, प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना।
 - (ग) बालक के समुचित स्वास्थ्य, देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवहार में परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम आदि को सुकर बनाना।

- (घ) उत्पीड़न का शिकार होने से बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा विकास और वृद्धि के लिए बालक की सहायता करना।
- (ङ) परिवर्तित व्यक्ति के रूप में समुदाय के भीतर पुनः सम्मिलित होने के लिए बालक को तैयार करना।
- (च) विशेष कार्यक्रम—
- (एक) अपने कार्यों के उत्तरदायित्वों से बचने के बजाए उन्हें स्वीकार करने में बालक की सहायता करना।
 - (दो) उन समस्याओं का समाधान करने में बच्चों की मदद करना, जो उनका आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली होती है।
 - (तीन) तनावों का सामना करने के लिए व्यावहारिक अनुकल्पिक उपायों को विकसित करने में बालक की सहायता करना।
 - (चार) जहां संभव हो, अपराधियों के कुटुम्बों को ऐसे पारिवारिक मुद्दों पर काम करने में जिनसे अपराध कम होने की संभावना हो, शामिल करना।
 - (पाँच) सामाजिक सक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी शैक्षणिक कर्मियों का उपचार करना।
 - (छः) मार्केट स्थापन के कार्य संबंधी कौशल को विकसित करने में मदद करना, जो प्रशिक्षण संबंधी अवसर अर्हताएं तथा वास्तविक रोजगार को और आगे बढ़ा सके।
 - (सात) ऐसे अन्य विशिष्टजनों से, जो सलाहकार तथा आदर्श भूमिका वाले व्यक्ति हो सकते हैं, संबंध स्थापित करने और सुदृढ़ करने में बालक की सहायता करना।
 - (आठ) बालकों की स्वयं की आवश्यकताओं के निर्धारण तथा उनके स्वयं के मामलों संबंधी योजनाएं बनाने और उन्हें मॉनीटर करने के अनुभवों के सशक्तिकरण में उन्हें शामिल करना।
 - (नौ) सकारात्मक नेतृत्व और स्व-अनुशासन के लिए कौशल और विश्वास बढ़ाने में बालक की मदद करना।
- (2) ऐसे विशेषज्ञों के साथ रुचि रखने वाले तथा सक्षम अशासकीय संगठनों को शामिल करते हुए पीड़ित अपराधी पुनर्मिलाप कार्यक्रम को विकसित करने के प्रयास किए जा सकेंगे (विकटिम आफेंडर, रिकान्सिलिएशन प्रोग्राम से ली गई संकल्पना डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी. ओ.आर.पी.कॉम) ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य, संसूचना, उत्तरदायित्व, पुनर्मिलाप तथा पुनःस्थापन के लिए मार्ग प्रशस्त करना हो सकेगा।
- (3) समूह परामर्श के लिए कार्यक्रम तथा अन्य ऐसी सेवाएं, क्षेत्र में के विशेषज्ञों की मदद से विकसित की जाएंगी।
- (4) अर्थपूर्ण तथा प्रभावी सामुदायिक सेवा देने तथा उनका अनुश्रवण करने के लिए आदेशित कार्यक्रम के लिए आदेशित विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को सक्षम तथा संवेदनशील अशासकीय संगठनों/विशेषज्ञों की मदद से विकसित किया जाएगा। ऐसी सामुदायिक सेवा का उद्देश्य बालक को समुदाय में समन्वय स्थापित करने के प्रति

आगे बढ़ने की दिशा में समर्थ बनाना होगा और इससे उसमें आगे किसी भी प्रकार विकृति या उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा।

विशेषगृह का प्रबंध-

विशेष गृह का प्रबंध किसी ऐसे भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो संस्था के अधीक्षक के रूप में पद धारण करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो, जो आयुक्त/संचालक, जो महिला सशक्तिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

बालक का प्रवेश -

- (1) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को, संस्थागत कार्यक्रम लेने के प्रयोजन के लिए, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और जारी किए गए लिखित स्थानन आदेश पर प्रवेश दिया जाएगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य स्थानन आदेश के बिना विशेषगृह में किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा या उसे रखा नहीं जाएगा।
- (3) किसी भी बालक को विशेषगृह में उस तारीख के बाद तक नहीं रखा जाएगा, जिस तारीख तक बालक को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार रखा जा सकता है।
- (4) यदि बालक को विशेष गृह में उस तारीख के बाद तक, जिस तक बालक को उस संस्था में रखे जाने के लिए आदेशित किया गया था, शिक्षा संबंधी या व्यावसायिक प्रशिक्षण को शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने तक पूर्ण करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का औपचारिक आदेश अग्रिम में प्राप्त किया जाएगा।

17. निर्मुक्ति :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोरों का एक रोजर तैयार करेगा, जिन्हें वहां रहने की अवधि की समाप्ति के पश्चात् बोर्ड के आदेशानुसार रिहा किया जाना है।
- (2) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामले का कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक मामले को इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि किशोर की निर्मुक्ति और निर्मुक्ति के पश्चात् समाज की मुख्यधारा में उसका प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) निर्मुक्ति, वैयक्तिक देखरेख योजना के अधीन तैयार निर्मुक्ति पूर्व और निर्मुक्ति के पश्चात् योजना तथा इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षित योजना के अनुसार की जाएगी और निर्मुक्ति के सभी मामलों में निर्मुक्ति की तारीख से काफी पहले आवश्यक कार्यवाही और तैयारी शुरू

कर दी जाएगी और जिसमें निर्मुक्ति के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही की तैयारी भी शामिल होगी।

- (4) किशोर की निर्मुक्ति की सूचना और निर्मुक्ति की सही तारीख की सूचना माता-पिता अथवा संरक्षक को समय रहते दी जाएगी और माता-पिता अथवा संरक्षक को निर्मुक्ति की तारीख पर किशोर को ले जाने के लिए संस्था में उक्त तारीख को आमंत्रित किया जाएगा।
- (5) यदि आवश्यक हो तो माता-पिता अथवा संरक्षक के संस्था तक आने व वापस जाने तथा किशोर के संस्था से जाने का वास्तविक व्यय माता-पिता अथवा संरक्षक को प्रभारी अधिकारी द्वारा किशोर की निर्मुक्ति के समय दे दिया जाएगा।
- (6) यदि माता-पिता अथवा संरक्षक निर्धारित तारीख को किशोर को ले जाने के लिए नहीं आ पाते हैं तो उसे संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़की को महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा।
- (7) किशोर की निर्मुक्ति या निर्मोचन के समय यदि प्रभारी अधिकारी आवश्यक समझता है तो किशोर को गर्मी या सर्दी के कपड़ों का एक जोड़ा तथा प्रसाधन का जरूरी सामान देगा।
- (8) यदि किशोर का कोई संरक्षक या माता-पिता नहीं है तो उसे किसी पश्चात्वर्ती देखभाल संगठन के पास अथवा उसका रोजगार लग जाने की स्थिति में उस व्यक्ति के पास जिसने किशोर को नियोजन में लिया है भेजा जाए।
- (9) लड़कियों की संस्था का प्रभारी अधिकारी लड़की की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन, अठारह वर्ष से अधिक आयु की लड़की को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रवेश दिलाकर या उसे कोई लाभदायक रोजगार या नौकरी दिलाकर या उसका विवाह कराकर उसे समाज की मुख्यधारा में लाने में उसकी सहायता कर सकता है।
- (10) प्रभारी अधिकारी, किसी किशोर के निरोध की अवधि की समाप्ति पर प्रपत्र -सात में निर्मोचन का आदेश देगा और सक्षम प्राधिकारी को सात दिनों के अंदर की गई कार्यवाही की सूचना देगा और यदि निर्मुक्ति की तारीख रविवार को या किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ती हो तो किशोर को उससे एक दिन पूर्व निर्मोचित किया जाएगा और निर्मोचन रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि की जाएगी।
- (11) उपयुक्त मामलों में, प्रभारी अधिकारी राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर जीवन-निर्वाह हेतु धन

और यथास्थिति, रेल अथवा सड़क या दोनों के किराये का संदाय करने का आदेश देगा।

- (12) उपयुक्त मामलों में, प्रभारी अधिकारी किशोर को कोई कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यथावश्यक लघु औजार दे सकता है, लेकिन उनका अधिकतम मूल्य निर्मुक्ति उपरांत योजना के एक भाग के रूप में संस्था द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं हो।
- (13) जहां किसी लड़की की निर्मुक्ति के उपरांत उसके रहने का कोई स्थान नहीं है और वह उसके रहने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् संस्था में रुकने का अनुरोध करती है तो प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन, उसे कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था होने तक वहां रुकने की अनुमति दे सकता है।

18. अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

- (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अभिकथित उपबंधों के उल्लंघन की दशा में -
 - (क) बोर्ड द्वारा प्रिंट अथवा इलैक्ट्रानिक प्रचार-माध्यमों द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार आवश्यक जांच शुरू की जाएगी तथा उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे; और
 - (ख) जहां राष्ट्रीय अथवा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है, वहां आयोग संबंधित जिले या राज्य के जिला अथवा राज्य बालक संरक्षण इकाई को यह निर्देश देते हुए सूचित करेगा कि बोर्ड के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- (2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के भाग जाने की दशा में चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :-
 - (क) संस्था के प्रभारी अधिकारी उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई को किशोर अथवा बालक के विवरण सहित एक रिपोर्ट तत्काल भेजेगा, जिसके साथ उसका पहचान चिन्ह और फोटो भेजा जाएगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी भेजी जाएगी।
 - (ख) आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी, गाड़ों को अथवा संबंधित कर्मचारियों को किशोरों की तलाश में ऐसे स्थानों, जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा, जहां उसके जाने की संभावना हो सकती है।
 - (ग) माता-पिता अथवा संरक्षकों को बच्चे के ऐसे भाग जाने के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा; और
 - (घ) आश्रय गृह अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्था का प्रभारी अधिकारी बच्चे के भाग जाने के मामले की जांच करेगा और बोर्ड अथवा समिति और संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यह रिपोर्ट इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के खिलाफ अपराध, जो धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 में निर्दिष्ट हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के साथ-साथ या तो जमानती या गैर जमानती होंगे और ये कार्यवाहियां तदनुसार पुलिस, बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारी और अधिकारियों पर लागू होंगी।

अध्याय 4**देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक****19. बाल कल्याण समिति**

प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति होगी जिसका गठन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

20. बाल कल्याण समिति की संरचना

1. समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होगी।
2. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नियम 91 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
3. चयन समिति समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करेगी कि उसमें से कोई भी किसी दत्तक ग्रहण अभिकरण से न हो।
4. राज्य सरकार, समिति के सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, किशोर न्याय के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों में यथावश्यक प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करेगी।

21. समिति का कार्यकाल

1. समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।
2. समिति के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम दो लगातार अवधियों हेतु नियुक्तियों के पात्र होंगे।
3. समिति के सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा उनके निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर और चयन समिति की सिफारिश पर होगी।
4. समिति के कार्यकाल के पूरा हो जाने पर निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार वर्तमान समिति की अवधि समाप्त होने से पूर्व नई समिति का गठन करेगी, जिसके पश्चात् वर्तमान समिति सभी अभिलेख तथा सूचनाएं नव-गठित समिति को सौंप देगी।
5. समिति के अध्यक्ष और सदस्य एक मास की लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय पद त्याग कर सकेंगे अथवा अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (4) में उपबंध के अनुसार पद से हटाए जा सकेंगे।

6. समिति में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को, चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा वह व्यक्ति समिति के शेष कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा।

22. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएं

1. समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में चयन किए जाने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं में से एक अर्हता के साथ-साथ उसके संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होगा।
 - (i) कोई व्यक्ति, जो समाज कार्य, मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, समाज शास्त्र, विधि, अपराध शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तथा जब ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो व्यक्ति सामाजिक विज्ञान की किसी एक विधा में कम से कम स्नातक हो।
 - (ii) शिक्षक, डॉक्टर सेवानिवृत्त लोकसेवक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो बालकों से संबंधित कार्य में संलग्न हो।
2. समिति के अध्यक्ष या सदस्य की आयु 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक न हो।
3. किसी भी व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य बनाने पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह:-
 - (एक) विगत में दोषसिद्ध हो चुका हो,
 - (दो) किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित रहा हो।
 - (तीन) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय एवं ध्यान न दे सकता हो, सेवारत शासकीय सेवक हो अथवा विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (चार) अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विहित अर्हताएं एवं अनुभव पूरा न करता हो, ऐसे मामलों में चयन समिति जांच कर लेने के बाद तथा ऐसे तथ्यों के सिद्ध होने पर उसके आवेदन को रद्द करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई सूची में से अगले व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी।

23. बैठक एवं यात्रा भत्ता

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

24. समिति की बैठकें

1. समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था अथवा जैसा की कलेक्टर समय-समय पर अवधारित करे उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगी।
2. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक अथवा बालकों की सूचना मिलने पर यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि बालक अथवा बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति बालक अथवा बालकों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बालक अथवा बालकों हेतु सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।
3. परिसर जहां समिति अपनी बैठकों का आयोजन करती है, बालकों के अनुकूल होगा तथा किसी भी रूप में चाहे वह कोई न्यायालय हो, न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा। उदाहरणार्थ समिति उंचे उठे हुए मंच पर नहीं बैठेगी तथा बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहां साथियों का कठघरा नहीं होगा।
4. समिति सप्ताह में कम से कम तीन दिन बैठकें आयोजित करेगी, जिसे राज्य सरकार मामले अथवा लम्बित कार्य के आधार पर बढ़ा सकेगी।
5. एक वर्ष में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की न्यूनतम तीन-चौथाई उपस्थिति आवश्यक होगी।
6. बैठक की अवधि समिति के समक्ष लम्बित कार्य पर आधारित होगी।
7. समिति का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में कम से कम चार घण्टे उपस्थित होगा।

25. समिति के कार्य एवं शक्तियां

समिति, अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी। अर्थात्:

- (क) समिति के समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना एवं प्राप्त करना,
- (ख) समिति के समक्ष लाए गए मामलों में विनिश्चय देना,
- (ग) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद ऐसे बालकों, जो विषम परिस्थितियों में रहने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं है, के पास जिला बाल संरक्षण इकाईयो अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से पहुंचना,
- (घ) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों के बारे में आवश्यक जांच करना,
- (ङ) बाल कल्याण अधिकारियों अथवा परिवीक्षा अधिकारियों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच करने तथा समिति को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देना।

- (च) आवश्यक देखरेख और संरक्षण, जिसके अंतर्गत तत्काल आश्रय भी है, सुनिश्चित करना।
- (छ) जिला बाल संरक्षण इकाईयों अथवा राज्य दत्तक संसाधन अभिकरणों तथा अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही तथा समन्वय के अतिरिक्त माता-पिता अथवा संरक्षकों अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करने सहित बच्चों का उपयुक्त पुनर्वास एवं उनका पुनःस्थापन सुनिश्चित करना।
- (ज) आश्रय और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को प्राप्त करने के लिए बाल गृहों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देना।
- (झ) समिति द्वारा निपटाए गए प्रत्येक मामले के सार के साथ मामले का विस्तृत अभिलेख तैयार करना और उसका रख-रखाव करना।
- (ञ) बालकों के लिए बालकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- (ट) उपयुक्त व्यक्ति की घोषणा करना।
- (ठ) किसी बालक को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना।
- (ड) अपनी अधिकारिता में गुमशुदा बच्चों के संबंध में जानकारी रखना तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करना।
- (ढ) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद मामलों के संबंध में बोर्ड के साथ संपर्क बनाए रखना।
- (त) राज्य सरकार के सहयोग से संस्थाओं में बालकों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रत्येक संस्था का, जहां देखरेख और संरक्षण के लिए या दत्तक ग्रहण के लिये बालक भेजे जाते हैं, कम से कम तीन मास में एक दौरा करना तथा आवश्यक कार्यवाही का सुझाव देना।
- (थ) बालकों के शोषण एवं बाल उत्पीड़न की पड़ताल करने के उद्देश्य से अपनी अधिकारिता के बालकों से संबंधित संगमों एवं अभिकरणों का मॉनीटर करना।
- (द) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार के सहयोग से पुलिस श्रम विभाग तथा बच्चों की देखरेख और संरक्षण में संलग्न अन्य अभिकरण के साथ समन्वय करना।
- (ध) जब कभी अपेक्षित हो सामाजिक जांच, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास सहित उपरोक्त के लिए कारपोरेट सेक्टर तथा गैर सरकारी संगठनों से संपर्क एवं नेटवर्क बनाना।

- (न) बच्चों एवं वयस्कों से जानकारी प्राप्त करने को बढ़ावा देने के लिए सुझाव पेटिका का रखरखाव करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

26. समिति से संबंधित प्रक्रिया :-

- (1) बैठक के लिए कोरम तीन सदस्यों की उपस्थिति से होगा, जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित हो सकता है।
- (2) जब समिति में बैठक में न हो, किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी विनिश्चय का समिति की अगली बैठक में अनुसमर्थन कराना अपेक्षित होगा।
- (3) समिति को मामले को निपटाने से पहले, बच्चे की आयु, विकासात्मक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की राय तथा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामले पर कार्य कर रहे कार्यकर्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा।
- (4) मामले के अंतिम निपटान के लिए समिति के आदेश को कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होना चाहिए।

27. समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाना:-

- (1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को समिति के समक्ष यात्रा में लगे समय को निकालकर चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (क) कोई पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारी
 - (ख) कोई लोक सेवक,
 - (ग) चाइल्डलाईन, पंजीकृत संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन अथवा अभिकरण
 - (घ) सामाजिक कार्यकर्ता
 - (ङ) लोक भावना से युक्त कोई नागरिक; अथवा
 - (च) स्वयं बालक द्वारा
- (2) दो वर्ष से कम आयु के बालक के जो चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ नहीं हो, के मामले में व्यक्ति अथवा संगठन बालक के फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट समिति को चौबीस घंटे के भीतर भेजेगा तथा जैसे ही बालक चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ होगा उसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।
- (3) समिति उसकी जानकारी में लाए गए मामले का स्वतः संज्ञान ले सकती है तथा जहां आवश्यक हो, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी बालक तक पहुंच सकती है।

- ऐसे कार्य करने में समिति को जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगी।
- (4) समिति के बैठक में न होने की दशा में, बालक को समिति के समक्ष पेश किए जाने तक माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त संस्था की सुरक्षा में रखने के लिए अधिनियम की धारा 30 की उप धारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार, समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को पेश किया जा सकता है।
- (5) एक सदस्य तक भी न पहुंच पाने की दशा में अथवा समय कार्य-समय से परे हो, बालक को गैर-सरकारी संगठन अथवा चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के लिए पंजीकृत उपयुक्त संस्थान ले जाया जाएगा तथा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय तक ऐसे संस्थान में रखा जाएगा।
- (6) संबंधित संस्थान समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को ऐसे बालक के बारे में सूचित करेगा तथा चौबीस घंटे के अंदर बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा और ऐसे मामलों में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को संस्थान तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को समिति के समक्ष पेश करते समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा।
- (7) समिति के समक्ष बालक को जो कोई भी पेश करेगा उसे उन परिस्थितियों की रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिनके अधीन बालक उनकी जानकारी में आया है तथा उनके द्वारा पुलिस एवं गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल को सूचित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन अथवा किसी पुलिस कार्मिक द्वारा बच्चे को समिति के समक्ष पेश करने की दशा में उन्हें बच्चे के परिवार को खोजने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की रिपोर्ट भी पेश करेगा।
- (8) समिति के समक्ष बालक को पेश करने अथवा संस्था में उसके प्रवेश के लिए बालक की किसी सामान्य चिकित्सक अथवा स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी आवश्यक नहीं होगी।
- (9) समिति, खोए हुए बालकों के साथ-साथ हिंसा, शोषण एवं बाल उत्पीड़न के मामलों में पुलिस शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सहायता करेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला या राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण अथवा स्वैच्छिक संगठनों में उपलब्ध विधि अधिकारी के माध्यम से अपेक्षित विधिक सहायता का प्रबंध करेगी।

- (10) प्रत्येक समिति उसके द्वारा प्राप्त किए गए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के बारे में तिमाही सूचना जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी।
- (11) समिति द्वारा कार्यवाहियों के दौरान बालक को बालकों के अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाएगा।
- (12) समिति के पास अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगी, जो बाल उत्पीड़न के मामलों के निपटान में समिति की सहायता करेंगे तथा जब ऐसे बालकों से संबंधित मामलों को नियमित आपराधिक न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया जाएगा तब ये पीड़ित बालक को विधि सेवाओं को सुकर कराने के लिए लोक अभियोजक अथवा सहायक लोक अभियोजक से विचार विमर्श भी करेंगे।
- (13) जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से बालक के कुटुम्ब को खोजने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे तथा मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस की भी सहायता ली जाएगी।
- (14) समिति बालक को आयु एवं लिंग विशिष्ट सेवाओं वाले नामनिर्दिष्ट सुरक्षित स्थानों पर भेजेगी तथा ऐसी परिस्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार परिवहन की व्यवस्था करेगी अथवा ऐसे व्यय के लिए वास्तविक किराये पर आधारित आवश्यक बजटीय आबंटन करेगी।
- (15) बालक के साथ पुलिस अधिकारी अथवा स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधि मार्गरक्षी होगा अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से समिति द्वारा उपयुक्त कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी तथा लड़की के मामले में उसके साथ महिला मार्गरक्षी जाएगी।
- (16) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समिति को अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथाविहित उपयुक्त सुविधाओं तथा क्षमता के साथ सभी मान्यताप्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं की सूची, बच्चों से संबंधित सभी संसाधन सेवाओं की सूची तथा संपर्क सूत्रों की सूची प्रदान की जाएगी।
- (17) समिति जांच लम्बित होने एवं पुनः स्थापन के समय, जैसा भी मामला हो, माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालको को रखने के लिए प्रपत्र-आठ में आदेश करते समय ऐसे माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति को प्रपत्र-नौ में वचनबंध देने के लिए निर्देश देगी।

- (18) जब कभी समिति जांच लंबित होने तक बालक को किसी संस्था में रखने के लिए आदेश करेगी। समिति ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को अल्पावधि स्थापन के आदेश की प्रति गृह तथा माता-पिता अथवा संरक्षकों एवं पिछले अभिलेखों का ब्यौरा प्रपत्र- दस में भेजेगी।
- (19) जब समिति अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (3) के उप खंड (च) के अधीन पुनर्स्थापन के एक भाग के रूप में बालक को किसी उपयुक्त संस्था में रखने के लिए आदेश करती है, समिति ऐसे संस्थान के प्रभारी अधिकारी को प्रपत्र- ग्यारह में पुनर्स्थापन के आदेश की एक प्रति भी भेजेगी।
- (20) बालक को जहां तक संभव हो, उसके माता-पिता अथवा संरक्षक के निवास स्थान के सबसे निकट की संस्था में रखा जाएगा, जब तक कि बालक माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा शोषण अथवा उत्पीड़न का शिकार न रहा हो।

28. जांच प्रक्रिया:-

- (1) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, समिति प्रपत्र-बारह में आदेश के माध्यम से बालक को जांच करने के लिए यथास्थिति, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा संस्था के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण को सौंपेगी।
- (2) समिति व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने तथा उपयुक्त पुनर्वास के विकास के लिए विवरण या विशिष्टियों की जांच करने के लिए संबंधित व्यक्ति अथवा संगठन को निर्देश देगी।
- (3) सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा संस्थान के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा की गई सभी जांचों का ब्यौरा प्रपत्र-तेरह के अनुसार होगा तथा बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण भी दिया जाएगा तथा यह टिप्पणी लिखित में करनी होगी कि क्या बालक को उसके परिवार में पुनः स्थापित करने में उसका हित होगा।
- (4) जांच चार मास के अंदर या ऐसी कम अवधि के भीतर, जिसे समिति द्वारा नियत किया जाए पूर्ण की जानी चाहिए।
परन्तु समिति बालक के सर्वोत्तम हित में तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि को बढ़ा सकती है।
- (5) जांच पूरी होने के पश्चात् यदि बालक को बाल गृह में ही रहने का आदेश दिया जाता है, समिति गृह के प्रभारी अधिकारी को ऐसे बालक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा बालक को प्रगति की वार्षिक समीक्षा के लिए समिति के समक्ष पेश करने के लिए निर्देश देगी।

29. बाल गृह:-

- (1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रीति से देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए पृथक् गृहों की स्थापना करेगी:
 - (क) अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (3) तथा इन नियमों के नियम 71 के अधीन सभी बाल गृहों को बाल देखरेख संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
 - (ख) नियम 70 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार, सभी बालगृह प्रमाणित होंगे।
 - (ग) सभी बाल गृह उनके द्वारा प्राप्त किए गए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद प्रत्येक बालक के बारे में संबंधित समिति को रिपोर्ट देंगे।
 - (घ) 10 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़कियों को एक ही गृह में रखा जाएगा, किन्तु 5 से 10 वर्ष के आयु समूह के लड़कों और लड़कियों हेतु अलग-अलग सुविधाएं होंगी।
 - (ङ) प्रत्येक बाल गृह में शिशुओं हेतु उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष के आयु समूह के बालकों हेतु अलग-अलग सुविधाएं होंगी।
 - (च) 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग बाल गृह स्थापित किए जाएंगे।
 - (छ) 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को 10-15 वर्ष तथा 15-18 वर्ष के दो आयु समूहों में अलग-अलग रखा जाएगा।
- (2) प्रत्येक बाल गृह, व्यापक बाल देखरेख केन्द्र होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंध समिति के माध्यम से समुदाय एवं स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के द्वारा बालकों की देखरेख के लिए समेकित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार इन बाल गृहों के किए कार्यों की वार्षिक निष्पादन समीक्षा करेगी।
- (3) ऐसे केन्द्रों के कार्यकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित होंगे :
 - (क) अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक बच्चे हेतु व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना तथा उसका अनुसरण करना विशेष रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक आवश्यकताओं, शिक्षा, कौशल विकास, संरक्षण तथा विशिष्ट आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की पूर्ति करना।
 - (ख) परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाएं जैसे:- पालन पोषण परिवार देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं प्रायोजन
 - (ग) संघर्ष अथवा आपदा की स्थिति में तथा संक्रमित अथवा ठीक न होने वाली बीमारियों से प्रभावित किशोरों अथवा बालकों को उपेक्षा से बचाने के लिए

परिवार परामर्श, पोषण स्वास्थ्य सेवाएं, मनोसामाजिक उपायों तथा प्रायोजन के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाएं।

- (घ) चाइल्ड लाइन (निःशुल्क हेल्प लाइन नम्बर 1098) के माध्यम से आपात कालीन सेवाओं का विस्तार।
- (ङ) छह वर्ष से कम आयु के बालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना से संकेन्द्रण।
- (च) बालकों को समर्थन सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों से संपर्क।
- (छ) बालकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक स्वैच्छिक कर्मियों के लिए अवसर।

30. आश्रय गृह:-

- (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों जैसे बेघर बालकों तथा घर से भागे हुए बालकों के लिए राज्य सरकार स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपेक्षित संख्या में आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटर्स की स्थापना में सहायता करेगी।
- (2) आश्रय गृहों में निम्नलिखित भी होंगे:
 - (क) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आश्रय देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अल्प अवधि गृह।
 - (ख) चार मास की अधिकतम अवधि के लिए बालकों को तत्कालिक देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए अन्तःकालीन गृह।
 - (ग) दिवस देखरेख अथवा रात्रि आश्रय सुविधाओं के जरूरतमंद बालकों के लिए चौबीस घंटे खुले रहने वाले ड्रॉपइन सेंटर।
- (3) आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटर्स में कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख एवं पोषण सुरक्षित पेयजल एवं सफाई के मामलों में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधानों के अलावा रहने एवं खाने की सुविधाएं होंगी।
- (4) इन नियमों के नियम 40(2) (घ) के अनुसार लड़कियों एवं लड़कों के लिए अलग-अलग आश्रय गृह होंगे।
- (5) सभी आश्रय गृहों में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण परामर्श तथा मनोरंजन की अपेक्षित सुविधाएं होंगी अथवा स्वैच्छिक संगठनों अथवा कारपोरेट क्षेत्र के सहयोग से इनकी व्यवस्था की जाएगी।
- (6) समिति, विशेष किशोर न्याय इकाई, सरकारी कर्मचारी, चाइल्ड लाइन, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे आश्रय गृहों में बालकों को भेज सकेंगे तथा बालक स्वयं इन गृहों में जा सकेंगे।
- (7) सभी आश्रय गृह समिति, गुमशुदा व्यक्ति तलाश ब्यूरो अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई को आश्रय गृह की सुविधाओं का उपयोग करने वाले बच्चों की उनके फोटों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (8) अधिनियम की धारा 32, 33, 38 एवं 39 के अधीन जांच एवं मामले के निपटान के लिए आश्रय गृह द्वारा समिति के समक्ष बच्चे को पेश करने की आवश्यकता होगी, जो इन नियमों के नियम 30 (2) (ग) में यथोल्लिखित ड्रॉपइन सेंटर्स से भिन्न केवल आश्रय गृहों पर ही लागू होगी।
- (9) प्रभारी अधिकारी बालक कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाएं आश्रय गृहों के बालकों की उपयुक्त देखरेख, संरक्षण, विकास, पुनर्वास और पुनः एकीकरण आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाएगी।
- (10) कोई भी बालक समिति के अनुमोदन से विशेष परिस्थितियों के अलावा एक वर्ष से अधिक समय के लिए अल्प अवधि ठहराव गृह में सामान्यतः नहीं रुकेगा।

- 31. बालक के यौन दुर्व्यवहार निवारण के लिए दिशा-निर्देश :-केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां, अन्य सक्षम प्राधिकारी और अभिकरण तथा प्रत्येक व्यक्ति बालकों के सर्वोत्तम हित में बालकों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

अध्याय 5**पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन****32. पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन**

पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन का मुख्य उद्देश्य बालकों को उनके सम्मान और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने तथा जहां कहीं संभव हो, उनके ही परिवार में पुनर्वास के माध्यम से अथवा अन्यथा वैकल्पिक देखभाल कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता करना है तथा दीर्घकालीन संस्थागत देखभाल अंतिम प्रयास होगा।

33. दत्तकग्रहण

1. दत्तकग्रहण का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालकों को, जिसकी उसके जन्मदाता माता-पिता द्वारा देखभाल नहीं की जा सकती है, स्थायी वैकल्पिक परिवार प्रदान करना है।
2. दत्तकग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा जारी किए गए तथा अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देश लागू होंगे।
3. अनाथ और परित्यक्त बालकों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्
 - (क) विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण ऐसे सभी अनाथ और परित्यक्त बालकों को जिन्हें दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है, ऐसे बालकों की प्राप्ति के समय से, यात्रा में लगे समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर, समिति के समक्ष पेश करेंगे।
 - (ख) कोई बालक दत्तकग्रहण हेतु तब पात्र हो जाता है, जब समिति अपनी जांच पूरी कर लेती है तथा बालक को दत्तकग्रहण विधिक रूप से मुक्त घोषित कर देती है।
 - (ग) ऐसी घोषणा प्रपत्र-चौदह में की जाएगी।
 - (घ) किसी बालक को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करते समय उस बालक को समिति के समक्ष अवश्य पेश किया जाएगा।
 - (ङ) जब कभी पुलिस को किसी परित्यक्त शिशु के बारे में सूचना प्राप्त होती है, पुलिस उस शिशु को अपने अधिकार में लेगी तथा शीघ्र चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगी।

तत्पश्चात् बालक को विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा मान्यताप्राप्त और प्रमाणित बाल गृह अथवा किसी सरकारी अस्पताल के शिशु इकाई में रखा जाएगा, तत्पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

किसी बालक को परित्यक्त घोषित करने और दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त प्रमाणित करने की प्रक्रिया :

- (एक) किसी परित्यक्त बालक के मामले में, मान्यताप्राप्त अभिकरण चौबीस घंटे के भीतर उस पुलिस स्टेशन में, जिसकी अधिकारिता में बालक परित्यक्त पाया गया था, फाइल की गई रिपोर्ट की प्रति के साथ समिति के समक्ष रिपोर्ट करेगा और बालक को पेश किया जाएगा।
- (दो) समिति जांच प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की गई जांच भी है और जो एक मास के भीतर प्रपत्र- तेरह में निष्कर्षों वाली अपनी रिपोर्ट समिति को देगा।
- (तीन) विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा यह कथन करने वाली एक घोषणा की जाएगी कि दो वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में अधिसूचित करने के पश्चात् भी बालक के लिए कोई दावा करने वाला /वाली नहीं है तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए टेलीविजन अथवा रेडियो पर अतिरिक्त उद्घोषणा की जाएगी तथा गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल अथवा ब्यूरो को अधिसूचित किया जाएगा।
- (चार) उपरोक्त (तीन) में कथित उपाय, दो वर्ष से कम आयु के बालकों के मामले में, बालक के पाए जाने के समय से साठ दिन की अवधि के भीतर किए जाएंगे तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के मामले में, यह अवधि चार माह होगी।
- (पांच) अधिसूचना की अवधि, इस उप नियम के खंड (दो) के अधीन की जाने वाली जांच और रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ चलेगी।
- (छह) समिति, विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण की इस उप नियम के खंड (दो) और (तीन) के अधीन घोषणा सहित जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(सात) सात वर्ष से अधिक आयु के किसी भी बालक को जो समझ सकता है तथा अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उसकी सहमति के बिना दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित नहीं किया जाएगा।

4. अभ्यर्पित बालकों के मामले में, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात् :

- (क) अभ्यर्पित बालक, ऐसा बालक है, जिसे समिति द्वारा सम्यक् जांच प्रक्रिया के पश्चात् उस रूप में घोषित किया गया है तथा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के लिए "अभ्यर्पित" है। अभ्यर्पित बालक निम्नलिखित में से कोई होगा।
 - (एक) असहमति से बने संबंधों के परिणामस्वरूप जन्मा बालक;
 - (दो) अविवाहित मां अथवा विवाहेत्तर संबंध से जन्मा बालक;
 - (तीन) ऐसा बालक, जिसके मामले में जन्मदाता माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा जीवित माता/पिता उसकी देखभाल करने में असमर्थ हैं;
 - (चार) कोई बालक, जहां उसके माता-पिता अथवा अभिभावक अपने नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक कारणों से उसका त्याग करने के लिए मजबूर है।
- (ख) समिति द्वारा माता-पिता को समझाने, उन्हें दत्तकग्रहण के परिणामों को बताने तथा माता-पिता द्वारा बालकों को रखने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे तथा यदि माता-पिता बालक को रखने के इच्छुक नहीं हैं, तब ऐसे बालकों को शुरू में पालन-पोषण देखरेख में रखा जाएगा तथा उनके प्रायोजकों की व्यवस्था की जाएगी।
- (ग) यदि अभ्यर्पण अपरिहार्य है तो समिति के समक्ष गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र-पन्द्रह में अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- (घ) दत्तकग्रहण अभिकरण, अभ्यर्पण के बाद जन्मदाता माता या पिता अथवा माता-पिता को पुनः विचार करने के लिए दिए गए दो मास के समय के पूरा होने तक इंतजार करेगा।
- (ङ) जन्मदाता माता या पिता अथवा माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक के मामले में, माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण दस्तावेज समिति के समक्ष निष्पादित किया जाएगा।

- (च) समिति, प्रपत्र-तेरह में सम्यक् जांच के पश्चात् केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार साठ दिन की पुनः विचार की अवधि के पश्चात् यथास्थिति, प्रपत्र-चौदह में अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

5. अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी दत्तकग्रहण और संरक्षता के मामलों पर अधिकारिता है तथा इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश का न्यायालय, परिवार न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी है।

34. पालन पोषण देखभाल:-

- (1) जिन बालकों को दत्तकग्रहण में नहीं रखा जा सकता है, उनके लिए इस अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (2) तथा इन नियमों के नियम 35 (1) के अनुसार, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी अथवा केस वर्कर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-सत्रह में पालन-पोषण देखभाल का आदेश जारी किया जाएगा और पालन-पोषण देखभाल की अवधि बच्चे की जरूरत पर निर्भर करेगी।
- (2) यथासंभव ऐसे छोटे बालकों को, जिन्हें छोड़ दिया गया हो अथवा जो निराश्रित हों, उनकी निरंतर देखरेख के हित में, पोषण देखरेख में नहीं, बल्कि दत्तकग्रहण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) ऐसे छोटे बालकों को, जिन्हें कि दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है, अधिमान्यतः किसी दंपति के साथ वैयक्तिक पोषण देखरेख/समूह पोषण देखरेख में बालक की पारिवारिक परिस्थितियां सहायक समझी जाने पर उसके घर लौटने में समर्थ होने तक रखा जाएगा। तरुणों को समूह पोषक गृहों को निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- (4) अधिक आयु के बालकों को कुलीन समूह गृहों में ऐसे व्यक्तियों की पोषण देखरेख के अधीन रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि ऐसे इंतजामों का पर्यवेक्षण करने के इच्छुक हों।
- (5) पोषण देखरेख, भले ही वह अस्थायी स्वरूप की हो, यदि आवश्यक हो तो वयस्क होने तक जारी रहेगी, किंतु वह बालक को या तो स्वयं के माता-पिता के पास पहले लौटने अथवा उसके दत्तकग्रहण में व्यवधान नहीं डालेगी।
- (6) पोषक पारिवारिक देखरेख के समस्त मामलों में भावी पोषक माता-पिता, उपयुक्त बालक और उसके स्वयं के माता-पिता पर्याप्त रूप से भाग लेंगे, बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करने हेतु बाल कल्याण समिति उत्तरदायी होगी।

- (7) जुड़वां तथा सहोदर भाई या बहनों को पोषक स्थानन द्वारा असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, पृथक् नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से उन्हें पृथक् किया गया है तो उनके लिए संपर्क में बने रहने के इंतजाम किए जाएंगे।
- (8) प्रस्तावित पोषण व्यवस्था के संबंध में बालक की इच्छाओं पर स्थानन के पूर्व ध्यान दिया जाएगा।
- (9) व्यक्ति, जो पोषक माता-पिता होने के लिए सक्षम होंगे — पोषक माता-पिता होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे।
- (10) कोई एकल माता-पिता
- (11) दंपत्ति
- (12) बालक के विस्तारित कुटुम्ब के सदस्य
- (13) ऐसे गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य मान्यताप्राप्त व्यक्ति/अथवा अभिकरण जो व्यक्तिगत तौर पर अथवा समूह पोषण देखरेख के लिए बालक/बालकों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हों।

टारगेट ग्रुप —

- (क) दुष्क्रियारत परिवारों या संस्थाओं के बालक या जिनके जैविक माता-पिता या तो अक्षम हैं या संकट की स्थिति में हैं तथा बालक की देखरेख तथा स्थिति में नहीं है।
- (ख) पोषण देखरेख ऐसे बेसहारा बालकों के लिए है जो कि अनाथालयों में पल रहे तथा बाल कल्याण संस्थाओं द्वारा उन्हें पारिवारिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।
- (ग) ऐसे बालकों की पोषण देखरेख के लिए विचार किया जा सकेगा, जिन्हें विभिन्न कारणों से दत्तक में नहीं दिया जा सकता।
- (घ) पोषण देखरेख आवश्यकतानुसार अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है।
- (ङ) बाल कल्याण समिति की सहमति से बालक को संस्था से दूर रखते हुए उन्हें पोषण देखरेख में रखा जा सकता है।

फॉलोअप –

- (क) यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सोशल केसवर्कर द्वारा नियमित मुलाकात इस प्रकार की जाएगी कि बालक के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा हो सके।
- (ख) स्थानन रिपोर्ट का पुनर्विलोकन प्रत्येक छह माह में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। इन रिपोर्टों को बाल कल्याण समिति तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) पोषक गृह में बालक के उत्पीड़न की दशा में, माता-पिता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।
- (घ) जब पोषण स्थानन प्रारंभ हो तो बालक को रखने वाला व्यक्ति, बालक के संबंध में किए गए प्रतिरक्षणों की एक सूची पोषक माता-पिता को प्रस्तुत करेगा तथा बालक के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य प्रतिरक्षणों की सूची पोषक माता-पिता को उपदर्शित करेगा और पोषक माता-पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रतिरक्षण कर लिए जाते हैं। पोषक माता-पिता और जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा बाल विकास अधिकारी बालक के संबंध में प्रतिरक्षणों का अभिलेख हर समय रखेंगे।
- (ङ) जहां पोषक माता-पिता के पास रखा गया बालक पांच वर्ष से अधिक आयु का हो, वहां एक वर्ष में एक बार चिकित्सा कृत्यकारियों द्वारा बालक का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर, अपेक्षाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में पोषक माता-पिता की यथासंभव सहायता करेंगे।

विच्छेद–

- (क) यदि परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर को यह प्रतीत हो कि यह बालक के सर्वोत्तम हित में है तो वह विच्छेद की आवश्यकता के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगा/सकेगी तथा उसे बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।
- (ख) परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर, कुसमायोजन के उपचार के लिए किए गए प्रयासों के अभिलेख को भी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (ग) जब कहीं कुसमायोजन हो, बाल कल्याण समिति की सहमति अभिप्राप्त करने तथा पोषक माता-पिता को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात् बालक को हटाया जा सकेगा और किसी आनुकल्पिक गृह /ट्रांजिट होम में रखा जा सकेगा।

- (घ) किसी आपात् की दशा में, बाल गृह के अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के परामर्श से परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर के विवेक के आधार पर शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या शोषण की दशा के अनुसार बालक को हटाया जा सकेगा।
- (ङ) स्थानन के विच्छिन्न होने पर बाल कल्याण समिति, सलाह देने तथा देखरेख करने के यथोचित उपबंधों के साथ बालक के आनुकल्पिक स्थानन की सिफारिश करेगी।

बालक की बीमारी / मृत्यु या पोषक माता-पिता की मृत्यु होने की स्थिति में -

- (क) यदि बालक गंभीर रूप से बीमार हो तो पोषक माता-पिता यथाशक्य शीघ्र, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर को सूचित करेगा, जो माता-पिता संरक्षकों तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।
- (ख) यदि पोषक बालक की मृत्यु हो जाती है तो पोषक माता-पिता 24 घण्टे के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभिप्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा।
- (ग) वह संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर को भी तत्काल सूचित करेगा जो माता-पिता/संरक्षकों, महिला सशक्तिकरण संचालनालय तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।
- (घ) ऐसे मामले में, जहां बालक को एकल पोषक माता-पिता के साथ रखा गया है, उसकी मृत्यु होने पर बालक को उस मान्यताप्राप्त गृह, जहां से बालक को प्राप्त किया गया था, वापस भेज दिया जाएगा।

35. पालन-पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु मानदंड:-

- (1) इन नियमों के नियम 34 के अंतर्गत आने वाले बालकों के मामलों में, पालन-पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे, अर्थात्
- (एक) पोषक माता-पिता का परिवार के साथ स्थायी भावनात्मक सामंजस्य होना चाहिए।
- (दो) पोषक माता-पिता की अपनी ऐसी आय होनी चाहिए, जिसमें वे बालक की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हों तथा वे पालन-पोषण देखभाल भत्ते के संदाय पर निर्भर न हों।
- (तीन) परिवार की मासिक आय पोष्य बालकों की देखरेख करने के लिए पर्याप्त तथा समेकित बाल संरक्षण योजना में उल्लिखित समिति द्वारा अनुमोदित होगी।
- (चार) यह निर्धारित करने के लिए कि परिसर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ है एच.आई.वी. (ह्यूमेन इम्यून डैफिशिएंसी

- वायरस) क्षयरोग एवं हैपीटाइटिस बी संबंधी जांचों सहित उनकी चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।
- (पांच) पोषक माता-पिता में बाल देखरेख का अनुभव तथा अच्छी बाल देखभाल प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।
- (छह) पोषक माता-पिता शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।
- (सात) घर में पर्याप्त स्थान एवं बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।
- (आठ) पालन-पोषण देखभाल करने वाला परिवार शिशु रोग विशेषज्ञ से बालक की नियमित जांच कराने बालक के स्वास्थ्य एवं उनके रिकार्ड की देखरेख सहित अभिकथित किए गए नियमों का पालन करने का इच्छुक होना चाहिए।
- (नौ) परिवार ऐसे कशर पर हस्ताक्षर करने का तथा जब कभी ऐसा करने को कहा जाए बालक को विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण को वापस करने का इच्छुक होना चाहिए।
- (दस) पोषक माता-पिता को प्रशिक्षण अथवा अभिविन्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का इच्छुक होना चाहिए।
- (ग्यारह) पोषक माता-पिता को बालक का अभिकरण द्वारा अनुमोदित शिशु रोग विशेषज्ञ के पास नियमित जांच (शिशुओं के मामले में मास में कम से कम एक बार) के लिए जे जाने का इच्छुक होना चाहिए।
- (2) पोषक माता-पिता के चयन में जाति, धर्म, जातीय परिस्थिति, विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या पालन-पोषण देखभाल स्थापन का विनिश्चय करने में बालक की दशा या स्वास्थ्य और उसका सर्वोत्तम हित ही प्रमुख होगा।
- (3) प्रपत्र-सोलह के अनुसार, बाल कल्याण अधिकारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के बाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (एक) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार, बच्चे को पालन-पोषण हेतु देने से पहले पोषक माता-पिता को समिति द्वारा "उपयुक्त व्यक्ति" घोषित किया जाएगा।

36. पूर्व दत्तकग्रहण-पालन-पोषण:-

पूर्व दत्तकग्रहण पालन-पोषण देखभाल के मामले में, अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (1) तथा धारा 41 की उप धारा (3) के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बच्चों के दत्तकग्रहण के मार्गदर्शी सिद्धांत, 2015 लागू होंगे।

37. प्रायोजन/प्रवर्तकता:-

1. प्रवर्तकता सेवाएं बालक तथा उसके माता-पिता या संरक्षक के स्त्रोतों के अनुपूरक के रूप में समझी जाएंगी जिसमें बालक को समुदाय में पुनः मिलाने के साथ उसकी शिक्षा,

व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य आदि की देखरेख हेतु आर्थिक व्यवस्था के प्रयासों में सहयोग हो या माता-पिता या संरक्षक को बालक के प्रति उनके दायित्व को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुटुम्ब की आय के अनुपूरक के रूप में समझी जाएगी।

2. राज्य सरकार बालकों के लिए आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर प्रवर्तकता हेतु उपबंध कर सकेगी, जब वे स्वागत इकाई, आश्रयगृह/बालगृह/विशेषगृह/पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों से उन्मुक्त हो।
3. राज्य सरकार व्यक्तियों, संस्थाओं, कारपोरेट सेक्टर, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों आदि द्वारा बिना किसी लाभ की आशा के निम्नलिखित के लिए प्रवर्तक या समर्थक करना अनुज्ञात कर सकेगी :-

1. बालकों को उच्च शिक्षा के लिए बाल श्रमिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए किसी बालक या उसके कुटुम्ब की प्रवर्तकता के अधीन समर्थन दिया जाएगा।
2. व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से बालकों के व्यवहार में सुधार हेतु किन्हीं कार्यकलापों में संलग्न होना।
3. ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए बालकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पिकनिक, अवकाश कैम्प, चिकित्सीय सहायता टीकाकरण कार्यक्रम, विशेष चिकित्सा सहायता आदि अंतर्विद्यालय खेलकूद गतिविधियां सृजनात्मककला प्रतियोगिता सेमीनार।
4. धंधा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कोई क्रियाकलाप, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, सामुदायिक महाविद्यालय आदि की स्थापना।
5. पुस्तकालय, खेलकूद क्रियाकलाप, उद्यान, विद्यान/रेशम उद्योग, सृजनात्मक कला और प्रतियोगिताएं आदि या किसी अन्य विकास कार्यक्रम की स्थापना।
6. भवन की अधोसंरचना तथा सुविधाओं में सुधार करना, उसका निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना आदि।

4. प्रवर्तकता योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया :-

- (1) भारत सरकार द्वारा प्रवर्तकता योजना संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे।
- (2) राज्य सरकार गैर-सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समितियों, अन्य सुसंगत सरकारी अभिकरणों तथा कारपोरेट क्षेत्र के परामर्श से प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी।
- (3) राज्य सरकार जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाइयों की सहायता से, जोखिम में रह रहे परिवारों और बालकों की पहचान करेगी तथा बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए प्रायोजन के रूप में आवश्यक समर्थन सेवाएं प्रदान करेगी।
- (4) बाल गृह और विशेष गृह अधिनियम की धारा 43 में यथा अभिकथित प्रायोजित कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे।

- (5) प्रायोजन प्राप्त करने वाली संस्थाएं कार्यक्रम के लिए सभी प्राप्तियों और संदायों के उचित और पृथक लेखे रखेंगी।
- (6) बोर्ड अथवा समिति किसी किशोर अथवा बालक को सहायता देने के लिए प्रपत्र—अठारह में एक आदेश करेगी तथा इसकी एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी।

38. पश्चात्तर्वर्ती देखभाल संगठन:—

- (1) राज्य सरकार सामाजिक पुनर्समेकन हेतु किशोरों अथवा बालकों को संस्था आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु उनके पारगमन को सुकर बनाने के उद्देश्य से विशेष गृहों एवं बाल गृहों को छोड़ने के पश्चात् उनके लिए पश्चात्तर्वर्ती देखभाल कार्यक्रम तैयार करेगी।
- (2) अधिनियम की धारा 44 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाइयों द्वारा पश्चात्तर्वर्ती देखभाल कार्यक्रम 18-21 वर्ष के उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके पास कहीं जाने का कोई स्थान नहीं है अथवा स्वयं अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं।
- (3) जब बोर्ड या समिति किसी किशोर अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे को पश्चात्तर्वर्ती देखभाल कार्यक्रम के अधीन रखने के लिए प्रपत्र— चौदह में आदेश करती है तो ऐसे आदेश की एक प्रति जिला और राज्य बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो पश्चात्तर्वर्ती देखभाल की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (4) पश्चात्तर्वर्ती देखभाल में रखे गये व्यक्ति पर बोर्ड अथवा समिति की अधिकारिता होगी।
- (5) इन संगठनों का उद्देश्य ऐसे बालकों को समाज के प्रति अनुकूल होने के लिए समर्थ बनाना है।
- (6) कार्यक्रम के मुख्य संघटकों में निम्नलिखित होंगे—
 - (क) 18-21 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक समूह आवास;
 - (ख) व्यवसाय सीखने या रोजगार प्राप्त करने और किराए तथा गृह के संचालन में अभिदाय करने के लिए प्रोत्साहित करना;
 - (ग) धीरे-धीरे राज्य की सहायता के बिना आत्मनिर्भर बनने के लिए तथा अपने उपार्जन के माध्यम से पर्याप्त रकम बचाने के पश्चात् समूह गृह से निकलकर अपने स्वयं के गृह में निवास करने के लिए प्रोत्साहित करना;
 - (घ) इन समूहों से उनकी पुनर्वास योजनाओं पर विचार विमर्श करने तथा उनकी ऊर्जा हेतु सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रदान करने और उनके जीवन में आने वाली संकटमय अवधि पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले अभिजात परामर्शदाता के लिए व्यवस्था करना।

- (7) व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान युवाओं को, जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है, वृत्तिका प्रदान की जाएगी।
- (8) पश्चात्वर्ती देखभाल कार्यक्रम में युवाओं को उनके द्वारा किए गये आवेदन तथा ऐसे ऋण की आवश्यकता के सम्यक् सत्यापन एवं आवश्यक व्यावसायिक सलाह के आधार पर उद्यम/क्रियाकलाप स्थापित करने के लिए ऋणों की व्यवस्था की जाएगी और इस संबंध में पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- (9) प्रत्येक समूह गृह में 5-8 युवा शामिल किए जाएंगे। जिन्हें पश्चात्वर्ती देखभाल योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा। पांच समूह गृहों के लिए एक अभिजात परामर्शदाता भी होगा।

39. संपर्क एवं समन्वयन:—

- (1) राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति के माध्यम से किशोरों अथवा बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्संभेदन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी, कारपोरेट एवं अन्य सामुदायिक अभिकरणों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करने के लिए अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की एक प्रति परिचालित करेगी।
- (2) राज्य सरकार, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से, अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रत्येक विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व का पता लगाएगी तथा उन्हें अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करेगी।
- (3) राज्य सरकार राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से तथा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय से इन विभागों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा संचेतना पैदा करने की व्यवस्था समय-समय पर करेगी।
- (4) राज्य सरकार, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य उपाय, नशा मुक्तिकरण तथा विधिक सहायता सेवाओं जैसी विशेषज्ञ सेवाओं एवं तकनीकी सहायता हेतु स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी नेटवर्क और संपर्क स्थापित करेगी।

अध्याय 6**संस्थाओं के लिए देखरेख के मानक**

40. **भौतिक अवसंरचना:-** (1) विधियों के उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु गृह अलग परिसर में कार्य करेंगे।
- (2) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंड के अनुसार होगा, अर्थात्-
- (क) सम्प्रेक्षण गृह
(एक) लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग सम्प्रेक्षण गृह ;
(दो) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए किशोरों का उनकी आयु वर्ग के आधार पर, अधिमानतः 7-11 वर्ष, 12-16 वर्ष एवं 16-18 वर्ष, वर्गीकरण और पृथक्करण।
- (ख) विशेष गृह:-
(एक) लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग विशेष गृह ;
(दो) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर, किशोरों का वर्गीकरण और पृथक्करण।
- (ग) बाल गृह:-
(एक) 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और लड़कों को एक ही गृह में रखा जा सकता है किन्तु 5-10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए नहाने और सोने की व्यवस्था अलग-अलग होगी।
(दो) 7-11 और 12-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग बाल गृह।
(तीन) शिशुओं के लिए उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु अलग सुविधाएं।
- (घ) आश्रय गृह:-
(एक) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग आश्रय गृह
(दो) 10 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों और 11-15 और 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों हेतु अलग-अलग आश्रय गृह।
- (3) 50 किशोरों या बालक वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार है-
- | | |
|-------------------------|---|
| (एक) 2 शयनकक्ष | 25 किशोरों/बालकों के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग फीट अर्थात् 2000 वर्गफीट |
| (दो) 2 क्लासरूम | 25 किशोरों/बालकों के लिए प्रत्येक 300 वर्गफीट अर्थात् 600 वर्गफीट |
| (तीन) रोगीकक्ष/प्राथमिक | 10 किशोरों/बालकों के लिए प्रत्येक 75 वर्ग फीट (सहायता कक्ष) अर्थात् 750 वर्गफीट |
| (चार) किचन | 250 वर्गफीट |
| (पांच) डाईनिंग हॉल | 800 वर्गफीट |

- | | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| (छह) | स्टोर | 250 वर्गफीट |
| (सात) | मनोरंजन कक्ष | 300 वर्गफीट |
| (आठ) | लाइब्रेरी | 500 वर्गफीट |
| (नौ) | 5 बाथरूम | 25 वर्गफीट प्रत्येक अर्थात् 125 वर्गफीट |
| (दस) | 8 टॉयलेट/लेट्रीन | 25 वर्गफीट प्रत्येक अर्थात् 200 वर्गफीट |
| (ग्यारह) | कार्यालय कक्ष | (क) 300 वर्गफीट (ख) अधीक्षक कक्ष 200 वर्ग फीट |
| (बारह) | काउंसलिंग और मार्गदर्शन कक्ष | 120 वर्गफीट |
| (तेरह) | वर्कशाप | 15 किशोरों के लिए प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फीट की दर से 1125 वर्गफीट |
| (चौदह) | अधीक्षक के लिए निवास | (क) 250 वर्गफीट प्रत्येक के 2 कक्ष (ख) किचन 75 वर्ग फीट (ग) बाथरूम कम टॉयलेट/लेट्रीन 50 वर्गफीट |
| (पन्द्रह) | किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति | — 300 वर्ग फीट प्रत्येक अर्थात् 600 वर्गफीट के लिए 2 कमरे |
| (सोलह) | खेल मैदान कुल | किशोरों या बालकों की कुल संख्या के अनुरूप पर्याप्त क्षेत्र 8745 वर्गफीट |
- (4) अधीक्षक संस्थान में ही रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि न्याय संगत कारणों से वह गृह में रहने में असमर्थ है (निदेशक, बाल संरक्षण की अनुज्ञा से) तो संस्थान के कर्मचारिवृंद में से कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य संस्थान में रहेगा तथा बालकों तथा किशोरों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने की स्थिति में होगा और किसी समस्या और आपात्काल की दशा में निर्णय लेगा।
- (5) (i) नियम 40 (2) में अभिकथित मानकों के अनुसार आवास का संभव सीमा तक अनुपालन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं शामिल होगी।
- | | | |
|-----|-------------------|---|
| (क) | शयनकक्ष (शयनागार) | 40 वर्गफीट प्रति किशोर या बालक |
| (ख) | क्लासरूम | 25 किशोर या बालक के लिए 300 वर्गफीट |
| (ग) | वर्कशाप | 75 वर्गफीट प्रति किशोर या बालक |
| (घ) | खेल मैदान | पर्याप्त खेल मैदान क्षेत्र, संस्था में किशोरों की कुल संख्या के अनुसार प्रत्येक संस्था में प्रदान किया जाएगा। |
- (ii) दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपयुक्त और स्मूथ फर्श होगा।
- (iii) लिंग आयु उपयुक्तता और पहुंचनीयता की शर्तों में पर्याप्त लाईटिंग, वेंटीलेशन, हीटिंग और कूलिंग और व्यवस्थाएं, सुरक्षित पीने का पानी और साफ टॉयलेट होंगे।

- (iv) अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएं प्राथमिक उपचार किट, रसोई, शयनकक्ष, स्टोर रूम, काउंसलिंग कक्ष में आग बुझाने के यंत्र इलेक्ट्रानिक उपकरणों का समय कालिक निरीक्षण, खाद्य वस्तुओं का उपयुक्त स्टोरेज व निरीक्षण जल संचारण और आवश्यक लाइटिंग के लिए तुरन्त व्यवस्था करने के लिए प्रावधान बनायेगी।
- (6) संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह बालक मित्रतापूर्ण होंगे और किसी भी तरीके में वे जेल या लॉक-अप के समान नहीं लगें।
41. **कपड़े और बिस्तर :-** कपड़े और बिस्तर मानक और जलवायु-विषक परिस्थितियों तथा प्रत्येक किशोर या बाल की आवश्यकतानुसार होंगे। कपड़ों और बिस्तर हेतु न्यूनतम मानक इन नियमों की अनुसूची - I में अभिकथित किए गए हैं।
42. **सेनीटेशन और हाईजीन:-** प्रत्येक संस्था के पास निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्
- (क) पर्याप्त उपचारित पीने का पानी, वाटर फिल्टर लगाये जायेंगे,
- (ख) स्नान करने और कपड़े धोने, परिसर के रख-रखाव और साफ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी,
- (ग) उपयुक्त जल-निकासी पद्धति,
- (घ) कूड़े को निस्तारित करने के लिए व्यवस्थाएं,
- (ङ) मच्छर जाली प्रदान करते हुए मच्छरों से सुरक्षा,
- (च) वार्षिक कीट (दीमक) नियंत्रण,
- (छ) सात बच्चों के लिए कम से कम एक टॉयलेट के अनुपात में पर्याप्त रोशनीवाला और हवादार टॉयलेट की पर्याप्त संख्या,
- (ज) दस बच्चों के लिए कम से कम एक बाथरूम के अनुपात में पर्याप्त रोशनीवाला और हवादार बाथरूम की पर्याप्त संख्या,
- (झ) कपड़े धोने के लिए पर्याप्त स्थान,
- (ञ) साफ और मक्खी रहित रसोई और बर्तन धोने के लिए अलग स्थान,
- (ट) बिस्तर और कपड़ों को सुखाने का स्थान,
- (ठ) मेडिकल केन्द्र में सफाई का रख-रखाव।
43. **दैनिक दिनचर्या :** (1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श से किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ-साथ नियमित और अनुशासित जिंदगी, व्यक्तिगत साफ-सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और शनिवार तथा छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

44. पोषण और आहार मानक : संस्था निम्नलिखित पोषण और खुराक मानकों का अनुसरण करेगी, अर्थात् :-

- (क) नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन बालक को प्रदान किया जाएगा।
- (ख) इन नियमों की अनुसूची 2 में वर्णित न्यूनतम पोषण मानक और खुराक मान के अनुसार स्वाद में संतुलित खुराक और वैरायटी सुनिश्चित करने के लिए पोषणीय विशेषज्ञ या डॉक्टर की सहायता से मेन्यू तैयार किया जाएगा।
- (ग) अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्था अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पोषण मानकों और खुराक मानकों को कड़ाई से पालन करेगी।
- (घ) किशोर या बालक को अवकाश और त्यौहार पर विशेष भोजन प्रदान किया जाएगा।
- (ङ) शिशुओं और बीमार किशोरों या बालकों को उनकी खुराक की आवश्यकता पर संबंधित डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष खुराक प्रदान की जाएगी।

45. चिकित्सा देखरेख:-प्रत्येक संस्था,-

- (क) मासिक चिकित्सा चेकअप के आधार पर प्रत्येक बालक या किशोर का चिकित्सा रिकार्ड रखेगी और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी।
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा रिकार्ड में भार और कद का रिकार्ड, कोई बीमारी और उपचार और अन्य शारीरिक या मानसिक समस्या शामिल हैं।
- (ग) चिकित्सा सुविधाओं के लिए व्यवस्था करेगी जिसमें किशोर या बालक के नियमित चिकित्सा चेकअप और उपचार के लिए सभी कार्यदिवसों पर बुलाये जाने पर डॉक्टर का उपलब्ध होना शामिल है।
- (घ) मामूली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपकरण होंगे, जिसमें आवश्यक दवाओं और सामग्री के स्टॉक के साथ प्राथमिक उपचार किट शामिल हों।
- (ङ) प्राथमिक उपचार करने में सभी स्टाफ को प्रशिक्षित करेगी।
- (च) उनके डॉक्टरों और विद्यार्थियों द्वारा नियमित भ्रमण के लिए और संस्थाओं के भीतर समयकालिक स्वास्थ्य केम्प लगाने के लिए स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी अस्पताल, चिकित्सा कॉलेज, अन्य अस्पताल, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं से जुड़ी रहेगी।
- (छ) प्रतिरक्षण कवरेज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी
- (ज) संक्रामक और छूत वाली बीमारियों के फैलने की दशा में निवारक उपाय करेगी
- (झ) नजदीकी सिविल अस्पताल या मान्यताप्राप्त उपचार केन्द्र में बिगड़े स्वास्थ्य और गंभीर मामलों को भेजने के लिए प्रणाली की स्थापना करेगी।
- (ञ) बीमार बालक को लगातार चिकित्सीय निगरानी में रखेगी।
- (ट) प्रवेश के समय चिकित्सीय प्रमाणपत्र का कहे बिना बालक या किशोर को प्रवेश देगी।

- (ठ) चौबीस घण्टों के भीतर और विशेष मामलों में या चिकित्सा इमरजेंसी में तुरन्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्था में प्रविष्ट प्रत्येक बालक या किशोर की चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगी।
- (ड) ट्रांसफर से पहले चौबीस घण्टों के भीतर ट्रांसफर के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा किशोर या बालक की चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगी।
- (ढ) उसके माता-पिता या संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना किसी किशोर या बालक पर कोई सर्जिकल उपचार नहीं करेगी, जब तक कि माता-पिता या संरक्षक में से कोई भी विलम्ब चिकित्सा अधिकारी की राय में किशोर या बालक के अनावश्यक पीड़ा उपहति में परिवर्तित हों, या अन्यथा संस्था के प्रभारी अधिकारी से इस संबंध में लिखित सहमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगी।
- (ण) प्रत्येक किशोर या बालक के नियमित काउंसलिंग के लिए प्रावधान या व्यवस्था करेगी और ऐसी सेवाओं की आवश्यकता में उस बालक या किशोर के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगी, जिसमें संस्था के परिसर के भीतर काउंसलिंग सत्र के लिए अलग कक्ष शामिल होते हैं।
- (त) "ऐसे बालक, जो अल्कोहल या अन्य नशीले द्रव्यों के व्यसनी है जिससे व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन होता है, उन व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्र या मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्ति के लिए राज्य (स्थापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के व्यक्ति सहित) सरकार द्वारा अनुरक्षित उन्ही केन्द्रों में ऐसे किशोर या बालक के अंतरंग रोगी उपचार हेतु अपेक्षित अवधि के लिए भेजा जाएगा।" (As per 2011 Amendment of Rules)

46. **मानसिक स्वास्थ्य.**—(1) प्रत्येक किशोर या बालक का मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधित संस्थाओं द्वारा रखा जाएगा।

- (2) दोनों परिस्थिति आधारित हस्तक्षेप, जो बालक और वैयक्तिक थेरेपी के लिए पक्षयोग्य पर्यावरण को उत्पन्न कर रही हो, प्रत्येक बालक के लिए होनी चाहिए और सभी संस्थाओं में प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, परिवेश आधारित अन्तःक्षेप पुनःनिरोग होने की एक प्रक्रिया है जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक की योग्यताओं का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिंदगी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है और इस प्रकार, वे विकास करते हैं तथा अपने नकारात्मक अनुभवों से परे अपना विकास और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अन्तःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

- (3) किसी संस्था का परिवेश शोषण से मुक्त होना चाहिए, ताकि किशोर या बालक अपनी परिस्थितियों का सामना कर सके तथा वे पुनः आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें।
- (4) किसी संस्था में किशोर या बालकों की देखभाल में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाने में भाग लेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

- (5) व्यक्तिगत चिकित्सा एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अन्तःक्षेप की व्यवस्था करेगी।
 - (6) प्रत्येक संस्था में किशोर या बालक के लिए विशेषीकृत तथा नियमित व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बालक मार्गदर्शन केन्द्रों, मनोविज्ञान और मनःचिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों से भी प्राप्त की जा सकती है।
 - (7) प्रत्येक किशोर या बालक के लिए संस्था से संबंध मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श से बाल कल्याण अधिकारी द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल योजना विकसित की जाएगी तथा इसे संबंधित किशोर या बालक की व्यक्तिगत देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
 - (8) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को रखा जाएगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
 - (9) इस देखभाल योजनाओं की प्रति मास इन नियमों के नियम 55 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के समक्ष तथा प्रत्येक तिमाही में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (10) किसी भी किशोर या बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी।
47. शिक्षा— (1) प्रत्येक संस्था सभी किशोरों या बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार आवश्यकता के अनुसार, संस्था के भीतर या बाहर शिक्षा प्रदान करेगी।
- (2) शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा जहां आवश्यकता हो विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा और आगत शामिल हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - (3) जहां कहीं भी आवश्यक हों, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों से संपर्क करके प्रदान की जाएगी।
 - (4) उन बालकों को जो अशिक्षित हैं, अथवा जिन्हें संज्ञानात्मक अथवा सीखने के संबंध में कठिनाई हो विशेष शिक्षा का अधिकार होगा।
 - (5) उन बालकों को, जो कि स्कूल जाने की अनिवार्य आयु से ऊपर के हों और जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हों, अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें समुचित शैक्षणिक कार्यक्रम सुलभ हो सकें, इस हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।
 - (6) अधिनियम के अधीन बालकों को प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा अथवा शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाया जाएगा कि बालक ऐसी संस्था में रहा है।
 - (7) प्रत्येक संस्था को ऐसा पुस्तकालय सुलभ करना चाहिए जिसमें बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण संबंधी तथा आनंदप्रद दोनों ही प्रकार की पुस्तकों का तथा नियतकालिक पत्रिकाओं

(पीरियोडिकल्स) का पर्याप्त स्टॉक हो, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित और इसका पूरा उपयोग करने के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए।

- (8) बालकों के धार्मिक विश्वासों का सम्यक् आदर किया जाएगा और ऐसी कोई कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी, जो शिक्षा के नाम पर धर्मान्तरित करने का प्रयास करती हों।

48. **व्यावसायिक प्रशिक्षण.**—(क) प्रत्येक संस्था किशोरों या बालकों को लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

- (ख) इस प्रयोजनार्थ संस्थाएं, तकनीकी अनुदेश संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, विशेषज्ञता-प्राप्त सरकारी और निजी संगठनों या उद्यमों, अभिकरणों या गैर-सरकारी संगठनों अथवा रोजगार दिलाने वाले अभिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करेगी।

- (ग) उन बालकों को छोड़कर, जो कि संप्रेक्षणगृह में अस्थायी रूप से देखरेख में हो, अनिवार्य स्कूल शिक्षा की आयु के ऊपर के प्रत्येक बालक को उस व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो भविष्य में उसे रोजगार के लिए तैयार कर सके।

- (घ) उचित व्यावसायिक चयन और संस्थागत प्रशासन की अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए बालकों को उस प्रकार का कार्य चुनने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिसे वे करना चाहते हो।

- (ङ) जहां संभव हो तथा चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार बालकों को पारिश्रमिक सहित कार्य तलाशने के तथा अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण जारी रखने के अवसर दिए जाएंगे परंतु उनसे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कार्य, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण, संस्था में बालक के बने रहने का कारण नहीं बनेंगे।

- (च) जहां संभव हो, बालकों को अपने समुदायों में लौटने पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ाने की दृष्टि से दिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के पूरक के रूप में, यदि संभव हो तो स्थानीय समुदाय में पारिश्रमिक सहित कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य इस प्रकार का हो, जिससे बालक को ऐसा समुचित प्रशिक्षण मिल सके, जो उनके निर्मुक्त होने पर उनके लिए लाभदायक हो। संगठन और दक्षताओं में दिए जाने वाले काम की रीतियों में एवं समुदाय में उसी प्रकार के काम में यथासंभव निकटतम रूप से समानता होगी, ताकि बालकों को सामान्य व्यावसायिक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके।

- (छ) प्रत्येक बालक को, जो कि काम करता है, यदि काम पारिश्रमिक वाला है तो उसे न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होगा बालकों के और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के हितों को किशोर न्याय संस्था या किसी तीसरे पक्ष को कोई लाभ दिलवाने के प्रयोजन के अधीन नहीं होंगे किसी बालक के उपार्जन के भाग को बचत निधि गठित करने के लिए अलग रखा जा सकेगा, जो निर्मुक्त होने पर उसे सौंप दिया जाए। बालक को उस उपार्जन के शेष भाग को उसके स्वयं के उपयोग की वस्तुएं क्रय करने के लिए या उसके अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त पीड़ित की क्षतिपूर्ति करने के लिए या उसे उसके परिवार को अथवा संस्था के बाहर के किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भेजने का अधिकार हो सकेगा।

49. **मनोरंजन सुविधाएं—** (1) संस्थाओं में सभी किशोरों या बालकों को मार्गदर्शन के अंतर्गत मनोरंजन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) मनोरंजन सेवा के अंतर्गत चार दीवारी के भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेल, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुस्तकालय शामिल हैं।
50. **किशोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था—**(1) संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले नए किशोरों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :
- (क) इन किशोरों को स्वीकार करना तथा इनकी तलाशी लेना,
- (ख) किशोरों के व्यक्तिगत सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विसंक्रमण और भण्डारण करना,
- (ग) उन्हें प्रसाधन कराना व उनके बाल कटवाना (यदि उनके धर्म के अनुसार ऐसा करना प्रतिषिद्ध न हो),
- (घ) उन्हें प्रसाधन सामग्री पहनने के लिए नए कपड़े, बिस्तर तथा अन्य जरूरी सामान और उपस्कर देना (मानदण्डों के अनुसार),
- (ङ) जहां कहीं आवश्यक हो तथा ऐसे किसी किशोर की दशा में चिकित्सीय जांच और उपचार, जो संक्रामक रोग, मानसिक रोग या अन्य किसी प्रकार से आदी हो गया हो,
- (च) किसी संक्रामक रोग से पीड़ित और विशेष देखभाल के अपेक्षित बालकों को विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित शयनशाला या वार्ड या अस्पताल में अलग से रखा जाएगा,
- (छ) किशोरों की तात्कालिक और अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति की जाएगी, जैसे कि परीक्षा देना, उनके माता-पिता को उनसे मिलने के लिए पत्र भेजना, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाना इत्यादि तथा बोर्ड के आदेशानुसार किशोर की आयु का प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- (2) इन संस्थाओं के साथ संबद्ध परिवीक्षा अधिकारियों का बाल कल्याण अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं या अन्य स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा परामर्शदाताओं में से कोई एक व्यक्ति ऐसी संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक नए बालक या किशोर की दशा में विशिष्ट कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (3) संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक नए किशोर को उस संस्था और उसके कामकाज से परिचित कराया जाएगा और उसे निम्नलिखित बातों की जानकारी भी दी जाएगी।
- (क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई
- (ख) संस्थागत अनुशासन और व्यवहार संबंधी मानक, वृद्धों और अध्यापकों के लिए आदर।
- (ग) दैनिक कार्यकलाप, साथियों के साथ व्यवहार, विकास संबंधी अवसरों का इष्टतम उपयोग और,
- (घ) संस्था के भीतर उसके अधिकार, उत्तरदायित्व और दायित्व।

- (4) नामनिर्दिष्ट अधिकारी किशोर या बालकों का नाम प्रवेश रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उसे उपयुक्त आवास सुविधा आवंटित करेगा।
- (5) अभिलेख के लिए किशोर का फोटो तत्काल खींचा जाएगा और किशोर या बालक द्वारा नामित व्यक्ति के साथ मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या कल्याण अधिकारी अन्वेषण और पत्राचार आरंभ करेगा,
- (6) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था को किशोर या बालक से प्राप्त उसका व्यक्तिगत सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है तथा व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में दर्ज भी किया गया है और यह सामान किशोर या बालक को संस्था छोड़ते समय वापस किया जाना चाहिए।
- (7) किशोरी या बालिका की तलाशी किसी महिला सदस्य द्वारा ली जाएगी और ऐसा करते समय उस किशोरी या बालिका की शिष्टता और सम्मान को ध्यान में रखा जाएगा।
- (8) अध्यापक, कार्यशाला पर्यवेक्षक और अन्य तकनीकी कर्मचारीवृंद द्वारा ली गई परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश पाए किशोर के शैक्षणिक स्तर व व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाएगा और बाह्य विशेषज्ञों एवं समुदाय आधारित कल्याण अभिकरणों, मनोवैज्ञानिकों, मनःचिकित्सकों, बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों, अस्पतालों, स्थानीय चिकित्सकों, मुक्त विद्यालयों या जन शिक्षण संस्थाओं से ही आवश्यक संपर्क स्थापित किया जाएगा।
- (9) संस्था में प्रवेश पाने वाले किशोर या बालक के मामले का पूर्ववृत्त प्रपत्र XX में रखा जाएगा, जिसमें किशोर या बालक की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना होगी और ये सूचना, यथासंभव सभी उपलब्ध स्रोतों, जैसे कि किशोर या बालक के घर, माता-पिता या अभिभावकों, नियोक्ताओं, विद्यालय मित्रों और समुदाय के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
- (10) किशोरों या बालकों की रिहाई के पूर्व योजना तथा विशेष गृहों से मुक्त हुए किशोरों या बालकों के मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही के सुविचारित कार्यक्रम विद्यमान सरकारी और स्वैच्छिक कल्याण संगठनों के सहयोग से सभी संस्थाओं में तैयार किए जाएंगे।
- (11) किसी किशोर या बालक के बिना अनुमति के संस्था से चले जाने अथवा संस्था के भीतर अपराध करने की दशा में संबंधित संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस और संबंधित किशोर या बालक के परिवार को, यदि ज्ञात हो, भेजी जाएगी और किशोर या बालक के गुम रहने की स्थिति में उसे ढूँढने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों सहित उक्त घटना की परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को भेजी जाएगी।
- (12) संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक किशोर या बालक के पूर्ववृत्त, परिस्थितियों और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार परक उसके पुनर्वास और समाज में उसको पुनः सम्मिलित करने के उद्देश्य से उसके लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी और व्यक्तिगत देखरेख योजना निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर आधारित होगी :
 - (क) किसी भी संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक बालक के लिए उसके प्रवेश की तारीख से एक मास के भीतर प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता, बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता

या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रपत्र XXI के अनुसार तैयार करेगा,

- (ख) सभी देखरेख योजनाओं में किशोर या बालक के पुनरुद्धार, पुनःसम्मिलित करने और अनुवर्ती योजना शामिल होगी,
- (ग) किशोर या बालक की रिहाई या उसे उसके परिवार या उसकी पोषक देखरेख करने वालों या दत्तक माता-पिता के पास वापस भेजने के विकल्पों सहित उसके उपयुक्त विकास और पुनर्वास के लिए इन नियमों के नियम संख्या 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति. उक्त देखरेख योजना का तिमाही के आधार पर पुनर्विलोकन करेगी,
- (घ) किशोरों या बालकों की देखरेख योजना तैयार करते समय उनकी सलाह भी ली जाएगी,
- (ङ) किशोरों या बालकों के स्थानांतरण या पुनरुद्धार या घर वापसी के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त देखरेख योजना का कार्यान्वयन जारी रहे,

51. **प्रतिषिद्ध वस्तुएं**—कोई भी व्यक्ति संस्था में प्रतिषिद्ध वस्तुएं लेकर नहीं आएगा, अर्थात् :—

- (क) आग्नेयास्त्र या अन्य कोई अस्त्र-शस्त्र, चाहे उसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो या नहीं (जैसे कि चाकू, ब्लेड, लाठी, भाला और तलवार)
- (ख) अल्कोहल और किसी प्रकार की सिप्रट,
- (ग) भांग, गांजा, अफीम या अन्य कोई स्वापक या मनःप्रभावी पदार्थ,
- (घ) तम्बाकू, या
- (ङ) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्तु

52. **तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएं**—(1) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक किशोर की तलाशी ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए तथा उसके पास पाए गए धन या अन्य किसी मूल्यवान वस्तु को उस प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

- (2) बालिकाओं की तलाशी संस्था की महिला सदस्य द्वारा ली जाएगी और बालकों और बालिकाओं दोनों की तलाशी शिष्टता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी।
- (3) किसी किशोर के पास पाए गए धन, मूल्यवान वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में रखा जाएगा।
- (4) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में प्रत्येक किशोर के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थिति में उस किशोर को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रतीक के रूप में उक्त साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तथा इन प्रविष्टियों पर प्रभारी अधिकारी प्रति हस्ताक्षर करेगा।

53. **वस्तुओं का निपटान** :—किसी संस्था में प्राप्त या रखे गए किशोर के धन या मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति में निपटान किया जाएगा :—

- (क) किसी किशोर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे किसी संस्था में भेजे जाने का निर्देश देते हुए जारी किए गए आदेश पर प्रभारी अधिकारी ऐसे किशोर का धन और उसकी आय समय-समय पर अभिकथित रीति से उसके नाम पर जमा कराएगा।
- (ख) किशोर का धन प्रभारी अधिकारी के पास रखा जाएगा और उसकी मूल्यवान वस्तुएं, बिस्तर, कपड़े, और अन्य वस्तुएं, यदि कोई हों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे,
- (ग) जब ऐसे किशोर को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता है, तब उसकी पूर्ण धनराशि, मूल्यवान वस्तुएं और अन्य वस्तुएं बालक के साथ उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजे जाएंगे, जिसमें उस किशोर का स्थानांतरण किया गया है और उसमें सारे सामान का वर्णन और उसके प्राक्कलित मूल्य का पूरा और सही विवरण होगा,
- (घ) ऐसे किशोर को रिहा करते समय सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं और उसके नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावकों को सौंपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी, जिस पर प्रभारी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा,
- (ङ) जब संस्था में किसी किशोर की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक, द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा उसके नाम में जमा धनराशि प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जाएंगे, जो उन पर अपना दावा सिद्ध करता है और एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करता है,
- (च) ऐसी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस प्राप्ति की रसीद ली जाएगी,
- (छ) यदि ऐसे किसी किशोर की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो मृतक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम पर जमा धनराशि का इन नियमों की नियम संख्या 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति के विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा।

54. मामले की फाइल का रखरखाव :- (1) प्रत्येक किशोर और बालक की मामला फाइल संस्था में रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी :-

- (क) किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट,
- (ख) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और मामला कार्यकर्ता की रिपोर्ट,
- (ग) पिछली संस्था से प्राप्त जानकारी,
- (घ) किशोर से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी,
- (ङ) अतिरिक्त जानकारी का स्रोत,
- (च) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्टें,

- (छ) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टें जहां कहीं आवश्यक हो, मनोवैज्ञानिक परामर्श या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य किसी कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्टें,
- (ज) बुद्धिलब्धि (आई.क्यू.) परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, शैक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षाओं के परिणाम,
- (झ) सामाजिक इतिवृत्त,
- (ञ) मामला विशिष्ट कार्यकर्ता और प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सार और विश्लेषण,
- (ट) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम तथा विशेष सावधानियां रखे जाने के संबंध में अनुदेश,
- (ठ) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार,
- (ड) विशेष उपलब्धियां तथा नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो
- (ढ) तिमाही प्रगति रिपोर्ट,
- (ण) प्रपत्र XXI में यथाविहित रिहाई पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना एवं अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना,
- (त) संस्था से अनुपस्थित रहने या पर्यवेक्षणाधीन रिहाई की अनुमति,
- (थ) रिहाई,
- (द) अनुवर्ती रिपोर्ट,
- (ध) वार्षिक फोटोग्राफ,
- (न) प्रपत्र XX में यथाविहित मामले का सम्यक् रूप से भरा गया इतिवृत्त,
- (प) सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, यदि कोई हो, विभिन्न मामलों में रिहाई के उपरांत अनुवर्ती रिपोर्ट, तथा,
- (फ) टिप्पणियां,
- (2) संस्थाओं और बोर्ड या समिति द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइलें यथासंभव कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्क में भी प्रविष्ट की जाएंगी ताकि ये आंकड़े राज्य और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से उपलब्ध हो सके।

55. **प्रबंधन समिति :-** (1) संस्था के प्रबंधन और उसमें रहने वाले किशोर और बालकों की प्रगति को मानीटर करने के लिए प्रत्येक संस्था की प्रबंधन समिति होगी।

(2) किशोरों या बालकों की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार, उनकी समुचित देखरेख और उपचार सुनिश्चित करने के लिए उनकी आयु, अपराध की प्रकृति या अपेक्षित देखरेख की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा रोक आदेश की अवधि के आधार पर उनको समूहों में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति में निम्नलिखित कार्मिक होंगे:-

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई)

—अध्यक्ष

- प्रभारी अधिकारी — सदस्य—सचिव
- परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता — सदस्य
- चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
- मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता — सदस्य
- कार्यशाला पर्यवेक्षक या व्यवसाय अनुदेशक — सदस्य
- अध्यापक — सदस्य
- किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य— सदस्य
- प्रत्येक बाल समिति का किशोर या बालक प्रतिनिधि — सदस्य
- (सभी आयु वर्गों के किशोरों या बालकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मासिक चक्रानुक्रम के आधार पर) — सदस्य
- (4) जिन जिलों में, जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन नहीं किया गया है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उसके द्वारा नामित व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष होगा।
- (5) जहां स्वैच्छिक संगठन व्यावसायिक और तकनीकी सेवाएं जैसे कि शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोसामाजिक देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हों, वहां प्रबंध समिति ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि को अपनी बैठकों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप से आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) (क) प्रबंधन समिति निम्नलिखित पर विचार करने और उनका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रति मास बैठक करेगी :—
- (एक) अभिरक्षात्मक देखरेख या संस्था में देखरेख, आवास, कार्यकलाप का क्षेत्र और अपेक्षित पर्यवेक्षण या अन्तःक्षेप का स्वरूप,
- (दो) चिकित्सा सुविधाएं और उपचार,
- (तीन) भोजन, पानी, स्वच्छता और आरोग्य संबंधी दशाएं,
- (चार) किशोरों और बालकों के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य अन्तःक्षेप,
- (पांच) किशोरों और बालकों की व्यक्तिगत समस्याएं, विधिक सहायता सेवाओं और संस्थागत समायोजन की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं की तिमाही समीक्षा,
- (छह) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर,
- (सात) शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम,
- (आठ) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, सामूहिक क्रियाकलाप, मार्गदर्शन और परामर्श,
- (नौ) किशोरों और बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय कार्यक्रमों की प्रगति समायोजन और उपांतरणों का पुनर्विलोकन,
- (दस) रिहाई या पुनरुद्धार के उपरांत पुनर्वास कार्यक्रम और पश्चात्पूर्ति देखरेख सेवाओं के सहयोग से दो वर्ष की अवधि के लिए अनुवर्ती योजना,

- (ग्यारह) रिहाई या पुनुरुद्धार पूर्व तैयारियां,
 (बारह) रिहाई या पुनुरुद्धार
 (तेरह) रिहाई या पुनुरुद्धार के उपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई,
 (चौदह) अवसंरचना और उपलब्ध सेवाओं सहित देखरेख के न्यूनतम मानक,
 (पंद्रह) दैनिक कार्यक्रम,
 (सोलह) बालकों की आवासीय अवधि के दौरान उनके शैक्षणिक, व्यावसायिक कार्यकलापों, मनोरंजन तथा रुचि के कार्यकलापों में सामुदायिक भागीदारी और स्वैच्छिक सहयोग,
 (सत्रह) यह अवलोकन करना कि इस अधिनियम और नियमों के अधीन यथापेक्षित सभी रजिस्टर संस्था द्वारा रखे जाते हैं, इन रजिस्ट्रों की जांच और सत्यापन हो, मासिक पुनर्विलोकन बैठकों में सम्यक् रूप से इन पर मुहर लगाई जाए तथा इन पर हस्ताक्षर किए जाएं,
 (अठारह) बाल समितियों से संबंधित विषय,
 (उन्नीस) अन्य कोई मामला, जो प्रभारी अधिकारी द्वारा उठाया जाए।
- (ख) प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर या बालक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उसके मामले से संबंधित फाइल में फाइल करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाई और बोर्ड या समिति को भेजेगा।
- (7) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी और बाल सुझाव पेटी किसी ऐसे स्थान पर रखी जाएगी, जहां किशोर या बालक आसानी से आ सकते हो और यह स्थान संस्था के कार्यालय के स्थापना से दूर और बच्चों के निवास या कमरों या शयनशालाओं के निकट होगा।
- (8)(क) बाल सुझाव पेटी की चाबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पास रहेगी और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष या उसके द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से नामित कोई प्रतिनिधि बाल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सप्ताह में एक बार इस पेटी की जांच करेगा।
- (ख) यदि कोई ऐसी समस्या या सुझाव हो, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष उस विषय में विचार-विमर्श करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति की आपात बैठक बुलाएगा।
- (ग) आपात बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी, जिसमें बाल समितियों के दो सदस्य, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति समिति या बोर्ड का सदस्य तथा संस्था का प्रभारी अधिकारी सम्मिलित हैं।
- (घ) संस्था के प्रभारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए जाने या उसके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत किए जाने की स्थिति में वह आपात बैठक में भाग नहीं लेगा और उसके स्थान पर प्रबंधन समिति के अन्य किसी उपलब्ध सदस्य को शामिल किया जाएगा।
- (ङ) सुझाव पेटी के माध्यम से प्राप्त सभी सुझावों और आपात बैठक में लिए गए विनिश्चयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई या अपेक्षित कार्रवाई के विषय पर

प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा और इस विषय पर पुनर्विलोकन किया जाएगा।

- (9) प्रत्येक संस्था में बाल सुझाव पुस्तिका रखी जाएगी जिसमें शिकायतों और उन शिकायतों पर प्रबंधन समिति द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा और प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के पश्चात् उक्त अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना बाल समिति को दी जाएगी।
- (10) बोर्ड या समिति तीन मास में एक बार बाल सुझाव पुस्तिका का पुनर्विलोकन करेगी।

56. बाल समितियां :-(1) प्रत्येक संस्था का प्रभारी अधिकारी 6-10 वर्ष, 11-15 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के तीन भिन्न आयु समूहों के लिए बाल समितियां गठित कराएगा और ये बाल समितियां केवल बालकों द्वारा गठित की जाएंगी।

- (2) इन बाल समितियों को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा :-
 - (क) संस्था की दशा में सुधार,
 - (ख) संस्था में जिन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है उन मानकों का पुनर्विलोकन करना,
 - (ग) दैनिक कार्यक्रम और आहार मापदंड की तैयारी करना,
 - (घ) शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं को विकसित करना,
 - (ङ) संकट से निपटने में एक दूसरे की सहायता करना,
 - (च) साथियों और देखभाल करने वालों के हाथों दुर्व्यवहार और शोषण की रिपोर्ट करना,
 - (छ) वॉल पेपर या न्यूज लेटर या पेंटिंग या संगीत या थिएटर के माध्यम से अपने विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति,
 - (ज) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था का प्रबंधन,
- (3) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियां प्रति मास अपनी बैठकें करें और अपने कार्यकलापों और कार्यवाहियों का ब्यौरा रजिस्टर में अभिलिखित करें तथा इसे प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों के समक्ष प्रस्तुत करें।
- (4) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियों को कारगर ढंग से अपना कार्य करने के लिए लेखन सामग्री, स्थान और मार्गदर्शन सहित आवश्यक सहायता और सामग्री प्रदान की जाती है।
- (5) प्रभारी अधिकारी बाल समितियों की स्थापना और कामकाज के लिए यथासंभव स्थानीय स्वैच्छिक संगठन या बालक की भागीदारी के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करेगा।
- (6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन या बालक की भागीदारी का विशेषज्ञ निम्नलिखित कार्य करने में बाल समितियों की सहायता करेगा :-

- (क) उनके नेता का चयन,
- (ख) मासिक बैठकों का संचालन,
- (ग) बाल समितियों के कामकाज के नियम विकसित करना और इनका अनुपालन करना,
- (घ) अभिलेख और बाल सुझाव पुस्तिका और अन्य सुसंगत दस्तावेज रखना,
- (ङ) अन्य कोई अभिनव कार्यकलाप।
- (7) प्रबंधन समिति बाल समितियों की स्थापना और कामकाज के बारे में प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और अपनी मासिक बैठकों में इस रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी और जहां अपेक्षित हों आवश्यक कार्रवाई करेगी।

57. **पुरस्कार और उपार्जन :-** प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार किसी किशोर या बालक को उसके नियमित कार्य और अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस किशोर या बालक को लेने के लिए आने वाले उसके माता-पिता अथवा अभिभावक अथवा स्वयं बच्चे को देकर रसीद ली जाएगी।

58. **किशोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान :-** (1) किशोर या बालक के माता-पिता और रिश्तेदारों को महीने में एक बार उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी अथवा विशेष परिस्थिति में प्रभारी अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मुलाकात की अवधि के अनुसार मास में एक से अधिक बार भी बालक से मिलने की अनुमति उसके माता-पिता या रिश्तेदारों को दी जाएगी, उसके सिवाय जब यह पाया जाता है कि उन माता-पिता या रिश्तेदारों या अभिभावकों ने ही बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण किया था।

(2) संस्था में रह रहे किशोरों या बालकों को अपने पत्र प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा और उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे यथोचित समय पर जितने चाहे पत्र लिखें तथा यदि किशोरों या बालकों के माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों का पता मालूम हो, तो संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक किशोर या बालक प्रतिमास अपने अभिभावकों को एक पत्र लिखे, जिसका डाक महसूल संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) प्रभारी अधिकारी किसी भी किशोर या बालक द्वारा लिखे गए पत्र का परिशीलन कर सकेगा तथा पर्याप्त समझे गए कारणों से वह ऐसे पत्र को देने या भेजने से इंकार कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में अपने कारणों को लेखबद्ध करके पत्र समिति को भेजेगा।

(4) प्रभारी अधिकारी विशेष परिस्थितियों में या बोर्ड या समिति के आदेशानुसार किसी किशोर या बालक को उसके माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को फोन पर बातचीत करने की अनुमति देगा।

59. **किशोर या बालक की मृत्यु :-** संस्था में किसी किशोर या बालक की मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- (1) संस्था में किसी किशोर या बालक की आप्राकृतिक मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में संस्था के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मृत्यु समीक्षा और शव परीक्षण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए।

- (2) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी किशोर या बालक की मृत्यु की दशा में प्रभारी अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा तथा इस मामले की लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति, राष्ट्रीय अथवा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी तथा उस किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।
 - (3) अकस्मात मृत्यु या हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु या आत्महत्या के कारण मृत्यु या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या कल्याण अधिकारी द्वारा इस घटना की सूचना प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत दी जाएगी तथा प्रभारी अधिकारी तत्काल, निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और मृतक किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।
 - (4) यदि संस्था में प्रवेश पाने के 24 घंटे के भीतर किसी किशोर या बालक की मृत्यु हो जाती है तो संस्था का प्रभारी अधिकारी उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल तथा मृतक किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को इस विषय में अविलंब सूचित करेगा।
 - (5) प्रभारी अधिकारी, उस निकटवर्ती मजिस्ट्रेट को, जो मृत्यु समीक्षा कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, तथा यथास्थिति बोर्ड या समिति को तत्काल इस मामले की सूचना देगा।
 - (6) संस्था के प्रभारी अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियों का ब्यौरा दर्ज करके एक रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट, जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में यह मामला आता हो, उस थाने के प्रभारी अधिकारी, समिति और जिला चिकित्सा अधिकारी या जिस निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच हेतु किशोर या बालक का शव भेजा गया हो, उस अस्पताल को भेजेंगे और प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार अभिलिखित करेंगे और इसकी रिपोर्ट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देंगे, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो।
 - (7) ऐसे किसी किशोर या बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य ब्यौरों के संबंध में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच की कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।
 - (8) मृत्यु समीक्षा होते ही मृतक किशोर या बालक का शव उसके माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा अथवा किसी दावेदार के उपस्थित न होने की दशा में उस किशोर या बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार प्रभारी अधिकारी की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
60. **किशोर या बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण.**— (1) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी किशोर या बालक का शोषण, उपेक्षा और उससे दुर्व्यवहार न किया जा सके। कर्मचारियों को शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के अर्थ और ऐसे शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के प्रारंभिक संकेतों तथा इन समस्याओं के समाधान के उपायों से परिचित कराना इसमें सम्मिलित है।

- (2) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में, जिसमें उनकी उपेक्षा सम्मिलित है, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।
- (एक) दुर्व्यवहार और शोषण की घटना की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल प्रभारी अधिकारी को दी जानी चाहिए।
- (दो) शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुर्व्यवहार का आरोप जानकारी में आने पर प्रभारी अधिकारी बोर्ड या समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो विशेष अन्वेषण का आदेश देगी।
- (तीन) बोर्ड या समिति ऐसे मामलों को दर्ज करने तथा ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने का स्थानीय पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी।
- (चार) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि समस्त जांच कार्य संपन्न हो और किशोर या पीड़ित बच्चे को विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराए जाएं।
- (पांच) बोर्ड या समिति ऐसे किशोर या बालक को किसी अन्य सुरक्षित संस्था या स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थानांतरित करेगी।
- (छह) संस्था का प्रभारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और ऐसी घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखेगा।
- (सात) संस्थाओं में किशोरों या बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में, बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी।
- (आठ) बोर्ड या समिति दुर्व्यवहार और शोषण के आरोप की जांच करने के लिए प्रत्येक संस्था में गठित बाल समिति से परामर्श कर सकेगी और किसी संस्था में किशोरों या बालकों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों से निपटने में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकारों के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों अथवा संकट अन्तःक्षेप केन्द्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।
61. **भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किशोर या बालक :-** (1) जब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखा गया किशोर या बालक किसी ऐसे रोग या ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित पाया जाता है, जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो, या वह किशोर या बालक किसी स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ का आदी पाया जाता है। तो उस किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार संस्था में रहने की शेष अवधि या ऐसी अवधि के लिए उपयुक्त स्थान पर भेजा जाएगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उस किशोर के समुचित उपचार के लिए आवश्यक समझा जाता है।
- (2) उस किशोर या बालक के रोग या शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार हो जाने पर यदि उस बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति या संस्था की देखरेख में रखा जाना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी उस किशोर या बालक को उस उपयुक्त व्यक्ति या संस्था

की देखरेख में रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जहां से उसे उपचार के लिए ले जाया गया था और यदि उस किशोर या बालक को और अधिक समय तक उपयुक्त व्यक्ति या संस्था की देखरेख में रखा जाना आवश्यक नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी उसे मुक्त करने का आदेश कर सकेगा।

- (3) किसी संक्रामक रोग से पीड़ित किशोर या बालक को उसके माता-पिता या अभिभावकों के पास वापस भेजने का आदेश उस किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के आधार पर यह बात ध्यान में रखते हुए पारित किया जाएगा कि उसे कलंक का जोखिम न हो और उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो तथा उसका उपचार भी जारी रखा जाए।
 - (4) जिस स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर या निटकवर्ती जिले या राज्य में गंभीर मनोरोग या शारीरिक रोग और संक्रमण से पीड़ित किशोर या बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए इस अधिनियम की धारा 58 के अधीन यथावश्यक संगठन मौजूद नहीं है उस स्थान पर राज्य सरकार ऐसे किशोरों या बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथावश्यक संगठनों की स्थापना करेगी।
- 62. किशोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्टी.**—(1) किसी संस्था में रहने वाले किशोर या बालक को संस्था की देखरेख में परीक्षण या भर्ती कराने के लिए परिवार में विवाह जैसे विशेष अवसरों पर या मृत्यु या दुर्घटना या गंभीर बीमारी के आपातकालीन समय में अवकाश पर जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (2) यात्रा के समय को छोड़कर सामान्य रूप से अधिकतम सात दिनों की अल्पकालिक छुट्टी प्रभारी अधिकारी द्वारा सिफारिश की जाती है, किंतु ऐसी छुट्टी बोर्ड या समिति द्वारा मंजूर की जाएगी।
 - (3) किशोर के माता-पिता या अभिभावक या किशोर या बालक की ओर से प्रभारी अधिकारी छुट्टी के लिए बोर्ड या समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें छुट्टी का प्रयोजन और छुट्टी की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए छुट्टी पर किशोर या बालक को छोड़ने का अनुरोध होगा।
 - (4) अनुपस्थिति की छुट्टी के आवेदन पर विचार करते समय बोर्ड या समिति, किशोर या बालक या उनके माता-पिता या अभिभावकों को सुनेगी और यदि बोर्ड या समिति यह समझती है कि ऐसी छुट्टी को मंजूर करना किशोर या बालक के हित में है तो समुचित आदेश दिया जाएगा और बोर्ड या समिति परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी से एक रिपोर्ट उस दशा में मांग सकेगा, जब किशोर या बालक या संबंधित माता-पिता या अभिभावक द्वारा दी गई प्रारंभिक सूचना उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - (5) यथास्थिति छुट्टी मंजूर करने का आदेश जारी करते समय या पर्यवेक्षण के अधीन मुक्त करते समय सक्षम प्राधिकारी छुट्टी के आदेश के साथ छुट्टी की अवधि तथा शर्तों का उल्लेख करेगा और यदि छुट्टी की अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो किशोर या बालक को संस्था में वापस बुलाया जा सकेगा।
 - (6) माता-पिता या अभिभावक किशोर या बालक के मार्गरक्षक की व्यवस्था करेगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां प्रभारी अधिकारी परिवार के स्थान तक और वहां से वापस आने के समय किशोर या बालक के मार्गरक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि किशोर या बालक के माता-पिता

या अभिभावक मार्गरक्षण के लिए इच्छुक हों किंतु आर्थिक रूप से सक्षम न हों, तो प्रभारी अधिकारी उनके लिए नियमों के अधीन यथा-अनुज्ञेय यात्रा खर्च की व्यवस्था करेगा।

- (7) यदि किशोर या बालक छुट्टी की अवधि के दौरान परिवार से भाग जाता है तो इनके माता-पिता या अभिभावक से संस्था के प्रभारी अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाना अपेक्षित है तथा उन्हें ढूँढने का प्रयास किया जाना आवश्यक है और यदि वे पाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल संस्था में वापस लाया जाएगा।
- (8) यदि किशोर या बालक 24 घंटे के भीतर नहीं पाया जाता है तो प्रभारी अधिकारी निकटतम पुलिस थाने और गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो को इसकी सूचना देगा किंतु किशोर या बालक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और अधिनियम के अधीन अभिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (9) यदि किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावक छुट्टी की अवधि में इनकी उचित देखरेख नहीं करते हैं या निर्धारित अवधि के भीतर किशोर या बालक को संस्था में वापस नहीं लाते हैं तो आगे से ऐसे अवसरों पर छुट्टी से इंकार किया जा सकेगा।
- (10) यदि किशोर या बालक मंजूर की गई छुट्टी के अवसान पर संस्था में वापस नहीं आता है तो बोर्ड या समिति किशोर का प्रभार संभालने तथा उसे संस्था में वापस लाने के लिए ऐसे मामलों को पुलिस को सौंप देगी।
- (11) ऐसी छुट्टी की अवधि संस्था में किशोर या बालक के ठहरने की अवधि की गणना करते समय संस्था में रहने की अवधि में शामिल होगी, और छुट्टी की अवधि के पश्चात् संस्था में अनुपस्थित रहने की अवधि संस्था में रहने की अवधि से अपवर्जित की जाएगी।

63. (क) निरीक्षण— (1) महिला सशक्तिकरण का आयुक्त/संचालक या इनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करेगा। कार्यक्रम विकास मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन सेल, जिला सलाहकार, समिति स्थानीय शासन प्राधिकारी, किशोर न्याय प्रशासन का संस्थागत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों का निरीक्षण, मानिटरिंग एवं मूल्यांकन करेंगे।

(2). मत निरीक्षण दोष निकालने की कार्यप्रणाली नहीं होनी चाहिए, वस्तुतः इसे रचनात्मक होना चाहिए, निरीक्षण अधिकारी, प्रतिवेदन आयुक्त/संचालक महिला सशक्तिकरण को आवश्यक फालोअप हेतु देगा।

(3) दल (टीम) या तो पूर्व सूचना द्वारा या अचानक गृह का निरीक्षण कर सकेगा।

(ब) रिपोर्ट करना :— (1) निरीक्षण समाप्त होने के पश्चात् समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह कम से कम पन्द्रह दिन से अनधिक संभावित समय के भीतर निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, रिपोर्ट में संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझावों, निवेदनों या शिकायतों को, इन नियमों से सुसंगत उपबंधों सहित सुविधाओं के अनुपालन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(2) अन्य संबंधित व्यक्तियों की राय को, जो उसके लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है या जिनका नाम शिकायत में सम्मिलित है भी नोट किया जाएगा तथा उनके कारणों व स्पष्टीकरण को शब्दशः नोट किया जाएगा।

(3). निरीक्षण समिति किसी सदस्य के संबंध में अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो अंतिम रूप से कोई सिफारिश कर सकेगी।

(4) यदि निरीक्षण समिति द्वारा कोई ऐसा तथ्य खोजा गया है जो दर्शाता है कि बालकों के अधिकारों से संबंधित विधिक उपबंधों का या किशोर न्याय संस्थाओं के कार्यों का उल्लंघन हुआ हो तो सक्षम प्राधिकारी को अन्वेषण तथा अभियोजन हेतु संसूचित किया जाएगा।

(5) समस्त संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के निष्कर्षों तथा बालकों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

- 64. सामाजिक लेखा जोखा.—** (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार बोर्ड या समिति या विशेष किशोर पुलिस इकाई, जहां अपेक्षित हो, की स्थापना से सम्बद्ध मामलों की, बोर्ड या समिति या विशेष किशोर अपराधी पुलिस इकाई के कामकाज की, संस्थाओं और कर्मचारियों के कामकाज की, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कामकाज की, किशोर न्याय के बालक अनुकूलन प्रशासन और राज्य में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बद्ध अन्य किसी भी मामले की मानीटरिंग और मूल्यांकन करेगी।
- (2) मानसिक स्वास्थ्य, बालक देखरेख और संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारतीय बाल कल्याण परिषद, चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन, केन्द्र और राज्य स्तरीय समाज कल्याण बोर्डों, समाज कार्य के विद्यालय तथा विधि के विद्यालय जैसे स्वशासी निकायों को शामिल करके इनके सहयोग से सामाजिक लेखा-जोखा किया जाएगा।
- 65. वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई —** (1) बोर्ड या समिति, किशोर अपराधी या बालक और उनके माता-पिता या अभिभावक की समुचित सुनवाई और साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए बोर्ड या समिति द्वारा निदेशित पर्यवेक्षण अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टों और मामले के निर्णय के लिए बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए सम्बद्ध कागजात या रिपोर्ट के आधार पर किशोर या बालक को वापस भेजने का आदेश देगी।
- (2) बोर्ड या समिति प्रपत्र— बाईस के अनुसार, मार्गरक्षण के लिए आदेश की एक प्रति के साथ वापस भेजने के आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भेजेगी, जो किशोर या बालक को वापस भेजने के लिए निधि उपलब्ध कराएगी।
- (3) वापस भेजे जाने के मामले के यथास्थिति कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं या बाल कल्याण अधिकारियों या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के भाग के रूप में वापस भेजने की योजना तैयार की जाएगी और यह इन नियमों के नियम 55 के अधीन स्थापित प्रबन्ध समिति के पुनर्विलोकन और सिफारिश पर आधारित होगी।
- (4) पुलिस के अतिरिक्त बोर्ड या समिति भी किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।
- (5) किशोरियों या बालिकाओं को महिला मार्गरक्षण दल के साथ भेजा जाएगा।
- (6) यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए किये गये खर्चें जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (7) जब कोई किशोर या बालक अपने घर वापस नहीं जाना चाहता तो बोर्ड या समिति अपने अभिलेख में इस बात को दर्ज करेगा या उसे घर जाने हेतु न तो बाध्य किया जाएगा, और न ही समझाया जाएगा, विशेष रूप से यदि बाल कल्याण अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी

की सामाजिक जांच रिपोर्ट से यह निश्चित हो गया हो कि उसका घर वापस जाना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है या उसके माता-पिता या अभिभावक उसे स्वीकार करने से इंकार कर चुके हैं।

- (8) बालक को वापस भेजने में सहायता के लिए बोर्ड या समिति द्वारा नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एक अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी, जो व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं के एक भाग के रूप में होगी।
 - (9) सम्बद्ध बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन दो वर्ष की अवधि तक तिमाही अनुवर्ती रिपोर्ट बोर्ड या समिति को तथा इसकी एक प्रति उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा, जहां किशोर या बालक रह रहा है।
 - (10) अनुवर्ती रिपोर्ट में किशोर या बालक को वापस भेजने के पश्चात् उसकी स्थिति तथा किशोर या बालक की सुरक्षा में उत्तरोत्तर कमी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली इनकी जरूरतों के बारे में स्पष्ट उल्लेख होगा।
 - (11) प्रभारी अधिकारी किशोर या बालक की केस फाइल में अनुवर्ती रिपोर्ट भी रखेगा तथा अगली बैठक में इसे, इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
 - (12) प्रभारी अधिकारी अनुवर्ती रिपोर्टों की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजेगा।
 - (13) सरकारी कार्यकर्ताओं या गैर-सरकारी संगठनों के न होने के कारण जहां अनुवर्ती कार्रवाई संभव नहीं है वहां सम्बद्ध जिला बाल संरक्षण इकाई बोर्ड या समिति को जरूरी सहायता प्रदान करेगी।
- 66. आगंतुक पुस्तिका** — (1) प्रत्येक संस्था में एक आगंतुक पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें वहां आने वाले व्यक्ति अपने आगमन की तारीख और उचित सुझावों को लेखबद्ध करेंगे।
- (2) संस्था का प्रभारी अधिकारी ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भेजेगा। प्रविष्टियां भेजते समय अपनी इच्छानुसार अपना स्पष्टीकरण अथवा अन्य अभ्युक्तियां भी दे सकता है, जिस पर नामनिर्दिष्ट अधिकारी आवश्यकतानुसार आदेश जारी कर सकता है।
- 67. रजिस्ट्रों का रखा जाना** — प्रभारी अधिकारी अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जरूरी तथा इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रों और प्रपत्रों को अपने कार्यालय में रखेगा। रजिस्ट्रों, फाइलों या पुस्तिकाओं की सूची में कम से कम निम्नलिखित सामग्री शामिल होगी :-
- (क) प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर
 - (ख) पर्यवेक्षण रजिस्टर
 - (ग) चिकित्सा फाईल या चिकित्सा रिपोर्ट
 - (घ) पोषण आहार फाईल
 - (ङ) भंडारण रजिस्टर
 - (च) लाग-बुक
 - (छ) आदेश पुस्तिका

- (ज) बैठक पुस्तिका
- (झ) रोकड़ बही
- (ञ) बजट विवरण फाईल
- (ट) जॉच रिपोर्ट फाईल
- (ठ) व्यक्तिगत देखरेख योजना के साथ व्यक्तिगत केस फाईल
- (ड) बाल सुझाव पुस्तिका
- (ढ) आगन्तुक पुस्तिका
- (ण) कर्मचारी संचालन रजिस्टर
- (त) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर
- (थ) प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर;
- (द) बाल समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर;
- (घ) कर्मचारियों और किशोरो या बालकों की उपस्थिति रजिस्टर

68. गृहों के कार्मिक या कर्मचारी—(1) किसी गृह के कार्मिकों की संख्या, कर्तव्य, पदों, प्रतिदिन कार्य के घंटों और इनके द्वारा देखभाल किये जाने वाले बालकों के प्रवर्गों के अनुसार अवधारित की जाएगी, जिनके लिए कर्मचारीवृंद होते हैं।
- (2) संस्थागत संगठनात्मक स्थापन गृह के आकार, क्षमता, कार्यभार कार्यों के वितरण और कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुसार निश्चित किया जाएगा।
- (3) किसी गृह में पूर्णकालिक कर्मचारियों में आवश्यकतानुसार, प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी (पर्यवेक्षण गृह या विशेष गृह की दशा में), मामला कार्यकर्ता (बाल गृह या आश्रय गृह या परवर्ती देखरेख संगठन की दशा में) बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता, शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक, चिकित्सा कर्मचारिवृंद, प्रशासनिक कर्मचारिवृंद, केयरटेकर, स्वयंसेवक, संबंधित संस्था या आश्रय गृह के गृह पिता और गृह माता, चाइल्ड मेन्टर भंडारपाल, रसोइया, सहायक धोबी, सफाई कर्मचारी तथा माली शामिल हो सकते हैं।
- (4) अंशकालिक कर्मचारीवृंद में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और समय-समय पर अपेक्षित अन्य वृत्तिक सम्मिलित हो सकेंगे।
- (5) गृह के कर्मचारी प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण और सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में रहेंगे, जो आदेश द्वारा उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों को निश्चित करेगा और समय-समय पर आदेशों की सूचना सम्बद्ध अधिकारी को देगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्व अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित किये जाएंगे।
- (7) प्रभारी अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारीवृंद, जो अपेक्षित हों, गृह के परिसरों के भी उपलब्ध क्वार्टरों में रहेंगे।
- (8) प्रत्येक प्रवर्ग में कर्मचारियों के पदों की संख्या, संस्था की क्षमता के आधार पर निर्धारित होगी तथा कर्मचारीवृंद की नियुक्ति प्रत्येक प्रवर्ग के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, प्रशिक्षण और अनुभवों के आधार पर की जाएगी।

- (9) 100 किशोरों या बालकों की योग्यता वाली किसी संस्था के लिए निम्नलिखित पैटर्न पर कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है।

क्र	कर्मचारी / कार्मिक	पदों की संख्या
1	2	3
1	अधिकारी (अधीक्षक)	1
2	परामर्शदाता	2
3	परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता	3
4	गृह माता या गृह पिता	4
5	शिक्षक	2 (स्वैच्छिक या अंशकालिक)
6	चिकित्सक	1
7	पैरा-चिकित्सीय कर्मचारीवृंद	1
8	भंडार रक्षक सह लेखाकार	1
9	कला और हस्तशिल्प-सह-संगीत शिक्षक	1 (अंशकालिक)
10	शारीरिक शिक्षक अनुदेशक-सह-योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)
11	वाहन-चालक	1
12	रसोईया	2
13	सहायक	2
14	गृह प्रबंधक	2
15	माली	1 (अंशकालिक)
	कुल	25

- (10) संस्था की क्षमता में वृद्धि के अनुपात में, परामर्शदाता, मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी गृह पिता या गृह माता, शिक्षक और व्यावसायिक अनुदेशक के पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- (11) शिशुओं को रखने वाली संस्थाओं की दशा में, आया और पैरा-चिकित्सक कर्मचारीवृंद की व्यवस्था उनकी आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।

अध्याय -7

विविध

69. उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थाओं को मान्यता :-

- (1) किसी भी व्यक्ति को, जो देखरेख, संरक्षण या उपचार के जरूरतमंद किशोरों या बालकों को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, उसके प्रत्यायक और प्रतिष्ठा की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।
- (2) किसी स्थान या संस्था को, जिसका प्रबंधक, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किशोर या बालक को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।
- (3) उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यताप्राप्त संस्था :-
 - (क) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करेगी।
 - (ख) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करने की क्षमता तथा इच्छा होगी।
 - (ग) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किशोरों और बालकों को स्वीकार करेगी और बुनियादी सेवाएं प्रदान करेगी।
 - (घ) किशोर या बालक को किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा का शिकार होने से बचाएगी।
 - (ङ) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन करेगी।
- (4) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संस्थाओं की सूची बोर्ड और समिति के कार्यालय में रखी जाएगी।
- (5) संपार्श्विक शाखाओं वाली उपयुक्त संस्था, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसके यहां रखे गए किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अपनी किसी भी शाखा में भेज सकेगी।

- (6) किसी व्यक्ति को, उपयुक्त व्यक्ति घोषित करने या किसी संस्था की उपयुक्त संस्था के रूप में सिफारिश करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी आवश्यक जांच करेगा तथा संतुष्ट होने के पश्चात् ही मान्यता दी जाएगी।

70. संस्थाओं और परवर्ती देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना अथवा हस्तांतरण.

- (1) अधिनियम के अधीन प्रमाणन के इच्छुक किसी भी संगठन को राज्य सरकार के पास नियमों, संगम-अनुच्छेद के उपनियमों, सोसायटी या संगठन का संचालन कर रहे संगमों के सदस्यों की सूची, पदाधिकारियों की सूची तथा संगठन द्वारा प्रदान की जा रही बाल देखरेख विशेषज्ञ सेवाओं की स्थिति और पिछला अभिलेख दर्शित करने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संगठन में ठहरने और भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, शैक्षिक सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उपचार सेवाओं के लिए किये गए उपबंधों के सत्यापन के पश्चात् अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 और 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणन या मान्यता प्रदान करेगी, परंतु यह तब जबकि संगठन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित सेवाओं के मानकों को पूरा करता हो और समय-समय पर यह भी सुनिश्चित करेगी कि उसके प्रभार में रखे गए किशोरों या बालकों का समग्र विकास और वृद्धि हो।
- (2) अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त करने का इच्छुक कोई संगठन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो आवश्यक जांच के पश्चात् मान्यता के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।
- (3) राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था का प्रबंधन प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को, जो ऐसी संस्था को चलाने की क्षमता रखता हो, हस्तांतरित करेगी तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए समझौते के ज्ञापन के अधीन अपेक्षित उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए उक्त स्वैच्छिक संगठन को उपयुक्त संस्था के रूप में प्रमाणन या मान्यता प्रदान कर सकेगी।
- (4) राज्य सरकार, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठन की शर्तों, नियमों, प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है, किसी भी समय संगठन के प्रबंधक को सूचना जारी करके यह घोषित करेगी कि संगठन का प्रमाण या मान्यता, यथास्थिति सूचना में उल्लिखित विशेष तारीख से वापस ले ली गई है तथा उक्त तारीख से संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41, अथवा 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देगा।

परंतु यह कि संबंधित संगठन को तीस दिन की अवधि के भीतर उस संगठन के प्रमाण या मान्यता की वापसी के कारणों के विरुद्ध लिखित में प्रतिवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

- (5) प्रमाण पत्र या मान्यता को वापस लेने या पुनः प्रदान करने का विनिश्चय अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत विशेष रूप से गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यापक जांच के आधार पर लिया जा सकेगा।
- (6) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संस्था के प्रभारी अधिकारियों को तीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओं नोटिस दिया जाएगा।
- (7) जब कोई संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41, अथवा 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, तब वहां रखे गए किशोरों या बालकों को अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा या उनके छोड़ने और स्थानांतरण से संबंधित अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन छोड़ दिया जाएगा तथा यथास्थिति उनके छोड़ने अथवा स्थानांतरण की सूचना, बोर्ड या समिति को दी जाएगी।

71. अधिनियम के अधीन पंजीकरण :-

- (1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए संस्थागत अथवा गैर संस्थागत देखरेख करने वाली सेवाओं का संचालन कर रही सभी संस्थाएं और संगठन, चाहे उनका संचालन सरकार या स्वैच्छिक संगठन कर रहे हों, अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के अधीन अपना पंजीकरण कराएंगे।
- (2) ऐसी सभी संस्थाएं या संगठन राज्य सरकार के पास प्रत्येक नियम, उपविधियों, संगम ज्ञापन, शासी निकाय की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले 3 वर्षों के तुलनापत्र तथा संस्था या संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक या सार्वजनिक सेवाओं के पिछले अभिलेख दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करेंगे, जो देखरेख और संरक्षण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ठहरने और भोजन की सुविधाएं, यदि कोई हों, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था और पुनर्वास की परिधि के सत्यापन के पश्चात् इस अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के अधीन, ऐसे संगठनों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी।

72. प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता अनुदान :-

- (1) अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उप धारा (3), धारा 37 या धारा 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यताप्राप्त या पंजीकृत संगठन या प्रमाणन या

मान्यताप्राप्त या जब पंजीकरण प्रवृत्त हो, उस अवधि के दौरान अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके स्वीकारे किशोरों या बालकों के रखरखाव के लिए तथा उनकी शिक्षा, उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास पर किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

- (2) सहायता अनुदान ऐसी दर पर अनुज्ञेय हो सकेगा, जो निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और इस प्रकार और ऐसी शर्तों के अनुसार हो, जो आपसी सहमति से दोनों पक्षकारों द्वारा तय की गई हों।
- (3) अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उप धारा (3), धारा 37 और धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा संचालित गृहों के प्रबंधन को स्वैच्छिक संगठनों को हस्तांतरण करने की दशा में जो बजट सरकार उस गृह पर खर्च कर रही थी, उतनी ही राशि, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संगम-ज्ञापन के, जिसमें उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व का विवरण होगा, अधीन सहायता अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संगठन को दी जाएगी।

73. बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश, —

- (1) संस्था के परिसर में किसी भी अजनबी व्यक्ति को, प्रभारी अधिकारी की अनुमति या बोर्ड या समिति के आदेश के सिवाय प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (2) विशिष्ट मामलों में जहां माता-पिता या अभिभावक अन्य राज्यों या जिलों से लंबी दूरी तय करके आए हैं, प्रभारी अधिकारी माता-पिता या अभिभावकों को परिसर में प्रवेश करने और बालकों से मिलने की अनुज्ञा देगा परंतु यह तब जबकि उनके पास उपयुक्त, पहचान-पत्र हो तथा उनके बारे में किशोर या बालक को प्रताड़ित और उत्पीड़ित करने की रिपोर्ट न हो।

74. पहचान फोटो, —

- (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित गृह में प्रवेश के समय प्रत्येक किशोर या बालक का फोटो खींचा जाएगा।
- (2) एक फोटो किशोर या बालक की केस फाइल में रखा जाएगा, एक फोटो सूचक-कार्ड में चिपकाया जाएगा, एक फोटो क्रमिक संख्या दी हुई एलबम में रखा जाएगा तथा निगेटिव दूसरी एलबम में रखा जाएगा। फोटो की एक-एक प्रति यथार्थिति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ-साथ जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी।

- (3) संस्था से गुमशुदा बालक या संस्था द्वारा गुमशुदा बालकों को स्वीकार करने की दशा में संबंधित विवरण के साथ बालक का एक फोटो गुमशुदा ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा।

75. पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होना — इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किशोर या बालक से निपटते समय गिरफ्तारी के समय को छोड़कर पुलिस अधिकारी पुलिस की वर्दी में नहीं होंगे तथा सादा कपड़ें पहनेंगे।

76. हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध :— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विधि के उल्लंघन के मामले में किशोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी।

77. मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.—

- (1) जब किसी किशोर या बालक को बोर्ड या समिति से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि पेश व्यक्ति एक किशोर या बालक है, वह कारण लेखबद्ध करेगा तथा किशोर या बालक को उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा।
- (2) यदि किशोर को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट मामले को जांच और निपटान के लिए बोर्ड को अंतरित करेगा।
- (3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को अपराध के पीड़ित के रूप में ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसे अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट बालक की देखरेख और संरक्षण, पुनर्वास और वापस भेजने के लिए उपयुक्त समिति के पास भेज देगा।

78. स्थानांतरण.—

- (1) जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किशोर या बालक बोर्ड या समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर के स्थान से है, तो बोर्ड या समिति किशोर या बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी तथा आदेश की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

बशर्ते कि :

- (एक) ऐसा स्थानांतरण किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित में है :
- (दो) किसी बालक के मात्र इस आधार पर कि बालक ने समस्याएं पैदा की हैं या विद्यमान संस्थान में उसको संभालना मुश्किल हो गया है या किसी पुरानी या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित होने या असमर्थता के कारण स्थानांतरण अथवा स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।
- (तीन) ऐसा स्थानांतरण साक्ष्यों के पूरा होने और उनकी प्रतिपरीक्षा के पश्चात ही, जो किशोरों या बालकों से संबंधित विधायी प्रक्रिया में अपेक्षित हो, किया जाएगा।
- (चार) ऐसे स्थानांतरण के कारण या परिस्थितियों को लेखबद्ध किया जाएगा।
- (2) तदनुसार, राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई :-
- (एक) उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी को, जिसके कार्यक्षेत्र में बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानांतरण का आदेश किया गया है, स्थानांतरण की सूचना भेजेगी।
- (दो) संस्था के प्रभारी अधिकारी को, जहां बालक को स्थानांतरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।
- (3) राज्य सरकार या राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई से सूचना की प्रति प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी आदेश में उल्लिखित स्थान या व्यक्ति से बालक को लाने के लिए सरकारी खर्चे पर अनुरक्षक की व्यवस्था करेगा।
- (4) ऐसे स्थानांतरण पर किशोर या बालक की केस फाइल और अभिलेख किशोर या बालक के साथ भेजी जाएगी।

79. किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रिया.-

- (1) किशोर या बालक, जिसका सामान्य निवास-स्थान सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है, सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 50 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, वह परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी निवास के स्थान पर किशोर या बालक को प्राप्त करने के लिए नातेदारों या अन्य व्यक्ति की उपयुक्तता और इच्छा जानने तथा क्या ऐसा नातेदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति किशोर या बालक की उचित देखभाल और नियंत्रण कर सकता है, की जांच करने के लिए निदेश देगा।

- (2) जहां किशोर या बालक को उसके सामान्य निवास-स्थान अथवा नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का आदेश किया जाता है, उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति से प्रपत्र- पांच या प्रपत्र- नौ में वचन लेने के साथ-साथ प्रपत्र- छह जैसे प्रपत्र में किशोर या बालक से किसी प्रतिभूत के बिना बंधपत्र का निष्पादन आवश्यक होगा।
- (3) इस नियम के उपनियम (2) के अधीन दिए गए बंधपत्र या वचन पत्र या दोनों के किसी उल्लंघन से किशोर सक्षम प्राधिकारी के सामने लाए जाने का दायी होगा, जो किशोर को किसी संस्था या गृह में भेजने का आदेश कर सकेगा।
- (4) किसी भी किशोर या बालक को, जो विदेशी है तथा उसका परिवार से सम्पर्क टूट चुका है, संरक्षण का अधिकार होगा।
- (5) विदेशी किशोर या बालक को संबंधित देश के दूतावास और उच्च आयोग के साथ समन्वय करके उसके मूल देश को यथाशीघ्र प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- (6) बोर्ड या समिति अपने आदेशों पर प्रत्यावर्तित किए गए प्रत्येक विदेशी किशोर या बालक के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित करेगा।
- (7) अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी :-
 - (क) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, जिसे इस नियम के उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
 - (ख) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके कार्यक्षेत्र में वह स्थान आता है, जहां किशोर या बालक को भेजा जाना है।
 - (ग) सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान आता है, जहां किशोर या बालक को भेजा जाना है।
 - (घ) नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति, जिसे किशोर या बालक को प्राप्त करना है।
- (8) इस नियम के उपनियम (6) के अधीन आदेश लंबित रहने के दौरान सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को यथास्थिति के प्रेक्षणगृह या बालगृह भेजेगा।
- (9) जब कभी सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को धारा 50 के अधीन उनके निवास के सामान्य स्थान पर भेजना उपयुक्त समझता है, सक्षम प्राधिकारी नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, जो किशोर या बालक को प्राप्त करेगा, सूचित करेगा तथा उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को गृह में आने के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख को किशोर या बालक का प्रभार लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

- (10) किशोर या बालक को भेजते समय, इस नियम के उपनियम (8) के अधीन उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति की समुचित श्रेणी में दोनों ओर की यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय, किशोर या बालक की गृह से उसके निवास के सामान्य स्थान तक की यात्रा हेतु व्यय का भुगतान करने के लिए गृह के प्रभारी अधिकारी को निदेश भी दे सकेगा।
- (11) यदि नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को किशोर या बालक का कार्यभार लेने में असफल रहता है तो किशोर या बालक को उसके निवास के सामान्य स्थान पर संप्रेक्षण गृह के अनुरक्षक द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़कियों की दशा में कम-से-कम एक अनुरक्षक महिला होगी।

80. राज्य बाल संरक्षण इकाई :- राज्य बाल संरक्षण इकाई के विनिर्दिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) अधिनियम का तथा अधिनियम के अधीन अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और उनको मानीटर करना।
- (ख) जिला बाल संरक्षण इकाईयों की स्थापना, सहायता और मानीटर करना।
- (ग) बोर्ड या समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रतिनिधित्व करना।
- (घ) अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं को उपलब्ध कराने और उन्हें स्थापित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाईयों को आवश्यक राशियां उपलब्ध कराना।
- (ङ) बाल संरक्षण मुद्दों पर अन्तर्क्षेत्रीय संबंध बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज-कल्याण, शहरी, बुनियादी सेवाएं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों युवा सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य, एड्स नियंत्रण सोसायटी भी है, सभी सरकारी विभागों से नेटवर्क और समन्वय करना।
- (च) अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना।
- (छ) अधिनियम के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर-सरकारी) को प्रशिक्षण और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
- (ज) देखभाल के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना और अधिनियम के अधीन स्थापित सभी संस्थाओं में इन मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- (झ) समितियों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करना।
- (ञ) अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी अन्य कार्य।

81. जिला बाल संरक्षण इकाई .—

- (1) जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला स्तर पर सभी बाल अधिकार और संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय और कार्यान्वयन करेगी।
- (2) जिला बाल संरक्षण इकाई के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—
 - (क) जिला या शहर स्तर पर उपयुक्त अवसंरचना के सृजन अर्थात् प्रत्येक जिले में बोर्डों, समितियों, विशेष किशोर पुलिस इकाईयों तथा गृहों की स्थापना में सहायता करके अधिनियम का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
 - (ख) जोखिम में रह रहे परिवारों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना।
 - (ग) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का निर्धारण करना तथा कठिन परिस्थितियों में बालकों की प्रवृत्ति और पद्धति को मानीटर करने के लिए जिला विशिष्ट डाटाबेस तैयार करना।
 - (घ) संसाधन निदेशिका तैयार करने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना तथा समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध करना।
 - (ङ) प्रयोजन, पालन पोषण, देखभाल, दत्तक ग्रहण और परवर्ती देखभाल सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाओं का क्रियान्वयन करना।
 - (च) कार्यक्रमों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के साथ-साथ अपने कार्यों के निष्पादन हेतु जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिश्चित करना।
 - (छ) संस्थागत, दत्तक ग्रहण, पालन पोषण, देखभाल और प्रयोजन के माध्यम से बालकों का उनके परिवार में समेकन अथवा दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक पुनर्वास के लिए बालकों को रखने के लिए सभी स्तरों पर बालकों के स्थानांतरण में सहायता करना।
 - (ज) जिला स्तर पर परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं के क्रियान्वयन में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता करना।

- (झ) बाल संरक्षण मुद्दों पर अन्तर्क्षेत्रीय संबंध बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, शहरी बुनियादी सेवाएं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, युवा कार्य, पुलिस न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी सहित सभी सरकारी विभागों से नेटवर्क और समन्वय स्थापित करना।
- (ञ) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना।
- (ट) बाल कल्याण क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से जिले में अभिकरणों और संस्थाओं के दक्षतापूर्ण मानीटर और पर्यवेक्षण के लिए परिमाण और यंत्र विकसित करना।
- (ठ) जिले में बालकों को आवसीय सुविधा प्रदान कर रही सभी संस्थाओं या अभिकरणों का पर्यवेक्षण और मानीटर करना।
- (ड) बालकों को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन करने वाले सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर सरकारी) को प्रशिक्षण देना और उनकी क्षमता निर्माण करना।
- (ढ) अधिनियम के क्रियान्वयन तथा प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए चाईल्ड लाईन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों, गृहों के प्रभारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा लोक सदस्यों सहित जिला स्तर पर सभी पक्षों के साथ तिमाही बैठकों का आयोजन करना।
- (ण) राज्य स्तर पर बाल कल्याण इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों तथा अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाइयों के साथ सम्पर्क बनाना।

82. बालक कल्याण समितियां स्थापित करना .—

- (1) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रत्येक जिले में सुचारु रूप से संचालन करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना, कार्मिकों तथा निधियों वाली, जैसी की नीचे सूचीबद्ध है, बाल कल्याण समितियों का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठन करेगी।
- (क) अवसंरचना में बैठक कक्ष, समिति के लिए एक अलग कक्ष, कार्यालय कर्मचारीवृंद के लिए कक्ष, बालकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, माता-पिता या अभिभावक के लिए प्रतीक्षा कक्ष, बालकों और माता-पिता तथा समिति के बीच व्यक्तिगत बातचीत के लिए कक्ष, अभिलेख कक्ष, सुरक्षित पेयजल सुविधा तथा शौचालय होंगे।

(ख) राज्य सरकार, प्रत्येक समिति के लिए कल्याण अधिकारी, आशुलिपिक टंकक या कम्प्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, सफाई कर्मचारी सहित आवश्यक मानव संसाधन सहायता प्रदान करेगी।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों को भत्तों का संवितरण इन नियमों के नियम 23 के अनुसार बाल कल्याण संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

83. **किशोर न्याय बोर्डों का गठन.**— राज्य सरकार प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों तथा वित्त के अलावा निम्नलिखित सूची के अनुसार आवश्यक अवसंरचना, कार्मिक सहित गठन करेगी :

- (1) अवसंरचना में बोर्ड कक्ष, बच्चों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों के लिए एक कक्ष, अभिलेख कक्ष, परिवीक्षा अधिकारियों के लिए कक्ष, माता-पिता तथा आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, सुरक्षित पेयजल सुविधा तथा शौचालय होंगे।
- (2) राज्य सरकार, प्रत्येक बोर्ड के लिए परिवीक्षा अधिकारी, आशुलिपिक-टंकक या कम्प्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, सफाई कर्मचारी सहित आवश्यक मानव संसाधन सहायता प्रदान करेगी।

84. **विशेष किशोर पुलिस इकाई.**—

विशेष किशोर पुलिस इकाई.— (1) राज्य सरकार, जिले में कम से कम एक विशेष किशोर पुलिस इकाई सृजित करेगी, जो अधिनियम के अधीन बालकों के लिये व्यापक प्रथम सम्पर्क देखरेख के एक केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

(2) विशेष किशोर पुलिस इकाई के उद्देश्य:— विशेष किशोर पुलिस इकाई के उद्देश्य नीचे दिए अनुसार होंगे:—

- (क) प्रथम सम्पर्क के केन्द्र पर बालकों की पहचान करना और प्राप्त करना, जोखिम में रह रहे बालकों की पहचान करने के लिये क्षेत्राधिकार में पहुंच से बाहर के कार्य हाथ में लेना और बालकों की गृह यात्रा संचालित करना, ।
- (ख) बालक के साथ मित्रवत् संबंध बनाना, जिससे कि वह उसकी वर्तमान स्थिति के कारणों को समझने और बांटने और उससे संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में किसी विनिश्चय में भाग लेने में समर्थ हो सके, ।
- (ग) एक वैयक्तिक शीघ्र निर्धारण और जांच संचालित करना तथा परामर्श, चिकित्सीय देखभाल, आमोद-प्रमोद सेवाएं, साथ ही विस्तृत निर्धारण और अन्य सेवाओं का, संदर्भ प्रस्थापित करना।

- (घ) 1098 के माध्यम से चाइल्ड हेल्प लाइन और आपातकालीन पहुंच बाह्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- (ङ) क्षेत्र की चाइल्ड हेल्प लाइन और विशेष पुलिस इकाई के कार्य में सहायता करने के इच्छुक समस्त अन्य मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ नेटवर्क तथा उस अधिकारिता के अधीन आने वाले अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों और संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना।
- (च) बालक मित्रवत् प्रथम मध्यक्षेप केन्द्रों की भूमिका का निर्वहन करना और प्राप्त करने के लिये संप्रेक्षणगृह/बालगृह की समुदाय आधारित स्वागत इकाई के कृत्यों का निर्वहन करना, प्रारंभिक जांच हाथ में लेना, विभिन्नता के सिद्धांत को प्रवर्तन में लाते हुए यथासमय परामर्श और शीघ्र मध्यक्षेप उपलब्ध कराना।
- (छ) बालकों के प्रति पुलिस के व्यवहार को समन्वित और उन्नत करना।
- (ज) एक चलित विशेष किशोर पुलिस इकाई की व्यवस्था करना, जिसे कि जब कभी कोई बालक अधिनियम के अधीन या तो पकड़ा जाए या प्राप्त किया जाए, तब संबंधित पुलिस थाने द्वारा उसे बुलाया जा सके।
- (झ) बालकों के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य करना।
- (ञ) कोई अन्य कार्य, जिन्हे इकाई द्वारा किसी बाल केन्द्रित रीति में उसके सामान्य कर्तव्यों के अनुक्रम में पूरा करना होगा।
- (3) विशेष किशोर पुलिस इकाई की अवस्थिति— विशेष किशोर पुलिस इकाई किसी पुलिस थाने की परिसीमा के भीतर अवस्थित नहीं होगी परंतु किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा या किसी लोक शिक्षण संस्था द्वारा या किसी ऐसे स्थान द्वारा उपयोग में लाई जा रही जगह के परिसर में अवस्थित होगी। इसके अतिरिक्त विशेष किशोर पुलिस इकाई की चलित इकाई स्थापित की जा सकेगी जो संबंधित अधिकारिता वाली विशेष किशोर पुलिस इकाई से संबंध बनाए रखेगी।
- (4) अधिकारिता— (क) विशेष किशोर पुलिस इकाई की अधिकारिता किसी विशेष क्षेत्र (जोन) में उतनी संख्या में पुलिस थानों पर होगी, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा क्षेत्र में जोखिम में रह रहे बालकों की सघनता को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक परिलक्षित हो प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होगी।

(ख) अधिकारिता के पुलिस थाने से संबद्धता— प्रत्येक विशेष किशोर पुलिस इकाई, दस्तावेजीकरण और किसी विशिष्ट सहायता के लिये निकटतम पुलिस थाने में संबद्ध होगी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई एककों का गठन करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1. बाल कल्याण अधिकारी (1) —पुलिस निरीक्षक या उपनिरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो।
 2. सामाजिक कार्यकर्ता (2 पदेन)— जिला बाल संरक्षण समिति में पदस्थ सामाजिक कार्यकर्ता।
 3. स्वैच्छिक कार्यकर्ता (2) — विषम परिस्थितियों में बालकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव (2 सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक महिला होगी)
 4. पुलिस महिला आरक्षक 1
 5. हेल्पर 1
- (6) इकाई, बालकों के विरुद्ध अपराधों के वयस्क अपराधकर्ताओं का संज्ञान गंभीरता से लेगी तथा यह देखेगी कि उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए तथा विधि के उपयुक्त उपबंधों के अधीन मामला दर्ज किया जाए और इस प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय इकाई पुलिस स्टेशन की अन्य इकाइयों से संपर्क बनाए रखेगी।
- (7) विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान करने के साथ-साथ बालकों के विरुद्ध हिंसा बालक की उपेक्षा और बालक शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों तथा ग्राम सभाओं, निवासी कल्याण संगमों की सहायता लेगी।
- (8) विशेष किशोर पुलिस इकाई इन नियमों के नियम 11 (12) के अनुसार गिरफ्तारी के समय आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में, बोर्ड के समक्ष किशोर को पेश करने तक किशोर को प्रभार में लेने के लिए तथा उसे बोर्ड के समक्ष पेश करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन की सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अभिकरण के रूप में विशेषकर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से सहायता लेगी।
- (9) किसी जिले में पुलिस अधीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रधान होगा तथा समय-समय पर इसके कामकाज का विलोकन करेगा।
- (10) अधिनियम के अधीन बालकों या किशोरों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर समन्वय तथा पुलिस की भूमिका में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रत्येक राज्य

में, पुलिस ने एक नोडल अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक स्तर से कम का न हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (11) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जांच के बाद बालक को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अपराध के लिए मुकदमा चलाने के अतिरिक्त सेवा से हटा दिया जाएगा।
- (12) गुमशुदा बालकों का ब्यूरो.—(क) राज्य सरकार, गुमशुदा बालकों से संबंधित जानकारी के दस्तावेजीकरण और प्रकाशन के लिए गुमशुदा बालकों का एक ब्यूरो स्थापित करेगी। ऐसी सेवा को सुकर बनाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। सम्पूर्ण देश में स्थापित इसी प्रकार की समस्त अन्य सुविधाओं को जोड़ने के प्रयत्न किए जाएं जिससे कि सम्पूर्ण देश में ऐसे बालकों के बारे में शीघ्र जानकारी परीक्षण और पारेषण को सुकर बनाया जा सके। यह गुमशुदा बालकों के डाटाबेस के रूप में भी सहायक होगा।
- (ख) गुमशुदा बालकों के ब्यूरो का चाइल्ड लाइन से, जहां कहीं उपलब्ध हो, साथ ही साथ, प्रत्येक जिले में समस्त मुख्य पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा।
- (ग) समस्त नागरिकों की जो इस जानकारी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाए गए हों या इस जानकारी तक पहुंचने के लिए अन्यथा प्राधिकृत किए गए हों, इस डाटाबेस तक निर्बाध पहुंच होगी, बालकों के हितों के विरुद्ध इस डाटाबेस का दुरुपयोग करते पाए गए व्यक्तियों का अन्वेषण किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

85. **अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी** :— विद्यमान परिवीक्षा सेवा में वृद्धि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाए गए स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और समक्ष प्राधिकारी के आदेश से उनकी सेवाओं को क्रियान्वयन तंत्र में भी सहयोजित किया जाएगा।

86. **किसी संस्था के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य** :—

- (1) प्रभारी अधिकारी का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के रख-रखाव का होगा तथा किशोरों या बालकों और कर्मचारीवृंद को आवश्यकता पड़ने पर हर समय उपलब्ध रहने के लिए संस्था के परिसर में ही रहेगा और यदि संस्था के परिसर में वास सुविधा उपलब्ध नहीं है तो प्रभारी अधिकारी संस्था के परिसर में वास सुविधा उपलब्ध कराए जाने तक संस्था के निकट ही किसी स्थान पर रहेगा।
- (2) प्रभारी अधिकारी के सामान्य कर्तव्यों और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

- (क) अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन,
- (ख) बोर्ड या समिति के आदेशों का अनुपालन,
- (ग) किशोरों या बालकों को प्यार, स्नेह, देखरेख, विकास और कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करना,
- (घ) संस्था में देखरेख के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना,
- (ङ) भवन और परिसरों का समुचित रखरखाव,
- (च) संस्था का प्रतिदिन निरीक्षण, खाद्य सामग्री के अलावा परोसे जाने वाले भोजन आदि का उचित भण्डारण तथा निरीक्षण सहित सुरक्षा उपाय तथा आवधिक निरीक्षण,
- (छ) किशोरों या बालकों के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और मानीटर करना,
- (ज) यथास्थिति प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों या सुधारात्मक कार्यकलापों सहित सभी संस्थागत कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा प्रचालनों का नियोजन, कार्यान्वयन और समन्वयन,
- (झ) आकस्मिकताओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई,
- (ञ) संस्था के परिसर के भीतर दुर्घटना और आग से बचाव के निवारक उपाय सुनिश्चित करना,
- (ट) जल भण्डारण, बिजली संयंत्र, आपातकालीन रोशनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था,
- (ठ) संयंत्रों और उपस्करों का सावधानीपूर्वक संचालन,
- (ड) सांसर्गिक या संक्रामक रोगों से पीड़ित किशोरों या बालकों को अलग-अलग रखना,
- (ढ) दैनिक कार्य का अनुपालन और अनुवर्तन,
- (ण) केस फाईल में किशोर या बालक की मासिक रिपोर्ट को फाइल करना,
- (त) संस्था में स्थानीय और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन,
- (थ) किशोरों या बालकों के भ्रमण या सैर अथवा पिकनिक का आयोजन करना,
- (द) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण,
- (ध) कार्मिकों को कार्यों का आबंटन,

- (न) कार्मिकों के कल्याण तथा कर्मचारीवृंद के अनुशासन पर ध्यान देने सहित कार्यालय प्रशासन का पर्यवेक्षण,
- (प) सभी अनुशासनिक मामलों में त्वरित, कठोर और विचारशील कार्रवाई,
- (फ) इन नियमों के नियम 55 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना,
- (ब) अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव तथा इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति द्वारा इनका मासिक सत्यापन,
- (भ) जब कभी आवश्यक हो, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के साथ सम्पर्क, समन्वयन तथा सहयोग करना, और -
- (म) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक किशोर को विधिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता मिल रही है, जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि अधिकारी से समन्वय करना और जहां कहीं जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन नहीं हुआ है, वहां जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सेवाएं उपलब्ध कराना।

87. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्तव्य :-

- (1) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बोर्ड या समिति अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा :-
 - (क) व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परिवार, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्रोतों के माध्यम से किशोर (प्रपत्र चार) अथवा बालक (प्रपत्र तेरह) का सामाजिक अन्वेषण करना,
 - (ख) बोर्ड या समिति की कार्रवाई में उपस्थित रहेगा और जब कभी अपेक्षित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना,
 - (ग) किशोरों या बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करेगा तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाईयों को हल करना,
 - (घ) अभिविन्यास, मानीटरिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना,

- (ड) किशोर या बालक तथा प्रभारी अधिकारी के बीच सहयोग और सद्भावना स्थापित करना,
 - (च) किशोर या बालक के परिवार के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता करना तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना,
 - (छ) किशोर या बालक के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना;
 - (ज) मुक्ति पूर्व कार्यक्रम में भाग लेना तथा किशोर या बालक की सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो उनको मुक्त करने के पश्चात भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं,
 - (झ) किशोरों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुकर बनाने तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना।
 - (ञ) किशोरों की मुक्ति के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना।
 - (ट) उनके पर्यवेक्षणाधीन किशोरों या बालकों के आवास तथा रोजगार के स्थान या ऐसे विद्यालय का, जिसमें किशोर या बालक पढ़े हैं, नियमित दौरा करना और प्रपत्र— इक्कीस में यथाविहित पाक्षिक रिपोर्ट पेश करना।
 - (ठ) जहां कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से यथास्थिति प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति तक, किशोर या बालकों के साथ जाना और
 - (ड) केस फाईल और ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (ख) के अधीन पुलिस या पुलिस के किशोर या बालक कल्याण अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर परिवीक्षा अधिकारी किशोर या बालक के पूर्ववत तथा परिवार के इतिहास और अन्य प्रांसंगिक परिस्थितियों की, जो आवश्यक हो, जांच करेगा और बोर्ड को यथाशीघ्र प्रपत्र चार या प्रपत्र तेरह में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

88. गृह पिता या गृह माता के कर्तव्य :- गृह पिता, गृह माता तथा अन्य केयरटेकरों के सामान्य कर्तव्य, कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :-

- (क) किशोर या बालक के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना।
- (ख) किशोर या बालक की उचित देखरेख करना तथा उसका कल्याण
- (ग) किशोरों या बालकों के बीच अनुशासन बनाए रखना।

- (घ) अनुरक्षण, सफाई और स्वच्छता।
- (ङ) दैनिक कार्यों का दक्षतापूर्ण रीति से क्रियान्वयन तथा इसमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- (च) गृह की सुरक्षा और संरक्षण व्यवस्था की देखभाल।
- (छ) किशोरों या बालकों का, वे जब कभी भी गृह से बाहर जाते हैं मार्गरक्षण करना।

89. प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर, गृह पिता अथवा गृह माता तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हताएं :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केसवर्कर, गृह पिता या गृह माता और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारीवृंद अपने पर्यवेक्षण या स्वयं के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किशोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।
- (2) किसी देखभाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किशोर या बालक के शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जांच के पश्चात निरर्हता का पात्र बनाएगी।

90. कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

- (1) राज्य सरकार या प्रभारी अधिकारी कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्ट कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण देगा।
- (2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-
 - (क) नए भर्ती किए गए कर्मचारीवृंद का अभिविन्यास और प्रतिस्थापना प्रशिक्षण,
 - (ख) समस्त देखभालकर्ताओं के लिए वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, तथा
 - (ग) कर्मचारीवृंद सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं,
- (3) राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण इकाई, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की सहायता से नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेगी तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में संलग्न कार्मिकों के लिए उनकी क्षमता निर्माण करेगी।

91. चयन समिति तथा इसकी संरचना :—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- (क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
- (ख) जिला कलेक्टर,
- (ग) जिला पुलिस अधीक्षक,

92. चयन समिति के कार्य :—

(1) (क) बोर्ड या समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति जिला या राज्य बालक संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा इस आशय के सार्वजनिक विज्ञापन की प्रतिक्रिया में प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और

(ख) चयन समिति, प्राप्त आवेदनों में से बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों का चयन करेगी राज्य सरकारों को नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(2) बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी शिकायत की दशा में, चयन समिति आवश्यक जांच करेगी तथा यदि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार को ऐसे सदस्य की नियुक्ति को बर्खास्त करने की सिफारिश करेगी।

(3) (क) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति, इन रिक्तियों को भरने के लिए जो बोर्ड या समिति की कालावधि के दौरान उद्भूत होती है, प्रत्येक बोर्ड या समिति के लिए नामों का एक पैनल भी तैयार करेगी।

(ख) बोर्ड या समिति में किसी रिक्ति की दशा में, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसी रिक्ति को भरने के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(ग) राज्य सरकार चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल के आधार पर रिक्तियों को भरेगी।

(4) चयन समिति, अधिनियम की धारा 35 की अपेक्षानुसार जिला या नगर स्तर की निरीक्षण समितियों का गठन करने के लिए नामों की सिफारिश करेगी।

93. सलाहकार बोर्ड :— राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला सलाहकार बोर्ड तथा नगर स्तर के सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 62 के अधीन यथा अपेक्षित सलाहकार बोर्ड गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग	— अध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, विधि	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम तथा नियोजन	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, कुटीर एवं लघु उद्योग	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	— सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय	— सदस्य
पुलिस महानिदेशक	— सदस्य
यूनिसेफ का प्रतिनिधि	— सदस्य
एक उद्योगपति	— सदस्य
एक पत्रकार	— सदस्य
प्रेस परिषद् का एक प्रतिनिधि	— सदस्य
दो सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि	— सदस्य
आयुक्त/संचालक, महिला सशक्तिकरण	सदस्य— सचिव

(2) सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा, अर्थात् :-

(क) विभिन्न शासकीय तथा समुदाय कल्याण पर आधारित अभिकरणों के माध्यम से किशोर न्याय सेवाओं का विकास ;

(ख) दोनों प्रवर्णों के किशोरों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानवीय तथा भौतिक साधन गतिशील करने के उपाय तथा साधन ;

- (ग) किशोर न्याय पद्धति के विस्तार में आने वाले विभिन्न प्रवर्गों के किशोरों के लिए शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाओं का विकास ;
- (घ) विधि की प्रक्रियागत माध्यम से किशोरों की समस्याओं को निपटाते समय बाल विकास के विभिन्न सेक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करना ;

- (3) राज्य द्वारा संचालक/आयुक्त महिला सशक्तिकरण की सिफारिश पर सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाएगा, अशासकीय सदस्य नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अशासकीय सदस्यों को सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। अशासकीय सदस्यों में आकस्मिक रिक्ति को किसी अन्य अशासकीय सदस्य की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा, जो इस शर्त पर पदधारण करेगा, कि वह व्यक्ति जिसके स्थान पर नियुक्त किया गया हो, रिक्ति न होने की स्थिति में पदधारण करता। सलाहकार बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अभिकथित की जाएगी।

नियम 93 के उपनियम (1) में गठित राज्य सलाहकार बोर्ड, अधिनियम की धारा 62 -क के प्रयोजनों के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई के रूप में भी कार्य करेगा, ऐसी इकाई के निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसा कि नियम 93 में उपबंधित है।

5. जिला सलाहकार बोर्ड, राज्य सरकार एक जिला सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जो अधिनियम के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के निरीक्षण के कर्तव्य का भी पालन करेगा। जिला सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

कलेक्टर	-चेयरपर्सन
पुलिस अधीक्षक	- सदस्य
जिला पंचायत का प्रतिनिधि	- सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य
उप संचालक, शिक्षा	- सदस्य
सचिव, रेडक्रास	- सदस्य
अध्यक्ष रोटरी/लायंस क्लब	- सदस्य
दो सामाजिक कार्यकर्ता	- सदस्य
नेबरहुड कमेटी के दो सदस्य	- सदस्य

व्यापारी	— सदस्य
दो दानदाता	— सदस्य
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	— सदस्य—सचिव
संबंधित गृह का अधीक्षक	— सदस्य

उद्देश्य— जिला सलाहकार बोर्ड, जिले में किशोर न्याय के प्रशासन से संबंधित क्रियाकलापों की निम्नलिखित दशा में समीक्षा करेगा :—

- (क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित संस्थाओं के प्रशासन एवं क्रियाकलापों की समीक्षा करना।
- (ख) अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा संचालक/आयुक्त, समाज कल्याण विभाग को उसकी रिपोर्ट भेजना।
- (ग) गृहों के उन्नयन एवं विकास हेतु उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तावित करना।
- (घ) जिले में परिवीक्षा कार्यों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना।
- (ङ) समाज में बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम को सहयोग देना।
- (च) बच्चों के समस्त विकास एवं पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता करना।
- (छ) बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों के मध्य समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने के लिए वातावरण निर्मित करना।
- (ज) अधिनियम के अधीन संस्थाओं के सेटअप में सुनिश्चित न्यूनतम मानकों की समीक्षा करना।
- (झ) असंस्थागत सेवाएं जैसे— परिवीक्षा, पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण, प्रवर्तकता कार्यक्रम आदि की समीक्षा करना।
- (ञ) विभिन्न विभागों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों आदि के बीच सम्पूर्ण समन्वय तथा उनके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना।
- (ट) संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाओं में प्रभावी रूप से सुधार करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तावित करना।

अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन,—

(क) जिला सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(ख) अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में कालावधि तीन वर्ष होगी। कलेक्टर द्वारा अशासकीय सदस्यों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पदच्युत किया जा सकेगा।

बैठक — जिला सलाहकार बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होगी।

94. खुलापन और पारदर्शिता :—

- (1) समस्त बाल गृहों को प्रभारी अधिकारी की अनुमति से आंगंतुकों के लिए खोला जाएगा और समिति या प्रभारी अधिकारी स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, प्रख्यात व्यक्तियों, मीडिया तथा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आंगंतुकों के रूप में अनुमति देने पर विचार कर सकती है, जैसा प्रभारी अधिकारी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और हित का समुचित ध्यान रखते हुए उचित समझे ;
- (2) यदि स्थानीय समाज के सदस्य संस्था में सेवा करना चाहते हो या वे अपनी विशेषताओं के माध्यम से संस्था में योगदान देना चाहते हों, तो इन गृहों के प्रभारी अधिकारी इन गृहों की स्थितियों में सुधार करने के लिए स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे ;
- (3) प्रभारी अधिकारी आंगंतुकों संबंधी पुस्तिका रखेंगे तथा इस पुस्तिका में आंगंतुकों द्वारा दी गई टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा ;
- (4) किसी संस्था का दौरा करते समय, आंगंतुक न ऐसा कुछ कहेंगे या न ऐसा कुछ करेंगे, जो प्रभारी अधिकारी के प्राधिकार को क्षति पहुंचाता हो या जिससे इस अधिनियम या नियमों का उल्लंघन हो या बालकों की गरिमा को ठेस पहुँचती हो ;
- (5) आंगंतुकों को सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति से प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

95. किशोर न्याय निधि .—

- (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन बालकों के कल्याण तथा पुर्नवास के लिये राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 61 के अधीन राज्य स्तर पर स्वैच्छिक दान के अलावा एक निधि सृजित करेगा जो "किशोर न्याय निधि" जो इस नियम में इस के पश्चात निधि के रूप में निर्दिष्ट हो के नाम से जानी जाएगी।

- (2) निधि का उपयोग .—
 - (क) बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले तथा बालकों के कल्याण तथा पुर्नवास कार्यक्रम को कार्यान्वित करना ;
 - (ख) गैर-सरकारी संगठनों का सहायता, अनुदान का संदाय करने ;
 - (ग) राज्य सलाहकार बोर्ड तथा उसके प्रयोजनों के व्ययों को पूरा करने ;
 - (घ) उपरोक्त प्रायोजनों के लिए समस्त अन्य आनुषंगिक तथा सहायक बातों को करने के लिए किया जाएगा।
- (3) राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा निधि का प्रबंधन तथा प्रशासन किया जायेगा।
- (4) निधि की आस्तियों में किसी व्यक्ति या संगठन से स्वैच्छिक दान के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कानूनी या गैर कानूनी निकायों से आवर्ती या अनावर्ती समस्त अनुदान और अभिदाय सम्मिलित होंगे।
- (5) राज्य सलाहकार बोर्ड के आहरण चैक द्वारा 20,000/- तक की राशि के सचिव और उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जाएंगे तथा रुपए 20,000/- से अधिक के चैक हेतु सचिव या बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।
- (6) समस्त धन तथा सम्पत्तियों तथा निधि के सम्पूर्ण आय और व्यय के नियमित लेखे रखे जाएंगे, उन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की किसी अधिसूचित फर्म या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों से संपरीक्षित कराया जायेगा। संपरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि से लिये गये व्यय सचिव द्वारा रखे जाएंगे। समस्त संविदाएँ और अन्य आश्वासन प्रबंध बोर्ड के नाम से होंगे और उनकी ओर से सचिव द्वारा तथा प्रयोजनों के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
- (7) प्रबंध बोर्ड अपने एक या एक से अधिक सदस्यों की ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा जो उनके मत में मात्र एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है।

96. इन नियमों का लागू होना — यह घोषणा की जाती है कि जब तक अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अनुरूप नए नियम नहीं बनाए जाते हैं, नियम 2015 आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्य में लागू होंगे।

97. लंबित मामले .—

- (1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा।
- (2) सभी लंबित मामले, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन निपटाए जाएंगे।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को, इस नियम के उपनियम (1) के अधीन फायदे दिए जाएंगे और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फायदे उन सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो किसी अपराध को करने के

समय किशोर या बालक थे। ये फायदे उन्हें तब भी दिए जाएंगे जब वे किसी जांच या विचारण के दौरान किशोर या बालक नहीं रहते हैं।

- (4) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक के निरोध या रहने या दण्ड की अवधि की संगणना करते समय, सभी ऐसी अवधि, जिसे कोई किशोर या बालक अभिरक्षा, निरोध, दण्ड के रूप में पहले से ही बिता चुका है, न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में अंतर्विष्ट रहने या निरोध या कारावास दंड के हिसाब में लिया जाएगा।

98. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का निपटान :—विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर की तुरंत रिहाई के लिए, जिसके निरोध या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा हो गई है, यथास्थिति राज्य सरकार या बोर्ड या तो स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजनार्थ किए गए आवेदन पर विधि का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति या किशोर के मामले का पुनर्विलोकन, इस अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के नियम 12 के उपबंधों के अनुसार उसकी किशोरावस्था का निर्माण कर सकेगा तथा इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

99. अभिलेखों या दस्तावेजों का निपटान :— विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक से संबंधित अभिलेख या दस्तावेजों को सात वर्ष के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और उसके पश्चात नहीं और मामले के अनुसार उसके पश्चात यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या बोर्ड या समिति द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे।

100. निरसन और व्यावृत्ति :—इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 निरसित हो जाएंगे ; परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या किए गए कोई आदेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या किए गए समझे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

अनुसूची - एक

कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन एवं अन्य सामग्री (नियम 41)

(1) किशोरों अथवा बालकों के निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान की जाएंगी :

क्र.	वस्तु	प्रति बालक आपूर्ति की मात्रा	प्रस्तावित
1	तौलिया	4 प्रतिवर्ष	2 प्रतिवर्ष
2	सूती चादर	2 प्रति 2 वर्ष	2 प्रति 2 वर्ष
3	तकिया (रुई भरा हुआ)	1 प्रति 2 वर्ष	1 प्रति 5 वर्ष
4	तकिया के कवर	2 प्रति 2 वर्ष	2 प्रति 3 वर्ष
5	ऊनी कम्बल	2 प्रति 2 वर्ष	2 प्रति 5 वर्ष
6	सूती दरी	2 प्रति 2 वर्ष	2 प्रति 2 वर्ष
7	रुई भरी रजाई	1 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)	1 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
8	गद्दा	1 प्रति 2 वर्ष	1 प्रति 3 वर्ष
9	मच्छरदानी	1 प्रति 2 वर्ष	1 प्रति 3 वर्ष
10	गद्दे का कवर	1 प्रति 5 वर्ष में (स्थायी बच्चों के लिए)	
11	रजाई का कवर	1 प्रति 5 वर्ष में (स्थायी बच्चों के लिए)	
लड़कियों के लिए कपड़े			
1	स्कर्ट और ब्लाउज या सलवार कमीज या आधी साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट	आयु और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर 5 सैट प्रतिवर्ष	प्रथम वर्ष स्कूल यूनिफार्म सहित
2	बनियान (एक-एक मीटर)	छोटी लड़कियों के लिए 6 प्रतिवर्ष	छोटी लड़कियों के लिए 2 प्रतिवर्ष
3	ब्रेजर	बड़ी लड़कियों के लिए 6 प्रतिवर्ष	बड़ी लड़कियों के लिए 2 प्रतिवर्ष
4	पेन्टीज (1 मीटर कपड़ा)	6 प्रतिवर्ष	4 प्रतिवर्ष
5	सैनिटरी टॉवल	बड़ी लड़कियों के लिए 12 पैकेट प्रतिवर्ष	बड़ी लड़कियों के लिए 12 पैकेट प्रतिवर्ष (मीडियम साइज के)
6	ऊनी स्वेटर	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
7	ऊनी शाल	1 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)	1 प्रति 3 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
लड़कों के लिए कपड़े			
1	कमीज	5 सैट प्रति वर्ष	5 सैट प्रति वर्ष (यूनिफार्म)

			सहित)
2	निककर	छोटे बच्चों के लिए 5 सेट प्रति वर्ष	छोटे बच्चों के लिए 5 सेट प्रति वर्ष (यूनिफार्म सहित)
3	पैट	बड़े बच्चों के लिए 5 सेट प्रतिवर्ष	बड़े बच्चों के लिए 5 सेट प्रतिवर्ष (यूनिफार्म सहित)
4	बनियान	4 सेट प्रति वर्ष	2 सेट प्रति वर्ष
5	अण्डर वियर	4 सेट प्रति वर्ष	2 सेट प्रति वर्ष
6	ऊनी जर्सी	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
7	स्कार्फ	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
विविध वस्तुएं			
1	चप्पल	1 जोड़ी प्रतिवर्ष	
2	जूते	1 जोड़ी प्रतिवर्ष	
3	स्कूल की बर्दी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 2 सेट प्रतिवर्ष	
4	स्कूल के जूते	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सेट प्रतिवर्ष	
5	स्कूल बैग और स्टेशनरी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सेट प्रतिवर्ष	
6	रूमाल	6 प्रतिवर्ष	

टिप्पणी :

(क) ऊपर विनिर्दिष्ट पहनावे के अतिरिक्त, प्रत्येक बालक को समारोहों के अवसरों पर उपयोग के लिए तीन वर्ष में एक बार एक सूट दिया जाएगा, जिसमें एक सफेद कमीज, एक जोड़ी खाकी निकर या पैट, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठण्डे इलाकों में) शामिल होंगे। लड़कियों को आधी साड़ी (सफेद) या एक सलवार कमीज या एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठण्डे इलाकों में) दिए जायेंगे।

(2) संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक अस्पताल में, जहां दाखिल मरीजों के लिए शैय्याओं का प्रावधान है, निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे :

रात के कपड़े एवं बिस्तर

1. गद्दा
2. सूती चादरें
3. तकिया
4. तकिया के कवर
5. ऊनी कम्बल
6. पायजामा एवं ढीली कमीज (लड़कों हेतु हॉस्पिटल टाइप)
7. लड़कियों हेतु स्कर्ट ब्लाउज या सलवार कमीज
8. सूती दरी

आपूर्ति हेतु मापदण्ड

- एक प्रति शैय्या प्रति तीन वर्ष
चार प्रति शैय्या प्रति वर्ष
एक प्रति शैय्या प्रति दो वर्ष
चार प्रति शैय्या प्रति वर्ष
एक प्रति शैय्या प्रति दो वर्ष
तीन जोड़ी प्रति बालक प्रतिवर्ष
तीन जोड़ी प्रति बालक प्रतिवर्ष
एक प्रति शैय्या प्रति तीन वर्ष

टिप्पणी :

- (i) जब तक बालक संस्था के अस्पताल में दाखिल रोगी के रूप में भर्ती रहता है, तब तक संस्था का डॉक्टर दाखिल रोगी को अस्पताल में कपड़े देगा तथा उसके द्वारा पहने हुए कपड़े रख लिए जाएंगे। अस्पताल से बालक की छुट्टी के समय उन कपड़ों को धुलवाकर उन्हें बालक को वापस दे दिया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक बालक को सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार किट बॉक्स अथवा लॉकर दिया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक बालक को सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार पारम्परिक चारपाइयों की जगह दो स्तरीय शैय्याओं की व्यवस्था करेगा।
- (3) प्रसाधन :- गृह के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मापदंड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री दी जाएगी :

बालों में लगाने के लिए तेल	100 मि.ग्रा. प्रतिमास
नहाने-धोने का साबुन अथवा कार्बोलिक साबुन	1 बड़ी टिकिया प्रतिमास
दूध पेस्ट एवं ब्रुश	1 ब्रुश प्रति 6मास, 50 ग्राम पेस्ट प्रतिमास
कंधा	1 प्रति 2 वर्ष

टिप्पणी :

- (क) संस्था से बाहर विद्यालय जाने वाले बालकों को उनकी स्कूल यूनीफार्म धोने के लिए कपड़े धोने के साबुन एक अतिरिक्त टिकिया (100 ग्राम) प्रतिमास दी जाएगी।
- (ख) कपड़े तौलिए, चादरें आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा :
- (i) कपड़े धोने का साबुन साबुन की टिकिया (125 ग्राम) प्रति मास
- (ii) सफेदी/विरंजक कर्मक सफेद कपड़े के लिए अपेक्षानुसार

तथापि, धुलाई के समय अन्य कपड़ों में अस्पताल के कपड़े शामिल नहीं किए जा सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो, अधीक्षक, अस्पताल के कपड़े धोने के लिए उपरोक्त मदें अलग से दे सकता है।

- (4) गृहों को साफ-सुथरा रखने के लिए निम्नलिखित मदें उपलब्ध कराई जाएंगी :

मद	आपूर्ति हेतु मापदण्ड
1. झाड़ू	संस्था के क्षेत्र के आधार पर 25 से 40 नग प्रति 2 मास
2. डी.डी.टी का छिड़काव	संस्था के डॉक्टर की सलाह के अनुसार
1. फिनाइल एवं सफाई करने हेतु पर संस्था एसिड (प्रतिदिन)	साफ किए जाने वाले शौचालय क्षेत्र के आधार डॉक्टर की सलाह के अनुसार

अनुसूची - दो
पोषण एवं आहार मापदण्ड (नियम 44)

आहार की सामग्री का नाम	मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
1. चावल/गेंहू/रागी/ज्वार लिए),	600 ग्राम (700 ग्राम 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के जिसमें कम से कम 100 ग्राम गेंहू या रागी या ज्वार हो।
2. दाल/राजमा/चना	120 ग्राम
3. खाद्य तेल	25 ग्राम
4. प्याज	25 ग्राम
5. नमक	25 ग्राम
6. हल्दी	05 ग्राम
7. धनिया (पिसा हुआ)	05 ग्राम
8. अदरक	05 ग्राम
9. लहसुन	05 ग्राम
10. इमली/अमचूर	05 ग्राम
11. दूध (नाश्ते में)	150 मि.ली.
12. मिर्च	05 ग्राम
13. सब्जी(पत्तेदार)	100 ग्राम
(बिना पत्ते वाली)	130 ग्राम
14. दही या छाछ	100 ग्राम /मि.ली.
15. गुड और मूंगफली या पनीर	60-60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम) सप्ताह में एक बार
16. चीनी	40 ग्राम

50 बच्चों के लिए प्रतिदिन निम्नलिखित मर्दे

17. काली मिर्च	25 ग्राम
18. जीरा	25 ग्राम
19. चना दाल	50 ग्राम
20. सरसों	50 ग्राम
21. अजवाइन	50 ग्राम

रूग्ण बच्चों के लिए

22.	ब्रेड	500 ग्राम
23.	दूध	500 मि.ली.
		अन्य मदें
24.	रसोई गैस	केवल खाना पकाने के लिए

अनुदेश :

(2) आहार में विविधता :-

- (क) तीन प्रकार की दालें अर्थात् तूर (तुवारी), मूंग (हरा चना) तथा चना (बंगाली चना) बारी-बारी से वितरित की जाएं।
- (ख) शाकाहारी बच्चों को लड्डू के रूप में प्रति बच्चा 60 ग्राम गुड एवं 60 ग्राम मूंगफली दाना अथवा अन्य कोई मिठाई अथवा 100 ग्राम पनीर वितरित किया जाए।
- (ग) सप्ताह में एक बार पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मैथी, पालक, गौंगुरा थोटकुरा अथवा अन्य कोई साग भी वितरित की जाए। यदि कहीं किसी संस्था में किचन गार्डन हो तो वहां सहजन के पेड़, कडी पत्ता के पेड़, धनिया के अलावा पत्तेदार सब्जियां उगायी जानी चाहिए और अधीक्षक को अलग-अलग तरह की सब्जियां वितरित करनी चाहिए एवं ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रकार की सब्जी सप्ताह के भीतर पुनः वितरित न की जाए।
- (घ) अधीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अथवा संस्था के डॉक्टर की सलाह पर वह व्यक्ति विशेष मामलों में आहार के मापदण्ड में अस्थायी परिवर्तन कर सकता है बशर्ते कि निर्धारित मापदण्ड से मात्रा अधिक न हो।

(3) भोजन का समय एवं व्यंजन सूची :-

- (क) पूर्वाह्न 8.00 बजे के बाद नाश्ता
 - (i) (प) उपमा अथवा गेंहू या रागी की रोटी अथवा अन्य कोई व्यंजन
 - (ii) (पप) गौंगुरा अथवा ताजाकडी पत्ता अथवा ताजे धनिया अथवा नारियल की
 - (iii) चटनी और पुत्ता दाल/सब्जी को एक व्यंजन के रूप में वितरित किया जाए।
 - (iv) (पपप) दूध
 - (v) (पअ) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल
- (ख) लंच दोपहर 1.00 बजे तथा रात्रि को भोजन अपराह्न 7.00 बजे के बाद
 - (i) (प) चावल/चपाती अथवा दोनों
 - (ii) (पप) पकी हुई सब्जी
 - (iii) (पपप) सांभर अथवा दाल

(iv) (पअ) दही अथवा छाछ

(4) अन्य :-

- (क) मौसम के अनुसार, अधीक्षक स्व-विवेक से भोजन वितरण के समय में परिवर्तन कर सकेगा।
- (ख) संस्था के डॉक्टर की सलाह पर प्रत्येक बीमार बच्चे को, जिसे उसके अस्वस्थ होने के कारण नियमित भोजन करने से रोका गया है, आहार मापदण्डों में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सीय आहार वितरित किया जाए।
- (ग) वजन बढ़ाने के लिए अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों से संस्था के डॉक्टर की सलाह पर नियमित आहार के अलावा पोषण हेतु दूध, चीनी एवं फल जैसे अतिरिक्त आहार दिए जाने चाहिए और दैनिक राशन की गणना के प्रयोजनार्थ बीमार बच्चों को उस दिन बच्चों की संख्या में शामिल न किया जाए।
- (घ) निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्वों एवं त्यौहारों के अवसर पर आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर गृह के सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाए :
 1. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
 2. अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल)
 3. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
 4. महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
 5. बाल दिवस (14 नवंबर)
 6. बाल अधिकार दिवस (20 नवंबर)
 7. दशहरा (विजय दशमी)
 8. दीपावली
 9. रमजान (ईद-उल-फितर)
 10. बकरीद (ईद-उल-जुहा)
 11. किसमस (25 दिसंबर)

राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरिक्त त्यौहार विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

प्रपत्र - 1
{ नियम 13 (1) (घ) }
पर्यवेक्षण आदेश

जब किशोर को उसके माता-पिता, संरक्षक या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति / उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखा जाए (दिनांक 20 की प्रोफाइल संख्या.....

चूँकि (किशोर का नाम) को इस दिन अपराध करते पाया गया है और इसे (नाम) पता की देखरेख में उक्त द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रखा गया है और बोर्ड इस विषय में संतुष्ट है कि उक्त किशोर/किशोरी को पर्यवेक्षण में रखकर उसके मामले का उचित निपटान किया जा सकता है।

एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उक्त किशोर को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन की अवधि के लिए परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में रखा जाए :-

1. यह किशोर इस आदेश और उक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र की प्रतियों के साथ उसमें नामित परिवीक्षा /मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यह किशोर उपर्युक्त परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता को पर्यवेक्षण हेतु सौंपा जाएगा।
3. यह किशोर की अवधि तक पर / में रहेगा।
4. इस किशोर को परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता की अनुमति लिए बिना के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5. इस किशोर को दुष्चरित्र व्यक्तियों के साथ मिलने नहीं दिया जायेगा।
6. यह किशोर ईमानदारी से और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा तथा नियमित रूप से स्कूल जाएगा या ईमानदारी से जीविका कमाने का प्रयास करेगा।
7. यह किशोर नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित रहेगा।
8. जिस व्यक्ति की देखरेख में इस किशोर को रखा गया है, वह व्यक्ति इसकी देखरेख, शिक्षा एवं कल्याण की समुचित व्यवस्था करेगा।
9. जिस व्यक्ति की देखरेख में किशोर को रखा गया है, उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करने होंगे कि इस किशोर से ऐसा कोई अपराध न हो, जो भारत में किसी विधि के अनुसार दण्डनीय हो।
10. इस किशोर को स्वापक औषधियाँ अथवा मनः प्रभावी पदार्थ या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।
11. परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता ऊपर उल्लिखित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए समय-समय पर जो निदेश देंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक मास 20

(हस्ताक्षर)

प्रधान दंडाधिकारी

किशोर न्याय बोर्ड

यदि कोई अतिरिक्त शर्त / शर्त जोड़ी जानी हों तो किशोर न्याय बोर्ड वह शर्त/वे शर्तें यहां जोड़ सकता है।

प्रपत्र-II

{ नियम 13 (1) (ड) }

धारा की उपधारा धारा की उपधारा
और धारा की उपधारा के अधीन निरोध किए जाने का आदेश

प्रभारी अधिकारी

.....
.....

चूंकि (दिनांक) माह 20 (वर्ष) को
(किशोर/किशोरी का नाम), पुत्र/पुत्री आयु निवासी
को प्रोफाइल संख्या में विधि/धारा का/की विरोध करते पाया गया, इसलिए मैं
..... प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड उक्त किशोर/किशोरी को किशोर न्याय
अधिनियम, 2000 की धारा के अंतर्गत अवधि तक पर्यवेक्षण
गृह/विशेष गृह में रखे जाने का आदेश देता हूं।

इसके द्वारा आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त
किशोर/किशोरी को अपनी देखरेख में लें और विधि के अनुसार उपर्युक्त आदेश का निष्पादन करने
के लिए उसे अवधि तक पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह में रखें।

मेरे हस्ताक्षर और किशोर न्याय बोर्ड की मुहर द्वारा (दिनांक)
(माह) 20 (वर्ष) को प्रदत्त।

(हस्ताक्षर)

प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड

संलग्नक :

निर्णय (यदि कोई हो) या आदेशों की प्रति, किशोर/किशोरी के गृह का विवरण, इतिवृत्त एवं
व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो का ब्यौरा :

जो अपेक्षित न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र -III
{ नियम 13 (1) (च) और (7) }
सामाजिक अन्वेषण/जांच का आदेश

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता चूंकि इस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए (किशोर/किशोरी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री आयु लगभग निवासी के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा के अंतर्गत रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त हुई है।

आपको एतद द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त किशोर के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की परिस्थितियों की जांच करके अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को/या इससे पहले अथवा इस बोर्ड द्वारा अनुज्ञात समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतद्वारा यह निदेश भी किया जाता है कि आप आवश्यक होने पर बाल मनोविज्ञान, मनःचिकित्सक उपचार या परामर्श के किसी विशेषज्ञ से विचार-विमर्श करके उनके विचार जाने तथा अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

..... (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)।

(हस्ताक्षर)

प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र -IV

{ नियम 13 का उपनियम (7) तथा नियम 87 का उपनियम (1)(क) व(2) }
सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

क्र. संख्या

किशोर न्याय बोर्ड (पता) को प्रस्तुत

परिवीक्षा विभाग/राज्य सरकार का संबंधित प्राधिकरण/स्वैच्छिक संगठन
..... (हस्ताक्षर व मुहर)

प्रोफाईल संख्या :

धारा : के अधीन

प्रोफाईल का शीर्षक :

थाना :

आरोपित अपराध का स्वरूप :

नाम

धर्म

पिता का नाम

जाति

स्थायी पता

जन्म का वर्ष

पकड़े जाने से पूर्व अंतिम पता

आयु

लिंग

विगत में किसी संस्था में रखे जाने/किसी मामले तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो, का इतिवृत्त

परिवार

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यवसाय	मासिक आय	विकलांगता	अन्य कोई ब्यौरा जैसै कि सामाजिक आदतें
पिता								
सौतेला पिता								

माता								
सौतेली माता								
भाई-बहन								
अन्य कोई विधिक संरक्षक / नातेदार								

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विशिष्टियां

अन्य नजदीकी रिश्तेदार या इच्छुक अभिकरण

धर्म, सामान्य गृह के एवं नैतिक संहिता के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि

सामाजिक और आर्थिक स्थिति

परिवार के सदस्यों का अपचारित का रिकार्ड

मौजूद जीवन दशा

माता-पिता/माता-पिता व उनके बच्चे विशेषकर अन्वेषणाधीन

..

किशोर/किशोरी के बीच संबंध

अन्य कोई महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो

किशोर का इतिवृत्त

मानसिक स्थिति (मौजूदा और विगत)

शारीरिक स्थिति (मौजूदा और विगत)

आदतें, शौक (नैतिक, मनोरंजन इत्यादि)

चरित्र एवं व्यक्तित्व की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं

साथी और उनका प्रभाव

बिना अनुमति के घर छोड़ने का ब्योरा, यदि कोई हो

शिक्षा स्कूल (स्कूल, के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति किशोर/

किशोरी का और उसके प्रति इनका दृष्टिकोण
 कामकाज का रिकार्ड (किए गए काम, छोड़ने के कारण, व्यावसायिक
 अभिरूचियां, काम या नियोक्ता के प्रति दृष्टिकोण)
 आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट
 घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और
 बालक की प्रतिक्रिया
 अन्य कोई अभियुक्ति

जांच का परिणाम

भावनात्मक कारक

शारीरिक दशा

बौद्धिक क्षमता

सामाजिक व आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

समस्याओं के संबंध में सुझाए गए विभिन्न कारण

अपचारिता के कारणों सहित मामले का विश्लेषण

जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया गया, उनके विचार

अपचार एवं इसकी योजना के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिश

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता

प्रपत्र -V

[नियम 15 का उपनियम (5), नियम 79 का उपनियम (2)]

जिन माता/पिता/संरक्षकों/नातेदारों अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा जाए, उनके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला वचनबंध/बंधपत्र

चूंकि मैं माता-पिता, संरक्षक, नातेदार या वह उपयुक्त व्यक्ति होने के नाते, जिनकी देखरेख में (किशोर/किशोरी का नाम) को रखे जाने का आदेश किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिया गया है, उक्त बोर्ड द्वारा मुझे जमानत सहित अथवा जमानत के बिना रूपए (अंकों में)/ रूपए (शब्दों में) वचनपत्र/बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं अपनी देखरेख में रखे गए उक्त के संबंध में स्वयं को एतद्वारा आबद्ध करता हूं। मैं उक्त की समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि उक्त अच्छा व्यवहार करें और मैं से वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा।

1. मैं परिवीक्षा अधिकारी /मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूंगा।
2. मैं किशोर न्याय बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किशोर/किशोरी को उक्त न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर नहीं ले जाऊंगा।
3. मैं उक्त किशोर/किशोरी को स्कूल/उक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय के लिए भेजूंगा, यदि मेरे नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हुआ।
4. मैं उक्त किशोर/किशोरी को नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र भेजूंगा यदि मेरे नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हुआ।
5. मैं आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को तत्काल रिपोर्ट करूंगा।
6. यदि मेरी देखरेख में रखे गए किशोर/किशोरी ने बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं किया या उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया तो मैं उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
7. मैं परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता को पर्यवेक्षण दायित्व निभाने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करूंगा।
8. मैं वचन देता हूं कि उपर्युक्त शर्तों के पालन में मुझसे कोई चूक हो जाने पर मैं, यथास्थिति, उपर्युक्त कार्यवाही के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने या सरकार को रूपए (अंकों में)/ रूपए (शब्दों में) अदा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

..... दिनांक (माह) 20 (वर्ष)।
वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड
यदि किशोर न्याय बोर्ड कोई अतिरिक्त शर्त/शर्तें जोड़ना चाहे तो उसे/उन्हें समुचित संख्यांक देते हुए जोड़ें। (जहां जमानत सहित बंधपत्र निष्पादित किया जाना हो, वहां जोड़ें)
मैं/हम निवासी (निवास स्थान का पूरा पता) इस वचनबंध/बंधपत्र की शर्तों के पालन हेतु उक्त (वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) के लिए स्वयं को एतद्वारा जमानती घोषित करता हूं/करते हैं। इन शर्तों के पालन में (वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) से कोई चूक हो जाने पर, मैं/हम संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग सरकार को रूपए (अंकों में)/ रूपए (शब्दों में) अदा करूंगा/करेंगे। की उपस्थिति में दिनांक (माह) 20 (वर्ष) को निष्पादित।

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
हस्ताक्षर

जमानती (जमानतियों) के

प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र -VI

किशोर/बालक से वचनबंध

{ नियम 15 का उप-नियम (6) तथा नियम 79 का उपनियम (2) }

अधिनियम की धारा की उपधारा के खण्ड
 के अंतर्गत आदेशानुसार किशोर/बालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला मुचलका
 चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा ..
 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति
 द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मुझे निवासी
 (मकान नं., सडक, गांव/शहर, तहसील, जिला, राज्य का पूरा ब्यौरा दें) को आगे दर्शाई गई शर्तों
 का अनुपालन करने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के नियम 9 के
 उपनियम 6 और नियम 66 के उपनियम 2 के अंतर्गत मेरे द्वारा मुचलका भरे जाने पर मेरे मूल
 निवास स्थान पर वापस भेज दिया जाए। इसलिए अब मैं सत्यानिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि
 अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूंगा।

मैं एतद्वारा स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ :

1. अवधि के दौरान मैं सामान्यता: उस गांव/शहर/जिले को छोड़कर
 कहीं नहीं जाऊंगा, जहां मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड/समिति की पूर्वानुमति के
 बिना न तो लौटूंगा और न ही उक्त जिले से बाहर कहीं जाऊंगा।
2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव/शहर अथवा जिले में स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण
 पर जाऊंगा जहां मुझे भेजा जा रहा है।
3. उक्त जिले में अन्य कहीं स्थिति स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं
 उक्त बोर्ड/समिति को अपने सामान्य निवास स्थान की सूचना दूंगा।

मैं एतद्वारा यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें, मुझको
 पढ़कर सुनाया/समझाया गया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

(किशोर या बालक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें
 (किशोर या किशोरी/बालक) को पढ़कर सुनाई या समझा दी गई हैं तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों
 के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किए/रखे जाने की अवधि
 रद्द की जा सकती है।

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त किशोर/किशोरी या बालक को
 (दिनांक) को छोड़/रिहा दिया गया है।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी अधिकारी

के हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र -VII

[नियम 17 का उप-नियम (10)]

निर्मुक्ति/उन्मोचन आदेश

मैं (उन्मोचन अधिकारी का नाम एवं पदनाम) राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस आदेश के द्वारा पुत्र/पुत्री निवासी को, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण गृह/ विशेष गृह/परवर्ती देखरेख गृह में (दिनांक) (माह) 20..... (वर्ष) को अवधि हेतु रखे जाने का आदेश दिया गया था और जिसे अब पर स्थित गृह में रखा गया है, और उक्त गृह में उन्मोचित किए जाने तथा उसके निवास की शेष अवधि के दौरान उसे के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रखे जाने की अनुमति देता हूँ।

यह आदेश आगे दर्शाई गई शर्तों के अधीन दिया गया है इनमें से किसी भी शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में इसे रद्द किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :

उन्मोचन प्राधिकारी के

हस्ताक्षर व पदनाम

शर्तें

1. उन्मोचित व्यक्ति निरुद्ध किए जाने की अवधि के समाप्त होने तक, यदि यह माफी पहले ही रद्द न की गई हो, में जाकर के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रहेगा/ रहेगी।
2. वह की अनुमति के बिना उस स्थान या उक्त द्वारा बताए गए अन्य किसी स्थान से कहीं नहीं जाएगा/जाएगी।
3. वह स्कूल में/ व्यावसायिक प्रशिक्षण पर या अन्य कहीं समयनिष्ठ व नियमित उपस्थिति के विषय में उक्त के अनुदेशों का पालन करेगा/करेगी।
4. वह स्थित उपस्थिति केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित होगा/होगी।
5. वह कोई भी अपराध करने से बचेगा/बचेगी और के लिए संतोषप्रद ढंग से सीधा-सादा व परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा/करेगी।
6. उसके द्वारा किसी भी उपर्युक्त शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में निरोध की अवधि की इस आदेश द्वारा प्रदत्त माफी रद्द की जा सकती है और यह माफी रद्द किए जाने पर उसके साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 59 की उप-धारा (3) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

मैं एतद्वारा यह अभिस्वीकार करता/करती हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जो मुझे पढ़कर सुनाई/समझाई गई है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

(उन्मोचित किशोर/किशोरी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें किशोर या किशोरी / बालक, को पढ़कर सुनाई/समझाई गई है तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिनके आधार पर उसके निरोध की अवधि को रद्द किया जा सकता है।

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त किशोर या किशोरी/बालक को को उन्मोचित किया गया है।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र -VIII

{ नियम 27 का उप-नियम (17) }

पर्यवेक्षण आदेश

जब बच्चे को उसके माता-पिता, संरक्षक या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति
की देखरेख में रखा जाए

..... 20 का मामला संख्या

चूँकि इस दिन यह पाया गया है कि (बालक का नाम) को देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है तथा उसे (नाम), निवासी (पता) द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर उक्त (नाम) की देखरेख व पर्यवेक्षण में रखा गया और समिति इस विषय में संतुष्ट है कि उक्त बालक को पर्यवेक्षण में रखने का आदेश पारित करके उसके मामले का समुचित निपटान किया जा सकता है।

इसलिए, एतद्वारा उक्त बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन अवधि के लिए (नाम) निवासी (पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाता है :

1. जब कभी आवश्यकता हो, तब यह बंधपत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति इस आदेश व उक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ इस बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. इस बालक को उपयुक्त माता-पिता/संरक्षक/उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।
3. यह बालक अवधि हेतु पर निवास करेगा।
4. बालक को समिति की अनुमति के बिना के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5. बालक नियमिति रूप से स्कूल जाएगा या जाएगी/ईमानदारी से आजीविका कमाने का प्रयास करेगा या करेगी।
6. जिस व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखा जाएगा, उस व्यक्ति को उक्त बालक की समुचित देखरेख, शिक्षा व कल्याण की व्यवस्था करनी होगी।
7. बालक को अवांछनीय तत्वों के सम्पर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे कानून का उल्लंघन करने से रोका जाएगा।
8. बालक को नशीली दवाएं अथवा नशीले पदार्थ लेने या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।
9. उपर्युक्त शर्तों के विधिवत पालनार्थ समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

..... दिनांक (माह) 20 (वर्ष)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति

यदि कोई अतिरिक्त शर्त हो तो बाल कल्याण समिति वह शर्त जोड़ सकती है।

प्रपत्र -IX

{ नियम 27 का उप-नियम (17) तथा नियम 79 का उपनियम (2) }

माता-पिता अथवा जिस "उपयुक्त व्यक्ति" को बालक सुपुर्द किया जाता/की जाती है,
उनके द्वारा वचनबन्ध

मैं निवासी, म.नं. गली गांव/शहर
..... जिला राज्य एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं निम्नलिखित
शर्तों के अधीन बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार
(बालक का नाम) आयु की देखरेख का दायित्व संभालने का इच्छुक हूँ :

1. यदि उसका आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं तत्काल समिति को सूचित करूँगा /करूँगी।
2. जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूँगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूँगा/करूँगी।
3. उसके रोगग्रस्त होने पर मैं निकटवर्ती अस्पताल में उसका समुचित उपचार करवाऊँगा/करवाऊँगी।
4. मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी आवश्यक होगा, मैं उक्त बालक/बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

..... (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)

गवाह (गवाहों) के हस्ताक्षर और पता
(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
अध्यक्ष बाल कल्याण समिति

हस्ताक्षर

प्रपत्र -X

{ नियम 27 का उप-नियम (18) }

जांच के लंबित रहने के दौरान बालक को अल्पकाल के लिए
संस्था में रखे जाने का आदेश

बालक का नाम :
लिंग :
आयु :
पिता का नाम :
माता का नाम :
पता :
संगठन/संस्था को बालक के प्राप्त होने की तारीख :
बालक को प्रस्तुत करने वाला :

इस आदेश द्वारा आपको यह प्राधिकार व निदेश दिया जाता है आप उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) के अंतर्गत आश्रय गृह/बालगृह में रखें।

अगली तारीख :

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष /सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र -XI

{ नियम 27 का उप-नियम (19) }

किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेश

प्रभारी अधिकारी

चूँकि (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34 (3) के अंतर्गत देखरेख व संरक्षण में रह रहे (बालक का नाम), पुत्र/पुत्री आयु निवासी को अवधि के लिए बालगृह/आश्रय गृह में रखे जाने का आदेश बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया है।

एतद्वारा आपको यह प्राधिकार दिया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त आदेश के विधिवत कार्यान्वयन हेतु उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे बालगृह/आश्रय गृह में रखें।

मेरे हस्ताक्षर एवं बाल कल्याण समिति की मुहर से जारी।

..... (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

संलग्नक :

आदेश की प्रतियां, गृह और पूर्ववृत्त की विशिष्टियां, मामले का इतिवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, जो भी लागू हों।

प्रपत्र -XII

{ नियम 28 का उप-नियम (1) }

जाँच आदेश

बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/

सामाजिक कार्यकर्ता/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता

चूँकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए (बालक का नाम), आयु (लगभग) वर्ष, पुत्र/पुत्री निवासी के संबंध में से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इसलिए आपको एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि आप उक्त बालक की सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि की जाँच करके अपनी जाँच रिपोर्ट को या उससे पहले अथवा इस समिति द्वारा अनुज्ञेय समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि आप आवश्यक होने पर बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक उपचार या परामर्श के किसी विशेषज्ञ से विचार-विमर्श करके उनके विचार जानें तथा अपनी जाँच रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप उक्त किशोर के चरित्र एवं सामाजिक पूर्ववृत्त की जाँच करके अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को या उससे पहले अथवा बोर्ड/समिति द्वारा अनुज्ञेय समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

..... (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)।

(हस्ताक्षर)

मुहर :

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

प्रपत्र -XIII

{ नियम 28 (3); 33 (छ) (ii) य और 33 (4)(च); 87 (1)(क) और (2) }

जाँच-रिपोर्ट का प्रपत्र

क्र. संख्या

बाल कल्याण समिति (पता) के समक्ष प्रस्तुत :

मामला संख्या

सम्बद्ध सरकारी विभाग/स्वैच्छिक संगठन

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की श्रेणी :

नाम

पिता का नाम

स्थायी पता

अंतिम निवास का पता

धर्म

जाति

जन्म का वर्ष

आयु

लिंग

पिछली संस्था/मामले का इतिवृत्त और व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो
परिवार

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यवसाय	मासिक आय	विकलांगता	अन्य कोई ब्यौरा जैसे कि सामाजिक आदतें
पिता								
सौतेला पिता								
माता								
सौतेली माता								
भाई-बहन								
अन्य कोई विधिक संरक्षक/नातेदार								

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विशिष्टियां
 अन्य नजदीकी रिश्तेदार या इच्छुक अभिकरण
 धर्म, तथा गृह की सामान्य एवं नैतिक संहिता के प्रति दृष्टिकोण
 सामाजिक और आर्थिक स्थिति
 परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अपचारित का रिकार्ड
 मौजूद जीवन दशा
 माता-पिता/माता-पिता एवं बालकों, विशेषकर उक्त बालक के साथ संबंध
 अन्य कोई महत्वपूर्ण कारक

बच्चे का पूर्ववृत्त

मानसिक स्थिति (मौजूदा और विगत)
 शारीरिक स्थिति (मौजूदा और विगत)
 आदतें एवं रुचियां (नैतिक, मनोरंजन इत्यादि)
 चरित्र एवं व्यक्तित्व की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं
 साथी व उस पर उनका प्रभाव
 बिना अनुमति के गृह से बाहर रहने का मामला, यदि कोई हो
 स्कूल (स्कूल, के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति बालक
 का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण
 कामकाज का रिकार्ड (किए गए काम, छोड़ने के कारण, व्यावसायिक
 अभिरूचियां, काम या नियोक्ता के प्रति दृष्टिकोण)
 आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट
 घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और
 बालक की प्रतिक्रिया
 अन्य कोई अभ्युक्ति

जांच का परिणाम

भावनात्मक कारक

भौतिक परिस्थितियाँ

शारीरिक दशा

बौद्धिक क्षमता

सामाजिक व आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

बालक के देखरेख व संरक्षण का जरूरतमंद होने के कारण

जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया गया, उनके विचार

बालक को प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के विषय में बाल कल्याण अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना।

बाल कल्याण अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र -XIV

{ नियम 33 (3) (ग) }

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी आदेश

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा की उपधारा तथा इन नियमों के नियम के उपनियम के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के (दिनांक) के आदेश के अनुसार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण यथा नाम..... (नाम व पता) की अभिरक्षा में रखे गए (दिनांक) को जन्मे अवयस्क को आगे दर्शाए गए ब्यौरे के आधार पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित किया गया है :
 (क) बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता द्वारा की गई जांच/पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन
 (ख) माता-पिता द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण के दस्तावेज और इन नियमों के नियम 21 के उपनियम 12 (ङ) और (ग) के अधीन समितियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित अभ्यर्पण विलेख
 (ग) इन नियमों के नियम 21 के उपनियम 11 (छ) (iii) के अधीन विशेष दत्तक अभिकरण द्वारा प्रस्तुत घोषणा।
2. (विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा तत्सम्बन्धी नियमों विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरी करेगा और इस अवयस्क के संबंध में समिति एवं राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा यथापेक्षित दत्तक ग्रहण डिक्री /संरक्षा आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा।

दिनांक :

स्थान :

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा सम्पन्न किए जाने के लिए।

- (प) मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अध्याय (iii) एवं (iv) तथा उनके अंतर्गत उपबंधित नियम पढ़ एवं समझ लिए हैं और मैं उक्त अवयस्क का दत्तक ग्रहण कराते समय इन उपबंधों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ।
- (पप) मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा में उल्लिखित ब्यौरा सत्य एवं सही है। यदि यह ब्यौरा असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो समिति को यह अधिकार है कि वह (अवयस्क का नाम) के रिहाई आदेश को निलंबित कर उक्त अवयस्क को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने को कहे।

दिनांक :

स्थान :

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता

प्रपत्र -XV
{ नियम 33 (4) (ग) }

अभ्यर्पण विलेख

मैं पुत्र अथवा पुत्री निवासी सामाजिक कारणों से/एकल/बीमार/विकलांग होने के कारण लगभग वर्ष के अपने बालक (नाम, यदि कोई है) की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम) द्वारा मेरे बच्चे के अभ्यर्पण के परिणामों के बारे में बताया गया है। इन सभी तथ्यों को पूरी तरह जानते हुए मैं आज दिनांक को समिति के समक्ष अपने बच्चे को अभ्यर्पित कर रहा/रही हूँ। उक्त तिथि से दो माह के भीतर यदि मैं अपने बच्चे को वापस लेने के अपने निर्णय को नहीं बदलता/बदलती हूँ तथा इसके लिए उक्त समिति से सम्पर्क नहीं करता/करती हूँ, तो समिति मेरे बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु वैध होने की घोषणा करेगी तथा आगे मेरा अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक :

मैंने बाल कल्याण अधिकारी/ सामाजिक कार्यकर्ता ने दिनांक को संबंधित माता-पिता/संरक्षक को बच्चे के अभ्यर्पण की प्रक्रिया तथा परिणामों से अवगत करा दिया है।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र -XVI

{ नियम 35 (3) }

(क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन

1. अभिकरण का ब्यौरा

अभिकरण का नाम

पता

टैलीफोन नं.

फैक्स

ई-मेल

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम

टैलीफोन नं.

तारीख (प्रपत्र भरने की)

2. आवेदक का ब्यौरा

उपनाम

पूरा नाम जन्मतिथि

धर्म

घर पर बोली जाने वाली भाषा(एँ)

व्यवसाय

कार्य की प्रकृति

कार्य के घण्टे

पता

टैलीफोन नं.

देखभालकर्ता किस प्रकार के बालक का पालन पोषण करना चाहेगा
(देखभालकर्ता) के साथ पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात भरा जाए

3. पालन-पोषण के लिए वांछनीय बालक का ब्यौरा

आयु वर्ग 2 वर्ष से कम आयु 3-6 वर्ष 7-12 वर्ष 13-15 वर्ष 16-18 वर्ष

स्थापन का प्रकार

अवधि

(i) दत्तक ग्रहण-पूर्व

(ii) आपातकालीन

(iii) अल्प-अवधि

(iv) निर्धारण

(v) दीर्घ-अवधि

कोई आवेदक बालक की देखभाल कर सकता है यदि (कृपया चिन्हित करें)

कोई बालक जो :

I. उपेक्षित है

II. अनाथ है

III. शारीरिक रूप से विकलांग है

IV. मानसिक रूप से विकलांग है

- V. बधिर है
- VI. मूक है
- VII. विशेष शिक्षा का जरूरतमंद है
- VIII. सीखने में कोई कठिनाई है
- IX. शारीरिक रूप से उत्पीड़ित है
- X. यौन उत्पीड़न का शिकार है
- XI. कोई बालक, जिसके लिए दूसरों से जुड़ना मुश्किल है
- XII. कोई बालक, जिसे नियंत्रण की जरूरत है/जो प्राधिकारी का विरोध कर सकता है।
- XIII. बलात्कार/कौटुंबिक व्याभिचार से उत्पन्न बालक
- XIV. जिसके माता-पिता रोग से पीड़ित है
- XV. जिसके माता-पिता एचआईवी पॉजिटिव के शिकार है
- XVI. जिसके माता-पिता एड्स के रोगी हैं
- XVII. जिसके माता-पिता नशीली दवाओं के आदी है
- XVIII. माता-पिता कारागार में हैं
- XIX. त्यागे हुए बच्चे
- XX. अन्य जाति से संबंधित बच्चे
- XXI. अन्य धर्म के बच्चे

4. परिवार की संक्षिप्त रूपरेखा

नाम	लिंग	लगभग आयु	व्यवसाय	शिक्षा	आवेदक से संबंध

(व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, अनुभव आदि बताएं। परिवार के विशिष्ट गुणों को भी उजागर करें, जो बालक की आवश्यकताओं से मेल खाते हों। इस ब्यौरे से परिवार के उन गुणों की प्रथमदृष्टया पहचान में सहायता मिलनी चाहिए, जिसके बालक की आवश्यकताओं से मेल खाने की संभावना हो।

आवास (घर)

प्रकार, आकार, स्वयं का/किराए पर, सुविधाओं आदि का ब्यौरा पास-पड़ोस

संरचना, सुख-सुविधाएँ, सार्वजनिक यातायात के साधन आदि

5. आवेदक की पहचान का सत्यापन

निवास स्थान

निवास की अवधि

राष्ट्रीयता

वैवाहिक स्थिति

विवाह की तारीख/विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं

क्या आवेदक ने पूर्व में कोई विवाह किया है, ब्यौरा दें

यदि पूर्व के विवाह से बच्चे हैं तो उनका ब्यौरा :

देखे गए दस्तावेज तथा उन्हें देखने की तारीख का विवरण :

6. आजीविका का इतिवृत्त

शिक्षा, रोजगार, स्वैच्छिक कार्य, आंशिक कार्य, अवकाश क्रियाकलाप का ब्यौरा

7. अभिकरण की जांच :

चिकित्सा जांच

पुलिस जांच

नियोक्ता

8. व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से)

संदर्भ व्यक्तियों के साक्षात्कार के पश्चात यह खण्ड भरा जाए और इन साक्षात्कारों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए :

- कितने समय से जानते हैं
- आवेदक से संबंध
- में संलग्न कार्यों को निष्पादित करने की आवेदक की योग्यता का साक्ष्य दें
- बालकों की देखरेख
- सुरक्षित एवं देखरेख वाला वातावरण प्रदान करना
- पड़ोसी के रूप में आवेदक
- रुचियाँ, प्रतिभाएं व्यक्तित्व

सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इन संदर्भों का मूल्यांकन

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट

उपर्युक्त प्रपत्र में एकत्रित सूचना के आधार पर विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज के परिणामस्वरूप पालन-पोषण देखरेखकर्ताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट में व्यापक रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

- सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि
- घर का हुलिया
- जीवनस्तर, जैसा कि घर में हो
- घर के सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध
- पहले से घर में मौजूद बालकों (यदि कोई हो) के विकास की स्थिति
- रोजगार तथा आर्थिक परिस्थिति
- स्वास्थ्य का ब्यौरा
- आस-पड़ोस में उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का ब्यौरा
- पालन-पोषण देखभाल हेतु किसी बालक को चाहने के कारण
- दादा-दादी तथा अन्य संबंधियों का दृष्टिकोण

- पोष्य बालक के लिए प्रत्याशित योजना
- पालन-पोषण देखरेखकर्ताओं का कानूनी दर्जा
- प्रशिक्षण लेने की उत्सुकता

(ग) आवेदक (कों) का ब्यौरा

1. पृष्ठभूमि :

माता पिता तथा सहोदर भाई-बहनों के ब्यौरे की पारिवारिक संरचना, परिवार के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण ब्यौरा, बचपन के अनुभव आदि।

2. संबंध:

यदि दम्पति है— वैवाहिक जीवन की अवधि, प्रत्येक आवेदन की सहभागिता रखने की क्या गुणवत्ताएँ हैं, क्या प्रत्येक के साथ सकारात्मक संबंध बनाता है, संबंध स्थापित रखते हुए आवेदक किस तरह से समस्याओं/तनाव/क्रोध का सामना करता है आवेदक किस तरह से एक-दूसरे की सहायता करते हैं। पालन-पोषण स्थापन उसके संबंध को किस तरह से प्रभावित करेगा, इस बारे में प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन क्या है।

3. विनिश्चय-निर्माण:

इस संबंध में किस तरह से निर्णय लिया जाता है तथा आवेदकों में से प्रत्येक का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है क्या दम्पति के निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार की भागीदारी को और अधिक व्यापकता प्रदान की जाती है यदि हां, तो यह भाव बालक को किस तरह से प्रभावित करेगा।

इस भागीदारी में शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं।

4. आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :

आवेदकों द्वारा इस समय प्रयुक्त समर्थन प्रणालियों का एक सामान्य ब्यौरा दें, जिसमें स्थल के ब्यौरे सहित परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, धार्मिक क्रियाकलापों, सामुदायिक समूहों आदि का विस्तृत ब्यौरा हो।

5. परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य :

घर में अथवा घर से बाहर रहने वाले सदस्य। आवेदकों के साथ उनका संबंध, वे कितना समय घर में व्यतीत करते हैं, प्रस्तावित स्थापन के बारे में उनका दृष्टिकोण, स्थापन के लिए उनकी स्वीकारोक्ति आवेदक हेतु कितनी महत्वपूर्ण है।

6. परिवार की जीवन शैली का वर्णन :

परिवार किसे महत्वपूर्ण समझता है अर्थात् धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार कितने महत्वपूर्ण हैं, रूपरेखा दें। परिवार में किस तरह की अनुरक्ति है, सदस्य कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, परिवार के सदस्य व्यक्तिगत समय के बारे में क्या आशाएं रखते हैं, शिक्षा/शौक तथा अवकाश क्रियाकलाप पर पूरे परिवार की सहमति को कितना महत्व दिया जाता है।

7. पालन-पोषण की क्षमताएँ :

आवेदकों का बालकों की देखरेख एवं कार्यकरण संबंधी अनुभव।
माता-पिता के साथ उनके सामंजस्य का वर्णन करें। बालकों का विकास करने में उनकी समझ क्या है, स्वयं के बचपन के अनुभवों का प्रयोग करते हुए वे कौन से पालन-पोषण की पद्धति दोहराएंगे तथा वे क्या परिवर्तन करेंगे व्यक्ति विशेष बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की पालन-पोषण की संभावनाओं तथा स्वयं के पालन-पोषण के

कौशलों के बारे में उनकी समझ क्या है। वे अपने बालकों/स्थापन बालकों के पालन-पोषण में परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग की कितनी अपेक्षा करते हैं। वे किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बालक अपने परिवार में तथा और अधिक व्यापक सहायता नेटवर्कों के भीतर शारीरिक यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहेगा।

8. प्रतिकूल व्यवहार को संभालने का तरीका :

घर में क्या नियम है आवेदक कैसे अनुमोदन/अननुमोदन दिखाते हैं उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अनुशासनात्मक उपाय क्या है। दण्ड के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है भावी मुद्दों एवं कठिनाईयों और अपने स्वयं के बालकों के प्रति तथा अपने सहायता नेटवर्क के लिए उनकी प्रत्याशा क्या है। वे बालकों के लिए भावी मुद्दों एवं कठिनाईयों का क्या पूर्वानुमान लगाते हैं। वे अपनी जीवन शैलीकी आगामी जरूरत के लिए परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाते हैं।

9. सामाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन :

पत्र के माध्यम से एकत्रित समस्त सूचना का विश्लेषण तथा पालन-पोषण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की क्षमता के बारे में इसकी महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। (आवेदकों के पास बालकों से संबंधित तथा बालकों के साथ कार्यकरण का कौन सा कौशल है आवेदक अभिकरण में तथा जन्म देने वाले माता-पिताओं के साथ कितनी अच्छी तरह से कार्य करेंगे। आवेदकों की संख्या तथा संसाधन क्या है तथा वो कौन सा क्षेत्र है जहां उन्हें कठिनाई महसूस हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदकों के बीच असहमति का बिंदु भी यहां अभिलिखित किया जाना चाहिए।

10. बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिशें

.....

.....

.....

.....

प्रपत्र -XVII

{ नियम 34 (1) }

पालन-पोषण संबंधी देखभाल का स्थापन का आदेश

श्री तथा श्रीमती अथवा सुश्री का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग है, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है।

..... संगठन के बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री/श्री की गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन-पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों की घोषणा की जाती है।

..... (नाम तथा संपर्क नं 1) उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में (दिनों/मासों) की अवधि के लिए बालक (नाम) का पालन पोषण देखभाल गृह में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र -XVIII

{ नियम 37 (5) }

प्रायोजक के स्थापन का आदेश

श्री तथा श्रीमती अथवा सुश्री का/की पुत्र अथवा पुत्री किशोर/बालक (नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग है, को राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तत्काल देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद जोखिम में रहे किशोर/बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि उक्त किशोर/बालक को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत है। उक्त की प्रायोजक सहायता के रूप में रुपये प्रतिमास (रूपए) निर्मुक्त करने के लिए राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को निदेश दिया जाता है। प्रायोजक सहायता तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के लिए भी राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को निदेश दिया जाता है।

मुख्य मजिस्ट्रेट
किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/
सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रति :

राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग।

प्रपत्र -XIX
 { नियम 38 (3) }
 उत्तररक्षा स्थापन का आदेश

किशोर/बालक (नाम) पुत्र अथवा पुत्री तारीख को 18 वर्ष की आयु का हो गया है/होने जा रहा है। उसे पुनर्वास तथा पुनः मुख्यधारा में सम्मिलित होने के उद्देश्य के लिए देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है। उसे उत्तररक्षा प्रदान करने के लिए (संगठन का नाम) के सुपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि वह बालक को प्रवेश दे तथा उसे पुनर्वास और पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यथार्थ रूप से सभी सम्भव अवसर प्रदान करे। इस व्यक्ति को अधिकतम केवल 21 वर्ष की आयु होने तक अथवा समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने तक, जो भी पहले हो, ये सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे। संगठन का प्रभारी, बाल कल्याण समिति को बालक या युवक की स्थिति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

..... (दिन/मास) अवधि तक तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए उक्त किशोर/बालक हेतु उत्तररक्षा का प्रबंध करने के लिए राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को निदेश दिया जाता है। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को उत्तररक्षा कार्यक्रम तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने का भी निदेश दिया जाता है।

मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/
 अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रति : राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग।

प्रपत्र -XX

नियम 50 (9), 54 (1) (न).

देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र

मामला/प्रोफाइल सं.

तारीख एवं समय

यहां
नवीनतम
फोटो
चिपकाएँ

(क) व्यक्तिगत आँकड़े

1. नाम
2. लिंग पुरुष/महिला (उचित वर्ग पर सही का निशान लगाएँ)
3. (क) भर्ती के समय आयु
(ख) वर्तमान आयु
4. प्रवर्ग
 - परिवार से अलग किया गया
 - परित्यक्त/अभित्यक्त
 - उत्पीड़न और हिंसा का शिकार (ब्यौरा दें)
 - भागा हुआ
 - कोई अन्य
5. धर्म

हिन्दू (अन्य जाति/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) मुस्लिम/इसाई/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
शहरी/अर्द्धशहरी/ग्रामीण/मलिन बस्ती/
औद्योगिक क्षेत्र अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
6. निवास अवस्थिति
7. मूल जिला और राज्य
8. आवास विवरण
 - (i) पक्का भवन/खपरैल का मकान/झोपड़ी/गली/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (ii) तीन शयनकक्ष/दो शयन कक्ष/एक शयन कक्ष/कोई पृथक शयन कक्ष नहीं
 - (iii) निजी/किराए पर
9. बाल कल्याण समिति के समक्ष किशोर को कौन लाया :
 - (i) पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/रेल्वे पुलिस/महिला पुलिस
 - (ii) परिवीक्षा अधिकारी
 - (iii) समाज कल्याण संगठन
 - (iv) सामाजिक कार्यकर्ता
 - (v) माता-पिता/अभिभावक (कृपया नातेदारी विनिर्दिष्ट करें)
 - (vi) शिशु स्वयं (लड़का/लड़की)
10. परिवार छोड़ने के कारण :
 - (i) माता-पिता/अभिभावक (कों) सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्यवहार

- (ii) रोजगार की खोज
 - (iii) मित्र मंडली के प्रभाव के कारण
 - (iv) माता-पिता की असमर्थता
 - (v) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
 - (vi) माता-पिता का अलगाव
 - (vii) माता-पिता की मृत्यु
 - (viii) गरीबी
 - (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
11. बालक के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार :
- (i) मौखिक दुर्व्यवहार— माता पिता/सहोदर भाई या बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
 - (ii) शारीरिक दुर्व्यवहार
 - (iii) यौन दुराचार—माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (iv) अन्य माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
12. बालक के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार :
- (i) भोजन न देना माता पिता/सहोदर भाई या बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
 - (ii) निर्दयतापूर्वक पीटा गया—माता पिता/सहोदर भाई या बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
 - (iii) चोट पहुंचाना—माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (iv) अन्य—माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
13. बालक का शोषण :
- (i) बिना वेतन दिए काम करना
 - (ii) न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम लेना
 - (iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
14. प्रवेश होने से पूर्व बालक के स्वास्थ्य की स्थिति :
- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (i) श्वसन संबंधी व्यतिक्रम | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (ii) बहरापन | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (iii) नेत्र रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (iv) दंत रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (v) हृदय रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (vi) चर्म रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (vii) यौन संक्रमित रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (viii) तंत्रिका संबंधी रोग | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |
| (ix) मानसिक विकलांगता | — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया |

- (x) शारीरिक विकलांगता — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 (xi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
15. बालक भर्ती होने से पूर्व किसके साथ रहता था :
- माता-पिता —माता/पिता/दोनों
 - अभिभावक-नातेदारी
 - मित्र
 - बेसहारा
 - रात्रिकालीन आश्रय गृह
 - अनाथालय/होस्टल/ऐसे अन्य गृह
 - अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
16. बालक से मिलने हेतु माता-पिता का आगमन :
- संस्थानीकरण से पूर्व —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/कभी नहीं
 - संस्थानीकरण के बाद —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/कभी नहीं
17. बालक का अपने परिवार में जाना :
- संस्थानीकरण से पूर्व —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/त्यौहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
 - संस्थानीकरण के बाद —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/त्यौहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
18. माता-पिता के साथ पत्र व्यवहार :
- संस्थानीकरण से पूर्व —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/त्यौहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
 - संस्थानीकरण के बाद —
बार-बार/अनियमित रूप से/कभी-कभी/त्यौहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं

(ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक)

19. गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन :
- पौष्टिक भोजन
 - सामान्य भोजन
 - अपर्याप्त भोजन

20. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य :

- संक्रामक रोग से संक्रमित मां

- II. मां द्वारा गर्भ निरोधक का प्रयोग
 III. एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक) दवाओं का सेवन
 IV. ऐसा कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं

21. जन्म का ब्यौरा :

- I. सामान्य प्रसव/दीर्घकालीन प्रसव/शल्य क्रिया द्वारा प्रसव
 II. कम वजन/सामान्य वजन/अधिक वजन

22. प्रतिरक्षण संबंधी ब्यौरा :

23. विकलांगता संबंधी ब्यौरा :

- I. बहरापन -जन्मजात/दुर्घटनावश/बीमारीवश
 II. गूंगापन -जन्मजात/दुर्घटनावश/बीमारीवश
 III. शारीरिक विकलांगता -जन्मजात/दुर्घटनावश/बीमारीवश
 IV. मानसिक विकलांगता -जन्मजात/दुर्घटनावश/बीमारीवश
 V. अन्य विकलांगता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ग) परिवार के ब्यौरे :

24. घरेलू संरचना :

क्र. सं.	नाम व संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय
1	2	3	4	5	6	7
स्वास्थ्य	मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत्त	विकलांगता	आदत	समाजीकरण		
8	9	10	11	12		

25. परिवार किस प्रकार का है :

एकल परिवार/संयुक्त परिवार/विश्रंखलित परिवार

26. परिवार के सदस्य के बीच संबंध

- I. माता-पिता -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
 II. पिता-बालक -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
 III. माता-बालक -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
 IV. पिता-सहोदर -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
 V. माता-सहोदर -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
 VI. किशोर-सहोदर -सौहार्द्रपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

27. परिवार के सदस्यों द्वारा कारित अपराध का पूर्ववृत्त :

क्र. सं.	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	की गई गिरफ्तारी, यदि हुई है	परिरोध की अवधि	दिया गया दण्ड
1	पिता				
2	सौतेला पिता				
3	माता				
4	सौतेली माता				
5	भाई (क) (ख) (ग) (घ)				
6	बहन (क) (ख) (ग) (घ)				
7	बालक				
8	अन्य (चाचा/चाची/दादा/दादी)				

परिवार

28. परिवार के नाम सम्पत्तियों का ब्यौरा :

- अचल सम्पत्ति (भू-सम्पत्ति) (कृपया क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें)
- घरेलू सामग्री/सम्पत्ति (गायें/मवेशी/सांड)
- वाहन-दुपहिया/तिपहिया/चार पहिया/(लारी/बस/कार/ट्रैक्स/जीप)
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

29. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति :

- माता-पिता-माता-पिता द्वारा तय विवाह/विशेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप
- भाई- तय विवाह/विशेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप
- बहनें - तय विवाह/विशेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप

30. परिवार के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियां

- सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेना
- सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना

III. सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेना

IV. अज्ञात

31. भर्ती से पूर्व माता-पिता द्वारा किशोर की देखरेख :

- I. अति संरक्षण
- II. स्नेहपूर्वक
- III. सतर्कता पूर्वक
- IV. उपेक्षा पूर्वक
- V. लापरवाही पूर्वक
- VI. तिरस्कार पूर्वक

(घ) किशोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) :

32.

- I. यौवनागम
- II. यौवनागम पूर्व
- III. यौवनागम मध्य
- IV. यौवनागम पश्चात्

33. आपराधिक आचरण का ब्यौरा, यदि कोई हो :

- I. चोरी
- II. जेब-तराशी
- III. ताड़ी बेचना
- IV. नशीली दवाईयां बेचना
- V. छोटे-मोटे अपराध
- VI. हिंसक अपराध
- VII. बलात्कार
- VIII. उपर्युक्त में से कोई नहीं
- IX. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

34. आपराधिक आचरण के कारण :

- I. माता-पिता की उपेक्षा
- II. माता-पिता का अति संरक्षण
- III. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
- IV. माता-पिता का प्रभाव
- V. संगी-साथियों का प्रभाव
- VI. नशीली दवाईयां/शराब खरीदना
- VII. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

35. आदतें

(क)

- I. धूम्रपान
- II. मद्यपान
- III. नशीली दवाओं का सेवन करना
(विनिर्दिष्ट करें)
- IV. जुआ खेलना
- V. भिक्षा मांगना

(ख)

दूरदर्शन / सिनेमा देखना
इंडोर/आउटडोर खेल खेलना
पुस्तकें पढ़ना
धार्मिक गतिविधियां
आरेखण/रंगसाजी/अभिनय/गायन

VI. अन्य

कोई अन्य

(ड) रोजगार का विवरण :

क्र. सं.	रोजगार के ब्यौरे	अवधि	कमाई गई मजदूरी
1	कुली		
2	रददी (कबाड़) बीनना		
3	मैकेनिक		
4	होटल कार्य		
5	चाय की दुकान में कार्य		
6	जूता पालिश		
7	घरेलू कार्य		
8	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

36. आय के उपयोग के ब्यौरे :

- I. परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु परिवार में भेजना
- II. कपड़े बनवाने के लिए
- III. जुआ खेलने के लिए
- IV. वेश्यावृत्ति के लिए
- V. शराब के लिए
- VI. नशे के लिए
- VII. धूम्रपान के लिए
- VIII. बचत करने के लिए

37. बचत के ब्यौरे

- I. नियोक्ता के माध्यम से
- II. मित्रों के माध्यम से
- III. बैंक/डाकघर
- IV. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

38. कार्य समय की अवधि :

- I. छः घण्टे से कम
- II. छः से आठ घण्टे के बीच
- III. आठ घण्टे से अधिक

(च) शैक्षणिक विवरण :

39. बालगृह में भर्ती होने से पूर्व किशोर का शैक्षणिक ब्यौरा

- i. अशिक्षित
- ii. पांचवी कक्षा तक अनुभव
- iii. पांचवी से अधिक परंतु आठवीं से कम अध्ययन
- iv. आठवीं से अधिक परंतु दसवीं से कम अध्ययन
- v. दसवीं से अधिक अध्ययन

40. विद्यालय छोड़ने का कारण :

- i. अंतिम बार अध्ययनरत कक्षा में अनुत्तीर्ण होना
- ii. विद्यालयों के क्रियाकलापों में रुचि की कमी
- iii. शिक्षकों का उदासीन रुझान
- iv. संगी साथियों का प्रभाव
- v. परिवार के लिए अर्जन तथा समर्थन
- vi. माता-पिता की अचानक मृत्यु
- vii. विद्यालय का सख्त माहौल
- viii. विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थिति
- ix. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

41. उस विद्यालय का ब्यौरा जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की :

- i. निगम/नगर निगम/पंचायत यूनियन
- ii. सरकारी /अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय/पिछड़ी जाति कल्याण विद्यालय
- iii. निजी प्रबंधन
- iv. कान्वेंट

42. शिक्षा का माध्यम

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड़/तेलगू/अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

43. बाल गृह में प्रवेश के बाद आगमन की तिथि से अब तक प्राप्त शिक्षा :

वर्ष संख्या कक्षा, जिसमें अध्ययन किया था प्रोन्नत/स्थगित

44. बाल गृह में आगमन की तारीख से अब तक प्राप्त किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण :

वर्ष संख्या व्यावसायिक ट्रेड का नाम प्राप्त प्रवीणता :

45. बाल गृह में आगमन की तारीख से अब तक विकसित पाठ्यक्रमेत्तर कार्यकलाप

- i. स्काउट
- ii. खेलकूद (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- iii. व्यायाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- iv. चित्रकला
- v. पेंटिंग
- vi. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(छ) चिकित्सीय इतिवृत्त :

46. प्रवेश के समय लंबाई और वजन
47. शारीरिक स्थिति
48. बालक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)
49. माता-पिता/अभिभावक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)
50. बालक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक प्रेक्षण	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
1	पुनर्विलोकन की तारीख				

2	लंबाई				
3	वजन				
4	दिया गया पौष्टिक आहार				
5	तनावजनित बीमारी				
6	दंत रोग				
7	नाक, कान और गला-टांसिल				
8	बाह्य नेत्र				
9	समस्याएं बायीं आंख दायीं आंख				

51. लंबाई और वजन का चार्ट

तारीख, मास व वर्ष	लम्बाई	स्वीकार्य वजन	वास्तविक वजन

(ज) सामाजिक इतिवृत्त :

52. बालगृह में प्रवेश से पूर्व मित्रों का ब्यौरा :

- सहकर्मी
- विद्यालय में सहपाठी
- पड़ोसी
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

53. अधिकतर मित्र :

- शिक्षित हैं
- अशिक्षित हैं
- हमउम्र हैं
- आयु में बड़े हैं
- आयु में छोटे हैं
- उसी लिंग के हैं
- विपरीत लिंग के हैं

54. समूह सदस्यता का ब्यौरा (कृपया सविस्तार विनिर्दिष्ट करें) :

- सिने प्रशंसक संगम से सहबद्ध हैं
- धार्मिक समूह से सहबद्ध हैं
- कला एवं खेलकूद क्लब से सहबद्ध हैं
- गिरोहों से सहबद्ध हैं

- v. स्वैच्छिक सामाजिक सेवा लीग से सहबद्ध हैं
- vi. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 55. समूहों/लीग में बालकों का स्थान :
 - i. अगुवा
 - ii. दायम स्तरीय अगुवा
 - iii. मध्यस्तरीय कार्यकर्ता
 - iv. सामान्य सदस्य
- 56. समूह की सदस्यता लेने का प्रयोजन :
 - i. सामाजिक सेवा क्रियाकलाप के लिए
 - ii. खाली समय व्यतीत करना
 - iii. सुखदायक क्रियाकलाप
 - iv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 57. समूह/लीग का नजरिया :
 - i. सामाजिक मानदण्डों का सम्मान तथा नियमों का पालन
 - ii. मानदण्डों के उल्लंघन में रुचि
 - iii. नियमों के उल्लंघन में प्रेरक
- 58. समूहों की अवस्थिति/बैठक स्थल :
 - i. सामान्यतः नियत स्थान
 - ii. बार-बार परिवर्तित स्थान
 - iii. कोई विशेष स्थान नहीं
 - iv. सुविधानुसार मिलने का नियत स्थान
- 59. बालक के पहली बार परिवार से आने पर समाज की प्रतिक्रिया:
 - i. समर्थनकारी
 - ii. तिरस्कार
 - iii. प्रताड़ना
 - iv. दुर्व्यवहारपूर्ण
 - v. शोषणपरक
- 60. बालकों के प्रति पुलिस का रवैया :
 - i. भावपूर्ण
 - ii. क्रूरतापूर्वक
 - iii. प्रताड़नापूर्वक
 - iv. शोषण का और
 - v. दुर्व्यवहारपूर्ण
- 61. बालकों के प्रति साधारण जनता की प्रतिक्रिया :
 - बालक का इतिवृत्त (संक्षेप में)
 - i. शिक्षा
 - ii. स्वास्थ्य
 - iii. व्यावसायिक प्रशिक्षण
 - iv. पाठ्यक्रमेत्तर कार्यकलाप
 - v. अन्य

किशोर/बालक के अधिविन्यास के बाद बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का सुझाव तथा अभिविन्यास पर प्रतिक्रिया।

बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही।

प्रबंधन समिति द्वारा व्यक्ति वृत्त का तिमाही पुनर्विलोकन।

प्रपत्र -XXI

{ नियम 50 (12) (क), 54 (ण), 87 (1) (ट) }

व्यक्तिगत देखरेख योजना

प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना बालक के अधिकतम हित के सिद्धांत पर बनायी जाएगी। व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाते समय देखरेख संबंधी विकल्पों को निम्नलिखित क्रम में वरीयता देने पर विचार किया जाएगा :

- i. जन्मदाता परिवार का संरक्षण
- ii. रक्त-संबंधियों द्वारा देखरेख
- iii. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण
- iv. पालन-पोषण देखरेखकर्ता
- v. अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण
- vi. संस्थानिक देखरेख

बोर्ड/समिति का वर्ष 20 का मामला/प्रोफाईल सं.

प्रवेश संख्या

प्रवेश की तारीख

क. व्यक्तिगत ब्यौरे

1. बालक का नाम
2. आयु
3. लिंग : पुरुष/महिला
4. पिता/माता का नाम
5. राष्ट्रीयता
6. धर्म/जाति
7. शैक्षणिक उपलब्धि
8. मामले के इतिवृत्त का सारांश :

- स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें
- भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समर्थन संबंधी जरूरतें
- शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें
- अवकाश, रचनात्मकता तथा खेलकूद
- संबंध एवं नातेदारी
- धार्मिक विश्वास
- सभी प्रकार के उत्पीड़न, तिरस्कार एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण
- समाज की मुख्य धारा में लाना

● बालगृह से रिहा किए जाने/प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्ती कार्यवाही
ख. परिवीक्षार्थी की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

भाग 1

1. परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर का नाम :
2. मास के
3. पंजीकरण सं. :
4. सक्षम प्राधिकारी
5. प्रोफईल सं. :
6. बालक का नाम :
7. पर्यवेक्षण आदेश की तारीख :
8. बालक का पता :
9. पर्यवेक्षण की अवधि :

भाग 2

साक्षात्कार स्थल

.....
.....
.....

तारीखें

.....
.....
.....

1. बालक कहाँ रहा है
2. किसी शैक्षणिक / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रगति
3. वह क्या कर रहा/रही है तथा यदि कहीं नियुक्त है तो उसका औसत मासिक अर्जन
4. डाकघर में की गई बचतें
5. उसके नाम के बचत बैंक खाता
6. उसके सामान्य आचरण एवं प्रगति पर टिप्पणियाँ
7. क्या समुचित रूप से देखभाल की गई है

भाग 3

1. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही या :
क. बंधपत्र की शर्तों में अंतर
ख. निवास स्थान में परिवर्तन
ग. अन्य मामले
2. तारीख को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि
3. टिप्पणियों सहित पर्यवेक्षण का परिणाम (यदि कोई हो)
4. माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति का नाम व पता, जिसके साथ किशोर को पर्यवेक्षण के बाद रहना है।

परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर के हस्ताक्षर

रिपोर्ट की तारीख

ग. रिहाई से पूर्व रिपोर्ट

जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं

अंतिम रिहाई

स्थानांतरण

1. स्थानांतरण के स्थान का ब्यौरा तथा स्थानांतरण/रिहाई के स्थान के उत्तरदायी सम्बद्ध प्राधिकारी
 2. किशोर/बालक को दूसरी संस्थाओं में भेजने संबंधी ब्यौरे
 3. चालू प्रशिक्षण एवं अर्जित कौशल
 4. प्रभारी अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केसवर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए)
 5. रिहाई/स्थानांतरण की तारीख
 6. संप्रत्यावर्तन की तारीख
 7. मार्गरक्षी की माँग, यदि अपेक्षित हो।
 8. मार्गरक्षी की पहचान
 9. संभावित स्थान सहित सिफारिश की गई पुनर्वास योजना
 10. प्रायोजित किए जाने की अपेक्षाएं और रिपोर्ट, यदि लागू हों।
 11. रिहाई के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही हेतु परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन की पहचान।
 12. रिहाई के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही हेतु पहचाने गए गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन।
 13. बालक की रिहाई के बाद उसको प्रायोजित करने वाले अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक, यदि कोई हो, की पहचान।
 14. प्रायोजित करने वाले अभिकरण और व्यक्ति के बीच समझौता ज्ञापन
 15. बालक के बचत खाते का विस्तृत ब्यौरा, यदि कोई हो
 16. बालक की कमाई तथा सामान, यदि कोई हो, का ब्यौरा
 17. बालक को मिले पुरस्कार का ब्यौरा, यदि कोई हो
 18. बालक की राय
 19. कोई अन्य सूचना
- टिप्पणा : रिहाई पूर्व रिपोर्ट किशोर/बालक की रिहाई/स्थानांतरण की तारीख से 6 मास पूर्व तैयार की जाएगी तथा अंतिम पुनर्विलोकन रिपोर्ट की सिफारिशों और अन्य सभी सुसंगत जानकारी पर ध्यान दिया जाएगा।

घ. रिहाई के पश्चात रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/स्थानांतरित
2. बालक की कमाई तथा सामान : बालक को दिया गया या उसके माता-पिता/अभिभावकों को दिया गया हाँ/नहीं
3. रिहाई के बाद बालक के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही हेतु पहचाने गए परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन के प्रथम विचार-विमर्श की रिपोर्ट
4. किशोर/बालक का स्थानन, यदि कोई हो
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ोसियों/समुदाय का दृष्टिकोण
7. बालक अर्जित कौशलों का उपयोग कर रहा है
8. क्या बालक को किसी विद्यालय या व्यावसायिक संस्था में भर्ती कराया गया है विद्यालय/संस्था/अन्य किसी अभिकरण का नाम व भर्ती की तारीख दें।
9. बालक के बारे में दूसरी व तीसरी अनुवर्ती कमश: दो, छह मास के बाद प्रस्तुत करें।

प्रपत्र -XXII

{ नियम 65 (2) }

मार्गरक्षण आदेश

मामला सं.

बालक/बालिका के मामले में

.....
 उम्र लगभग वर्ष को किशोर न्याय
 (बालकों की देखरेख और संरक्षण)
 अधिनियम 2000 की धारा 33 (2) के
 तहत एकमात्र अभिरक्षा में भेजने हेतु
 कार्यवाही की गई।

बालक/बालिका के माता-पिता को स्थान पर रहने की रिपोर्ट दे दी गई है। समुचित पुलिस/गैर-सरकारी संगठन मार्गरक्षा के अधीक्षण के अधीन बालक/बालिका को को भेजा जाए।

अतः उपर्युक्त बालक/बालिका के माता-पिता या निकट नातेदारों का पता लगाने हेतु बालक को उन्हें सौंपने के लिए बालक द्वारा दर्शाए गए उनके निवास स्थान के पते पर पुलिस की उचित निगरानी/गैर-सरकारी संगठन के मार्गरक्षण में उन्हें भेज दिया जाए। यदि माता-पिता या नातेदार का पता नहीं चलता है या पता तो चलता है लेकिन वे बालक/बालिका को बालगृह के अधीक्षक की अभिरक्षा में सौंपने के इच्छुक नहीं हैं तो उन्हें अग्रिम आदेश के लिए संबद्ध बाल कल्याण समिति के समक्ष हाजिर करेंगे।

आदेश

मार्गरक्षण की व्यवस्था होने तक उक्त बालक/बालिका बालगृह में रहेंगे, जो वर्तमान में पते पर रह रहे हैं। राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस विभाग या गैर-सरकारी संगठन/चाइल्ड लाइन इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से तत्काल व्यवस्था करेगा तथा उपर्युक्त बालक/बालिका को उपर्युक्त निवास के स्थान पर भेज देगा।

तारीख मास वर्ष

अध्यक्ष/सदस्य
 बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि प्रेषित :

2. अधीक्षक बालगृह

3. राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/गैर-सरकारी संगठन/चाइल्ड लाइन

संदर्भ : 1. अवयस्क का भर्ती आदेश जन्मतिथि

प्रोफाइल

Bhopal, the 28th December 2015

No. F 3-9/2015/50-2 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**-In this rules, unless the context otherwise requires.-
 - (1) (a) "abandoned" means an unaccompanied and deserted child who is declared abandoned by the Committee after due inquiry;
 - (b) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) as amended by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment, Act, 2006 (33 of 2006) and Amendment Act, 2011 (No. 12 of 2011);
 - (c) "best interest of the child" means a decision taken to ensure the physical, emotional, intellectual, social and moral development of juvenile or child;
 - (d) "child friendly" means any process and interpretation, attitude, environment and treatment, that is humane, considerate and in the best interest of the child;
 - (e) "child with special need" means the child with special needs will be such a child for whom specialised services or interventions are necessary to facilitate proper care and rehabilitation;

- (f) "community service" implies service rendered to the society by juveniles in conflict with law in lieu of other judicial remedies and penalties, which is not degrading and dehumanizing.
- Examples of this may include:
- (i) Cleaning a park;
 - (ii) Getting involved with Habitat for Humanity;
 - (iii) Serving the elderly in nursing homes;
 - (iv) Helping out a local fire or police department;
 - (v) Helping out at a local hospital or nursing home; and
 - (vi) Serving disabled children.
- (g) "detention" in case of juveniles in conflict with law means "protective custody" in line with the principles of restorative justice;
- (h) "extended family" means relative of the child with whom he can be placed in foster care;
- (i) "Form" means the form attached to these rules;
- (j) "Foster care" means placement of a child with a nuclear family or group foster home;
- (k) "Foster child" means a child placed with a foster parent or foster family;
- (l) "Foster parent's" means the persons who is not the parent's of the child but is willing to undertake the responsibility for care and maintenance of the child as his parent's without necessarily legal rights of the property etc;
- (m) "Group Foster Care" means care of a group of children in one family or a group foster home run by an Non-Government Organisation;
- (n) "individual care plan" is a comprehensive development plan for a juvenile or child based on age specific and gender specific needs and the case history of the juvenile or child, prepared in consultation with the juvenile or child, in order to restore the juvenile's or child's self-esteem, dignity and self-worth and nature him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following needs of a juvenile or a child:
- (i) Health needs;
 - (ii) Emotional and psychological needs;

- (iii) Educational and training needs;
 - (iv) Leisure, creativity and play;
 - (v) Attachments and relationships;
 - (vi) Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
 - (vii) Social mainstreaming; and
 - (viii) Follow-up post release and restoration.
- (o) "institution" means an observation home, or a special home, or a children's home or a shelter home set up, certified or recognized and registered under section 8, 9, 34, sub-section (3) of section 34 and section 37 of the Act respectively;
- (p) "Officer-in-charge" or such other nomenclature as issued by the State Government, means a person appointed for the control and management of the institution;
- (q) "orphan" means a child who is without parents or willing and capable legal or natural guardian;
- (r) "place of safety" means any institution set up and recognized under sub-section (3) of section 12 and sub-section (1) of section 16 of the Act for juvenile in conflict with law or children;
- (s) "Pre adoptive foster care" means placement of a child in a family temporarily till the child can be rehabilitated in a permanent home;
- (t) "recognised" means a person found fit by the competent authority or, an institution found fit by the State Government on the recommendation of the competent authority as per clauses (h) and (i) of section 2 of the Act; or, recognition of an institution or agency or voluntary organisation by the State Government to operate as a children's home, observation home and special home; or a shelter home, specialised adoption agency or after care organization under sub-section (1) of section 37, sub-section (4) of section 41 and clause (a) of section 44 of the Act;
- (u) "registered" means all institutions or agencies or voluntary organisations providing residential care to children in need of care and protection registered under sub-section(3) of section 34;
- (v) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (w) "Street and working children" means children without ostensible means of livelihood, care, protection and support in accordance with the provisions laid down under clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
- (x) "surrendered child" means a child, who in the opinion of the Committee, is relinquished on account of physical, emotional and social factors beyond the control of the parent or guardian;
- (y) "Take responsibility" means being responsible for the physical, mental, emotional and overall health and safety of the child;
- (2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II**FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF JUVENILE JUSTICE AND PROTECTION OF CHILDREN****3. Fundamental principles to be followed in administration of these rules.-(1)**

The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee or other competent authorities or agencies, as the case may be, while implementing the provisions of these rules shall abide and be guided by the principles, specified in sub-rule(2)

(2) The following principles shall, interalia, be fundamental to the application, interpretation and implementation of the Act and the rules made hereunder:

I. Principle of presumption of innocence:

- (a) A juvenile or child or juvenile in conflict with law is presumed to be innocent of any malafide or criminal intent up to the age of eighteen year.
- (b) The juvenile's or juvenile's in conflict with law or child's right to presumption of innocence shall be respected throughout the process of justice and protection, from the initial contact to alternative care, including aftercare.
- (c) Any unlawful conduct of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law which is done for survival, or is due to environmental or situational factors or is done under control of adults, or peer groups, is ought to be covered by the principles of innocence.
- (d) The basic components of presumption of innocence are:-

(i) Age of innocence

Age of innocence is the age below which a juvenile or child or a juvenile in conflict with law cannot be subjected to the criminal justice system. The Beijing Rule 4(1) clearly lays down that "the beginning of the age of

criminal responsibility shall not be fixed at too low an age level bearing in mind the facts of mental and intellectual maturity". In consonance with this principle, the mental and intellectual maturity of juvenile or child or a juvenile in conflict with law below eighteen years is considered insufficient throughout the world.

(ii) Procedural protection of innocence

All procedural safeguards that are guaranteed by the Constitution and other statutes to the adults and that go in to strengthen the juvenile's child's right to presumption of innocence shall be guaranteed to juveniles or the children or juveniles in conflict with law.

(iii) Provisions of Legal aid and Guardian Ad Litem

Juveniles in conflict with law have a right to be informed about the accusations against them and a right to be legally represented. Provisions must be made for guardian ad litem, legal aid and other such assistance through legal services at State expense. This shall also include such juveniles right to present his own case before the competent authority.

II Principle of dignity and worth:

- (a) Treatment that is consistent with the child's sense of dignity and worth is a fundamental principle of juvenile justice. This principle reflects the fundamental human right enshrined in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Respect of dignity includes not being humiliated, personal identity, boundaries and space being respected, not being labelled and stigmatized, being offered information and choices and not being blamed for their acts.
- (b) The juvenile's or child's right to dignity and worth has to be respected and protected throughout the entire process of dealing with the child from the first contact with law enforcement agencies to the implementation of all measures for dealing with the child.

III. Principle of Right to be heard:

Every child's right to express his views freely in all matters affecting his interest shall be fully respected through every stage in the process of juvenile justice. Children's right to be heard shall include creation of developmentally appropriate tools and

processes of interacting with the child, promoting children's active involvement in decisions regarding their own lives and providing opportunities for discussion and debate.

IV. Principle of Best Interest:

- (a) In all decisions taken within the context of administration of juvenile justice, the principle of best interest of the juvenile or the juvenile in conflict with law or child shall be the primary consideration.
- (b) The principle of best interest of the juvenile or juvenile in conflict with law or child shall mean for instance that the traditional objectives of criminal justice, retribution and repression, must give way to rehabilitative and restorative objectives of juvenile justice.
- (c) This principle seeks to ensure physical, emotional, intellectual, social and moral development of a juvenile in conflict with law or child so as to ensure the safety, well being and permanence for each child and thus enable each child to survive and reach his full potential.

V. Principle of family responsibility:

- (a) The primary responsibility of bringing up children, providing care, support and protection shall be with the biological parents. However, in exceptional situations, this responsibility may be bestowed on willing adoptive or foster parents.
- (b) All decision making for the child should involve the family of origin unless it is not in the best interest of the child to do so.
- (c) The family- biological, adoptive or foster (in that order), must be held responsible and provide necessary care, support and protection to the juvenile or child under their care and custody under the Act, unless the best interest measures or mandates dictate otherwise.

VI. Principle of Safety (no harm, no abuse, no neglect, no exploitation and no maltreatment):

- (a) At all stages, from the initial contact till such time he remains in contact with the care and protection system, and thereafter, the juvenile or child or juvenile in conflict with law shall not be subjected to any harm, neglect, maltreatment, corporal punishment or solitary or otherwise any confinement in jails and extreme care shall be taken to avoid any harm to the sensitivity of the juvenile or the child.

- (b) The state has a greater responsibility for ensuring safety of every child in its care and protection, without resorting to restrictive measures and processes in the name of care and protection.

VII. Positive measures:

- (a) Provisions must be made to enable positive measures that involve the full mobilization of all possible resources, including the family, volunteers and other community groups, as well as schools and other mainstream community institutions or processes, for the purpose of promoting the well-being of the juvenile or child through individual care plans carefully worked out.
- (b) The positive measures shall aim at reducing vulnerabilities and reducing the need for intervention under the law, as well as effective, fair and humane dealing of the juvenile or child.
- (c) The positive measures shall include avenues for health, education, relationships, livelihoods, leisure, creativity and play.
- (d) Such positive measures must facilitate the development of identity for the child and provide them with an inclusive and enabling environment.

VIII. Principle of non-stigmatizing semantics, decisions and actions:

The non-stigmatizing semantics of the Act must be strictly adhered to, and the use of adversarial or accusatory words, such as, arrest, remand, accused, charge sheet, trial, prosecution, warrant, summons, conviction, inmate, delinquent, neglected, custody or jail is prohibited in the processes pertaining to the child or juvenile in conflict with law under the Act.

IX. Principle of non-waiver of rights:

- (a) No waiver of rights of the child or juvenile in conflict with law, whether by himself or the competent authority or anyone acting or claiming to act on behalf of the juvenile or child, is either permissible or valid.
- (b) Non-exercise of a fundamental right does not amount to waiver.

X. Principle of equality and non-discrimination:

- (a) There shall be no discrimination against a child or juvenile in conflict with law on the basis of age, sex, place of birth, disability, health, status, race, ethnicity, religion, caste, cultural practices, work, activity or behaviour of the juvenile or child or that of his parents or guardians, or the civil and political status of the juvenile or child.

- (b) Equality of access, equality of opportunity, equality in treatment under the Act shall be guaranteed to every child or juvenile in conflict with law.

XI. Principle of right to privacy and confidentiality:

The juvenile's or child's right to privacy and confidentiality shall be protected by all means and through all the stages of the proceedings and care and protection processes.

XII. Principle of last resort:

Institutionalization of a child or juvenile in conflict with law shall be a step of the last resort after reasonable inquiry and that too for the minimum possible duration.

XIII. Principle of repatriation and restoration:

- (a) Every juvenile or child or juvenile in conflict with law has the right to be reunited with his family and restored back to the same socio-economic and cultural status that such juvenile or child enjoyed before coming within the purview of the Act or becoming vulnerable to any form of neglect, abuse or exploitation.
- (b) Any juvenile or child, who has lost contact with his family, shall be eligible for protection under the Act and shall be repatriated and restored, at the earliest, to his family, unless such repatriation and restoration is likely to be against the best interest of the juvenile or the child.

XIV. Principle of Fresh Start:

- (a) The principle of fresh start promotes new beginning for the child or juvenile in conflict with law by ensuring erasure of his past records.
- (b) The State shall seek to promote measures for dealing with children alleged or recognized as having impinged the penal law, without resorting to judicial proceedings.

CHAPTER - III

JUVENILE IN CONFLICT WITH LAW

4. Juvenile Justice Boards.— There shall be one or more Juvenile Justice Boards in every district, which shall be constituted by the State Government as per section 4 of the Act.

5. Composition of the Juvenile Justice Board.— (1) The Board shall consist of a Judicial Magistrate of the first class, and two social workers of whom at least one shall be a woman, forming a bench:

Provided that the Judicial Magistrate of the Board shall review the pendency of cases before the Board and take such steps, as may be necessary in the expeditious disposal of the cases.

(2) Every such bench shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).

(3) (i) A Magistrate with special knowledge or training in child psychology or child welfare shall be designated as the Judicial Magistrate of the Board.

(ii) In case the Judicial Magistrate with such special knowledge or training is not available, then, the State Government shall provide for such short-term training in child psychology or child welfare as it considers necessary.

(4) The two social workers, of whom at least one shall be a woman, shall be appointed by the State Government.

(5) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, national and international standards for juvenile justice to all members of the Board as it considers necessary, in accordance with the Integrated Child Protection Scheme of the Central Government.

6. Tenure of the Board.— (1) The Board shall have a tenure of five years and the appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board.

(2) A social worker being a member of the Board shall be eligible for appointment for a maximum of two consecutive terms.

(3) Any extension of the tenure of members of the Board shall be on the basis of their performance appraisal by the District Child Protection Unit of the State

Government and on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and the performance appraisal of members of the Board shall necessarily assess their participation in the proceedings of the Board and contribution in case disposal.

(4) A member may resign any time, by giving one month's advance notice in writing or may be removed from his office as provided in sub-section (5) of section 4 of the Act.

(5) Any vacancy in the Board may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and shall hold office for the remaining term of the Board.

7. Qualifications for Members of the Board.— (1) The social worker to be appointed as a member of the Board shall be a person not less than 35 years of age, who has a post-graduate degree in social work, health, education, psychology, child development or any other social science discipline and has been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to child welfare for at least five years.

(2) A teacher, a Doctor, Retired public servant who is involved in the work concerning Juveniles or a social worker who has been directly engaged in child welfare.

(3) No person shall be considered for selection as a Member of the Board, if he, -

- (a) has been convicted under any law;
- (b) have ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human rights violations or immoral act;
- (c) is holding such other occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Board;
- (d) does not fulfil the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under and in such a case the Selection Committee shall after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

8. Sitting and conveyance allowances.— The social worker members of the Board shall be paid such travel and sitting allowance, as the State Government may determine.

9. Sittings of the Board.— (1) The Board shall hold its sittings in the premises of an Observation Home or, at a place in proximity to the observation home or, at a suitable premise in any institution run under the Act, and in no circumstances shall the Board operate from within any court premises.

(2) The premises where the Board holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Board shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform, and there shall be no witness box.

(3) The Board shall meet on all working days of a week, unless the case pendency is less in a particular district and concerned authority issues an order in this regard.

(4) A minimum of three-fourth attendance of the Chairperson and Members of the Board is necessary in a year.

(5) Every member of the Board shall attend a minimum of five hours per sitting.

10. Functions of the Board.— The Board shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-

- (a) adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;
- (b) take cognizance of crimes committed under section 23 to 28 of the Act;
- (c) monitoring institutions for juveniles in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement based on suggestions of the Board;
- (d) to recommend for taking action to the government in case of non-compliance on the part of concerned government functionaries or functionaries of voluntary organizations, as the case may be;
- (e) pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the spirit of the Act;
- (f) maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;
- (g) liaison with Boards in other districts to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law;
- (h) take suitable action for dealing with unforeseen situations that may arise in the implementation of the Act and remove such difficulties in the best interest of the

- juvenile;
- (i) send quarterly information about juveniles in conflict with law produced before them, to the District Protection Unit, State Child Protection Unit, the State Government and also to the Chief Judicial Magistrate for review under sub-section (2) of section 14 of the Act;
 - (j) any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law.
11. **Pre and Post-Production action of police and other agencies.**— (1) As soon as a juvenile alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the concerned police officer shall inform:
- (a) the designated Juvenile or the Child Welfare Officer in the nearest police station to take charge of the matter;
 - (b) the parents or guardian of the juvenile alleged to be in conflict with law about the apprehension of the juvenile, about the address of the Board where the juvenile will be produced and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board;
 - (c) the concerned probation officer, of such apprehension to enable him to obtain information regarding social background of the juvenile and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry.
- (2) Soon after apprehension, the juvenile shall be placed under the charge of the Juvenile or Child Welfare Officer from the nearest police station, who shall produce the juvenile before the Board within twenty four hours as per sub-section (1) of section 10 of the Act and where such Juvenile or the Child Welfare Officer has not been designated as per provisions laid down under sub-section (2) of section 63 of the Act or is not available for some official reasons, the police officer who had apprehended the juvenile shall produce him before the Board.
- (3) The police apprehending a juvenile in conflict with law shall in no case send the juvenile in lock-up or delay his charge being transferred to the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, if such an officer has been designated and the police officer apprehending a juvenile in conflict with law shall not treat him as a "Criminal" but he will treat him as a child suffered under the circumstances and the special juvenile police shall take step to prevent the juvenile in conflict with law not to go again towards the criminal

activities, the child or juvenile in conflict with law shall be sent to observation home as a last alternative. The Juvenile in conflict with law against whom the charge of bailable and non-bailable offence is sustained he shall be bailed out immediately from the police station and in any case the police officer apprehending a juvenile could not produce the child or juvenile in conflict with law before the child welfare officer/Juvenile Justice Board/ Child Welfare Committee, then the child or Juvenile shall be kept in children's home or observation home until he can be produced to the competent officer and any way he will not be kept in police station.

- (4) A list of all designated Juvenile or the Child Welfare Officers in a district and members of Special Juvenile Police Unit with contact details shall be prominently displayed in every police station.
- (5) For gathering the best available information it shall be incumbent upon the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, to contact the parents or guardians of the juvenile and also apprise them of the juvenile's law breaking behaviour.
- (6) The police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall also record the social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed in the case diary of each juvenile, which shall be forwarded to the Board forthwith.
- (7) The police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall exercise the power of apprehending the juvenile only in cases of his alleged involvement in serious offences (entailing a punishment of more than 7 years imprisonment for adults).
- (8) In such cases where apprehension apparently seems to be in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall rather treat the juvenile as a child in need of care and protection and produce him before the Board, clearly explaining the juvenile's need for care and protection in its report and seek appropriate orders from the Board under clause (b) of sub-rule (1) of rule 13 of these rules.

- (9) For all other cases involving offences of non-serious nature (entailing a punishment of less than 7 years imprisonment for adults) and cases where apprehension is not necessary in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall intimate the parents or guardian of the juvenile about forwarding the information regarding nature of offence alleged to be committed by their child or ward along with his socio-economic background to the Board, which shall have the power to call the juvenile for subsequent hearings.
- (10) In case the Board is not sitting, the juvenile in conflict with law shall be produced before the single member of the Board as per the provisions laid down under the sub-section (2) of section 5 of the Act.
- (11) In dealing with cases of juveniles in conflict with law the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall not be required to register an FIR or file a charge-sheet, except where the offence alleged to have been committed by the juvenile is of a serious nature such as rape, murder or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults; instead, in matters involving simple offences, the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station shall record information regarding the offence alleged to have been committed by the juvenile in the general daily diary followed by a report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence and forward it to the Board before the first hearing.
- (12) The State Government shall recognize only such voluntary organizations that are in a position to provide the services of probation, counselling, case work, a safe place and also associate with the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, and have the capacity, facilities and expertise to do so as protection agencies that may assist the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the police at the time of apprehension, in preparation of the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence, in taking charge of the juvenile until production before the Board, and in actual production of the juvenile before the Board within twenty-four hours.

- (13) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, or the recognized voluntary organization shall be responsible for the safety and provision of food and basic amenities to the juveniles apprehended or kept under their charge during the period such juveniles are with them.
- (14) When a juvenile is produced before an individual member of the Board, and an order obtained, such order shall need ratification by the Board in its next meeting.

12. Procedure to be followed in determination of Age.— (1) In every case concerning a child or a juvenile in conflict with law, the court or the Board or as the case may be the Committee referred to in rule 19 of these rules shall determine the age of such juvenile or child or a juvenile in conflict with law within a period of 30 days from the date of making of the application for that purpose.

(2) The court or the Board or as the case may be the Committee shall decide the juvenility or otherwise of the juvenile or the child or as the case may be the juvenile in conflict with law, prima facie on the basis of physical appearance or documents, if available, and send him to the observation home or in jail.

(3) In every case concerning a child or juvenile in conflict with law, the age determination inquiry shall be conducted by the court or the Board or, as the case may be, the Committee by seeking evidence by obtaining –

- (a) (i) the matriculation or equivalent certificates, if available; and in the absence whereof;
- (ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof;
- (iii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat; and

(b) only in the absence of either (i), (ii) or (iii) of clause (a) above, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of the juvenile or child. In case exact assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons to be recorded by them, may, if considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of

one year.

and, while passing orders in such case shall, after taking into consideration such evidence as may be available, or the medical opinion, as the case may be, record a finding in respect of his age and either of the evidence specified in any of the clauses (a)(i), (ii), (iii) or in the absence whereof, clause (b) shall be the conclusive proof of the age as regards such child or the juvenile in conflict with law.

(4) If the age of a juvenile or child or the juvenile in conflict with law is found to be below 18 years on the date of offence, on the basis of any of the conclusive proof specified in sub-rule (3), the court or the Board or as the case may be the Committee shall in writing pass an order stating the age and declaring the status of juvenility or otherwise, for the purpose of the Act and these rules and a copy of the order shall be given to such juvenile or the person concerned.

(5) Save and except where, further inquiry or otherwise is required, inter alia, in terms of section 7A, section 64 of the Act and these rules, no further inquiry shall be conducted by the court or the Board after examining and obtaining the certificate or any other documentary proof referred to in sub-rule (3) of this rule.

(6) The provisions contained in this rule shall also apply to those disposed off cases, where the status of juvenility has not been determined in accordance with the provisions contained in sub-rule(3) and the Act, requiring dispensation of the sentence under the Act for passing appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law.

13. Post-production processes by the Board.— (1) On production of the juvenile before the Board, the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed provided by the officers, individuals, agencies producing the juvenile shall be reviewed by the Board, and the Board shall pass the following order in the first summary inquiry on the same day, namely:-

- (a) dispose off the case, if the evidence of his conflict with law appears to be unfounded or where the juvenile is involved in trivial law breaking;
- (b) While the juvenile or child is produced first time before the Board, then the Board shall determine whether the juvenile or child may release on bail and if the juvenile or child may be released on bail, the Board shall keep the Juvenile

or child in the custody of parents, guardian or fit person/institution then being released the juvenile or child on the execution of personal bond or Board may keep the Juvenile under the supervision of any probation officer;

- (c) transfer to the Committee, matters concerning juveniles clearly stated to be in need of care and protection in the police report submitted to the Board at the time of production of the juvenile;
- (d) release the juvenile in the supervision or custody of fit persons or fit institutions or probation officers as the case may be, through an order in **Form-I**, with a direction to appear or present a juvenile for an inquiry on a next date;
- (e) detain the juvenile in an Observation Home or fit institution pending inquiry, only in cases of juvenile's involvement in serious offences as per an order in **Form-II**;
- (f) in all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than 15 days of the first summary enquiry and also seek social investigation report from the concerned Probation Officer through an order in **Form-III**;

(2) The Board shall take the following steps to ensure fair and speedy inquiry, namely:-

- (a) at the time of initiating the inquiry, the Board shall satisfy itself that the juvenile in conflict with law has not been subjected to any ill-treatment by the police or by any other person, including a lawyer or probation officer and take corrective steps in case of such ill-treatment;
- (b) in all cases under the Act the proceedings shall be conducted in as simple a manner as possible and care shall be taken to ensure that the juvenile, against whom the proceedings have been instituted, is given child-friendly atmosphere during the proceedings;
- (c) every juvenile brought before the Board shall be given the opportunity to be heard and participate in his inquiry;
- (d) cases of petty offences, if not disposed off by the Special Juvenile Police Unit or at the police station itself, may be disposed off by the Board through summary proceedings or inquiry, while in cases of heinous offences entailing punishment of 7 years or more, due process of inquiry in detail may follow;
- (e) even in cases of inquiry pertaining to serious offences the Board shall follow the procedure of trial in summons cases.

- (3) When witnesses are produced for examination in inquiry relating to a juvenile in conflict with law, the Board shall keep in mind that the inquiry is not to be conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to question the juvenile and proceed with the presumptions that favour the juvenile's right to be restored.
- (4) While examining a juvenile in conflict with law and recording his statement, the Board shall address the juvenile in a child-friendly manner in order to put the juvenile at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence of which the juvenile is accused, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the juvenile might have been subjected.
- (5) The Juvenile or child is to be informed the accusation against him at once and directly by the Board in such language and manner which he simply knows and to understand by him.
- (6) It is not obligatory for the Juvenile or child to confess or to give witness on the matter of obtaining any information and he shall not be given ill treatment or coercion on this subject.
- (7) The Board may take into account the report of the police containing circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed and the social investigation report in **Form-IV** prepared by the Probation officer or the voluntary organization on the orders of the Board as per **Form-III**, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion about the juvenile.
- (8) Every inquiry by the Board shall be completed within a period of four months after the first summary inquiry and only in exceptional cases involving trans-national criminality, large number of accused and inordinate delay in production of witnesses, the period of inquiry may be extended by two months on recording of reasons by the Board.
- (9) In all other cases except where the nature of alleged offence is serious, delay

beyond four to six months shall lead to the termination of the proceedings.

(10) Where the proceedings are delayed beyond six months on account of serious nature of the offence alleged to have been committed by the juvenile, the Board shall send a periodic report of the case to the Chief Judicial Magistrate stating the reason for delay as well as steps being taken to expedite the matter.

14. Legal Aid.— (1) The proceedings before the Board shall be conducted in non-adversarial environment, but with due regard to all the due process guarantees such as right to counsel and free legal aid.

(2) The Board shall ensure that the Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall extend free legal services to all the juvenile in conflict with law.

(3) The Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall be under an obligation to provide legal services sought by the Board.

(4) In the event of shortfall in the State Legal Aid Services support, the Board shall be responsible for seeking legal services from recognized voluntary legal services organisations or the university legal services clinics.

(5) The Board may also deploy the services of the student legal services volunteers and non-governmental organisation volunteers in para-legal tasks such as contacting the parents of juveniles in conflict with law and gathering relevant social and rehabilitative information about the juveniles.

15. Completion of Inquiry and Dispositional Alternatives.— (1) The Board shall complete every inquiry within the stipulated time of four months and on recording a finding about juvenile's involvement in the alleged offence, pass one of the seven dispositional orders enumerated in section 15 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report prepared by the probation officer or by a recognized voluntary organization ordered to

do so by the Board, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an individual care plan for the concerned juvenile in conflict with law, prepared by a probation officer or voluntary organization on the basis of interaction with the juvenile and his family, where possible.

(4) Where the Board decides to release the juvenile after advice and admonition or after participation in group counselling or orders him to perform community service, necessary direction may also be made by the Board to the District or State Child Protection Unit or the State Government for arranging such individual counselling, group counselling and community service.

(5) Where the Board decides to release the juvenile in conflict with law on probation and place him under the care of the parent or guardian or fit person, the person in whose custody the juvenile is released may be required to submit a written undertaking in **Form-V** for the good behaviour and well-being of the juvenile for a maximum period of three years.

(6) The Board may order release of a juvenile in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form VI**.

(7) In the event of placement of a juvenile in conflict with law in care of a fit institution or special home, the Board shall keep in mind that the fit institution or special home is located nearest to the place of residence of the juvenile's parent or guardian.

(8) The Board, where it releases a juvenile in conflict with law on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the juvenile is released on probation and placed under the care of fit institution, may order that the juvenile be placed under the supervision of a probation officer. The period of supervision shall be a maximum of 3 years.

(9) Where the Board decides that a juvenile in conflict with law ought to be treated as a child in need of care and protection, it shall make necessary orders for production of such juvenile before the nearest Committee for suitable care, protection and

rehabilitation.

(10) Where it appears to the Board that the juvenile in conflict with law has not complied with probation conditions, it may order the juvenile to be sent for detention in a special home.

(11) Where a juvenile in conflict with law who has attained the age of sixteen years and the offence committed by him is of such a serious nature that in the satisfaction of the Board, it is neither in the interest of the juvenile himself nor in the interest of other juveniles of the special home, the Board may order the juvenile to be kept in a place of safety and in a manner considered most appropriate by it.

(12) The State Government shall make arrangement for complying with the detention of special category of juveniles in conflict with law in place of safety other than the special home.

(13) In no case the period of detention shall exceed beyond the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act.

16. Observation Home and Special Home for Juvenile in conflict with Law.- (1) the State Government may establish and maintain Observation Home either by itself or under an agreement with voluntary organisation in every district or a group of districts as may be required or the temporary reception of any child alleged to be in conflict with law during the pendency of any inquiry regarding them under the Act.

(2) Separate institution shall be maintained for boys and girls.

(3) Children of the institutions shall be classified and separated in accordance with their degree of offence .

(4) The State Government may also certify or recognise any institution as observation home for the purpose of this Act.

Objective of the Observation Home.-(1) Opportunities to pursue Education shall be offered through the provision of creative non-formal classes that enable the child to sustain his/her interest in formal education especially if the child has attended such school.

(2) Special counselling sessions may be conducted by trained persons to enable children alleged to be in conflict with law to deal with their feelings and fears about

their situation and to offer them legal aid.

(3) In any case, children shall be offered opportunities to make constructive use of their time even during this short period of observation

Management of Observation Home.- Management of Observation Home shall be maintained by an Officer in charge specifically appointed to hold office as superintendent of the institution, who is under the control and supervision of the Commissioner/Director of Women Empowerment. The custody of children in conflict with law in the observation home shall be Judicial Custody.

Admission of a child.-(1) Admission of child in the observation home shall be made round the clock and the Officer In charge of observation home is bound to receive the child irrespective of the time.

(2) Admission of child in the observation home or a place of safety shall be made by the Juvenile Justice Board by issuing a placement order duly signed and seal affixed. No child other than a child in conflict with law shall be kept in an observation home.

(3) The Officer-in-Charge shall be authorised to detain in the observation home a child brought during the night till he is produced before the juvenile justice board, the next day for obtaining an order.

(4) The Officer-in-Charge shall refuse admission of a child whose age, identification marks and offence for which he is charged etc. has not been mentioned specifically. Provided further admission can also be refuse if the placement order is not signed duly or corrections not attested properly or brought without any seal affixed.

(5) The Superintendent/Officer-in-charge will be personally responsible to see that no child is admitted unauthorised. He will keep a proper check when a child is admitted at odd hours.

Special Homes.-(1)The State Government may establish and maintain Special Home either by itself or under an agreement with voluntary organization in every district or a group of districts as may be required for the reception, care, treatment and rehabilitation of children in conflict with law who have been directed to undergo institutional training for his activities against law.

(2) Separate institutions shall be maintained for boys and girls.

(3) Inmates of the institutions shall classified and separated in accordance with their degree of offence and their age as follows.

(a) Age group of 12 years

- (b) Age group of 12 to 16 years
- (c) Age group of 16 to 18 years
- †) The State Government may also certify or recognised any institution as Special Home for the purpose of this Act.

Objectives of Special Home. - The objectives of the Special Homes shall be-

- 1)(a) to receive a juvenile in conflict with law who has been ordered by Juvenile Justice Board;
- (b) to provide opportunities to receive emotional and psychological support;
- (c) to facilitate the child to receive proper health care, education, vocational training behaviour modification programmes etc;
- (d) to ensure the child to be protected from secondary victimization and assist the child for development and growth;
- (e) to prepare the child for reintegration within the community as a changed person;
- (f) Special Programmes: Programmes may be to-
 - (i) Assist the child to accept rather than to avoid responsibility for his/her actions;
 - (ii) Help the child to focus on helping to resolve problems identified as contributing to their offending behaviours.
 - (iii) Assist the child to develop practical alternative ways of coping with stressors;
 - (iv) Involve, wherever possible, families of offenders to work on family issue likely to reduce offending;
 - (v) Remediating educational deficits in basic skill to raise social competence;
 - (vi) Help to develop market place work skills, which can lead to further training opportunities, qualifications and real job;
 - (vii) Assist the child in establishing and strengthening relationships with significant others who can then become mentors and role models;
 - (viii) Involve the child in empowering experiences of assessing their own needs and planning and monitoring their own case plans.
 - (ix) Help the child to develop skills and confidence to assert positive leadership and self-discipline.
- (2) Efforts may be made to develop a victim Offender Reconciliation Programme (Concept taken from Victim Offender Reconciliation Programme, www.Borp.com) with such experts involving interested and competent Non-Government Organizations.

The objective of such programmes may be to offer avenues for communication, responsibility reconciliation and restitution.

(3) A programme for Group Counselling and other such services shall be evolved with the help of experts in the field.

(4) A programme to offer and monitor meaningful and effective community service to children in conflict with law, who are ordered to undergo for the same, may be evolved with the help of competent and sensitive Non-Government Organizations/experts. The objective of such community service shall be to enable the child to move towards becoming an adjusted member of the community and it shall in no way further stigmatize the child or violate his rights.

Management of Special Home.- Management of Special Home shall be maintained by an Officer in charge specifically appointed to hold office as superintendent of the institution, who is under the control and supervision of the Commissioner/Director of Women and Child Development.

Admission of Child.-(1) A child in conflict with law shall be admitted on a written placement order issued and duly signed by the Juvenile Justice Board for the purpose of the receiving institutional programme.

(2) No child shall be admitted or kept in the special home without any valid placement order issued by the Juvenile Justice Board or any other Competent Authority exercising the powers of the Juvenile Justice Board.

(3) No child shall be kept in the Special Home beyond the date upto which the child can be kept as per orders of Juvenile Justice Board.

(4) If a child is to be kept in the Special Home beyond the date up to which the child was ordered to be kept in the institutions, the formal order of the juvenile justice board shall be obtained in advance to complete the academic or vocational training till the closure of the academic year.

17. Release.— (1) The Officer-in-charge shall maintain a roster of the cases of juveniles in conflict with law to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board.

- (2) Each case shall be placed before the Management Committee set up under rule 55 of these rules by the concerned probation officer or child welfare officer or case worker for ensuring proper release and social mainstreaming of the juvenile post-release.
- (3) The release shall be as per the pre-release and post-release plan prepared under the individual care plan and reviewed from time to time by the management committee set up under rule 55 of these rules and in all cases of release, necessary action and preparation shall be initiated well before the time of release and shall include preparation for post-release follow-up.
- (4) The timely information of the release of a juvenile and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be invited to come to the institution to take charge of the juvenile on that date.
- (5) If necessary, the actual expenses of the parent's or guardian's journey both ways and of the juvenile's journey from the institution shall be paid to the parent or guardian by the Officer-in-charge at the time of the release of the juvenile.
- (6) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the juvenile on the appointed date, the juvenile shall be taken by the escort of the institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort.
- (7) At the time of release or discharge, a juvenile shall be provided with a set of summer or winter clothing and essential toiletries, if the Officer-in-charge considers it necessary.
- (8) If the juvenile has no parent or guardian, he may be sent to an aftercare organization, or in the event of his employment, to the person who has undertaken to employ the juvenile.
- (9) The Officer-in-charge of a girls' institution may, subject to the consent of the girl and the approval of the competent authority, help the girl with her social re-integration by way of sending a girl above the age of eighteen years to an aftercare programme or, helping her with some vocation or gainful employment or, helping her settle into family life according to the procedure laid down by the competent authority

from time to time.

(10) The Officer-in-Charge shall order the discharge in **Form-VII** of any juvenile whose detention period has come to an end and inform the competent authority within seven days of the action taken and if the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the juvenile may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge.

(11) The Officer-in-charge shall in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State or the District Child Protection Unit or the State Government, and the railway or road, or both, fares, as the case may be.

(12) In deserving cases, the Officer-in-charge may provide the juvenile with such small tools, as may be necessary, to start a work or business subject to such maximum cost as may be fixed by the institution which shall also form part of the post-release plan.

(13) Where a girl has no place to go after release and requests for stay in the institution after the period of her stay is over, the Officer-in-charge may, subject to the approval of the competent authority, allow her to stay till the time some other suitable arrangements are made.

18. Procedure to be followed in respect of sections 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of the Act.—

(1) In the event of violation of provisions laid down under section 21 of the Act,-

(a) the Board shall take cognizance of such violation by print or electronic media and shall initiate necessary inquiry and pass appropriate orders as per provisions contained in sub-section (2) of section 21 of the Act; and

(b) where the National or the State Commission for Protection of Child Rights takes *suo motu* cognizance of violation under section 21 of the Act, it shall inform the District or the State Child Protection Unit of the concerned district and the State directing them to initiate necessary action through the Board.

(2) In the event of an escape of a juvenile in conflict with law or a child, the following action shall be taken within twenty-four hours,-

(a) the Officer-in-Charge of any institution shall immediately send a report to the

area Police Station or Special Juvenile Police Unit along with the details and description of the juvenile or child, with identification marks and a photograph, with a copy to the Board, District Child Protection Unit and other authorities concerned;

(b) the Officer-in-charge of institutions other than shelter homes or drop-in-centres shall send the guards or concerned staff in search of the juvenile, at places like railway stations, bus stands and other places where the juvenile is likely to go;

(c) the parents or guardians shall be informed immediately about such escape; and

(d) the Officer-in-charge of an institution other than a shelter home or drop-in-centre shall hold an inquiry about such escape and send his report to the Board or Committee and the authorities concerned and the report shall be placed before the Management Committee set up under rule 55 of these rules in the next meeting for review.

(3) The offences against a juvenile in conflict with law or a child specified in sections 23, 24, 25 and 26 shall be either bailable or non-bailable besides being cognizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the procedures shall apply on the Police, the Board and the concerned authorities and functionaries accordingly.

CHAPTER IV

CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

19. Child Welfare Committee.— There shall be a Child Welfare Committee in every district, which shall be constituted by the State Government by a notification in the Official Gazette as per sub-section (1) of section 29 of the Act.

20. Composition of the Child Welfare Committee.— (1) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members, of whom at least one shall be a woman.

(2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed by the State Government.

(3) The Selection Committee, while selecting the Chairperson and Members of the Committee, shall as far as possible ensure that none of them are from any adoption agency.

(4) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, national and international standards for juvenile justice to all members of the Committee as it considers necessary.

21. Tenure of the Committee.— (1) The tenure of the Committee shall be five years and the tenure of Chairperson and Members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.

(2) The Chairperson and Members of the Committee shall be eligible for appointment for a maximum of two consecutive terms.

(3) Extension of the tenure of members of the Committee shall be on the basis of their performance appraisal by the District Child Protection Unit or the State Government and on the recommendation of the Selection Committee.

(4) With a view to ensuring continuity on completion of the tenure of a Committee, the State Government shall constitute a new Committee before the expiry of the term of the existing Committee; where after the existing Committee shall handover all records and information to the newly formed Committee.

(5) The Chairperson and Members may resign at any time by giving one month's notice

in writing or may be removed from office as provided in sub-section (4) of section 29 of the Act.

(6) Any casual vacancy in the Committee may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and shall hold office for the remaining term of the Committee.

22. Qualifications for Chairperson and Members of the Committee.— (1) A person to be selected as a Chairperson or Member of the Committee shall have either of the following qualifications, in addition to a minimum of five years experience in their respective field:

- (i) a person with post graduate degree in social work, psychology, child development, education, sociology, law, criminology and, where such a person is not available, a person with at least a graduate degree in any of the social science disciplines;
- (ii) a teacher, doctor, retired government servant or a social worker who has been involved in work concerning children.

(2) The Chairperson or Member of the Committee shall be a person not less than 35 years of age and his/her maximum age shall not exceed 65 years.

(3) No person shall be considered for Selection as a Chairperson or Member of the Committee, if he,-

- (i) has previously been convicted;
- (ii) has been involved in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;
- (iii) is holding such full-time occupation that may not allow him to give proper time and attention to the work of the Committee as per the Act and these rules;
- (iv) does not fulfil the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made thereunder, and in such a case the Selection Committee shall after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next following person from the list of names prepared for filling the vacancies.

23. Sitting and conveyance allowances.— The Chairperson and Members of the Committee shall be paid such travelling and sitting allowance, as the State

Government may, determine.

24. Sitting of the Committee.— (1) The Committee shall hold its sittings in the premises of the children's home or, at a place in proximity to the children's home or, at a suitable premise in any institution run under the Act.

(2) On receiving information about child or children in need of care and protection, if circumstances are such that the child or children cannot be produced before the Committee, the Committee may move out to reach the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.

(3) The premises where the Committee holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Committee shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform and there shall be no witness boxes.

(4) The Committee shall meet a minimum of three days a week, which may be extended by the State Government depending on case and pendency of work.

(5) A minimum of three-fourth attendance of the Chairperson and Members of the Committee is mandatory in a year.

(6) The duration of a sitting is dependent on the pendency of work before the Committee.

(7) Every member of the Committee shall attend a minimum of four hours per sitting.

25. Functions and Powers of the Committee.— The Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:—

- (a) take cognizance of and receive children produced before the Committee;
- (b) decide on the matters brought before the Committee;
- (c) reach out to such children in need of care and protection who are not in a position to be produced before the Committee, being in difficult circumstances, with support from the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government;
- (d) conduct necessary inquiry on all issues relating to and affecting the safety and well being of the child;

- (e) direct the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organisations to conduct social inquiry and submit a report to the Committee;
- (f) ensure necessary care and protection, including immediate shelter;
- (g) ensure appropriate rehabilitation and restoration, including passing necessary directions to parents or guardians or fit persons or fit institutions in this regard, in addition to follow-up and coordination with District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency and other agencies;
- (h) direct the Officer-in-charge of children's homes to receive children requiring shelter and care;
- (i) document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee;
- (j) provide a child-friendly environment for children;
- (k) declare 'fit persons';
- (l) declare a child legally free for adoption;
- (m) keep information about and take necessary follow-up action in respect of missing children in their jurisdiction;
- (n) maintain liaison with the Board in respect of cases needing care and protection;
- (o) visit each institution where children are sent for care and protection or adoption at least once in three months to review the condition of children in institutions, with support of the State Government and suggest necessary action;
- (p) monitor associations and agencies within their jurisdiction that deal with children in order to check on the exploitation and abuse of children;
- (q) co-ordinate with the Police, Labour Department and other agencies involved in the care and protection of children with the support of District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or State Government;
- (r) liaison and network with the corporate sector and non-governmental organisations for any of the above, including for social inquiry, restoration and rehabilitation, as and when required; and
- (s) maintain a suggestion box to encourage inputs from children and adults alike and take necessary action.

26. Procedure in relation to Committee.— (1) The quorum for the meeting shall be three members attending, which may include the Chairperson.

(2) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall require ratification by the Committee in its next sitting.

(3) The Committee shall take into consideration the age, developmental stage, physical

and mental health, opinion of the child and the recommendation of the child welfare officer or caseworker, prior to disposal of cases.

(4) For final disposal of a case, the order of the Committee shall be signed by at least two members, including the Chairperson.

27. Production of a Child before the Committee.— (1) A child in need of care and protection shall be produced before the Committee within twenty-four hours, excluding journey time, by one of the following persons—

- (a) any police officer or Special Juvenile Police Unit or a designated police officer;
- (b) any public servant;
- (c) childline, a registered voluntary organization or by such other voluntary organization or an agency as may be recognized by the State Government;
- (d) social worker;
- (e) any public spirited citizen; or
- (f) by the child himself.

(2) In case of a child under two years of age, who is medically unfit, the person or the organization shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

(3) The Committee can suo motu take cognizance of cases brought to their notice and reach out to a child in need of care and protection where necessary and the District or the State Child Protection Unit or the State Government shall provide necessary support and assistance to the Committee for carrying out such functions.

(4) In case the Committee is not sitting, the child may be produced before the single member of the Committee as per the provisions laid down under the sub-section (2) of section 30 of the Act for being placed in safe custody of parent or guardian or fit person or fit institutions, as the case may be, till such time that the child can be produced before the Committee.

(5) In case the single member is also not accessible, or that the hours are odd, the child shall be taken by a non-governmental organisation or Childline or Police to an appropriate institution for children registered under the Act with all the necessary documents, and placed in such institution till the time of production before the

Committee.

- (6) The concerned institution shall inform the Chairperson or a member of the Committee about such child and produce the child before the Committee within twenty four hours and in such cases, it may not be necessary for the person who brings a child in need of care and protection to an institution to be present at the time of production of the child before the Committee.
- (7) Whoever produces a child before the Committee shall submit a report on the circumstances under which the child came to their notice and efforts made by them on informing the police and the missing persons squad and in cases where a recognized voluntary organization or any police personnel produce a child before the Committee, they shall also submit a report on the efforts made by them for tracing the family of the child.
- (8) Any general medical or gynaecological examination of children shall not be a pre-requisite for production of the child before the Committee or admission in an institution.
- (9) The Committee shall facilitate the filing of a police complaint and First Information Report in cases of missing children as well as matters of violence, exploitation and abuse of children and arrange for required legal aid through the Legal Officer in the District Child Protection Unit or District or State Legal Aid Services Authority or voluntary organisations.
- (10) Each Committee shall send quarterly information about children in need of care and protection received by them to the District or State Child Protection Unit or State Government.
- (11) Children shall be provided a child-friendly environment during the proceedings of the Committee.
- (12) The Committee shall have an empanelled list of lawyers, social workers and mental health expert who may assist the Committee in dealing with cases of abused children and who may also interface with the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor to facilitate legal services to the abused children, when the cases relating to such children are taken up in regular criminal courts.

(13) Every possible effort shall be made to trace the family with support from the District Child Protection Unit, and assistance of recognized voluntary organizations, childline or police may also be taken.

(14) The Committee shall send the child to the designated place of safety, with age and gender appropriate facilities, pending inquiry and in such eventuality, the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or State Government shall provide transport or make necessary budgetary allocations for such expenses based on the actual fare.

(15) The child may be escorted by the police officer or representative of the voluntary organization or by any other arrangement as considered appropriate by the Committee with support from the District Child Protection Unit and in case of a girl child, a female escort shall accompany the child.

(16) A list of all recognized child care institutions along with their capacity and appropriate facilities as prescribed under section 34 of the Act, a list of all child related resource services and a list of contact details of all Child Welfare Committees across the country shall be provided to the Committee by the District Child Protection Unit or State Government.

(17) The Committee may, while making an order in **Form VIII** placing a child under the care of a parent, guardian or fit person pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form IX**.

(18) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Officer-in-charge of such institution a copy of the order of short term placement pending inquiry, in **Form X** with particulars of the home and parents or guardian and previous record.

(19) Whenever the Committee orders a child to be kept in a fit institution as part of restoration under clause (f) of sub-section (3) of section 39 of the Act, it shall forward a copy of its order of restoration in **Form XI** to the Officer-in-charge of such institution.

(20) The child shall be placed in an institution closest to where his parents or guardians belong as far as possible, unless the child has been subjected to abuse or

exploitation by parents or guardians.

28. Procedure for inquiry.—(1) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a social worker or caseworker or child welfare officer or Officer-in-charge as the case may be, of the institution or any recognized agency for conducting the inquiry through an order in **Form-XII**.

(2) The Committee shall direct the concerned person or organization about the details or particulars to be enquired into for developing an individual care plan and suitable rehabilitation.

(3) All inquiries conducted by a social worker or caseworker or child welfare officer or Officer-in-charge of the institution or any recognized agency shall be as per **Form-XIII** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

(4) The inquiry must be completed within four months or within such shorter period as may be fixed by the Committee:

Provided that the Committee may, in the best interest of the child and for the reasons to be recorded in writing, extend the said period under special circumstances.

(5) After completion of the inquiry, if, the child is under orders to continue in the children's home, the Committee shall direct the Officer-in-charge of the home to submit quarterly progress report of such child and produce the child before the Committee for an annual review of the progress.

29. Children's Homes .— (1) The State Government itself or in association with voluntary organizations, shall set up separate homes for children in need of care and protection, in the manner specified below-

- (a) all children's homes shall be registered as child care institutions under sub-section (3) of section 34 of the Act and rule 71 of these rules;
- (b) all children's homes shall be certified as per the procedure laid down in rule 70;
- (c) all children's homes shall report to the concerned Committee about every child in need of care and protection received by them;
- (d) children of both sexes below ten years may be kept in the same home but separate facilities shall be maintained for boys and girls in the age group 5 to 10 years;

- (e) every children's home shall include separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for the infants;
- (f) separate children's homes shall be set up for boys and girls in the age group 10 to 18 years;
- (g) children in the age group of 10 to 18 shall be further segregated into two groups of 10 to 15 years and 15 to 18 years.

(2) Each children home shall be a comprehensive child care centre with the primary objective to promote an integrated approach to child care by involving the community and local Non-Governmental Organisations through the Management Committee set up under rule 55 of these rules and the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government shall make an annual performance review of functioning of the children's homes.

(3) The activities of such centre shall focus on:

- (a) preparing and following individual care plans for every child, with rights based approach, specifically addressing the child's physical and mental health, emotional needs, education, skill development, protection and special needs if any;
- (b) family based non-institutional services, such as, foster family care, adoption and sponsorship;
- (c) specialized services in situations of conflict or disaster and for juvenile or children affected by terminal or incurable disease to prevent neglect by providing family counselling, nutrition, health interventions, psycho-social interventions and sponsorship;
- (d) emergency outreach service through child line (Toll free Help Line No. 1098);
- (e) linkages with Integrated Child Development Services to cater to the needs of children below six years;
- (f) linkages with organizations and individuals who can provide support services to children; and
- (g) opportunities to volunteers willing to provide various services for children.

30. Shelter Homes.— (1) For children in urgent need of care and protection, such as street children and run-away children, the State Government shall support creation of requisite number of shelter homes or drop-in- centres through the voluntary organizations.

(2) Shelter homes shall include:

- (a) short-stay homes for children needing temporary shelter, care and protection for a maximum period of one year,
- (b) transitional homes providing immediate care and protection to a child for a maximum period of four months,
- (c) 24 hour drop-in-centres for children needing day care or night shelter facility.

(3) The shelter homes or drop-in-centres shall have the minimum facilities of boarding and lodging, besides the provision for fulfilment of basic needs in terms of clothing, food, health care and nutrition, safe drinking water and sanitation.

(4) There shall be separate shelter homes for girls and boys as per rule 40(2)(d) of these rules.

(5) All shelter homes shall provide requisite facilities for education, vocational training, counselling and recreation or make arrangements for it in collaboration with voluntary organizations or corporate sector.

(6) The Committee, Special Juvenile Police Units, public servants, Childlines, voluntary organizations, social workers and the children themselves may refer a child to such shelter homes.

(7) All shelter homes shall submit a report of children using the shelter home facility along with a photograph of the child to the Committee, the missing persons bureau or special juvenile police unit and the District Child Protection Unit or the State Child Protection Unit.

(8) The requirements of producing a child received by a shelter home before the Committee, inquiry and disposal under sections 32, 33, 38 and 39 of the Act shall apply only to shelter homes other than drop-in-centres as specified in rule 30(2)(c) of these rules.

(9) The services of Officer-in-charge, child welfare officer, social worker shall be provided for the proper care, protection, development, rehabilitation and reintegration needs of children in shelter homes.

(10) No child shall ordinarily stay in a short stay home for more than a year except

in special circumstances with the approval of the Committee.

31. Guidelines for prevention of sexual abuse of children.— The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee, other competent authorities and agencies shall, in the best interest of children, ensure that every person, school or such other educational institutions abide by the guidelines for the prevention of sexual abuse of children issued from time to time by Central Government and State Government.

CHAPTER V

REHABILITATION AND SOCIAL REINTEGRATION

32. Rehabilitation and Social Reintegration.— The primary aim of rehabilitation and social reintegration is to help children in restoring their dignity and self-worth and mainstream them through rehabilitation within the family where possible, or otherwise through alternate care programmes and long-term institutional care shall be of last resort.

33. Adoption.— (1) The primary aim of adoption is to provide a child who cannot be cared for by his biological parents with a permanent substitute family.

(1) For all matters relating to adoption, the guidelines issued by the Central Adoption Resource Agency and notified by the Central Government under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall apply.

(3) In case of orphaned and abandoned children the following procedure shall apply, namely:-

- (a) Specialized Adoption Agencies shall produce all orphaned and abandoned children who are to be declared legally free for adoption before the Committee within twenty-four hours of receiving such children, excluding the time taken for journey;
- (b) a child becomes eligible for adoption when the Committee has completed its inquiry and declares the child legally free for adoption;
- (c) such declaration shall be made in **Form XIV**;
- (d) a child must be produced before the Committee at the time of declaring such child legally free for adoption;
- (e) whenever intimation is received by the police about an abandoned infant,

the police shall take charge of the infant and arrange to provide immediate medical assistance and care;

- (f) subsequently, the child shall be placed in a specialized adoption agency or recognized and certified children's home or in a paediatric unit of a Government hospital followed by production of the child before the Committee within twenty-four hours;
- (g) procedure for declaring a child abandoned and certifying him legally free for adoption:
 - (i) in case of an abandoned child, the recognized agency shall within twenty four hours, report and produce the child before the Committee with the copy of the report filed with the police station in whose jurisdiction the child was found abandoned;
 - (ii) the Committee will institute a process of inquiry, which shall include a thorough inquiry conducted by the Probation Officer or Child Welfare Officer, as the case may be and who shall give report in **Form XIII** to the Committee containing the findings within one month;
 - (iii) there shall be a declaration by the specialized adoption agency, stating that there has been no claimant for the child even after making notification in at least one leading national newspaper and one regional language newspaper for children below two years of age and for children above two years, an additional television or radio announcement and notification to the missing persons squad or bureau shall be made;
 - (iv) the steps stated in (iii) shall be taken within a period of sixty days from the time when the child is found in case of a child below two years of age and in case of children above two years of age, this period shall be four months;
 - (v) the period of notification shall run concurrently with the inquiry to be conducted and report submitted under clause (ii) of this sub-rule;
 - (vi) the Committee shall declare the child legally free for adoption on completion of the process of inquiry, including declaration of the specialized adoption agency made under clauses (ii) and (iii) of this sub-rule;
 - (vii) no child above seven years who can understand and express his opinion shall be declared free for adoption without his consent.

(4) In case of surrendered children the following procedure shall apply, namely:-

- (a) a "surrendered" child is one who had been declared as such after due process of inquiry by the Committee and in order to be declared legally free for adoption, a surrendered child shall be any of the following:
 - (i) born as a consequence of non-consensual relationship;
 - (ii) born of an unwed mother or out of wedlock;
 - (iii) a child in whose case one of the biological parents is dead and the living parent is incapacitated to take care;
 - (iv) a child where the parents or guardians are compelled to relinquish him due to physical, emotional and social factors beyond their control;
- (b) serious efforts shall be made by the Committee for counselling the parents, explaining the consequences of adoption and exploring the possibilities of parents retaining to the child and if, the parents are unwilling to retain, then, such children shall be kept initially in foster care or arranged for their sponsorship;
- (c) if the surrender is inevitable, a deed of surrender in **Form XV** shall be executed on a non-judicial stamp paper in the presence of the Committee;
- (d) the adoption agencies shall wait for completion of two months reconsideration time given to the biological parent or parents after surrender;
- (e) in case of a child surrendered by his biological parent or parents, the document of surrender shall be executed by the parent or parents before the Committee;
- (f) after due inquiry, the Committee shall declare the surrendered child legally free for adoption in **Form XIII**, as the case may be, after a sixty days' reconsideration period as per Central Adoption Resource Agency guidelines.

(5) For the purposes of section 41 of the Act, 'court' implies a civil court, which has jurisdiction in matters of adoption and guardianship and may include the court of the district judge, family courts and city civil court.

34. Foster Care.— (1) For children who cannot be placed in adoption, order shall be issued by the competent authority in **Form XVII** for carrying out foster care, as given in sub-section (2) of section 42 of the Act and rule 35 (1) of these rules, under the supervision of a probation officer or case worker or social worker, as the case may be, and the period of foster care shall depend on the need of the child.

- (2) As far as possible the younger children who have been relinquished or destitute shall be referred to adoption rather than foster care in the interest of continued care;
- (3) Younger children who are not placed in adoption shall preferably be placed with a couple in individual foster care/group foster care till the child is able to return home whenever family circumstances are considered conducive pre adolescent may be referred to group foster homes.
- (4) Older children may be encouraged to live in peer group homes under the foster care of persons willing to supervise such arrangements.
- (5) Foster care, though temporary in nature, may continue, if necessary until adulthood, but should not preclude either prior return to the child's own parents or adoption.
- (6) In all matters of foster family care, the prospective foster parents, the appropriate child and his or her own parents shall adequately be participated. The Child Welfare Committee shall be responsible for supervision to ensure the welfare of the child.
- (7) Twins and siblings shall not be separated by a foster placement except under extraordinary circumstances. If for some reason they have been separated, arrangement shall be made for them to remain in contact.
- (8) The wishes of the child concerning the proposed fostering shall be taken into account before placement.
- (9) Persons competent to be foster parents.- The following persons may apply to be the foster parents.-
- (10) Any single parent;
- (11) Any couple;
- (12) Members of the extended family of the child; and
- (13) Non-Government Organisations or other recognised person or agency willing to take responsibility of a child/children in individual or foster care.

- Target Group-**(a) The children from dysfunctional in a state families or from institutions or the children whose biological parents are either incapacitated or in a state of crisis and unable to provide the care and protection to the child.
- (b) Foster care is a boon to children without roots growing up in orphanages and child welfare institutions to find an opportunity to lead a family life;
 - (c) Children who can not be placed on adoption due to various reason can be

considered for Foster Care;

- (d) Foster Care can be either short term or long term depending upon the needs.
- (e) Keeping the children away from Institution and placing them in foster care can be made with the consent of the child welfare committee.

Follow-up.- (a) There shall be a regular visits carried out by the Probation Officer/Child Welfare Officer/Social Case Worker, as the case may be, so as to protect the best interest of the child.

- (b) Review of the placement report to be made every six months by the Monitoring and Evaluation Committee. These Reports shall be submitted to the Child Welfare Committee and the Directorate of Women Empowerment.
- (c) In case of victimization of the child in the foster home, appropriate action shall be taken against the parents.
- (d) When the foster placement begins the person placing the child shall submit to the foster parent a list of immunizations carried out in respect of the child and indicate to the foster parent the list of the other immunizations required to be effected in respect of the child and foster parent shall ensure that those immunizations are carried out. The foster parents and the district probation and women and child development officer shall at all times keep a record of the immunizations in respect of the child.
- (e) where the child placed with a foster parent is under five years of age, the child shall be medically examined by a Competent Medical functionaries once in a year.
- (f) The Probation Officer/Case worker concerned shall, so far as possible assist the foster parent in ensuring the carrying out the requirement.

Disruption.-

- (a) If the Probation Officer/Case Worker feels that it is in the best interest of the child, he/she may make a report regarding the necessity for disruption and submit it to the Child Welfare Committee.
- (b) The Probation Officer/Case Worker shall also produce the record before the Child Welfare Committee of efforts put in to remedy the maladjustment;
- (c) The child may be removed and placed in an alternative home/transit home wherever mal adjustment occurs, after obtaining the consent of the Child

Welfare Committee and giving the foster parents an opportunity to be heard;

- (d) In the case of an emergency the child may be removed on the discretion of the probation Officer/ Case Worker in consultation with the Superintendent and other staff of the children's home, according to conditions such as physical, or sexual abuse, or exploitation;
- (e) Upon disruption of a placement the Child Welfare Committee shall recommend alternate placement of the child with adequate provisions for counselling and care.

In case of sickness/death of the child or death of the foster parent.-

- (a) If a child is seriously ill the foster parent shall as soon as possible inform to the concerned Probation Officer/Case Worker who shall inform the parents/guardians and the Child Welfare Committee;
- (b) If the foster child dies, the foster parent shall make every effort to obtain a medical certificate of death and a post mortem report within 24 hours;
- (c) He or she shall also immediately inform the Probation Officer/Case Worker concerned, who shall inform the parents/guardians. Directorate of Women Empowerment and the Child Welfare Committee;
- (d) In the case where the child has been placed with a single foster parent who has died the child shall be returned to the approved home from where the child was received;

35. Criteria for selection of family for foster care.— (1) In case of the children covered under rule 34 of these rules, the following criteria shall apply for selection of families for foster care, namely:-

- (i) foster parents should have stable emotional adjustment with family;
- (ii) foster parents should have an income in which they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment;
- (iii) the monthly family income shall be adequate to take care of foster children and approved by the Committee;
- (iv) the medical reports of all the members of the family residing in the premises should be obtained including checks on a Human Immune Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B to determine that they are medically

fit;

- (v) the foster parents should have experience in child caring and the capacity to provide good child care;
- (vi) the foster parents should be physically, mentally and emotionally stable;
- (vii) the home should have adequate space and basic facilities;
- (viii) the foster care family should be willing to follow rules laid down including regular visits to paediatrician, maintenance of child health and their records;
- (ix) the family should be willing to sign an agreement and to return the child to the specialized adoption agency whenever called to do so;
- (x) the foster parents should be willing to attend training or orientation programmes; and
- (xi) the foster parents should be willing to take the child for regular (at least once a month in the case of infants) checkups to a paediatrician approved by the agency.

(2) There shall be no discrimination in selection of foster-parents on the basis of caste, religion, ethnic status, disability, or health status and the best interest of the child shall be paramount in deciding foster-care placement.

(3) The foster parents shall be declared 'fit persons' by the Committee before placing the child as per the provisions laid down in clause (i) of section 2 of the Act after thorough assessment done by the Child Welfare Officer or Social Worker as per **Form XVI**.

36. Pre-adoption Foster Care.— In case of pre-adoption foster care, the provisions contained in sub-section (1) of section 42 and the corresponding guidelines 2015 by the Government of India notified under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall apply.

37. Sponsorship.—

1. Sponsorship services shall be considered to supplement the resources of the child and his/her parent or guardian so as to support/efforts to re-integrate the child in to the community and finance his/her education, vocational training, health care, etc or to supplement the family income to encourage parent or guardian to fulfil their responsibility to the child.
2. The State shall provide for the sponsorship of children based on need and

- availability of resources when they are discharged from the reception unit/ shelter home/children's home/after care institution.
3. The State Government may allow individuals, institutions, corporate sectors, financial institutors, industries etc. to sponsor or support the following without expecting any gain in return:-
 - (1) Any child or his family shall be supported under sponsorship to withdraw children from child labour/bonded labour for higher education;
 - (2) Any activities pertaining to improve the behaviour of children, through personality development programme;
 - (3) Cultural programmes, picnics, holiday camps, medical assistances, immunisation programmes, special medical assistance, etc. inter school sports activities, creative arts and competition seminars for children involving eminent personalities etc.;
 - (4) Any activities pertaining to the job oriented training programmes, establishment of vocational rehabilitation centres, community college etc.;
 - (5) Establishment of libraries, sports activities, horticulture/ sericulture, creative arts and competitions etc;
 - (6) Improving infrastructures and amenities construction or alteration of buildings etc.
 4. Procedure for implementation of sponsorship scheme:-
 - (1) All instructions and guidelines relating to sponsorship scheme shall be applied as notified by the Government of India.
 - (2) The State Government shall prepare sponsorship programme in consultation with the Non Governmental Organisations, Child Welfare Committees, other relevant government agencies and the corporate sector.
 - (3) The State Government, with the help of District or State Child Protection Units shall identify families and children at risk and provide necessary support services in the form of sponsorship for child's education, health, nutrition and other developmental needs.
 - (4) The children's homes and special homes shall promote sponsorship programmes as laid down in section 43 of the Act.
 - (5) The institutions receiving sponsorship, shall maintain proper and separate accounts of all the receipts and payments for the

programme.

- (6) The Board or the Committee shall make an order in **Form XVIII** for support to a juvenile or child through sponsorship and send a copy to the District or State Child Protection Unit or the State Government for appropriate action

38. After Care Organisation.— (1) The State Government shall set up an after care programme for care of juveniles or children after they leave special homes and children's homes with the objective to facilitate their transition from an institution-based life to mainstream society for social re-integration.

- (2) After care programmes shall be made available for 18-21 year old persons, who have no place to go to or who are unable to support themselves, by the District or State Child Protection Units in collaboration with voluntary organizations for the purpose of section 44 of the Act and this rule.

- (3) Once the Board or the Committee passes an order in **Form XIX** for placing a juvenile or a child completing 18 years of age under the aftercare programme, a copy of such order shall be sent to the District and the State Child Protection Unit and the State Government, who shall be responsible for arranging after care.

- (4) The Board or the Committee shall have jurisdiction over persons placed in after care programme.

- (5) The objective of these organisations shall be to make enable such children to adapt towards the society.

- (6) The key components of the programme shall include:-

- (a) community group housing on a temporary basis for groups of young persons aged 18-21 years;
- (b) encouragement to learn a vocation or gain employment and contribute towards the rent as well as the running of the home;
- (c) encouragement to gradually sustain themselves without state support and move out of the group home to stay in a place of their own after saving sufficient amount through their earnings;
- (d) provision for a peer counsellor to stay in regular contact with these groups

to discuss their rehabilitation plans and provide creative outlets for their energy and to tide over crisis periods in their life.

- (7) During the course of vocational training a stipend may be provided till such time that the youth gets employment.
- (8) Loans may be arranged for the youth in an aftercare programme aspiring to set up entrepreneurial activities on the basis of an application made by them and due verification of the need for such a loan, and necessary professional advice and training shall be made available to the youth in the aftercare programme in this regard.
- (9) The structure shall include 5 to 8 youths in each group home who may be benefitted with the aftercare programme and opt to stay together on their own and one peer counsellor for a cluster of five group homes.

39. Linkages and co-ordination.— (1) The State Government shall circulate a copy of the Act and the rules framed thereunder to establish effective linkages between various government, non-government, corporate and other community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of juveniles or children through the Board or the Committee as the case may be.

(2) The State Government with the help of State or District Child Protection Unit shall identify the roles and responsibilities of each department at State or district levels for effective implementation of the Act and the rules and inform them through a notification.

(3) The State Government with the help of State or District Child Protection Unit shall arrange for appropriate training and sensitization of functionaries of these departments from time to time in coordination with National Institute of Public Cooperation and Child Development and its Regional Centres.

(4) The State Government with the help of State or District Child Protection Unit shall develop effective networking and linkages with local non-governmental organisations for specialized services and technical assistance like vocational training, education, health care, nutrition, mental health intervention, drug de-addiction and legal aid services.

CHAPTER VI**STANDARDS OF CARE FOR INSTITUTIONS**

40. Physical infrastructure.— (1) The homes for juveniles in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises.

(2) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(a) Observation Home:

- (i) Separate observation homes for girls and boys;
- (ii) Classification and segregation of juveniles according to their age group preferably 7-11 years, 12-16 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(b) Special Home:

- (i) Separate special homes for girls and boys;
- (ii) Classification and segregation of juveniles on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.

(c) Children's Home:

- (i) While children of both sexes below 10 years can be kept in the same home, separate bathing and sleeping facilities shall be maintained for boys and girls in the age group of 5-10 years;
- (ii) Separate children's homes for boys and girls in the age group of 7-11 and 12-18 years;
- (iii) Separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for infants.

(d) Shelter Home:

- (i) Separate shelter homes for girls and boys;
- (ii) Separate shelter homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 15 and 16 to 18 years.

(3) The norms for building or accommodation for an institution with 50 juveniles or children shall be as under:

- (i) 2 Dormitories

Each 1000 Sq. ft. for 25 juveniles/children i.e. 2000 Sq. ft.

(ii)	2 Classrooms	300 Sq. ft. for 25 juveniles/children i.e. 600 Sq. ft.
(iii)	Sickroom/First aid room	75 Sq. ft. per juvenile/children for 10 i.e. 750 Sq. ft.
(iv)	Kitchen	250 Sq. ft.
(v)	Dining Hall	800 Sq. ft.
(vi)	Store	250 Sq. ft.
(vii)	Recreation room	300 Sq. ft.
(viii)	Library	500 Sq. ft.
(ix)	5 bathrooms	25 Sq. ft. each i.e. 125 Sq. ft.
(x)	8 toilets/latrines	25 Sq. ft. each i.e. 200 Sq. ft.
(xi)	Office rooms	(a) 300 Sq. ft. (b) Superintendent's room 200 sq. ft
(xii)	Counselling and guidance room	120 Sq. ft.
(xiii)	Workshop	1125 Sq. ft. for 15 juvenile @75 Sq. ft. per trainee
(xiv)	Residence for Superintendent	(a) 2 rooms of 250 Sq. ft. each (b) kitchen 75 Sq. ft. (c) bathroom cum Toilet/latrine 50 Sq. ft
(xv)	2 Rooms for Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee	300Sq. ft. each i.e. 600 Sq. ft.
(xvi)	Play ground	Sufficient area according to the total number of juveniles or children

Total**8745 Sq. ft.**

(4) The Superintendent shall stay within the institution and be provided with quarters and in case he is not able to stay in the home for legitimate reasons (to be permitted by Director, Child Protection), any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children or juveniles and, take decisions in the case of any crisis and emergency.

(5) (i) the standards of accommodation as per the norms laid down in rule 40(2) shall be observed to the extent possible and shall include a minimum of following facilities

- (a) Dormitory: 40 Sq. ft. per juvenile or child
- (b) Classroom: 300 Sq. ft for 25 juvenile or child
- (c) Workshop: 75 Sq. ft. per juvenile or child
- (d) Play ground: Sufficient play ground area shall be provided in every institution according to the total number of juveniles in the institution

(ii) there shall be proper and smooth flooring for preventing accidents.

(iii) there shall be adequate lighting, ventilation, heating and cooling arrangements,

safe drinking water and clean toilets, in terms of gender, age appropriateness and accessibility.

(iv) all institutions under the Act shall make provision of first aid kit, fire extinguishers in kitchen, dormitories, store rooms, counselling room, periodic review of electrical installations, proper storage and inspection of articles of food stuffs, stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

(6) The Observation homes and special homes shall be child-friendly and in no way shall they look like a jail or lock-up.

41. Clothing and Bedding.— The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each juvenile or child and the minimum standards for clothing and bedding are laid down in Schedule-I of these rules.

42. Sanitation and Hygiene.— Every institution shall have the following facilities, namely:-

- (a) sufficient treated drinking water; water filters shall be installed;
- (b) sufficient water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;
- (c) proper drainage system;
- (d) arrangements for disposal of garbage;
- (e) protection from mosquitoes by providing mosquito nets;
- (f) annual pest control;
- (g) sufficient number of well lit and airy toilets in the proportion of at least one toilet for seven children;
- (h) sufficient number of well lit and airy bathrooms in the proportion of at least one bath room for ten children;
- (i) sufficient space for washing;
- (j) clean and fly-proof kitchen and separate area for washing utensils;
- (k) sunning of bedding and clothing;
- (l) maintenance of cleanliness in the Medical Centre.

43. Daily Routine.— (1) Every institution shall have a daily routine for the juveniles or children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(2) The daily routine shall provide, *inter alia*, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organized recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for sundays and holidays.

44. Nutrition and Diet Scale.— The following nutrition and diet scale shall be followed by the institutions, namely:-

- (a) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;
- (b) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale set out in Schedule II of these rules;
- (c) every institution under this Act shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale specified in Schedule II;
- (d) juveniles or children may be provided special meals on holidays and festivals;
- (e) infants and sick juveniles or children shall be provided special diet according to the advise of the doctor on their dietary requirement.

45. Medical Care.— Every institution shall:

- (a) maintain a medical record of each juvenile or child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;
- (b) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problem;
- (c) have arrangement for the medical facilities, including a doctor on call available on all working days for regular medical check-ups and treatment of juveniles or children;
- (d) have sufficient medical equipments to handle minor health problems including first aid kit with stock of emergency medicines and consumables;
- (e) train all staff in handling first aid;
- (f) tie-up with local Primary Health Centre, government hospital, medical colleges, other hospitals, clinical psychologists and psychiatrists and mental health institutes for regular visits by their doctors and students and for holding periodic health camps within the institutions;
- (g) make necessary arrangements made for the immunization coverage;
- (h) take preventive measures in the event of outbreak of contagious or infectious diseases;

- (i) set up a system for referral of cases with deteriorating health or serious cases to the nearest civil hospital or recognised treatment centres;
- (j) keep sick children under constant medical supervision;
- (k) admit a juvenile or child without insisting on a medical certificate at the time of admission;
- (l) arrange for a medical examination of each juvenile or child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty four hours and in special cases or medical emergencies immediately;
- (m) arrange for a medical examination of the juvenile or child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;
- (n) not carry out any surgical treatment on any juvenile or child without the previous consent of his parent or guardian, unless either the parent or guardian cannot be found and the condition of the juvenile or child is such that any delay shall, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the juvenile or child, or otherwise without obtaining a written consent to this effect from the Officer-in-charge of the institution;
- (o) provide or arrange for regular counselling of every juvenile or child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution;
- (p) refer such children who is addicted of alcohol or other intoxicated drugs which lead to change the children's behaviour to such rehabilitation centres or centres of mentally retired person (along with the person addicted to Narcotic drugs and psychotropic substance) for treatment as Indoor patient maintained by the Government.

46. Mental Health.— (1) A mental health record of every juvenile or child shall be maintained by the concerned institutions.

(2) Both mileu based interventions that is creating an enabling environment for children and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, milieu based intervention is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and

environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take to decisions regarding their life and thus, they develop and identify beyond their negative experiences and such intervention has a critical emotional impact on the child.

(3) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing juveniles or children to cope with their situation and regain confidence.

(4) All persons involved in taking care of the juveniles or children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists.

(5) Individual therapy is a specialized process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.

(6) Every institution shall have the services of trained counsellors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar government and non-governmental agencies, for specialized and regular individual therapy for every juvenile or child in the institution.

(7) A mental health care plan shall be developed for every juvenile or child by the child welfare officers in consultation with mental health experts associated with the institution and integrated into the individual care plan of the concerned juvenile or child.

(8) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file and integrated into the care plan for every child.

(9) All care plans shall be produced before the Management Committee set up under rule 55 of these rules every month and before the Child Welfare Committee every quarter.

(10) No juvenile or child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by appropriately trained mental health professionals.

47. Education.— (1) Every institution shall provide education to all juveniles or children according to their age and ability, both inside or outside the institution as per

the requirement.

- (2) There shall be a range of educational opportunities including schools, bridge school, open school, non formal education and learning and input from special educators where needed, shall be available.
- (3) Wherever necessary, extra coaching services shall be made available to school going children in the institutions these services shall provide by encouraging volunteer or contracting with coaching centres.
- (4) Those children who are illiterate or who has been feeling difficult in respect of knowledgeable or learning shall have right of special education.
- (5) Those children who are upper age for education from the compulsory age of school going and they want to continue their education shall be allowed and shall be encouraged for this and to facilitate their appropriate educational programme and the endeavour shall be made as far as possible for this purpose.
- (6) In the diploma or certificate regarding education of the children under the Act shall not be showed in any manner that the children stayed any time in the institution.
- (7) Library should be available in every institution in which appropriate stock of periodical journals for children educational and amusement both type of books and for which the children should be made enable to be encouraged.
- (8) There religion shall be honoured to the belief of the children's and there will be conducted not such classes which force the children to exchange their religion.

48. Vocational Training.— (1) Every institution shall provide the vocational training which is to be benefitted the juvenile or children .

- (2) The institutions of such kind shall contact with Institute of Technical Instruction, Jan Shikshan Sansthan, Government and Private Organization, Enterprises, Agencies or non-governmental organisations with expertise or placement agencies.
- (3) Except those children who are temporally under care in the observation home and who are above the age of compulsory education school, every children shall have right to obtain the vocational training in that trade which can be prepared for his employment in future.
- (4) With due regard to the suitable vocational choice and requirements of institutional administration, the children should be encouraged to choose work

of the same nature which they would like to do.

- (5) The child shall be provided with the opportunity of searching work with the remuneration and to continue his education and training according to the Labour Act as far as possible but they will not be required to do so. These factors like work education or training etc. of the children would not be reason to keep them in the institution
- (6) As far as possible, with a view to increase possibility to obtain suitable employment to the children on being returned to his community to give opportunity of complementary as supplementary vocational training, the work with the remuneration shall be provided in the local community. The work shall be such as the child can get appropriate training which is beneficial to him after his release. The work and the manner taking of work to be done in the organisation and the like work in the community shall be similarly as nearest as possible, so that the children can be prepared to face the ordinary vocational life.
- (7) Every child, who works by virtue of remuneration shall have the right to obtain justifiable remuneration, in the interest of children and his vocational training, the juvenile justice institution or any third party shall not get any benefit under the provision. The part of amount of earning of the child can be kept secured separately for constituting saving fund. The child shall have the right to use of remaining part of amount of his earning for purchase of any article for his own uses or to compensate the victim suffered due to offence committed by him or of his family or can be sent to any other person outside the institution

49. Recreation facilities.—

- (1) Institutions shall provide the guided recreation services for all Juveniles or Children's.
- (2) Recreation services includes outdoor and indoor game to be played, music, television, picnic, outings, cultural programme and library.

50. Institutional Management of juveniles or children.— (1) The following procedure shall be followed in respect of the newly admitted juveniles:

- (a) receiving and search;
- (b) disinfection and storing of juvenile's personal belongings and other valuables;
- (c) bath and haircut (unless prohibited by religion);
- (d) issue of toiletry items; new set of clothes, bedding and other outfit and

- equipment (as per scales);
- (e) medical examination and treatment where necessary and in case of every juvenile suspected to be suffering from contagious or infectious diseases, mental ailments or addiction;
 - (f) segregation in specially earmarked dormitories or wards or hospitals in case of a child suffering from contagious disease requiring special care and caution;
 - (g) attending to immediate and urgent needs of the juveniles like appearing in examinations, interview letter to parents, personal problems and verification by the Officer-in-charge of age of juvenile as per order of the Board.
- (2) Every newly admitted juvenile or child shall be allotted a case worker from amongst the probation officers or child welfare officers or social workers or counsellors attached to the institutions or voluntary social workers or counsellors.
- (3) Every newly admitted juvenile shall be familiarized with the institution and its functioning and shall receive orientation in the following areas:
- (a) personal health, hygiene and sanitation;
 - (b) institutional discipline and standards of behaviour, respect for elders and teachers;
 - (c) daily routine, peer interaction, optimum use of developmental opportunities; and
 - (d) rights, responsibilities and obligations within the institution.
- (4) The designated officer shall enter the name of the juvenile or child in the Admission Register and allocate appropriate accommodation facility.
- (5) The photograph shall also be taken immediately for records and the case worker or probation officer or welfare officer shall begin the investigation and correspondence with the person, the juvenile or child might have named.
- (6) The Officer-in-charge shall see that the personal belongings of the juvenile or child received by the institution is kept in safe custody and recorded in the Personal Belonging Register and the item must be returned to the juvenile or child when he leaves the institution.
- (7) The girl juvenile or child shall be searched by a female member of the staff, and with due regard to decency and dignity of the juvenile or child.

(8) The educational level and vocational aptitude of the juvenile admitted, may be assessed on the basis of test and interview conducted by the teacher, the workshop supervisor and other technical staff and necessary linkages may also be established with outside specialists and community-based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and local doctors, open school or Jan Sikshan Sansthan.

(9) A case history of the juvenile or the child admitted to an institution shall be maintained as per **Form XX**, which shall contain information regarding his socio-cultural and economic background and these information's may invariably be collected through all possible and available sources, including home, parents or guardians, employer, school, friends and community.

(10) A well conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from special homes shall be organized in all institutions in close collaboration with existing governmental and voluntary welfare organizations.

(11) In the event of a juvenile or child leaving the institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the officer-in-charge of the concerned institution to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the juvenile or child where the juvenile or child is missing, shall be sent to the Board or Committee, as the case may be.

(12) An individual care plan for every juvenile or child in institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re-integrated based on their case history, circumstances and individual needs and the individual care plan shall be based on following guidelines:

- (a) the Officer-in-charge, counsellor along with the child welfare officer or case worker, or social worker shall prepare an individual care plan for every child in an institution within one month of his admittance as per **Form XXI**;
- (b) all care plans shall include a plan for the juvenile's or child's restoration, rehabilitation, reintegration and follow-up;
- (c) the care plan shall be reviewed quarterly by the Management Committee set up under rule 55 of these rules for appropriate development and

rehabilitation including options for release or restoration to family or foster care or adoption;

- (d) juveniles or children shall be consulted while determining their care plan;
- (e) continuity of care plan shall be ensured in cases of transfer or repatriation or restoration.

51. Prohibited Articles.— No person shall bring into the institution the following prohibited articles, namely:

- (a) fire-arms or other weapons, whether requiring license or not (like knife, blades, lathi, spears and swords);
- (b) alcohol and spirit of any description;
- (c) bhang, ganja, opium or other narcotic or psychotropic substances;
- (d) tobacco; or
- (e) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

52. Articles found on search and inspection.— (1) The Officer-in-Charge shall see that every juvenile received in the institution is searched, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the juvenile is kept in the safe custody of the Officer-in-Charge.

(2) The girls shall be searched by a female member of the staff and both the girls and boys shall be searched with due regard to decency and dignity.

(3) In every institution, a record of money, valuables and other articles found with a juvenile shall be maintained in the "Personal Belongings Register".

(4) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each juvenile, shall be read over to juvenile in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Officer-in-Charge.

53. Disposal of articles.— The money or valuables belonging to a juvenile received or retained in an institution shall be disposed of in the following manner, namely:

- (a) on an order made by the competent authority in respect of any juvenile, directing the juvenile to be sent to an institution, the Officer-in-Charge shall

deposit such juvenile's money together with the sale proceeds in the manner laid down from time to time in the name of the juvenile;

(b) the juvenile's money shall be kept with the Officer-in-Charge and valuables, clothing, bedding and other articles, if any, shall be kept in safe custody;

(c) when such juvenile is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be sent along with the juvenile to the Officer-in-Charge of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description and estimated value thereof;

(d) at the time of release of such juvenile, the valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in name of the juvenile shall be handed over to the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the Officer-in-Charge;

(e) when a juvenile in an institution dies, the valuable and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the juvenile shall be handed over by the Officer-in-Charge to any person who establishes his claim thereto and executes an indemnity bond;

(f) a receipt shall be obtained from such person for having received such valuables and other articles and the amount;

(g) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of such juvenile, the valuables and other articles and amount shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee set up under rule 55 of these rules.

54. Maintenance of case file.— (1) The case file of each juvenile and child shall be maintained in the institution containing the following information:

(a) report of the person or agency who produced the juvenile before the Board;

(b) officer-in-charge's, probation officer's or child welfare officer's, counsellor's and case-workers reports;

(c) information from previous institution;

(d) report of the initial interaction with the juvenile, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;

(e) source of further information;

- (f) observation reports from staff members;
- (g) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, progress reports *vis-a-vis* psychological counselling or any other mental health intervention, where applicable;
- (h) Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, educational or vocational tests;
- (i) social history;
- (j) summary and analysis by case-worker and Officer-in-charge;
- (k) instruction regarding training and treatment programme and about special precautions to be taken;
- (l) leave and other privileges granted;
- (m) special achievements and violation of rules, if any, ;
- (n) quarterly progress report;
- (o) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed in **Form XXI**;
- (p) leave of absence or release under supervision;
- (q) final discharge;
- (r) follow-up reports;
- (s) annual photograph;
- (t) case history duly filled in prescribed **Form XX**;
- (u) follow-up report of post release cases as per direction of the competent authority if any; and
- (v) remarks.

(2) All the case files maintained by the institutions and the Board or Committee shall, as far as possible, be computerised and networked so that the data is centrally available to the State and the District Child Protection Unit and the State Government.

55. Management Committee.—(1) Every institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every juvenile and child.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, a juvenile or child shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay order.

(3) The Management Committee shall consist of the following personnel:

District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)	-	Chairperson
Officer-in-charge	-	Member-Secretary
Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker	-	Member
Medical Officer	-	Member
Psychologist or Counsellor	-	Member
Workshop Supervisor or Instructor in Vocation Teacher-	-	Member
Social Worker Member of Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee	-	Member
A juvenile or child representative from each of the Children's Committees (on a monthly rotation basis to ensure representation of juveniles or children from all age groups)	-	Member

(4) In the districts where District Child Protection Unit is not constituted the District Magistrate or Collector or his nominee shall be the Chairperson of this Committee.

(5) Where voluntary organizations are involved in providing professional and technical services like education, vocational training, psychosocial care, mental health intervention and legal aid, the Management Committee may invite a representative of such voluntary organizations as a special invitee to the Management Committee meetings.

(6) (a) The Management Committee shall meet every month to consider and review—

- (i) custodial care or care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;
- (ii) medical facilities and treatment;
- (iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;
- (iv) mental health interventions with the juveniles and children;
- (v) individual problems of juveniles and children, provision of legal aid services and institutional adjustment, leading to the quarterly review of individual care plans;
- (vi) vocational training and opportunities for employment;
- (vii) education and life skills development programmes;

- (viii) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counselling;
- (ix) review of progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the juveniles and children;
- (x) planning post-release or post-restoration rehabilitation programme and follow up for a period of two years in collaboration with aftercare services;
- (xi) pre-release or pre-restoration preparation;
- (xii) release or restoration;
- (xiii) post release or post-restoration follow-up;
- (xiv) minimum standards of care, including infrastructure and services available;
- (xv) daily routine;
- (xvi) community participation and voluntarism in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;
- (xvii) oversee that all registers as required under the Act and rules are maintained by the institution, check and verify these registers, duly stamped and signed in the monthly review meetings;
- (xviii) matters concerning the Children's Committees;
- (xix) any other matter which the Officer-in-Charge may like to bring up.

(b) The officer-in-charge or child welfare officer shall file a quarterly progress report of every juvenile or child in the case file and send a copy to the District Child Protection Unit and Board or Committee, as the case may be.

(7) The Management Committee shall set up a complaint and redress mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible to juveniles and children away from the office set up and closer to the residence or rooms or dormitories of the children.

(8) (a) The Children's Suggestion Box, whose key shall remain in the custody of the Chairperson of the Management Committee, shall be checked every week by the Chairperson of the Management Committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

(b) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.

(c) The quorum for conducting the emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of Committee or the Board, as the case may be, and the Officer-in-Charge of the institution.

(d) In the event of a serious allegation or complaint against the Officer-in-Charge of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.

(e) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the monthly meeting of the Management Committee.

(9) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after every monthly meeting of the Management Committee.

(10) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once in three months.

56. Children's Committees.— (1) Officer-in-Charge of every institution for juveniles or children shall facilitate the setting up of Children's Committees for three different age groups of children, viz., 6-10 years, 11-15 years and 16-18 years and these Children's Committees shall be constituted solely by children.

(2) Such Children's Committee shall be encouraged to participate in following activities:

- (a) improvement of the condition of the institution;
- (b) reviewing the standards of care being followed;
- (c) preparing daily routine and diet scale;

- (d) developing educational, vocational and recreation plans;
 - (e) supporting each other in managing crisis;
 - (f) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;
 - (g) creative expression of their views through wall papers or newsletters or paintings or music or theatre;
 - (h) management of institution through the Management Committee.
- (3) The Officer-in-Charge shall ensure that the Children's Committees meet every month and maintain a register for recording its activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their monthly meetings.
- (4) The Officer-in-Charge shall ensure that the Children's Committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.
- (5) The Officer-in-Charge shall, as far as possible, seek assistance from local voluntary organization or child participation experts for the setting up and functioning of the Children's Committees.
- (6) The local voluntary organization or child participation expert shall support the Children's Committees in the following:
- (a) selecting their leaders;
 - (b) conducting the monthly meetings;
 - (c) developing rules for the functioning of Children's Committees and following it;
 - (d) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents;
 - (e) any other innovative activity.
- (7) The Management Committee shall seek a report from the Officer-in-Charge on the setting up and functioning of the Children's Committees, review these reports in their monthly meetings and take necessary action where required.
- 57. Rewards and Earnings.**— The rewards to a juvenile or child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, may be granted by the Officer-in-Charge as an encouragement to steady work and good behaviour;

and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian who comes to take charge of the juvenile or child or juvenile or child himself.

58. Visits to and communication with juveniles or children.— (1) The parents and relatives of the juveniles or children shall be allowed to visit once in a month or in special cases, more frequently at the discretion of the Officer-in-Charge as per the visiting hours laid down by him, except where parents or relatives or guardian have been found to be responsible for subjecting the juvenile or child to violence, abuse and exploitation.

(2) The receipt of letters by the juveniles or children of the institution shall not be restricted and they shall have freedom to write as many letters as they like at all reasonable times; and the institution shall ensure that where parents, guardians or relatives are known, at least one letter is written by the juvenile or children every month for which the postage shall be provided by the institution.

(3) The Officer-in-Charge may peruse any letter written by or to the juvenile or children, and may for the reasons that he considers sufficient refuse to deliver or issue the letter and forward it to the Committee after recording his reasons in a book maintained for the purpose.

(4) The Officer-in-Charge shall, in special circumstances or as per orders of the Board or Committee, allow a juvenile or child to make telephonic communication with his parents or guardians or relatives.

59. Death of a juvenile or child.— On the occurrence of any case of death or suicide in an institution the procedure to be adopted shall be as under: -

(1) In the event of an unnatural death or suicide of a juvenile or child in an institution it is imperative for the institution to ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.

(2) In case of natural death or due to illness of a juvenile or child, the Officer-in-charge shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the nearest Police Station, the Board or Committee, the National or State Commission for Protection of

Child Rights, District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other concerned authority and the parents or guardians or relatives of the juvenile or child.

(3) Whenever a sudden or violent death or death from suicide or accident takes place, immediate information shall be given by the case-worker or probation officer or welfare officer to the Officer-in-Charge and the Medical Officer and the Officer-in-Charge shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and the parents or guardians or relatives of the deceased juvenile or child.

(4) If a juvenile or child dies within 24 hours of his admission to the institution, the Officer-in-charge of the institution shall report the matter to the officer-in-charge of the Police Station having jurisdiction and the District Medical Officer or the nearest Government Hospital and the parents or guardians or relatives of such juvenile or child without delay.

(5) The Officer-in-charge shall also immediately give intimation to nearest Magistrate empowered to hold inquests and to the Board or as the case may be the Committee.

(6) The Officer-in-Charge and the Medical Officer at the institution shall record the circumstances of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the Officer-in-charge of the police station having jurisdiction, the Committee and the District Medical Officer or the nearest government hospital where the dead body of the juvenile or child is sent for examination, inspection and determination of the cause of death and the Officer-in-charge and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of the death if any, and submit it to the concerned Magistrate and the Officer-in-charge of the police station having jurisdiction.

(7) The officer-in-charge and the Medical Officer shall make themselves available for any inquiries initiated by the police or the Magistrate concerning the cause of death and other details regarding such juvenile or child.

(8) As soon as the inquest is held, the body shall be handed over to the parents or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rituals shall be performed under the supervision of the officer-in-charge in accordance with the known religion of the juvenile or child.

60. Abuse and exploitation of the juvenile or child.— (1) Every institution shall

have systems of ensuring that there is no abuse, neglect and maltreatment and this shall include the staff being aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment as well as early indicators of abuse, neglect and maltreatment and how to respond to these.

(2) In the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of juveniles and children in an institution by those responsible for care and protection, the following action shall be taken:

- (i) the incidence of abuse and exploitation must be reported by any staff member of the institution immediately to the Officer-in-Charge on receiving such information;
- (ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Officer-in-Charge, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn, shall order for special investigation;
- (iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance of such occurrences and conduct necessary investigations;
- (iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of all inquiry and provide legal aid as well as counselling to the juvenile or child victim;
- (v) the Board or Committee shall transfer such a juvenile or child to another institution or place of safety or fit person;
- (vi) the Officer-in-charge of the institution shall also inform the chairperson of the management committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken before the management committee in its next meeting;
- (vii) in the event of any other crime committed in respect of juveniles or children in institutions, the Board or the Committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police station or Special Juvenile Police Unit;
- (viii) the Board or Committee may consult Children's Committee setup in each

institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from relevant voluntary organizations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of juveniles or children in an institution.

61. Juvenile or Child suffering from dangerous diseases or mental health problems.—

(1) When a juvenile or a child placed under the care of a fit person or a fit institution under the provisions of the Act, is found to be suffering from a disease or physical or mental health problems requiring prolonged medical treatment, or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance, the juvenile or the child may be sent by an order of the competent authority to an appropriate place for such period as may be certified by medical officer to be necessary for proper treatment of the juvenile or the child or for the remainder of the term for which he has to stay.

(2) When the juvenile or the child is cured of the disease or physical or mental health problems, the competent authority may, if the juvenile or child is still liable to stay, order the juvenile or the child to be placed back in the care of fit person or institution from where the juvenile or child was removed for treatment and if the juvenile or the child is no longer liable to be kept under the care of fit person or institution, the competent authority may order him to be discharged.

(3) The order of restoration of a juvenile or a child suffering from an infectious or contagious disease to his parents or guardian shall be passed on the principle of best interest of the juvenile or child, keeping in mind that there will be no risk of stigmatization and discrimination and discontinuation of treatment.

(4) Where there is no organization either within the jurisdiction of the competent authority, or nearby District or State for care and protection of juveniles or children suffering from serious psychiatric or physical disorder and infection, as required under section 58 of the Act, necessary organization shall be set up by the State Government at such places to cater to the special needs of such juveniles or children.

62. Leave of absence of a juvenile or child.— (1) A juvenile or child living in an institution may be allowed to go on leave of absence or released under supervision for examination or admission, special occasions like marriage or emergencies like death or accident or serious illness in the family.

(2) While the leave of absence for short period generally not exceeding seven days excluding the journey time may be recommended by the Officer-in-charge, but granting of such leave shall be by the Board or the Committee.

(3) The parents or guardian of the juvenile or the Officer-in-charge on behalf of the juvenile or child may submit an application to the Board or Committee requesting for relieving the juvenile or child on leave, stating clearly the purpose for the leave and the period of leave.

(4) While considering the application of leave of absence, the Board or Committee shall hear the juvenile or child or the parents or guardians of the juvenile or child and if the Board or Committee considers that granting of such leave is in the interest of the juvenile or child, appropriate order shall be made and the Board or Committee may call for a report from the probation officer or child welfare officer in case the preliminary information gathered from the juvenile or child or concerned parent or guardian is not sufficient for the purpose.

(5) While issuing orders sanctioning the leave of absence or relieving under supervision, as the case may be, the competent authority shall mention the period of leave and the conditions attached to the leave order, and if any of these conditions are not complied with during the leave period, the juvenile or child may be called back to the institution.

(6) The parent or guardian shall arrange to escort the juvenile or child from and to the institution and where it is not possible, the Officer-in-charge may arrange to escort the juvenile or child to the place of the family and back. In case the parents or guardian is willing to arrange escort but does not have requisite financial means, the Officer-in-charge shall arrange for the travelling expenses as admissible under the rules.

(7) If the juvenile or child runs away from the family during the leave period, the parent or guardian is required to inform the Officer-in-charge of the institution

immediately and try to trace the juvenile or child, and if found, the juvenile or child shall be brought back to the institution immediately.

(8) If the juvenile or child is not found within twenty four hours, the Officer-in-Charge shall report the matter to the nearest police station and missing person's bureau, but no adverse disciplinary action shall be taken against the juvenile or child and procedure laid down under the Act shall be followed.

(9) If the parent or guardian does not take proper care of the juvenile or child during the leave period or does not bring the juvenile or child back to the institution within the stipulated period, such leave may be refused on later occasions.

(10) If the juvenile or child does not return to the institution on expiry of the sanctioned leave period, the Board or Committee shall refer the case to police for taking charge of the juvenile and bring him back to the institution.

(11) The period of such leave shall be counted as a part of the period of stay in the institution and the time which elapses after the failure of a juvenile to return to the institution within the stipulated period, shall be excluded while computing the period of his stay in the institution.

63. (A) Inspection.— (1) The director/commissioner Women Empowerment any other officer authorised by him shall inspect such organization. The programme development monitoring and evaluation cell, the district advisory committee, local government authority shall inspect, monitor and evaluate the institutional and non-institutional programs on juvenile justice administration.

(2) The inspection should not be a fault finding mechanism rather it should be constructive. the inspecting officer cell furnish a report to the director/ commissioner women Empowerment for necessary follow-up.

(3) The team may visit the home either by prior intimation or by surprise.

(B) Reporting- (1) after completing the inspection committee shall be required to submit a report on the findings within the shortest time not exceeding 15 days. the

report should include the suggestion, request or compliant as made by the concerned person, an objective evaluation of the compliance of the facilities with the relevant provisions of this rules.

(2) Opinion of other relevant persons including those directly responsible for names in the complaints shall also be noted and their reasons and explanations noted verbatim.

(3) The inspection committee shall finally make any recommendation regarding any steps considered necessary to ensure compliance.

(4) Any fact discovered by the inspection committee which indicate violation of legal provision concerning the right of children or the operation of juvenile justice institution has occurred shall be communicated to the competent authorised for investigation and prosecution.

(5) Follow up action- the findings of the inspection and the suggestion of the children shall be taken in to confederation by the all concerned authorities.

64. Social Audit.— (1) The State Government shall monitor and evaluate the implementation of the Act annually by reviewing matters concerning establishment of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit where required, functioning of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit, functioning of institutions and staff, functioning of adoption agencies, child friendly administration of juvenile justice and any other matter concerning effective implementation of the Act in the State.

(2) The social audit shall be carried out with support and involvement of organizations working in the field of mental health, child care and protection and autonomous bodies like the National Institute of Public Co-operation and Child Development, Indian Council for Child Welfare, Childline India Foundation, Central and State level Social Welfare Boards, School of Social Work and School of Law.

65. Restoration and Follow-up. — (1) The order for restoration of the juvenile or child shall be made by the Board or Committee on the basis of a fair hearing of the juvenile or child and his parents or guardian, as well as on the reports of the Probation Officers or Child Welfare Officers or non-governmental organisations directed by the Board or Committee to conduct the home study and any other relevant document or report brought before the Board or Committee for deciding the matter.

(2) The Board or Committee shall send a copy of the restoration order along with a copy of the order for escort as per **Form XXII** to the District Child Protection Unit or

State Government who shall provide funds for restoration of the juvenile or child.

- (3) Every restoration shall be planned for as part of the individual care plans prepared by the case-workers or counsellors or child welfare officers or probation officer, as the case may be, and shall be based on the review and recommendations of the Management Committee set up under rule 55 of these rules.
- (4) Besides police, the Board or Committee shall seek collaboration with non-governmental organisations to accompany juveniles or children back to their family for restoration.
- (5) In case of, the juvenile or child girls they shall be accompanied by female escorts.
- (6) The expenses incurred on restoration of a juvenile or child, including travel and other incidental expenses, shall be borne by the District Child Protection Unit or State Government.
- (7) When a juvenile or child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or Committee shall make a note of it in its records in writing and such juvenile or child shall not be coerced or persuaded to go back to the family, particularly if the social investigation report of the child welfare officer or probation officer establishes that restoration to family may not be in the best interest of the juvenile or child or, if the parents or guardians refuse to accept the juvenile or child back.
- (8) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plans by the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organisations assigned by the Board or Committee to assist in restoration of the child.
- (9) A quarterly follow-up report shall be submitted to the Board or Committee by the concerned Child Welfare Officer or Probation Officer or non-governmental organisation for a period of two years with a copy to the officer-in-charge of the institution from where the juvenile or child is restored.
- (10) The follow-up report shall clearly state the situation of the juvenile or child post restoration and the juvenile's or child's needs to be met by the State Government in order to reduce further vulnerability of the juvenile or child.
- (11) The officer-in-charge shall file the follow-up report in the case-file of the juvenile or

child and place the report before the management committee set up under rule 55 of these rules in its next meeting.

(12) The officer-in-charge shall also send a copy of the follow-up reports to the District Child Protection Unit.

(13) Where a follow-up is not possible due to unavailability of government functionaries or non-governmental organisations, the concerned District Child Protection Unit shall provide necessary assistance and support to the concerned Board or Committee.

66. Visitor's Book.— (1) A Visitor's Book shall be maintained, in every institution, in which the person visiting the home shall record the date of his visit with remarks or suggestions, which he may think proper.

(2) The Officer- in-charge shall forward a copy of every such entry to the District Child Protection Unit or State Government, with such remarks as he may desire to offer in explanation or otherwise; and thereon, the designated authority shall issue such orders as he may consider necessary.

67. Maintenance of Registers.— The Officer- in-charge shall maintain in his office, such registers and forms, as required by the Act and as specified by these rules made there under and the list of registers or files or books to be maintained shall minimally comprise of:

- (a) Admission and discharge register;
- (b) Supervision register;
- (c) Medical file or medical report;
- (d) Nutrition diet file;
- (e) Stock register;
- (f) Log book;
- (g) Order book;
- (h) Meeting book;
- (i) Cash book;
- (j) Budget statement file;
- (k) Inquiry report file;
- (l) Individual case file with individual care plan;
- (m) Children's Suggestion book;
- (n) Visitor's book;

- (o) Staff movement register;
- (p) Personal belongings register;
- (q) Minutes register of Management Committee;
- (r) Minutes register of Children's Committees; and
- (s) Attendance registers for staff and juveniles or children.

68. Personnel or Staff of a Home.— (1) The personnel strength of a home shall be determined according to the duty, posts, hours of duty per day and category of children that the staff is meant to cater to.

(2) The institutional organizational set up shall be fixed in accordance with the size of the home, the capacity, workload, distribution of functions and requirements of programmes.

(3) The whole-time staff in a home may consist of Officer-in-charge, Probation Officer (in case of Observation home or Special home), Case Workers (in case of Children's home or shelter home or after care organization), Child Welfare Officers, Counsellor, Educator, Vocational Training Instructor, Medical Staff, Administrative staff, Care Takers, house father and house mother of the concerned institution or the shelter home, child mentors, volunteers, store keeper, cook, helper, washerman, safai karamchari, gardener as required.

(4) The part-time staff, shall include Psychiatrist, Psychologist, Occupational therapist, and other professionals as may be required by time to time.

(5) The staff of the home shall be subject to control and overall supervision of the Officer-in-charge who by order, shall determine their specific responsibilities and shall keep the concerned authority informed of such orders made by him from time to time.

(6) The duties and responsibilities of the staff under the Officer-in-charge shall be fixed in keeping with the statutory requirements of the Act.

(7) The Officer-in-charge and such other staff who may be required, shall live in the quarters provided for them within the premises of the home.

(8) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution; and the staff shall be appointed in accordance with the educational qualifications, training and experience required for each category.

(9) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of one hundred juveniles or children could be as mentioned below:

Sl. No.	Staff/Personnel	No. of Posts
(1)	(2)	(3)
1.	Officer-in-Charge (Superintendent)	1
2.	Counsellor	2
3.	Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker	3
4.	House Mother or House Father	4
5.	Educator	2 (voluntary or part time)
6.	Doctor	1
7.	Paramedical staff	1
8.	Store-keeper cum Accountant	1
9.	Art and Craft cum Music Teacher	1 (part time)
10.	P.T. Instructor cum Yoga Trainer	1 (part time)
11.	Driver	1
12.	Cook	2
13.	Helper	2
14.	Housekeeping	2
15.	Gardener	1 (part time)
	Total	25

(10) The number of posts in the category of counsellor, case worker or probation officer, house father or house mother, educator, and vocational instructor shall proportionally increase with the increase in the capacity of the institution.

(11) In case of institutions housing infants, provision for *ayahs* and paramedical staff shall be made as per the need.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

69. Recognition of fit persons or fit institution.—

- (1) Any individual who is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care, protection or treatment for a period as may be necessary, may be recognized by the competent authority as a fit person after due verification of their credentials and reputation.
- (2) Any suitable place or institution, the manager of which is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care and protection for a period as may be necessary, may be recognized by the State Government as a fit institution on the recommendation of the competent authority.
- (3) An institution recognized as a fit institutions shall,—
 - (a) meet the standards of care laid down in the Act and the rules made thereunder;
 - (b) have the capacity and willingness to meet the standards of care laid down in the Act and the rules;
 - (c) receive and provide basic services for care and protection of the juveniles and children;
 - (d) prevent subjection of juvenile or child to any form of cruelty or exploitation or neglect; and
 - (e) abide by the orders of the competent authority.
- (4) A list of fit institutions approved by the State Government shall be kept in the office of the Board and the Committee.
- (5) A fit institution with collateral branches may send the juvenile or child placed therein by an order of the competent authority to any of its branches after seeking permission from the competent authority.
- (6) before declaring any person as a fit person or recommending an institution as a fit institution, the competent authority shall hold due enquiry and only on being satisfied, recognition shall be given.

70. Certification or recognition and transfer of Management of Institutions and after care organizations.—

(1) Any organization desiring certification under the Act shall make an application together with a copy each of the rules, bye-laws articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past record of specialized childcare services provided by the organization, to the State Government, who shall after verifying the provisions made in the organization for the boarding and lodging, general health, educational facilities, vocational training and treatment services may grant certification or recognition under sections 8, 9, 34, 37, 41 and 44 of the Act, as the case may be, on the condition that the organization shall comply with the standards or services as laid down under the Act and the rules framed thereunder, from time to time and to ensure an all round growth and development of juvenile or child placed under its charge.

(2) Any organization desiring recognition under the Act shall make an application to the Competent Authority, who shall after due inquiry, recommend the State Government for such recognition.

(3) The State Government may, transfer the management of any State run institution under the Act to a voluntary organization of repute, who has the capacity to run such an institution; and certify or recognize the said voluntary organization as a fit institution to own the requisite responsibilities under a Memorandum of Understanding for a specified period of time.

(4) The State Government may, if dissatisfied with the conditions, rules, management of the organization certified or recognized under the Act, at any time, by notice served on the manager or head of the organization, declare that the certificate or recognition of the organization, as the case may be, shall stand withdrawn as from a date specified in the notice and from the said date, the organization shall cease to be an organization certified or recognised under sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act, as the case may be:

Provided that the concerned organization shall be given an opportunity of making a representation in writing, within a period of thirty days, against the grounds of withdrawal of certificate or recognition of that organization.

(5) The decision to withdraw or to restore the certificate or recognition of the organization may be taken, on the basis of a thorough investigation by a specially constituted advisory board under section 62 of the Act.

(6) On the report of the advisory board, the Officer- in- charge of the institution shall be asked to show cause so as to give an explanation within thirty days.

(7) When an organization ceases to be an organization, certified or recognised under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act, the juvenile or the child kept therein shall, be transferred to some other institution of repute, certified or recognized under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act or discharged, in accordance with the provisions of the Act and the rules relating to their discharge and transfer by giving intimation of such discharge or transfer to the Board or the Committee, as the case may be.

71. Registration under the Act.—

(1) All institutions and organisations running institutional or non-institutional care services for children in need of care and protection, whether run by the government or voluntary organization, shall get themselves registered under sub-section (3) of section 34 of the Act.

(2) All such institutions shall make an application together with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, balance sheet of past 3 years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organization to the State Government, who shall after verifying that provisions made in the institution or organization for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, if any, vocational facilities and scope of rehabilitation, may issue a registration certificate to such organization under sub-section (3) of section 34 of the Act and as per this rule.

72. Grant in aid to certified or recognized organization.— (1) An organization certified or recognized or registered under sections 8, 9, 34, sub-section (3) of section 34, 37 or 44 of the Act, may during the period when certification or recognition or registration is in force, may apply for grants-in-aid by the State Government, for the maintenance of juvenile or child received by them under the provisions of the Act; and for expenses incurred on their education,

treatment, vocational training, development and rehabilitation.

(2) The grants-in-aid may be admissible, at such rates, which shall be sufficient to meet the prescribed norms, in such manner and subject to such conditions as may be mutually agreed to by both the parties.

(3) In case of transfer of management of government run homes under sections 8, 9, 34, sub-section (3) of section 34, 37 and 44 of the Act to a voluntary organization, the same budget which the Government was spending on that home, shall be given to the voluntary organization as grant-in-aid under the Memorandum of Understanding signed between both the parties describing their role and obligations.

73. Admission of outsiders.— (1) No stranger shall be admitted to the premises of the institution, except with the permission of the Officer-in-charge or by an order from the Board or Committee.

(2) In special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another state or district, the Officer-in-Charge shall allow parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children, provided they possess proper identification and are not reported to have subjected the juvenile or child to abuse and exploitation.

74. Identity Photos.— (1) On admission to a home established under the Act, the photo of every juvenile or child shall be taken.

(2) One photograph shall be kept in the case file of the juvenile or the child, one shall be fixed with the index card, a copy shall be kept in an album serially numbered with the negative in another album, and a copy of the photograph shall be sent to the Board or Committee as case may be, as well as to the district or State Child Protection Unit.

(3) In case of a child missing from an institution or in case of lost children received by an institution, a photograph of the child with relevant details shall be sent to the missing person's bureau and the local police station.

75. Police Officers to be in plain clothes.— While dealing with a juvenile or a child under the provisions of the Act and the rules made thereunder, except at the time of

arrest, the Police Officer shall wear plain clothes and not the police uniform.

76. Prohibition of use of handcuffs and fettered:- In the case of violation of law no juvenile or the child shall be handcuffs or fetters under the provision of the Act and the rules made thereunder.

77. Procedure to be followed by a Magistrate not empowered under the Act :-

(1) when any juvenile or child is produced before a magistrate other than Board or committee, and the Magistrate is of the opinion that such person is a juvenile or child, he shall record his reasons and send the juvenile or child to the appropriate competent authority.

(2) In case of a juvenile produced before a Magistrate not empowered under this Act, such Magistrate shall direct the case to be transferred to the Board for inquiry and disposal.

(3) In case of a child in need of care and protection produced as a victim of a crime before a magistrate not empowered under the Act this such case this Magistrate shall transfer the matter concerning care and protection, rehabilitation and restoration of the child to the appropriate committee.

78. Transfer;-(1) During the inquiry, if it is found that the juvenile or child is from place outside the jurisdiction of the Board or committee, the Board or Committee shall order the transfer of the juvenile or child and send a copy of the order to the State Government or State or Dietrich Child Protection Unit provided that .

(i) Such transfer is in the best interest of the juvenile or child,

(ii) no child shall be transferred or proposed to be transferred only on the ground that the child has created problems or, has become difficult to be managed in the existing institution or, is suffering from a chronic or terminal illness or, on account of disability,

(iii) such transfer shall only take place after the completion of evidence and cross, examination that may be required in a legal proceeding involving juveniles or child, and

(iv) the reasons circumstances of such transfer shall be reordereed in writing .

(2) The State Government or State or District Child Protection unit shall accordingly;

- (i) Sent the informant of transfer to the appropriate competent authority having Jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and
- (ii) Send a copy of the information to the officer-in charge of the institution where the child is placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) On receipt of copy of the information from the State Government or State or District child Protection Unit, the officer-in-charge shall arrange to escort the child at government expenses to the place or person as specified in the order.

(4) On such transfer, case file and records of the juvenile or child shall be sent along with the juvenile or child.

79. Procedure for sending a juvenile or child outside the jurisdiction of the competent authority ;-(1)In the case of a juvenile or a child whose ordinary place of residence lies outside the jurisdiction of the competent authority, and if the competent authority considers it necessary to take action under section 50 of the Act. it shall direct a probation officer or case worker or child welfare officer, as the case may be, to make enquires as to the fitness and willingness of the relative or other person to receive the juvenile or the child at the ordinary place of residence, and whether such relative or other fit person can exercise proper care and control over the juvenile or the child.

(2)Where a juvenile or child is ordered to be sent to the ordinary place of residence or to a relative or fit person, execution of a bond by the juvenile or child without any surety, in form VI, is necessary along with an undertaking by the said relative or fit person in Form V or IX as the case may be.

(3)Any breach of a bond or undertaking or of both given under sub-rule(2) of this rule, shall render the juvenile liable to be brought before the competent authority, who may make an order directing the juvenile to be sent to an institution home.

(4)Any juveniles or a child ,who is a foreigner and who has lost contact with his family shall also be entitled for protection .

(5) The juvenile or the child, who is a foreigner national, shall be repatriated, at the earliest, to the country of his origin in co-ordination with the respective Embassy or High Commission.

(6) The Board or committee shall inform the Ministry of External Affairs (informed) about repatriation of every juvenile or child or foreigner carried out on the orders of the Board or Committee.

(7) A copy of the order passed by the competent authority under section 50 of the Act shall be sent to :-

- (a) the probation officer or child welfare officer who was directed to submit a report under sub-rule (1) of this rule.
- (b) the probation officer or child welfare officer, if any, having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent,
- (c) the competent authority having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent, and
- (d) the relative or the person who is to receive the juvenile or the child.

(8) During the pendency of the order under sub-rule (6) of this rule, the juvenile or the child shall be sent by the competent authority to an observation home or children's home as the case may be.

(9) Whenever the competent authority considers it expedient to send the juvenile or the child back to his ordinary place or residence under section 50, the competent authority shall inform the relative or the fit person, who is to receive the juvenile or the child accordingly, and shall invite the said relative or fit person to come to the home, to take charge of the juvenile or the child on such date, as may be specified by the competent authority.

(10) The competent authority inviting the said relative or fit person under sub-rule (8) of this rule may also direct, if necessary, the payment to be made by the officer-in-charge of the home of the actual expenses of the relative or fit person's journey both

ways, by the appropriate class and the juvenile's or child's journey from the home to his ordinary place of residence, at the time of sending the juvenile or the child.

(11) If the relative or the fit person fails to take charge of the juvenile or the child on the specified date, the juvenile or the child shall be taken to his ordinary place of residence by the escort of the observation home and in the case of a girl, at least one escort shall be a female.

80. State Child Protection Unit:- The specific functions of the state child protection unit shall following:

- (a) to implementation of the Act and supervision and monitoring of agencies and institutions under the Act,
- (b) to set up, support and monitor the District Child Protection Units,
- (c) to represent State Child Protection Unit as a member in the selection committee for appointment of members of Boards or Committees,
- (d) to make necessary funds available to the District child Protection Units for providing or setting up required facilities to implementation the Act ,
- (e) to network and coordinate with all Government departments to build inter-Sectoral linkages on child protection issues, including Departments of Health, Education, Social welfare, Urban Basic Services, Backward classes and Minorities, Youth Services, police, Judiciary, Labour, State AIDS Control Society, among others,
- (f) to network and coordinate with civil society organizations working for the effective implementation of the Act,
- (g) to training and capacity building of all personnel (Government and 'Non-government) working under the Act,
- (h) to establish Minimum Standards of care and ensure its implementation in all institutions set up under the Act,
- (i) to review of the functioning of Committees, and
- (j) to all other functions necessary for effective implementation of the Act.

81. District Child production unit :-(1) The District Child protection unit shall coordinate and implement all child rights and protection activities at district level.

(2) The specific functions of the District Child Protection Unit shall include,

- (a) to ensure effective implementation of the Act at district or city levels by supporting assists creation of adequate infrastructure, such as, setting up Boards Committees, Special Juvenile Police Units homes in each districts,
- (b) to identify families at risk and children in need of care and protection,
- (c) to assess the number of children in difficult circumstances and creating district-specific databases to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances,
- (d) to periodic and regular mapping of all child related services at district for creating a resource directory and making the information available to the committees and Boards from time to time.
- (e) to implement of family based non-institutional services including sponsorship, foster care, adoption and after care,
- (f) to ensure establishment of District, Block and Village level Child Protection Committees for effective implementation of programmers as well as discharge of its functions;
- (g) to assist the transfer of children at all levels for either their restoration to their families or placing the child in long or short term rehabilitation through institutionalization adoption, foster care and sponsorship.
- (h) to supporting State Adoption Resource Agency in implementation of family based non-institutional services at district level,
- (i) to network and coordinate with all government departments to build inter-sectoral linkages on child protection issues, including Departments of Health, Education Social welfare, Urban Basic services, Backward classes and Minorities, youth Service, police judiciary, Labour, State AIDS control Society, among others,
- (j) to network and coordinate with civil society organizations working under the Act.

- (k) to develop parameters and tools for the effective monitoring and supervision of agencies and institutions in the district in consultation with experts in child welfare.
- (l) to supervise and monitor all institutions or agencies providing residential facilities to children in district,
- (m) to train and build capacity of all personnel $\frac{1}{4}$ Government and Non-government) implementing the Act to provide effective services to children.
- (n) to organize quarterly meeting with all stakeholders at district level Including CHILDLINE, Specialized Adoption Agencies, Officer-in-charge of homes, non-government organizations and members of public to review the progress and implementation of the Act and
- (o) to liaison with the State Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency at State level and District Child Protection Units of other districts.

82. Constitution of the child welfare committee:- The State Government shall by notification in Official Gazette constitute the child welfare committees under section 29 of the Act in every district with requisite infrastructure, personnel, and finances for smooth running as listed below:

- (a) the infrastructure shall consist of a sitting hall, a separate room for the committee room for office staff, waiting room for children, waiting room for parents or guardian, room for personal interaction between the child or parents and the Committee, a record room, safe drinking water facility and toilets;
- (b) the State Government shall provide necessary human resource support for every committee, including welfare officer, steno-typist or computer operator, peon, safai karmchari.

(3) The allowances of the Chairperson and Members shall be disbursed by the child Protection unit or State Government as per rule 23 of these rules.

83. Constitution of Juveniles Justice Board:- The State Government shall by notification in official Gazette, constitute the juvenile justice Board in every district,

with requisite infrastructure, personnel, besides the Judicial Magistrate and Members and finance as listed below .

- (i) infrastructure shall consist of Board room, waiting room for children, one room for Judicial magistrate and memigctis, aneiors room, one room for probation officer, waiting room for parents and visitors, safe drinking water and toilets;
- (ii) the State Government shall provide necessary human reassures support for every Boards including probation officer, steno typist or computer operator, peon, Safi karmchairi.

84. **Special Juvenile Police Unit :-**

(1) The state Government shall create a minimum one special Juvenile police unit at the district which shall operate as a centre for Comprensive First Contact Care for Children under the Act.

(2) Object of the Special Juvenile Police Unit :-

The object of the special Juvenile police unit shall be as under :-

- (a) to identify and receive children at the point of first contact, under outreach work in the jurisdiction to identify children at the risk and conduct home visits of children;
- (b) to build up a friendly relationship with child so as to enable him to understand and share reasons for his present situation as well as to participate in a decision regarding proceeding concerning him ;
- (c) to conduct an individualized quick assessment and inquiry and offer counselling , medical attention , recreation services as well as referral to detailed assessment and other services ;
- (d) to provide child help line and emergency outreach services through 1098;
- (e) to network with the child help line of the area and all other recognized fit person/institution and voluntary organisation willing to assist in the work of the special juvenile police unit as well as directly link up with competent authority and institution under the Act coming under that jurisdiction ;
- (f) to take on the role of the child friendly First Intervention Centres and performs the function of a Community Based Reception Unit of the observation home/children's

home to receive undertake preliminary inquiries provide timely counselling and early intervention by operationalising the principal of diversion;

(g) to-coordinate and upgrade the police treatment towards children;

(h) to operate a mobile special juvenile police unit which may be called upon by the concerned police station whenever a child is either apprehended or received under the act;

(i) the function as a place of safety for children ;

(j) any other tasks which he unit have to perform in the course of there ordinary duties in the child concerned manner.

(3) Location of special Juvenile Police Unit :- The special Juvenile police unit shall not located within the precincts of a police station, but it shall be located within the premises of a space being utilized by a recognized voluntary organization or a public educational institution or any such place. In addition mobile unit of a special juvenile police unit may be setup which shall liaison with the respective jurisdictional special juvenile police unit :

(4) Jurisdiction :- (a) the special juvenile police unit shall have the jurisdiction on a number of police stations in a particulars zone as identify as necessary by the special juvenile police unit for taking into account the density of children at risk in the area by the special juvenile police unit. Every district shall have a minimum of one special juvenile police unit ;

(b) affiliation to the jurisdictional police station :- every special juvenile police unit shall be affiliated to the nearest police station for documentation and for any specific assistance.

(5) Special Juvenile police unit shall constitute the following members :-

- (i) One Child welfare officer who shall not below the rank of police inspector or sub- inspector ;
- (ii) Two social workers (two ex-Officio) who shall posted in the district child protection committee ;
- (iii) Two voluntary social workers (whom one shall be women) who is having experienced as a professional with a minimum one year experience in dealing directly with children in specially different circumstances.

(iv) One women police constable

(v) One helper

(6) The unit shall take serious cognizance of adult perpetrators of crimes against children and see to it that they are without delay apprehended and large the case under the appropriate provisions of the law and for this purpose the district level units shall maintain liaison with other units of police station .

(7) The special juvenile police unit shall seek assistance from voluntary organizations, panchayats, Gramsabhas and resident welfare associations in identifying the juvenile in conflict with law as well as reporting cases of violence against children, child neglect and child abuse .

(8) The special juvenile police unit shall particularly seek assistance from voluntary organizations recognized as a protection agencies by the state government for the purpose of assisting special juvenile police unit and local police stations at the time of the apprehensions in preparations of necessary reports of taking charge of juveniles until production and at the time of production before the board as per rule sub rule (12) of rule 11 of these rules.

(9) The superintendent of police in a District shall head at the special Juvenile Police Unit and oversee its functioning from time to time .

(10) A nodal Officer from police not less than the rank of inspector general of police shall be nominate in each state to co-ordinate and upgrade role of police on all issues pertaining to care and protection of children or Juvenile under Act.

(11) If police officer found guilty, after due inquiry, of torturing a child mentally or physically, shall be liable to be removed from the service ,besides being prosecuted for the offence.

(12) Missing Children Bureau :-

(a) The State Government shall setup a Missing Children Bureau for documentation and publishing information relating to missing children. Computerized software shall be put in place to facilitate such a service. Attempts shall be made the network with all other similar facilities set up around the country so as to facilitate speed scanning and transmission of information about such children around the country. This shall also serve as a database or missing children .

(b) The Missing Children Bureau shall be lined up to the child help line whenever available as well as to all major police stations in each district.

(c) All citizen found to be directly related to or otherwise authorized to access this information shall be allowed free access to this database. person's found to be abusing this database against the interests or children shall be investigated and necessary action shall be taken.

85. Honorary or Voluntary Welfare Officers and Probation Officers :- to augment the existing probation service, honorary or voluntary welfare officers and probation officers may be appointed from the voluntary organization and social workers found fit for this purpose by the competent authority and their services may also be co-opted into the implementation machinery by the orders of the competent authority.

86. Duties of the Officer-in-Charge of an institution (1) The officer in-charge shall have the main responsibility of maintaining the institution and shall stay within the institutional premises to be readily available as and when required by the juvenile or children and the staff and in case where an accommodation is not available within the institutional premises officer in charge shall stay at a place in close proximity to the institution till such time that such an accommodation is made available within the institution.

(2) The general duties and functions of the officer-in-charge shall include :

- (a) Compliance with provisions of the Act and the rules and order made there under ;
- (b) Compliance of the orders of the board or committee;
- (c) Providing homely atmosphere of love, affection, care, development and welfare for Juveniles or children;
- (d) Maintaining minimum standards of care in the institution;
- (e) Proper maintenance of buildings and premises ;
- (f) Security measures and periodical inspection, including daily inspection and rounds of the institution, proper storage and inspection of food stuff(s) as well as food being served;
- (g) Supervision and monitoring of juvenile's and children's discipline and welfare ;
- (h) Planning implementation and coordination of all institutional activities, programmers and operations, including training and treatment programmers or correctional activities as the case may be ;

- (i) Prompt action to meet emergencies ;
- (j) Ensuring accident and fire preventive measures within the institutional premises ;
- (k) Stand by arrangements for water storage ,power plants , emergency lightning ;
- (l) Careful handling of plants and equipments;
- (m) Segregation of a juvenile or child suffering from contagious or infectious disease ;
- (n) Observance and follow-up of daily routine ;
- (o) Filing of monthly report of juvenile or child in the case file ;
- (p) Organize local and national festivals in the institution ;
- (q) Organize trips or excursions or picnics for juvenile or children ;
- (r) Preparation of budget and control over financial matters ;
- (s) Allocation of duties to personnel ;
- (t) Supervision over office administration including attention to personnel welfare and staff discipline ;
- (u) Prompt, firm and considerate action of all disciplinary matters;
- (v) To organize the meetings of the management committee set up under rule 55 of these rules and provide necessary support;
- (w) Maintenance of all records and registers required under the act and the rules and monthly verification of the same by the management committee set up under rule 55 of these rules ;
- (x) Liaisons, coordination and cooperation with the district child protection unit or State Government as and when required ; and
- (y) Coordination with the legal officer in the District Child Protection Unit to ensure that every juvenile is legally represented and provide free legal aid and other necessary support or, where the District Child Protection Unit has not been set up, services of the district or state legal services authority shall be made available .

87. Duties of a probation officer or child welfare officer or case worker :- (1) every probation officer or child welfare officer or case- worker shall carry out all directions given by the board or committee or concerned authority and shall perform the following duties, functions and responsibilities .

- (a) making social investigation of the juvenile(Form iv)or the child (FORM XIII) through personal interview and from the family, social agencies and other sources ;
- (b) Attending the proceedings of the board and committee and submitting reports as and when required ;
- (c) Clarifying problems of the juvenile or the child and dealing with their difficulties in

institutional life ;

- (d) Participating in the orientation , monitoring ,education, vocational and rehabilitation programme ;
- (e) Establishing co-operation and understanding between the the juvenile or the child and the officer- in charge;
- (f) Assisting the juvenile or the child to develop contracts with family and also providing assistance to family members ;
- (g) Developing a care plan for every child in consultation with the juvenile or the child and following up its implementation ;
- (h) Participating in the pre-release programme and helping the juvenile or the child to establish contacts which can provide emotional and social support to juvenile or child after their release ;
- (i) Establishing linkage with voluntary workers and organizations to facilitate rehabilitation and social reintegration of juveniles and to ensure the necessary follow up;
- (j) Follow up the juvenile after their release and extending help and guidance to them ;
- (k) Visiting regularly the residence of the juvenile or child under their supervision and also places of employment or school attended by such juvenile or child and submitting fortnightly reports as prescribed in FORM XXI ;
- (l) Accompanying with juvenile or children wherever possible, from the office of the board to observation home , special home, children's home or fit person , as the case may be ; and
- (m) Maintaining case file and such registers as may be specified from time to time .

(2) on receipt of information from the police or juvenile or child welfare officer of the police under clause (b) of section 13 of the act, the probation officer shall inquire into the antecedents and family history of the juvenile or the child and such other material circumstances , as may be necessary and submit a social investigation report as early as possible , in FORM -IV or FORM -XIII, to the board .

88. Duties of house father or house mother :- the general duties, functions and responsibilities of a house father, house mother and other care takers shall be as followed

- (a) handling juvenile or child with love and affection;
- (b) Taking proper care and welfare of the juvenile or child ;
- (c) Maintaining discipline among the juvenile or children;

- (d) Maintenance, sanitation and hygiene ;
- (e) Implementing daily routine in an effective manner and ensuring children's involvement ;
- (f) Looking after the security and safety arrangements of the home ; and
- (g) Escorting juveniles or children, whenever they go out of the home.

89. Disqualification of the officer in-charge, probation officer or child welfare officer or case worker , house father or house mother and other care givers and staff :- (1) the officer in-charge, probation officer or child welfare officer or case-worker, house father or house mother and other care givers and staff shall not employ of a juvenile or child under their supervision or care and protection for their own purpose or take any private service from them.

(2) any report or physical , sexual or emotional abuse of the juvenile or a child in an institution or outside the institution by a caregiver , shall liable for disqualification after due inquiry.

90. Training of personnel :- (1) The State Government of the officer in-charge shall provide training of personnel of each category of staff, in keeping with there statutory responsibilities and specific jobs requirements .

(2) the training programme shall include -

- (a) orientation and induction training of the newly-recruited staff ;
 - (b) Refresher training course and skill enhancement programmes for all care giver once a year ; and
 - (c) Staff conferences, seminars , workshops
- (3) the state government with the help of state child protection unit, national institute of public cooperation and child development and its regional centres shall organize regular training and capacity building of personnel involved in the implementation of the act and the rules made there under .

91. Selection committee and its composition :- The State Government shall constitute a selection committee by notification in the official gazette consisting of the following members namely:-

- (a) District and Session Judge
- (b) Collector of the Concerned district

(c) District Superintendent of Police

92. Functions of the selection committee :- (1) (a) in making appointment of members of the board or committee , the selection committee shall take into consideration applications received in this regard in response to public advertisement to this effect by the district ;

(b) The selection committee shall select the member and recommend a panel of names of the state child protection unit or State Government for appointment as members of the board or committee from amongst the applications received.

(2) in the event of any complaint against a member of the board or committee, the selection committee shall hold necessarily inquiry and recommend termination of appointment of such member of the State Child Protection Unit or State Government , if required .

(3) (a) The selection committee, at the time of recommending names for the appointment as member of board or committee shall also prepare a panel of names for each board or committee to fill in vacancies , which may arise during the tenure of the board or committee.

(b) in the event of the vacancy in the board or committee , the district child protection unit shall inform the State Child Protection Unit or State Government for filling up such vacancy.

(c) the State Child Protection Unit or State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the selection committee.

(4) The selection committee shall recommend names for district or city level inspection committees as per requirement under section 35 of the Act.

93. Advisory board :- The state government shall constitute the State Advisory Board, District Advisory Board and the City levels Advisory Board .

(1) All the Advisory Board shall hold at least two meetings in a year.

(2) The State Government shall constitute an Advisory Board as required under section 62 of the Act, constituting of the following :-

Minister , Mahila Evam Bal Vikas Department

Chairperson

Principal Secretary/Secretary, Mahila

Evam Bal Vikas	-Member
Principal secretary / secretary, education	
Department	- Member
Principal secretary / secretary, health	- Member
Principal secretary / secretary, home	- Member
Principal secretary / secretary, law	- Member
Principal secretary / secretary, labour and employment	- Member
Principal secretary / secretary, cottage and small scale industries	- Member
Principal secretary / secretary, technical and education	- Member
Principal secretary / secretary, industries	- Member
Principal secretary / secretary, finance	- Member
Principal secretary / secretary, social justice	- Member
Director general police	- Member
A representative of UNICEF	Member
An industrialist	Member
A journalist	Member
A representative of press council	
Member Two social workers/ representatives of voluntary organization	Member
Commissioner Women Empowerment	Member Secretary.

(3) The Advisory Board may advice to the State Government on the following matters , namely :-

- Development of the juvenile justice services through various official and community based welfare agencies ;
- The measures and means of mobilizing human and material resources to ensure social justice to the juvenile of both categories ;
- The development of facilities for educational vocational training and rehabilitation for various categories or juveniles coming within the preview of the juvenile justice system ;

(d) The co-ordination between various sectors of child development in dealing with the problems of juveniles proceed through the law.

(4) The non official members of the Advisory Board shall be nominated by the State Government on the recommendations of the commissioner women Empowerment . The non official members shall hold office for a period of three years from the date of nomination and shall be eligible for re-nomination . The non-official members shall be filled by the appointment of another non-official member who shall hold office so long as the person in whose place is appointed would have held if the vacancy had not occurred . The procedure for the meetings of the Advisory Board shall be laid down by the state government .

The State Advisory Board constituted by sub rule (1) of rule 93 shall act in the form of a State Child Protection Unit for the purpose of section 62-A of the Act. The terms and conditions of such unit shall be such as provided in rule 93.

(5) District Advisory Board - The State Government shall constitute a District Advisory Board which shall follow the duties to inspect the programme and activities for effective implementation of the Act. District advisory board shall consist of the following :-

Collector	- chairperson
Superintendent of police	- member
Representative of district Penchant	-member
Chief medical officer	- member
Dy. Director, education	- member
Secretary, red cross	- member
Chairman rotary/Lions club	- member
Two social worker	-member
Two member relating to neighbourhood committee	-member
Businessman	-member
Two donor	-member
District women Empowerment officer	-member
Superintendent of concerned home	-member -Secretary

Objectives :-The District Advisory Board shall review the activities relating to the administration of juvenile justice in the district on the following lines :-

- (a) To review the administration and activities of institutions established under the provision of the Act ;
- (b) To Inspect the institution established under the provision of the act and report to the director / commissioner, social welfare department .
- (c) To Propose suitable programmes for the upgradation and development of the homes ;
- (d) To Review the probation work in the district and propose suitable suggestions for effective implementation ;
- (e) To give support to the programme for the rehabilitation of inmates in the society ;
- (f) To generate financial support to the inmates in their entire development and rehabilitation;
- (g) To create linkage between various agencies working in the field of social welfare for consideration and co-operation , to bring the inmates in the main stream of the society;
- (h) To review the minimum standards ensured in the institutions setup under the Act
- (i) To review the non institutional services like Probation, Foster care, adoption, sponsorship programmes etc.;
- (j) To review the inter coordination between the various department community based programmes etc and suggest the suitable remedial measures for effective functionary ;
- (k) To propose necessary suggestion to improve quality of institution and non-institutional services effectively ;
- (l) Nomination of non-official member :
- (a) Nomination of the non-official members of District Advisory Board shall be made by concerning collector of the districts ;
- (b) The tenure of the non official members shall be for a period of three years. The non official members will be terminated by the collector after giving reasonable opportunity;
- (m) The District Advisory Board shall meet once in three months

94. Openness and transparency :- (1) all children's homes shall be open to visitors with the permission of the officer -in -charge and the committee or officer-in-charge as the case may be, may consider appropriate to allow the representatives of local self government, Voluntary Organizations, social workers , researchers , medicos

academicians , prominent personalities media and any other person visitors as the office-in-charge may consider appropriate keeping in view the security , welfare and the interest of the children .

(2) the officer in-charge the home shall encourage the active involvement of local community in improving the conditions in the homes , if the members of the community want to serve the institution or want to contribute through their expertise.

(3) The officer-in-charge shall maintain a visitor book and the remarks of the visitor given therein shall be considered by the Advisory Inspecting Authority .

(4) While visiting an institution the visitors will not say or do anything that undermines the authority of the Officer-in charge or is in contravention of the Act or rules or impinges on the dignity of the children.

(5) The visitors may be allowed to visit observation homes and special homes with the permission of the competent authority.

95. Juvenile Justice Fund :- (1) The state Government shall create a fund except voluntary donation at the state level under section 61 of the Act to be called the Juvenile Justice Fund (hereinafter referred to as the Fund) for the welfare and rehabilitation of the child dealt with under the provisions of the Act.

(2) The fund shall be applied :

- (a) to implement programmes for the welfare ,rehabilitation and restoration of juveniles or children;
- (b) to pay grant-in-aid to non- governmental organizations ;
- (c) to meet the expenses of the State Advisory Board and its purpose ;
- (d) to do all other things that are incidental and necessary for the above purpose.

(3) The management and administration of the fund shall be under the control of the State Advisory Board .

(4) The assets of the fund shall include all such grants and contributions recurring or non-recurring from the Central Government and State Government or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations from any individuals or organization .

(5) All withdrawals of the State Advisory Board up to rupees 20000/- shall be made by the cheques signed by the Secretary or the officer nominated by him and in case of amount exceeding rupees 20,000/- shall be signed jointly by Secretary and the Officer nominated by the State Advisory Board.

(6) The regular accounts shall be kept of all money and properties , and all incomes and expenditures' of the Fund and shall be audited by the notified firm of Chartered Accountants, or any other recognized authorities as may be appointed by the Board . The auditors shall also certify that the expenditure from the Fund made by the Secretary. All contracts and other assurance shall be in the name of the board of management and signed on their behalf by the secretary and one member of the board of management authorised by it for the purpose.

(7) The board of management may delegate to one or more of the members such of its powers, which in its opinion are merely a procedural arrangement .

96. Application of these rules :-It is hereby declared that until the new rules conforming to these rules are framed by the State Government under section 68 of the Act , these rules shall mutatis mutandis apply in the State .

97. Pending cases :- (1) no juvenile in conflict with law or a child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.

(2) All pending cases which have not a finality shall be dealt with and disposed of in terms of provisions of the Act and rules made there under.

(3) Any juvenile in conflict with law, or a child shall be given the benefits under sub-rule (1) of this rule, and it is hereby clarified that such benefits shall be made available to all those accused who were juvenile or a child at the time of commission of an offence, even if they cease to be a juvenile or a child during the pendency or any inquiry or trial .

(4) While computing the period of detention or stay any sentence of the juvenile in conflict with the law or of a child, all such period which the juvenile or the child has already spend in custody, detention, stay or sentence or imprisonment shall be counted as a part of period of stay of detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

98. Disposed off cases of Juveniles in conflict with law : The State Government or as the case may be the Board may, either suo motu or on an application made for the purpose, review the case of a person or juvenile in conflict with law, determine his juvenility in terms of the provisions contained in the Act and rule 12 of these rules and pass an appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law under section 64 of the Act for the immediate release of the juvenile in conflict with law whose period of detention or imprisonment has exceeded the maximum period provided in section 15 of the said Act .

99- Disposal of records or documents:- The records or documents in respect of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law shall be kept in a safe place for a period of seven years and no longer, and thereafter be destroyed by the Officer-in-charge or Board or Committee, as the case may be .

100. Repeal and saving:- The Madhya Pradesh Juveniles Justice (Care and Protection of Children) Rule, 2003 shall here by repealed:

Provided that any action taken or order made under the provisions of the rule so repealed shall be deemed to have been taken or made under the corresponding provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA SINGH, Dy. Secy.

Schedule -I

(see rule 41)

Clothing ,building, toiletries and other articles

(1) juvenile or children shall be provided of the following articles :

S.No	Articles	Quantity to be provided per child	Proposed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Towels	4 per year	2 per year
2.	Cotton bed sheets	2 per 2 years	2 per 2 years
3.	Pillow (cotton stuffed)	1 per 2 year	1 per 5 per year
4.	Pillow covers	2 per 2 year	2 per 3 year
5.	Woolen blankets	2 per 2 year	2 per 5 per year
6.	Cotton durry	2 per 2 per year	2 per 2 year
7.	Cotton filled quilt	1 per 2 year (in cold region)	1 per 2 year (in cold region)
8.	Mattress	1 per 2 year	1 per 3 years
9.	Mosquito net	1 per 2 year	1 per 3 year
10.	Mattress cover	1 per 5 year (for permanent children)	
11.	Filled quilt cover	1 per 5 year (for permanent children)	

Clothing for girls

1.	Skirt & blouse or salwar kameez or half saree with blouse and petticoat	5 set per year depending on the age and Regional preferences	First year includig school uniform
2.	Banyans (one meter cloth each)	6 per year for younger girls	2 per year for younger girls
3.	Brassieres	6 per year for older girls	2 per year for older girls
4.	Panties (one meter cloth each)	6 per year	4 per year
5.	Sanitary towels	12 packet per	12 packets per

		year for older girls	year for older girls
6.	Woolen sweaters	2 per 2 year (in cold region)	2 per 2 year (in cold region)
7.	Woolen shawls	1 per 2 year (in cold region)	1 per 3 year (in cold region)

Clothing for boys

1.	Shirts	5 sets per year	5 sets per year (including uniform)
2.	Shorts	5 sets per year for younger boys	5 sets per year for younger girl boys (including uniform)
3.	Pants	5 sets per year for older boys	5 sets per year for older boys including uniform
4.	Banyans	4 sets per year	2 sets per year
5.	Underwear	4 sets per year	2 sets per year
6.	Woolen jerseys	2 per 2 year (in cold region)	2 per 2 year (in cold region)
7.	Scarfs	2 per 2 year (in cold region)	2 per 2 year (in cold region)

miscellaneous articles

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Slippers | 1 pair per year |
| 2. Shoes | 1 pair per year attending out side school |
| 3. School uniform | 2 sets per year for children attending outside school |
| 4. School shoes | 1 pair per year
For children attending outside School |
| 5- School bags and Stationery | 1 set per year For children attending outside School |
| 6- Handkerchiefs | 6 per year |

Note:

- (1) In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of Khaki shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer (for cold regions) for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white blouse, a pair of white canvas shoes and a blazer (for cold regions).
- (2) In every hospital attached to the institution where there is provision for in-patient cots, the following scale has to be followed:

Night clothing & bedding Scale for supply

1	Mattress	One per bed per 3 years
2	Cotton Bed Sheets	Four per bed per year
3	Pillows	One per bed per two year
4	Pillow Covers	Four per bed per year
5	Woollen blankets	One per bed per 2 years
6	Pyjamas and loose shirts (Hospital type for boys)	3 pairs per child per year
7	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 pairs per child per year
8	Cotton durry	One per bed per three years

Note:

- (i) When a child is admitted as an in-patient in the institution Hospital, the Institution Doctor shall issue the in-patient with the hospital clothing, the clothes on body being preserved, duly washed and handed back, at the time of the child's discharge from the hospital.
- (ii) Each child shall be provided with Kit Box or a Locker, as per convenience and necessity.

(iii) The Superintendent shall make arrangements for two-tier bed system in place of conventional cots, as per convenience and necessity.

(3) Toiletry: Every resident of the Home shall be issued with oil, soap, and other material for in accordance with the following scales:

Hair oil for grooming the hair	100 mls per month
Toilet soap or carbolic soap	1 large bar per month
Tooth paste and brush	1 Brush per 3 months 50 gms paste per month
Comb	1 per year

Note:

(a) The children attending school outside the institution may be issued with one additional bar of washing soap (100 gms) per head per month for washing their school uniform.

(b) For washing of cloth and towels, bed-sheet etc., the following scale may be followed:

- | | |
|--------------------------------|--|
| (i) Washing Soap | 1 soap for one month (125 gms) |
| (ii) Whitening/bleaching agent | to the extent required only for white clothing |

Provided, however, the hospital clothing is not mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing.

(4) The following items shall be provided for maintaining the Homes in a healthy and sanitary condition:

Item	Scale of supply
(1) Broom Stick	25 to 40 Nos per month depending on the area of the institution
(2) DDT spray	As per the institution Doctor's advice
(3) Effective bugs killing agen	As required
(4) Phenyl and cleaning acid (daily)	Depending on the area of lavatories to be cleaned as per institution Doctor's advice

Schedule II

(see rule 44)

Norms of nutrition and diet

S-No	Name of the article of diet	Norms per head per day
(1)	Rice/ Wheat/ Ragi/jowar	600Gms(700Gms for 16-18 years age of which at least 100 Grm to be either wheat or Regi or Jowar
(2)	Dal / Ralma/ Chana	120GMS
(3)	Edible Oil	25Gms
(4)	Onion	25 Gms
(5)	Salt	25 Gms
(6)	Turmeric	05 Gms
(7)	Coriander Seed powder	05 Gms
(8)	Ginger	05 Gms
(9)	Garlic	05 Gms
(10)	Tamarind/Mango Powder	05 Gms
(11)	Milk (at break fast)	150MI
(12)	Dry Chillies	05 Gms
(13)	Vegetables Leafy/ Non-leafy	100Gms/130 Gms
(14)	Curd or Buteer milk	100 Gms
(15)	Jaggery & Ground nuts seeds or paneer (vegetarian only)	60 gms each(100gms for Paneer)once a week
(16)	Sugar	40 Gms
	Following items for 50 Children per day	
(17)	Pepper	25 Gms
(18)	Jeera Seeds	25 Gms
(19)	Gramdall	50 Gms
(20)	Mustard Seeds	50 Gms
21	Ajwain Seeds	50 Gms
22	Bread	500 Gms
23	Milk	500MI
	Other Items	
24	LP Gas	For cocking only

Instructions:**(2) Variation in Diet**

- (a) Three varieties of dal i.e., Toor (Tuvani), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be issued alternatively.
- (b) On non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 Gms of Jaggery and 60 Gms of Groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer.
- (c) Leafy vegetables such as Fenugreek (Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) Gongura Thotakura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen garden is attached to any institution leafy vegetables, in addition to drumstick trees, curry leaves trees and coriander leaves, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week.
- (d) The Superintendent may make temporary alternations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the institution Doctor's advice subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(3) Meal Timing and Menu:**a) Breakfast after 8:00 am**

- (i) Upma or chapattis made of Wheat or Ragi or any other dish.
- (ii) Chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and Pu tnadal etc., dal/vegetable may be issued as a dish.
- (iii) Milk

(iv) Any seasonal fruit in sufficient quantity**b) Lunch at 1:00 P.M. and Dinner After 7:00 P.M.**

- (i) Rice/ Chapattis or combination of both
- (ii) Vegetable Curry
- (iii) Sambar or Dal
- (iv) Butter Milk or curd

(4) Others:

- (a) Depending on the season, the Superintendent shall have the discretion to alter the

time for distribution of food .

* (b) On the advise of the Institution Doctor, every sick child who is prevented from taking regular food, on account of his ill-health, may be issued with medical diet, as indicated in diet scale.

(c) Extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution Doctor in addition to the regular diet, to pick up weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength.

(d) On the following national and festival occasions, sweet dishes may be distributed to all the children at the Home at the rate fixed by the Commissioner, from time to time.

1. Republic Day (26th January)
2. Ambedkar's Birthday (14th April)
3. Independence Day(15th August)
4. Mahatma Gandhi's Birth Day (2nd October)
5. Children's Day (14th November)
6. Child Rights Day (20th November)
7. Dussehra (Vijayadasami)
8. Deepavali
9. Ramzan (Id-UI-Fitr)
10. Bakrid (Id-UI-Zuha)
11. Christmas (25th December)

The States may specify additional festivals depending upon local preferences.

FORM 1

(see rule 13 (1) (d))

SUPERVISION ORDER

When the juvenile is placed under the care of a parent, guardian or other fit person/ fit institution profile No-----of----- 20-----

Whereas ----- (name of the juvenile/) has this day found to have committed an offence and has been placed under the care of (name)-----address -----
----- on executing a bond by the said ----- and
the Board is satisfy that it is expedient to deal with the said juvenile by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said juvenile be placed under the supervision of -----
----- Probation officer/case workers, for a period of -----
Subject to the following conditions.

That the juvenile along with the copies of the order and the bond executed by the said-----
----- shall be produced before the probation Officer/case worker-----
----- named therein -----

2. that the juvenile shall be handover to the supervision of the aforesaid probation officer/ case workers.
 3. that the juvenile shall reside at----- for a period of -----
 4. that the juvenile shall not be allowed to quit the district jurisdiction of-----without the permission of the probation officer/case, worker.
 5. that the juvenile shall not be allowed to associate with bad characters.
 6. that the juvenile shall live honestly and peacefully ; and will go to school regularly / endeavour to earn the honest livelihood.
 7. that the juvenile should attend the attendance centre regularly
 8. that the person should under whose care the juvenile is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the juvenile.
 9. that the preventive measures will be taken by the person under whose care the juvenile is placed to see that the juvenile does not commit any offence punishable by any law in India.
 10. that the juvenile shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substance or any other intoxicants.
 11. That the directions given by the probation officer/case workers from time to time , for the due observance of the condition mentiond above, shall be carried out.
- Dated this----- day of----- 20-----

(signature)

Judicial magistrate , Juvenile

Justice board

- Additional condition if any , may be inserted by the juvenile justice board

Form II**(See rule) 13 (1) (e)**

Order of detention under sub-section ----- of section -----
and sub-sections ----- of sections ----- .

To

The Officer in charge

Whereas on the ----- day of ----- 20 ----- (name of
the juvenile) Son/ daughter of ----- aged ----- residing at being
found in profile no ----- to be juvenile in conflict
with law/section ----- is ordered by me -----

Judicial magistrate, juvenile justice board under section ----- of
juvenile justice Act, 2000 to be kept in the observation home/Special/home -----
----- for a period of -----.

This is to authorize and require you to receive the said juvenile; into your charge, and to
keep him/her in the observation home/Special/Home ----- For
the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of juvenile justice board

This ----- day of ----- 20

(signature)

Judicial Magistrate, Juvenile Justice
Board

Encl:

Copy of the judgement , if any, or orders, particulars of home and case history and
individual care plan, if any :

Strike off which is not required.

Form 3

(see (Rule 13(1) (f) and (7))

Order of social investigation/enquiry

To

Probation officer/ case worker/person in-charge of voluntary organisation/case worker --
 ----- Whereas a report/complaint under section-----
 -----of juvenile justice (care and protection of children) act , 2000 has been received from
 ----- in respect of -----(name of the juvenile) son/daughter of-----
 ----- approximate age -----residing at ----- who has been
 produced before the Board.

You are hereby, directed to enquire into the social antecedents, family background and
 circumstances of the alleged offence by the said juvenile and submit your social
 investigation report on or before -----or within such time allowed to you by the
 Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric
 treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report
 along with your social investigation report.

Signature

Dated this ----- day of-----20-----

(signature)

Judicial Magistrate, Juvenile Justice Board

Form 4

See rule 13 (7) and 87 (1(a) and (2)

SOCIAL INVESTIGATION REPORT

Serial no.-----

Submitted to the juvenile justice board ----- (address)

Probation department/ concerned Authority /Voluntary Organisation of the State
Government

----- (signature and stamp)

Profile no.

Under section:

Title of profile:

Police station:

Nature of offence charge:

Name

Religion

Fathers's name

Caste

Permanent address

Year of the birth

Last address before apprehension

Age/Sex

To be placed in any Previous institutional/ case history and individual care plan, if any
to be please in any

Family

Members of family	Name	Age	Health	Education	Occupation	Monthly Income	Disabilities	Any other social habits
Father								
Step father								
Mother								
Step mother								
Siblings								
Any other legal Guardian/ Relative								

If married, relevant particulars

.....

Other near relatives or agencies

Interested-----

Attitude toward religion normal

and ethical code of home etc.-----

Social and economical status -----

Delinquency record of members of

family-----

Present living condition-----

Relationship between parents

Parents and children specially

With the juvenile under investigation-----

Other factors important if any-----

Juvenile history

Mental condition -----

(present and past)

Physical condition -----

(present and past)

Habits, interests -----

(moral, recreational etc)

Outstanding characteristics and

Personality traits-----

Companions and their influence Truancy -----

Without permission from home, if any

School(attitude towards school) -----

teacher, class mates and vice-versa)

Work record (jobs held reason for leaving-----

Vocational interests, attitude towards job , employees) -----

Neighbourhood and neighbours report -----

Parent's attitude towards discipline

in the home and child's reaction -----

Any other remarks

RESULT OF INQUARY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Suggested cause of the problems

Analysis of the case including reasons for delinquency

Opinion of expert consulted

Recommendation regarding treatment and its plan by probation officer

Signature of probation officer/ case worker

Form v**See rule 15(5) and 79 (2)*****UNDERTAKING/BOND TO BE EXECUTED BY A PARENT/ GUARDIAN/ RELATIVE /FIT PERSON IN WHOSE CARE A JUVENILE IS PLACED***

Whereas I----- being the parent, guardian, relative or fit person under whose care----- (name of the juvenile) has been ordered to be placed by the juvenile justice board-----, have been directed by the said board to execute an undertaking / bond with surety in the sum of Rs.----/- (Rupee)-----

or without surety. I hereby bind myself on the said-----being placed under my care. I shall have the said-----properly taken care of and I do further bind myself to be responsible for the good behaviour of the said-----and to observe the following conditions for a period of ----- years w.e.f-----

1. that I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer/Case Worker.
2. that I shall not remove the said juvenile from the limits of jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board .
3. that I shall send the said juvenile daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond control.
4. that I shall send the said juvenile to an Attendance centre regularly unless prevented from doing so by circumstances beyond my control.
5. that I shall report immediately to the board wherever so required by it;
6. that I shall produce the said juvenile in my care before the board, if he/she does not follow the orders of the Board or his/her behaviour beyond the control.
7. That i shall render all necessarily assistance to the Probation Officer/Case Worker to

enable him to carry out the duties of the supervision.

8. In the event of making default herein, I undertake to produce myself before the Board for appropriate action or bind myself, as the case may be, to forfeit to Government the sum of Rs-----/- (Rupees-----
-----)

Dated this-----day of-----20-----.

Signature of person executing the
Undertaking/Bond.

Signature of sureties

(Signed before me)

Judicial Magistrate, Juvenile Justice Board

, if any Additional condition, by the Juvenile Justice Board may be entered, if any, numbering them properly.

(Where a bond with sureties is to be executed, add)

I/We----- of -----

(place of residence with full particulars) hereby declare myself / ourselves as surety for the afore said----- (name of the person executing the undertaking bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of -----

----- (name of the person executing the bond) making fault therein,

I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to the Government the sum of Rs.-----/-(Rupees-----only)----- dated this ----- day of-----20-----

----- in the presence of -----.

Signature of surety /(sureties)

(Signed before me)

Judicial Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM VI

(See sub rule (6) of rule 15 and sub rule(2) or rule 79)

UNDERTAKING BY JUVENILE/CHILD

Personal Bond to be signed by the juvenile/child who has been ordered under clause-----
--- of sub section ----- of section ----- of the Act.

Whereas I----- inhabitant of -----(give full particulars such as house number, road village / town teasel, District, State)-----have been ordered to send back/restored to my native place by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee----- under section ----- of the Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act 2000 on my entering into a personal bond under sub-rule (6) of rule 9 and sub-rule of (2) of rule 66 of these Rules to observe the conditions mentioned herein below, Now, I do solemnly promise to abide by this condition during the period-----

I hereby bind myself as follow:

1. That during the period ----- I shall not ordinarily leave the village/town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to----- or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board/Committee.
2. That during the said period I shall attend school/vocational training in village/town or in the said district to which I am sent;
3. That in case of my attending school/vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board/Committee informed of my ordinarily place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above condition which have been read over/explained to me and that I accept the same.

Signature or thumb impression of the juvenile/child

Certified that the conditions specified in the above order have been read

over/explained to (Name of the Juvenile Child)-----

and that he has accepted them as the conditions upon which his period of detention/placement in safe custody may be revoked.

Certified accordingly that the said Juvenile /child has been released/relived on the-----

Signature and Designation

of certifying authority

officer in-charge of the

Institution

Form VII

(See sub rule (10) of rule 17)

DISCHARGE ORDER

I ----- (name and designation of the discharging) authority) do by this order permit ----- son/daughter of ----- residence-----

Profile Number ----- who was ordered to be detained/placed in a observation home/special home/after care home by the Juvenile Justice Board ----- under section----- of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, for a term of ----- on the ----- day of -----20 ----- and who is now in the -----home at----- -----to be discharged from the said-----home and supervision and the authorisation of ----- during the remaining period of stay.

This order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any condition of which shall be liable to be revoked .

Date :

Place:

Signature and
Designation of
Releasing Authority

Conditions

- 1.The discharge person shall proceed to----- and live under the supervision and authorization of ----- until the expiry of the period of his detention unless the remission is sooner cancelled.
- 2.He shall not without the consent of the ----- remove himself from that place or any other place. which may be named by the said-----
- 3.He shall obey such instruction as he may receive from the said ----- with regard to

punctual and regular attendance at the school/vocation or otherwise .

4.He shall attend the Attendance Centre located at ----- regularly.

5.He shall abstain from committing any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of -----

6.In the event of his committing a breach of any of the conditions the remission of the period of detention hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he shall be dealt with under sub-section (3) of section 59 of the Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act ,2000.

I hereby acknowledge that I am aware of the above condition which have been read over /explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb mark

of the released juvenile)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to(name of juvenile/child) ----- and the he has excepted them as the conditions upon which his period of detention may be revoked.

Certified accordingly that the said juvenile/child has been discharge on the -----.

Signature and Designation of the certifying authority

Officer-in-charge of the institution

Form VIII

(see sub rule (17) of rule 27)

SUPERVISION ORDER

When the child is placed under the case of parent/guardian or other fit person case no ---
 ----- of ----- 20----- whereas (name of the child) ----- this day has
 been found to be in need of care and protection, and has been placed under the care and
 supervision of (name)----- (address)-----on executing a bond by the said -----
 ----- and the committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by
 making an order passed to him under supervision.

It is hereby order that the said child be placed under the supervision of (name) -----
 ----- (address) ----- for a period of ----- subject to the following
 condition that:

1. the child along with the copies of the order and the bond , if any, executed by the said
 ----- shall be produced before the committee as and when required by the person
 executing the bond
 2. the child shall be placed under supervision of the aforesaid parent / guardian/fit
 person
 3. the child shall reside at ----- for a period of ----- .
 4. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of ----- with the
 permission of the Committee .
 5. the child shall go to school regulatory/ endeavour to earn an honest live- hood
 6. the person under whose care the child is placed shall arrange the proper care,
 education and welfare of the child.
 7. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be
 prevented from coming in conflict with the law.
 8. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or
 any other intoxications.
 9. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of
 the conditions mentioned above, shall be carried out.
- Dated this----- day of----- 20-----

Chairperson, child welfare committee

Additional conditions if any, may be added by the child welfare committee.

Form 9

(See Sub rule (17) of rule (27) and sub rule 2 of rule 79)

UNDERTAKING BY THE PARENT OR FIT PERSON TO WHOM THE CHILD IS RESTORED

I ----- resident of House no. ----- Street ----- Village/Town -----
District ----- State do hereby declare that i am willing to take charge of (name of the
child)----- Aged --- under the order of the child Welfare Committee ----- subject to
the following conditions:

- i. If his conduct is unsatisfactory. I shall at once inform the committee .
- ii. I shall do my best for the welfare and the education of the said child as long as
remain in the charge and shall make proper provisions for his Maintenance .
- iii. In the event of his illness, he shall have proper medical attention in the nearest
hospital.
- iv. I undertake to produce him before the competent authority us and when required.

Date this ----- day of -----

Signature

Signature and address of

Witness (es)

(Signed before me)

Chairperson , Child Welfare

Committee

Form X

(See sub rule (18) of rule 27)

ORDER OF SHORT TERM PLACEMENT OF CHILD DURING THE PENDING INQUIRY

Name of the child :

Sex :

Age :

Father's name:

Mother's name :

Address :

Date of receiving by Organization/ institution produced by -----

This is to authorize and direct you to receive the said child in your charge and keep her in the Shelter home / Children Home for care and protection under section 34(1) of the Juvenile Justice (care and protection of children) Act 2000 .

Next date:

Signature

Chairperson/Member

Form XI

(See Sub rule (19) of rule 27)

ORDER OF RESTORATION OF A CHILD TO AN INSTITUTION

To

The officer in-charge -----

Whereas on the ----- day of-----20----- (name of the child)-----
son /daughter of ----- aged----- residing at -----being in care and protection
under sub section (3) of section 34 of the juvenile justice (care and protection of children)
,Act ,2000 is ordered by the child welfare committee ----- to be kept in the children
home / shelter home ----- for a period of -----

This is to authorized and require you to receive the said child in your charge, and to kept
him/her in the children home /shelter home----- for the authorized order to be
carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of child welfare committee

This ----- day ----- 20---

(signature)

Chairperson/member

Child welfare committee

Encl:

Copy of the orders , particulars of home and previous record, case history and individual
care plan, whichever is applicable.

Form XII

(See sub rule (1) of rule 28)

ORDER FOR ENQUIRY

To

Child Welfare Officer/Person in-charge of voluntary organization / social worker/ case worker -----

Whereas a report under section ----- of the Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act , 2000 has been received from ----- in respect of (name of the child) -----

Aged (approximate)-----son/daughter of ----- residing at ----- . who has been produced before the committee under section of the juvenile justice (Care and Protection of Children) Act 2000.

You are hereby direct to inquiry into the Social and family back ground of the said child and submit you inquiry report on or before or within such time allowed to you to by the committee .

You are also here by directed to consult an expert in child psychology , psychiatric treatment or counseling for ther expert opinion if necessary, and summit such report along with your inquiry report.

You are hereby directed to inquire into the character and social antecedents of the said Juvenile and submit your social investigation report on or before-----or within such time allowed to you by the Board /committee .

Dated this ----- day of-----20-----

(signature)

Chairperson/member

Child welfare committee

Seal

Form XIII

See rule 28 (3), 33 (g)(ii) and 33 (4)(f) and 87 (1) (a) and (2)

Format for enquiry's report

Sl. No.-----

Produced before the Child Welfare Committee -----

Case No.

Concerned Government Department/ Voluntary Organisation

Category of child in need of care and protection

.....

Name Religion

Father's name Caste

Permanent address Year of birth

Address of last residence Age

..... Sex

Previous institutional /case history and individual care plan, if any

..... Family

Members of family	Name	Age	Health	Educational	occupation	Monthly earnings	Disabilities	Any other eg. social habit
father								
Step father								
Step mother								

sibltings								
Any other legal guardian/ relative								

If married , relevant particulars

Other near relatives or agencies Interested

Attitude towards religion, normal and ethical code of the home etc-----

Social and economic status -----

Delinquency record of other members of family-----

Present leaving condition-----

Relationship between parent/parent's and children especially with the said child -----

Other factors importance if any-----

Child's history

Mental condition

(present and past)-----

Physical condition

(present and past)-----

Habits, interests

(normal, recreational etc)-----

Outstanding characteristics and personality traits -----

Companions and there influence -----

Truancy without permission -----

from home, if any

School (attitude towards school

teachers , class mates and vice-versa

Work record (jobs held , reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employees -----

Neighbourhood and neighbours report-----

Parent attitude towards discipline in the home and child's recreation -----

Any other remarks

Result of inquiry

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Reasons for child's need for care and protection

Opinion of the experts consulted

Recommendation of Child Welfare Officers/Case Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan

Signature of the Child Welfare Officer/ Case Worker /Social Worker

Form XIV

(See rule 33 (3) (c))

ORDER RELATING TO DECLARING CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

1. IN exercise of the powers Conferred in the child welfare committee -----
 --- constituted under sub section ----- of section----- of juvenile justice
 (care and protection of children) Act, 2000 and sub rule ----- of rule -----of these
 rule, minor ----- born on (date)-----placed in custody of specialized
 adoption Agency (name, address)----- vide order-----date -----
 --of the Chairperson, Child Welfare Committee has been declare legally free from
 adoption on the basis of details furnished through :

(a) Inquiry/study of family background conducted by child welfare officer/social
 worker/case worker

(b) Document of surrender executed by the parent's and surrender deed signed
 in the presence of the committee under clause (c) and (e) of sub rules (12)of rule 21 of
 these rules .

(c) Declaration summated by the Specialized Adoption Agency under clause (g) (iii)
 of sub rule (11)of rule 21 of these rules.

2. ----- (name of the Specified Adoption Agency) shall
 full fill all conditions specified in juvenile justice (care and protection of children) Act
 2000 and the rules relating thereto and furnish a copy of adoption decree / guardian ship
 order in respect of the minor as may be required by committee and the concerned
 department of the state Government of -----

Date : Chairperson/ Member

Place : Child Welfare Committee

For completion by the Specialised Adoption Agency

- i. I have read and understood chapters III and IV of juvenile justice (Care and
 Protection of Children)act 2000 and the rules there under and agree to abide / be
 bound by the same while placing said minor in adoption
- ii. I further declare that the particulars stated in the declaration submitted by me on ----
 ----- trueo and correct. In case they are found to be false or incorrect. The
 committee has right to suspend this Release order(name of the minor) -----
 and ask for protection of the said minor before the committee

Date

Place Child Welfare officer/Case worker

Form XV

(rule 33 (4) (c))

DEED OF SURRENDER

I ----- daughter/son ----- residing at -----
 - am not in a position due to social reasons /due to being single/ill/disable to take care of my child (name, if any)----- approximate age ----- year. I am explained the consequences of surrendering my Child by the Child Welfare Officer/Social worker(name)----- the child welfare committee -----In full knowledge of all this facts, i am surrendering my child before the committee today, dated----- within two months this stated date if I do not revise my decision to take back my child and do not approach the said committee for the same,the committee shall declare my child legally free for adoption and I shall have no further claim on any child.

Signature of parent/guardian

Date :

Place :

That I ----- Child Welfare Officer/Social Worker have explained that the procedure and the consequence of surrendering the child to the concerned parent/guardian on (date)-----

Signature of child welfare officer/social worker

Date :

(Signed before me)

Chairperson /member

Child Welfare Committee

Form XVI

(See rule 35(3))

A. FOSTER CARER'S ASSESMENT

1. Particulars of agency

Name of the agency

Address

Telephone number

Fax

E-mail

Name of the social worker

Telephone no.

Date------(form completed)

2. Details of the applicant

Surname

Full name

Date of birth

Religion

Language(s) spoken at home

Occupation

(a) nature of work

(b)) hours of work

Address

Telephone No.

The type of child ,foster-carer would consider

(to be filled after a full discussion with the foster-carer)

3. Description of the preferred child for the foster

AgeGroup under 2 year 3-6 year 7-12year 13-15year 16-18year

Sl.NO	TYPE OF PLACEMENT	DURATION
(i)	Pre adoption	
(ii)	Emergency	
(iii)	Short term	
(iv)	Assessment	
(v)	Long Term	

an applicant who may care (Please Tick) the child

A child who is -----

- (i) Neglected
- (ii) Orphaned
- (iii) With physical impairment
- (iv) Mental impairment
- (v)Hearing impairment
- (vi)Speech impairment
- (vii)Special educational needs
- (viii). Learning difficulties
- (ix)physical abuse
- (x). Sexual abuse
- (xi). Who does not relate easily
- (xii). Who need control/may defy authority

- (xiii). Born of rape/ incest
- (xiv) Who's parent(s) suffering from disease
- (xv) Who's parent(s) is HIV positive
- (xvi). Who's parent(s) are aid patients
- (xvii).. Who's parent(s) are drug addict
- (xviii).. Are in jail
- (xix) Relinquished
- (xx)Belong to other caste
- (xxi).. Are of different religion

4-- Profile of the family

BRIEF FAMILY PROFILE

Name	Gender	Approx Age	Occupation	Education	Relation between the applicant

Form XVII

(See rule 34 (1))

ORDER OF PLACEMENT REGARDING FOSTER CARE

The child(name and address)----- approximate age ----- D/O or S/O Mr ----- and Mrs ----- or miss----- is in need of care and protection of a family. Mr-----or mrs----- or miss -----resident of (complete address and contact numbers) ----- is / are declared fit person/ person's for foster care placement of the child based on the home study report of the child welfare officer/social worker miss / Mr/Mrs ----- of the organization (address)-----

The child (name)----- is placed in foster care for a period of ----- (days)/ months) under the supervision of the aforesaid child welfare officer/ social worker/name and contact)-----

Chairperson/member

Child welfare committee

Form XVIII**(See rule 37 (5))****ORDER OF SPONSERSHIP OF PLACEMENT**

The Juvenile/Child (name and address)----- approximate age ----d/o
or s/o Mr.-----and MRS

----- or Ms.----- has been identified by the
State/ District child protection unit as a juvenile/ child at risk needing urgent care and
protection. On the basis of the inquiry report submit by the State/District child protection
unit/child welfare officer/social worker it is established that the said juvenile/ child needs
sponsorship support for education / health/nutrition/ other developmental needs The
state/district child protection unit is hereby directed to release Rs.----- per month----
----- as sponsorship support to the said juvenile/child for a period of -----
(day/months) are carryout necessary follow up.

The State/District child protection unit is also directed to clearly by down the terms and
conditions for the sponsorship support and follow up.

Judicial magistrate, Juvenile Justice Board/

Chairperson/Member,

Child Welfare Committee

Copy to: state/District Child Protection Unit or concerned department of the state
Government

Form XIX**(See rule 38 (3))****ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT**

The Juvenile/child (name)-----d/o or s/o ----- has/ will be completing 18 years of the age on (date) ----- . He is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration. He is placed in (name of organization) ----- for providing aftercare. The in-charge of the organization is directed to admit the child and provide all possible opportunities for his rehabilitation and reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The in-charge will send half yearly report on the status of the child/youth to the child welfare committee.

The State /District Child Protection Unit is hereby directed to arrange for aftercare for the said juvenile/child for a period of ----- (day/month) and carry out necessary follow up. The state/District Child Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and conditions for aftercare programme and carry out necessary follow up.

Judicial magistrate, juvenile justice Board/

Chairperson/Member, child welfare committee

Copy to: state/District Child Protection Unit or concerned department of the state Government

Form XX**[See rule 50(9) and 54 (1)(t)]****CASE HISTORY FORM FOR CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION**

Case/ profile No.-----

Date and time-----

Affix a latest
photograph
here

A. Personal Data**1 Name****2 Male/Female(tick the appropriate category)****3 (a) Age at the time of admission****(b) Present Age:****4 category**

- Separated from the family
- Abandoned/deserted
- Victim of exploitation and violence (give detail)
- Run-away
- Any other

5 Religion Hindu (other backward class/schedule caste/schedule tribe)

Muslim / Christian/Others (please specify)

6. Location of residence urban/ semi-urban/rural/slum/
industrial/other(please specify)

7 Native District and State

8 Description of the housing :

(i) Concrete building/tiled house/hut/
on the street/others (please specify)

(ii) Three bed room/two-bed room

One- Bed Room/ No separate bed room:

(iii) Owned/rental

9. Whom the juvenile was brought
before the child welfare committee:

(i) Police / special juvenile /police unit/railway unit/
women police

(ii) Probation officer

(iii) Social welfare organization

(iv) Social worker

(v) Parent(s) guardian(s) (please specify the relationship)

(vi) Child himself/herself

10. Reasons for leaving the family

(i) Abuse by parent(s) guardian(s)/ step parent(s)

(ii) Search of employment

(iii) Friend circle influence

(iv) Incapacitation ileitis of parents

(v) Criminal behaviour of parents

(vi) Separation of parents

(vii) Demise of parents

(viii) Poverty

(ix) Other (please specify)

11. Types of the abuse met by the child

(i) Verbal abuse - parents /siblings/

employers/ others((please specify)

(ii) Physical abuse

(iii) Sexual abuse parents/siblings

(iv) Sexual abuse parents/siblings/employees/others (please specify)

(v) Others- parents/sibling/employers/

others ((please specify)

12. Types of abuse met by the child

(i) Denial of food- parents/siblings

employees/other(please specify)

(ii) Beaten mercilessly-

parents siblings/employees/others (pl. specify)

(iii) Causing injury- parents/siblings/

employees/other(pl. specify)

(iv) Other (pl. specify)-parents/siblings/employers others

(pl. specify)

13. Exploitation of the child :

(i) Working without payment

(ii) Little (low) wages with longer duration of work

(iii) Others (please specify)

14. Health status of the child before admission

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| (i) Respiratory disorder | -present/not known/absent |
| (ii) Hearing impairment | -present/not known/absent |
| (iii) Eye diseases | -present/not known/absent |
| (iv) Dental diseases | -present/not known/absent |
| (v) Cardiac disease | -present/not known/absent |
| (vi) Skin disease | -present/not known/absent |
| (vii).sexually transmitted disease | -present/not known/absent |
| (viii). Neurological disorder | - present/not known/absent |
| (xi). Mental handicap | -present/not known/absent |
| (x). Physical handicap | -present/not known/absent |
| (xi). Others (please. specify) | -present/not known/absent |

15. To whom the child was staying prior to admission

- (i) Parent(s)-mother/father/both
- (ii) Guardian(s)-relationship
- (iii) Friends
- (iv) On the street
- (v) Night shelter
- (vi) Orphanages/hostels/similar home
- (vii). Other (please .specify)

16. Visit of the parents to meet the child

- (i) Prior to institutionalization -frequency/occasionally/rarely/never
- (ii) After institutionalization- frequency/Occasionally/Rarely/Never

17. Visit of the child to his family

- (i) Prior to institutionalization -Frequency/Occasionally/

Rarely/During Festival time/During summer

holidays/whenever fallen sick/never

(ii) After institutionalization-Frequency/occasionally/

Rarely/Never

18.correspondence with the parents-

(i) Prior to institutionalization- frequency/ occasionally

Rarely/ during festival times/during summer holidays/

whenever fallen sick/ never

(II). After institutionalization - frequency/Occasionally/

Rarely/During festival time/summer holidays/

whenever fallen sick/Never

B. CHILDHOOD HISTORY (Up to the Age of 12)

19. Diet of mother during pregnancy:

(i) Nutrient diet

(ii) Ordinary diet

(iii) Inadequate food intake

20. Health during pregnancy

(i) Mother infected with contagious diseases

(ii) Mother consumed/used contraceptives

(iii) Intake of antibiotics

(iv) No such details available

21. Birth details

(i) Normal delivery/prolonged delivery/caesarean

(ii) Under weight/normal weight/over weight

22. Details of immunization

23. Details of handicap

(i) Hearing impairment by birth/after accident/disease

(ii) Speech impairment by birth/after accident/diseas

(iii) Physical handicap by birth/after accident/disease

(iv) Mental handicap by birth/after accident/diseases

(v) Others (please specify) by birth/after accident/diseases

C. FAMILY DETAILS

24. HOUSEHOLD COMPOSITION

S.NO	NAME&RELATIONSHIP	AGE	SEX	EDUCATION	OCCUPATION	INCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

HEALTH	HISTORY OF MENTAL ILLNESS	HANDICAP	HABIT	SOCIALIZATION
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

25. Which type of family

Nuclear family/joint family/broken family

26. Relationship among the family members:

(i) Father and mother cordial/non cordial/not known

(ii) Father and child cordial/non cordial/not known

(iii) Mother and child cordial/non cordial/not known

(iv) Father and siblings cordial/non cordial/not known

(v) Mother and siblings cordial/non cordial/not known

(vi) Juvenile and siblings cordial/non cordial/not known

27. History of crime committed by family members:

S.No	Realation ship	Nature of crime	Arrest if any made	Period of confinement	Punishme nt awarded
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	father				
2.	Step father				
3.	mother				
4.	Step mother				
5.	Brother (a) (b) (C) (d)				
6.	Sister (a) (b) (c) (d)				
7.	child				
8.	Others (Uncle/aunty Grandparents)				

28. Details of property owned by the family

(i) Immovable property/ Landed properties

(ii) Household Property/ articles- cows/cattle/bull property

(iii) Vehicles-two wheelers/three wheelers/four wheelers

(lorry/ bus/ car/ tractor /jeep)

(iv) Others (please. specify)

29. Marital status of the family members

(i) Parents arrange/special marriage/local union

- (ii) brothers arrange/special marriage/local union
- (iii) Sisters arrange/special marriage/local union

30. Social activities of family members

- (i) Participate in social and religious functions
- (ii) Participate in cultural activities
- (iii) Does participate in social and religious functions
- (iv) Not known

31. Parental care towards juvenile before admission :

- (i) Over protection
- (ii) Affectionate
- (iii) Attentive
- (iv) Not affectionate
- (v) Not attentive
- (vi) Rejection

D. ADOLESCENCE HISTORY (between 12 and 18 years)

32.

- (i) Puberty
- (ii) early Puberty
- (iii) Middle Puberty
- (iv) Late

33. Details of delinquent behaviour if any

- (i) Stealing
- (ii) Pick pocketing
- (iii) Arrack selling
- (iv) Drug pedaling
- (v) Petty offences

- (vi) Violent crime
- (vii) Rape
- (viii) None of the above
- (ix) Others (please specify)

34. Reasons for delinquent behaviour

- (i) Parental neglect
- (ii) Parental overprotection
- (iii) Parents criminal behaviour
- (iv) Parents influence (negative)
- (v) Peer group influence
- (vi) To buy drugs/alcohol
- (vii) Others (please specify)

35. Habits

(A) (B)

- (i) Smoking (i) Watching TV/movies
- (ii) Alcohol consumption (ii) Playing indoor/outdoor games
- (iii) Drug use (specify) (iii) Reading books
- (iv) Gambling (iv) Religious activities
- (v) Begging (v) Drawing/ Painting/Acting
- (vi) Any other (vi) Any other

E. EMPLOYEMENT DETAILS

S.NO	Details of employment	duration	Wages earned
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cooly		
2	Rag picking		
3	Mechanic		
4	Hotel work		
5	Tea shop work		

6	Shoe polish		
7	Household work		
8	Others (please specify)		

36. Details of income utilization:

- (i) Sent to family to meet family need
- (ii) For dress material
- (iii) For gambling
- (iv) For prostitution
- (v) For alcohol
- (vi) For drugs
- (vii) For smoking
- (viii) Savings

37. Details of saving

- (i) Through employers
- (ii) Through friends
- (iii) Bank/post office
- (iv) Others (please specify)

38. Duration of working hours

- (i) Less than 6 hours
- (ii) Between 6 and 8 hours
- (iii) More than 8 hours

F. EDUCATIONAL DETAILS

39. The details of education of the juvenile prior to the admission to the children's home

- (i) Illiterate

- (ii) Studied up to V standard
- (iii) Studied above V standard below VIII standard
- (iv) Studied above VIII standard below X standard
- (v) Studied above X standard

40. The reason of leaving school

- (i) Failure in class last studied
- (ii) Lack of interest in school activities
- (iii) Indifferent attitude of the teacher
- (iv) Friend circle influence
- (v) To earn and support the family
- (vi) Sudden demise of parents
- (vii) Rigid school atmosphere
- (viii) Absenteeism followed by running away from school
- (ix) Others (please .specify)

41. The details of the school in which studied last:

- (i) Corporation/ Municipal/ panchayat union
- (ii) Government school Schedule caste welfare school/
other Backward welfare School.
- (iii) Private management
- (iv) Convents

42. Medium instruction:

Hindi/english/urdu/ tamil/malayalam/kannada/telegu, other language (please .specify)

43. After admission to children's home, the educational attainment from the date of admission till date :

No. of years class studied promoted/detained

44. Vocational training undergone from the date of admission into children's home till date :

No.of years name of vocational trade proficiency/attained

45. Extra curricular activities developed form the date of admission into the children's home till date

(i) Scout

(ii) Sports (please specify)

(iii) Athleclties (please specify)

(iv) Drawing

(v) Painting

(vi) Others (please specify)

G. Medical history

46. Height and weight at the time of admission :

47. Physical condition:

48. Medical history of the child:

49. Medical history of parent/guardian:

50. Present health status of the child:

S.No	Annual observation	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter	4 th quarter
1	Date of review				
2	height				
3	weight				
4	Nutrient diet given				
5	Stress disease				
6	ENT Tonsils				
7	External eye				

	problem				
	vision				
	left				
	right				

51. Height and weight chart

Date, month and year	Height	Admissible weight	Actual weight

H. SOCIAL HISTORY

52. Details of friendship prior to the admission the children's home

(i) Co-worker

(ii) School/classmate

(iii) Neighbour

(iv) Others (please specify)

53. Majority of friends are

(i) Educated

(ii) Illiterate

(iii) The same age group

(iv) Older in age

(v) Younger in age

(vi) Same sex

(vii) Opposite sex

54. Details of membership in group (please specify details)

- (i) Associated with cine fans associations
- (ii) Association with the religious group
- (iii) Associated with arts and sports club
- (iv) Associated with gangs
- (v) Associated with voluntary social service league
- (vi) Others (please specify)

55. The position of the child in the group/league

- (i) Leader
- (ii) Second level leader
- (iii) Middle level functionary
- (iv) Ordinary member

56. Purpose of taking membership in the group:

- (i) For social service activities
- (ii) For leisure time spending
- (iii) For pleasure seeking activities
- (iv) For deviant activities
- (iv) Others (please specify)

57. Attitude of the group/league

- i) Respect the social norms and follow the rules
- (ii) Interested in violating the rules
- (iii) Impulsive in violating the rules

58. The location meeting point of the group

- (i) Usually at fixed place
- (ii) Places are changed frequently
- (iii) No specific places
- (iv) Meeting point is fixed conveniently

59. The reaction of the society when the child first came out of the family

- (i) Supportive

- (ii) Rejection
- (iii) Abuse
- (iv) Ill-treatment
- (v) Exploitation

60. The reaction of the police toward the children

- (i) Passionate
- (ii) Cruel
- (iii) Abuse
- (iv) Exploitation
- (v) Illtreatment

61. The reaction of general public towards the child

HISTORY OF THE CHILD(GIST)

- (i) Education
- (ii) Health
- (iii) Vocational training
- (iv) Extra curricular activities
- (v) Others

Suggestion of child welfare officer/probation officer after orientation to juvenile/child and the the response towards orientation.

Follow up by the child welfare officer/ probation officer/ case worker/social worker

Quarterly review of case history by management committee

SUPERINTENDENT/

WELFARE OFFICER/

PROBATION OFFICER

Form XXI

(See rule 50 (12)(a), 54 (O) and 87(1)(k))

INDIVIDUAL CARE PLAN

Individual care plan for each child shall be prepared the principal of the best interest of the child. In preparing individual care plan the care option in the following order of the preferences shall be considered:

- (i) Preserving the biological family
- (ii) Kinship care
- (iii) In-country adoption
- (iv) Fosters-care
- (v) Inter national Adoption
- (vi) Institutional care

Case / profile No. Of 20 -----(years)of the
Board /committee

Admission No.

Date of admission

A. Personal Details

1. Name of the child :

2. Age :

3. Sex: Male/Female

4. Father's/ Mother's name:

5. Nationality :

6. Religion /Caste :

7. Educational Achievement :

8. SUMMARY OF CASE HISTORY

- Health needs
- Emotional and physical support needed
- Educational training needs
- Leave creativity and play
- Attachments and relationships
- Religious beliefs
- Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment
- Social mainstreaming
- Follow up post release/restoration from child home .

B. FORTNIGHTLY PROGRESS REPORT OF THE PROBATIONER

Part- one

1. Name of the Probation Officer/Case Worker
2. For the month of -----
3. Registration No:
4. Competent authority:
5. Profile No:
6. Name of the child:
7. Date of supervision order:
8. Address of the child:
9. Period of supervision:

Part- two

Place of interview

dates

1. Where the child is residing?
2. Progress made in any educational/ training course
3. What work he is doing and his monthly average earning, if employed.
4. Savings in the post office
5. Saving Bank account in his name
6. Remarks on his general conduct and progress
7. Whether properly cared for?

Part -Three

1. Any proceeding before the competent authority or
 - (a) Variation of conditions bond
 - (b) Charge of residence
 - (c) Other matters
2. Period of supervision completed on -----
3. Result of supervision with remarks(if any)
4. Name and address of the parent or guardian or fit person under whose care the juvenile is to live after the supervision

Date of report----- signature of the Probation Officer/Case worker -----

C. PRE-RELEASE REPORT

Tick whichever is applicable

Final release



Transfers



1. Details of place of transfer and concerned authority responsible in the place of transfer/release
2. Details placement of the juvenile/child in another institution
3. Training undergone and skills required
4. Final progress report of the officer in-charge/probation officer/ child welfare officer/ case worker/social worker (to be attached)
5. Date of release/ transfer
6. Date of repatriation
7. Requisition for escort if required
8. Identification of escort

9. Recommended rehabilitation plan including possible placement
10. Sponsorship requirement and report if possible
11. Identification of Probation Officer/Case Worker/Social Worker/Non Governmental Organization for posts release follows up
12. Memorandum of understanding with non governmental organization identified for the post-release follow up
13. Identification of sponsorship agency/individual sponsors for the child post-release if any
14. Memorandum of understanding between the sponsoring agency and individual sponsor
15. Details of Saving Account of the ,child if any
16. Details of child earning and belonging if any
17. Details of awards rewards to the child if any
18. Opinion of the child
19. Any other information

Note: pre-release report shall be prepared 6 months prior of the date of release/transfer to the juvenile/child and shall take into the account the recommendation of the last review report and all other relevant information

D. POST-RELEASE REPORT

1. Status of Bank Account : closed/transferred
2. Earning and belongings of the child handed over to the child or his parents/guardians- Yes/No
- 3 First interaction report of probation officer/child welfare officer/case worker/ social worker/ non-governmental organization identified and follow up with the child post release
- 4-Placement of the juvenile/child if any
- 5-Family's behaviour towards the child
- 6-Social environment of the child, particularly attitude of the neighbour/community
- 7-How is child using the skills acquired?
- 8- Whether the child has been admitted to school or vocation institution? Give date and name of the school/institute/ any other agency
- 9- Report of second and third follow up interaction with the child after two months and six months respectively .

Form XXII

(See rule 65 (2))

ESCORT ORDER

Case No-----

in the matter of Boy/Girl

Child-----

Aged about-----year

Taken action charged for

Sole custody under sub

Section (3) of section 33

of the juvenile justice Act,

2000

The parents of the boy/girl child has been given report to be residing at -----

----- He/she therefore be sent under

supervision of a proper police/nongovernmental organization escort to the -----

----- For tracing and for handling over to the parents or close relatives of the

said boy/girl child residing at the aforesaid address or at other place shown by the child

send in escort to the proper police/nongovernmental organization if no such parents and

relatives are traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in

custody of the superintendent----- children's home and the said

boy/girl child be produced before the concerned child welfare committee for further

orders.

ORDERS

Till the arrangement of escort, the said boy/girl child shall remain in the children's home,

residing at present at----- The State or District child protection

unit, or police department or non-governmental organization/ childline shall positively

make immediate arrangement not less then 15 days from the date of receipt of this order and send the said boy child/girl child at his/her aforesaid place of residence.

Dated this ----- day of-----20-----

Chairperson/ Member
Child Welfare Committee

Copy forward to :

1. The superintendent, children home
2. The State/District Child Protection Unit or non-governmental organization of the chidline.

Ref : 1. Order of admission of minor ----- date of birth on-----profile No-----

Chairperson/member
Child welfare committee,